राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 253

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 19 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सचिन को लॉरेस का 'सर्वश्रेष्ठ खेल लम्हे' का पुरस्कार

>> 14

सरोकार

30 साल के श्रम से चंदन वन में बदला ढाई किमी का बंजर

बिलासपुर : हिम्मत, जुनून और मेहनत के पसीने से हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पूर्व सैनिक ने बंजर जमीन को सींचा व फलदार बगीचे के साथ-साथ करीब ढाई किलोमीटर तक चंदन के पेड़ उगा दिए। अब इनकी खुशबू से क्षेत्र महक रहा है। (पेज-11)

जागरण विशेष

एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे सभी ऑनलाइन कोर्स

नई दिल्ली : आइआइटी दिल्ली के दो छात्रों वैभव श्रीवास्तव और मिलन रॉय द्वारा बनाई गई वेबसाइट एडवाइजर .कॉम पर छात्रों को एक लाख से अधिक ऑनलाइन कोर्स को चुनने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों की दिक्कतें खत्म होंगी। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन से मांगी माफी

मुंबई : महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव अमर सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर खेद जताया। अमर सिंह के बच्चन परिवार के साथ करीबी संबंध रह चुके हैं। कुछ साल पहले दोनों के संबंधों में दरार आ गई थी।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

शरजील का भाषण सुनकर ही लोग हुए थे हिंसक

नई दिल्ली : सीएए के खिलाफ 15 दिसंबर को दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी व जामिया नगर में शरजील इमाम के भाषण को सुनकर ही लोग आक्रोशित हुए थे और आठ घंटे तक हिंसक उपद्रव किया था। इस मामले में पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

लापता पाकिस्तानी जनरल की दो वर्ष पूर्व हो चुकी थी मौत

रियाद : कुछ वर्षों से लापता पाकिस्तान के सेवानिवृत्त जनरल शाहिद अजीज की दो साल पहले ही मौत हो चुकी है। यह दावा आतंकी संगठन अलकायदा की पत्रिका नवा-ए-अफगान जिहाद ने किया है। पत्रिका ने पहली बार यह भी दावा किया कि अलकायदा से अजीज के करीबी संबंध थे।

विविध ▶ पृष्ठ 15

महाराष्ट्र में एक और बैंक घोटाला, 76 नामजद

ठाणे : पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले के बाद महाराष्ट्र में एक और बैंक घोटाला सामने आया है। नया मामला कर्नाला नागरी सहकारी बैंक में 512.54 करोड़ रुपये की अनियमितता से जुड़ा है। इसमें पूर्व विधायक समेत 76 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बैंक का मुख्यालय रायगढ़ जिले के पनवेल में है।

राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त की घोषणा आज

इंतजार खत्म ▶ केंद्र की ओर से गठित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होगी पहली बैठक

महंत नृत्यगोपालदास को भी मिला है आमंत्रण, ट्रस्ट में शामिल किए जाने के संकेत

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

केंद्र सरकार द्वारा गठित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को पहली बैठक होगी। बैठक में राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त की घोषणा की जा सकती है। संभव है कि यह तिथि रामनवमी (2 अप्रैल) की हो। इसके साथ ही मंदिर के नक्शे, धन की व्यवस्था और ट्रस्ट के सदस्यों की जिम्मेदारियों का बंटवारा भी किया जा सकता है। वहीं बैठक में महंत नृत्यगोपालदास को आमंत्रण मिलने से ऐसे संकेत मिले हैं कि उन्हें भी ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है। महंत नृत्यगोपालदास मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट में शामिल होने के दावेदार थे, पर 5 फरवरी को ट्रस्ट की पहली सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर संतों में असंतोष भी उभरा था।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार ने किया था ट्रस्ट का गठन

बैठक का संभावित एजेंडा

- मंदिर निर्माण शुरू करने के मुहूर्त के साथ निर्माण की पूरी अवधि तय करना
- मंदिर के नक्शे के साथ धन संग्रहण की योजना तैयार करना
- बचे सदस्यों का चुनाव व पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों का बंटवारा
- निर्माण के दौरान पूजा के लिए भगवान राम की मूर्ति का स्थान तय करना

दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 में स्थित मकान (आर-20)। यह श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कार्यालय है। जागरण आर्काइव

केंद्र द्वारा गठित ट्रस्ट के सदस्य

- के. परासरन
- जगतगुरु स्वामी वासुदेवानंद
- जगतगुरु स्वामी विश्वास प्रसन्नतीर्थ, उडुपी
- स्वामी गोविंददेव गिरि
- युगपुरुष परमानंद
- कामेश्वर चौपाल
- डॉ. अनिल मिश्रा, होम्योपैथिक डॉक्टर
- विमलेंदु मोहन प्रताप मिश्रा, अयोध्या के शाही परिवार के सदस्य
- महंत धीरेंद्र दास, निर्मोही अखाड़ा

अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र सरकार ने भी मंगलवार के पेश बजट में अयोध्या को लेकर विशेष ख्याल रखा है। बजट में अयोध्या में प्रस्तावित एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये के अलावा पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 85 करोड़, तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। (विस्तृत खबर पेज 4 पर)

तय किए जाएंगे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष

बैठक में सदस्यों द्वारा ट्रस्ट के लिए दो अन्य सदस्यों व राम मंदिर कांप्लेक्स के विकास और प्रशासनिक देखरेख के लिए बनाई जाने वाली कमेटी के अध्यक्ष का चयन भी किया जा सकता है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समेत समिति के सदस्यों की जिम्मेदारियां भी तय की जानी हैं। बैठक में यह भी तय किया जाना है कि निर्माण कार्य के दौरान भगवान राम की मूर्ति कहां रखी जाएगी, ताकि दर्शन व पूजा-पाठ में कोई बाधा न आए। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि मंदिर निर्माण से जुड़े सभी विषयों को जल्द निपटा लिया जाए, ताकि निर्माण कार्य शुरू करने में देरी न हो।

विश्व हिंदू परिषद के मॉडल पर बन सकता है अयोध्या में मंदिर पेज>>7

भव्य मंदिर निर्माण के लिए दान-दाताओं की लगी कतार पेज>>7

मंदिर निर्माण को राम भक्तों की आस्था से जोड़ेंगे : ट्रस्ट की बैठक में मंदिर निर्माण के लिए फंड जुटाने की योजना पर विमर्श भी अहम होगा। प्रस्तावित मंदिर को लेकर जिस भव्यता-दिव्यता की कामना की जा रही है, उसे साकार करने में हजारों करोड़ रुपये का प्रबंध करना होगा। सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मंदिर निर्माण में शासकीय धन व्यय नहीं होगा। हालांकि पहले से ही मंदिर के लिए छह करोड़ रुपये से अधिक की राशि चंदे के रूप में जुटाई जा चुकी है। मंदिर निर्माण के लिए प्रयोग में आने वाले 70 फीसद पत्थरों को तराशने का काम भी पूरा हो चुका है। फिर भी मंदिर निर्माण को राम भक्तों की आस्था से जोड़ने के उद्देश्य से आगे की धन संग्रहण की रणनीति को भी उसी के अनुरूप अंतिम रूप दिया जाना है।

केंद्र ने घोषित किए हैं नौ सदस्य : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक दिल्ली में ग्रेटर कैलाश-1 स्थित कार्यालय में होगी, जो रामजन्म भूमि मामले की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन का कार्यालय है। वह भी केंद्र सरकार द्वारा इसी महीने गठित किए गए 15 सदस्यीय ट्रस्ट के अहम सदस्य हैं। सरकार ने परासरन समेत नौ सदस्यों के नाम घोषित किए हैं। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक-एक पदाधिकारी होंगे। अयोध्या के जिलाधिकारी (डीएम) भी इसके सदस्य हैं।

एनपीआर पर उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार के साथ

मुंबई, एजेंसियां : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वे राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर रोक नहीं लगाएंगे। इसमें कुछ भी विवादास्पद नहीं है। एनपीआर जनगणना है और मुझे नहीं लगता कि हर 10 साल बाद होने वाली इस कवायद से किसी पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, वे व्यक्तिगत रूप से एनपीआर में मांगी जाने वाली जानकारियों की जांच करेंगे। इससे महाराष्ट्र में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, सीएए और एनआरसी दोनों अलग हैं और एनपीआर अलग है। यदि सीएए को लागू किया जाता है, तो किसी को इससे डरने की जरूरत नहीं है। राज्य में एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा। यदि एनआरसी लागू किया जाता है, तो इससे न सिर्फ हिंदू या मुसलमान, बल्कि आदिवासी भी प्रभावित होंगे।

इस बीच, सीएए के मुद्दे पर गठबंधन साझीदार शिवसेना के अलग रुख के बारे में पूछे जाने पर राकांपा नेता शरद पवार ने कहा, ठाकरे का अपना विचार है, लेकिन जहां तक हमारा संबंध है, तो हमने इसके खिलाफ वोट डाला था। महाराष्ट्र में साझा सरकार है। किसी मुद्दे पर पार्टियों के विचार में फर्क हो सकता है, लेकिन हम मिल-बैठकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। बताते चलें कि कांग्रेस व राकांपा दोनों सीएए और प्रस्तावित एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने अपने यहां एनपीआर और सीएए लागू करने से इन्कार किया है। इनमें मप्र, बंगाल, केरल, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं।

ठाकरे बोले, भीमा कोरेगांव जांच केंद्र को नहीं सौंपेंगे : उद्धव ने कहा,उनकी सरकार भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच केंद्र को नहीं सौंपेगी। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में यलगार परिषद मामले की

- कहा-नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया जाता है तो किसी को इससे डरने की जरूरत नहीं
- ठाकरे के बयान को पवार ने निजी राय बताया, कहा-इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे

उद्धव ठाकरे फाइल फोटो

जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने की मंजूरी दी है। ठाकरे ने ट्वीट किया कि यलगार परिषद और भीमा कोरेगांव अलग-अलग मामले हैं। भीमा कोरगांव मामला अनुसूचित जाति की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। यह केंद्र को नहीं सौंपा जाएगा। अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ अन्याय नहीं होगा। इस बीच, शरद पवार ने दावा किया कि देवेंद्र फड़नवीस सरकार ने यलगार परिषद मामले में पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग किया। उन्होंने मांग की कि पुणे पुलिस की गतिविधि और फड़नवीस द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया जाना चाहिए।

ट्रंप के अहमदाबाद जाने को लेकर मोदी पर पवार का तंज : पवार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अहमदाबाद जाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, भारत आने वाली विदेशी हस्तियों के लिए गुजरात मनपसंद स्थान बन गया है। मोदी के पीएम बनने से पहले विदेशी हस्तियां आगरा, हैदराबाद और बेंगलुरु भी जाती थीं। यह अच्छी बात है कि पिछले पांच वर्षों में आने वाले लोगों ने सिर्फ अहमदाबाद को चुना। हमें खुशी है कि मोदी सोचते हैं कि भारत में विदेशी अतिथियों को दिखाने लायक अहमदाबाद सबसे अच्छी जगह है।

कश्मीर पंडितों के अच्छे दिन वापस आएंगे : शाह

नई दिल्ली : कश्मीरी पंडितों के खुशहाली भरे दिन वापस आएंगे। पंडितों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह भरोसा दिया है। शाह ने कहा कि उन्हें घाटी के उन जिलों में पूरी सुरक्षा के साथ वापस बसाया जाएगा, जहां से उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था। प्रतिनिधिमंडल ने अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के लिए अमित शाह को धन्यवाद दिया। (पेज-3)

अर्थव्यवस्था को कोरोना की मार से बचाने को सरकार तैयार

नई दिल्ली : अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने में जुटी केंद्र सरकार के सामने कोरोना वायरस ने नई चिंता पैदा कर दी है। सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने मौजूदा हालात की समीक्षा की। बुधवार को फिर बैठक होगी। पीएमओ भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। संभव है कि दो-तीन दिनों में कई उपायों का एलान किया जाए। (पेज-12)

गुलाम कश्मीर में आतंकियों से भरे पड़े हैं लांचिंग पैड : ढिल्लो

श्रीनगर, एजेंसी : सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने कहा है कि गुलाम कश्मीर में आतंकियों के लांचिंग पैड पूरी तरह सक्रिय व जिहादी आतंकियों से भरे पड़े हैं। पाकिस्तानी सेना अंतरराष्ट्रीय सीमा (आइबी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश रच रही है, लेकिन भारतीय सेना उसके नापाक मंसूबों को नाकाम कर रही है।

एक एजेंसी से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो ने कहा, आप पूरा यकीन रखें, पाकिस्तान अब घाटी में आतंकियों को धकेलने व शांति भंग करने में कामयाब नहीं होगा। सेना ने पुलिस, सीआरपीएफ व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कानून व्यवस्था व शांति बहाली की प्रक्रिया को मजबूत बनाया है। हमने कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रयास किए हैं। जम्मू-कश्मीर में बीते तीन दशकों से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हिंसा व छद्म युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, आज भी गुलाम कश्मीर में सभी आतंकी कैंप और लांचिंग पैड जिहादियों से भरे पड़े हैं।

- 15वीं कोर के कमांडर बोले-शांति भंग नहीं कर पाएगा पाकिस्तान
- घुसपैठ कराने की ताक में है पाकिस्तान सेना दे रही सबक सिखाने वाला जवाब

केजेएस ढिल्लो फाइल फोटो

पुलवामा के बाद पाक को बहुत कुछ समझ आ चुका : पुलवामा हमले से हफ्ते भर पहले चिनार कोर की कमान संभालने वाले ढिल्लो ने कहा, 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद आतंकियों और पाक को बहुत कुछ समझ आ गया है। इस हमले के बाद सेना ने न सिर्फ आतंकियों पर तीव्र प्रहार किए बल्कि पाक को उसकी ही भाषा में समझाया।

सेना ने आम लोगों के जान-माल व सम्मान को प्राथमिकता दी पेज>>6

मुंबई हमले को 'हिंदू आतंक' का रंग देने की पाकिस्तान ने रची थी साजिश : मारिया

मुंबई, एजेंसियां : पाकिस्तान और उसकी शह पर काम करने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मुंबई हमले को 'हिंदू आतंक' का रंग देने की साजिश रची थी, लेकिन आतंकी अजमल कसाब के जिंदा पकड़े जाने से चाल नाकाम हो गई थी। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त और आतंकी हमले की जांच करने वाले राकेश मारिया ने अपनी पुस्तक में ये सनसनीखेज राज उजागर किए हैं।

मारिया की पुस्तक 'लेट मी से इट नाउ' का सोमवार को विमोचन हुआ। उन्होंने कहा है कि लश्कर ने कसाब के हाथ में कलावा बांधकर भेजा था। उसके पास बेंगलुरु निवासी समीर चौधरी के नाम से पहचान पत्र भी था। अगर पाक और लश्कर की साजिश के मुताबिक, कसाब भी मार दिया गया होता तो हमले को 'हिंदू आतंक' का रूप दे दिया गया होता। तब मीडिया में इसे 'हिंदू आतंक' का कारनामा बताया जाता। अखबारों में 'हिंदू आतंकवाद' नाम पर बड़ी-बड़ी हेडलाइन होती, न्यूज चैनलों पर हिंदू आतंक के नाम से ब्रेकिंग खबरें चलती। कसाब के बेंगलुरु स्थिति घर पर उसके परिवार व पड़ोसियों से बात करने के लिए मीडिया की लाइन लग गई होती, लेकिन कसाब पाकिस्तान के फरीदकोट का अजमल आमिर कसाब निकला। मारिया ने कहा, लश्कर ने दूसरे आतंकियों के भी भारत में पते वाले पहचान पत्र बनाए थे। कसाब का फोटो जारी होने के सवाल पर कहा है कि यह केंद्रीय एजेंसियों का काम था। मुंबई पुलिस ने तो कसाब की पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि उसकी जान को खतरा था।

राकेश मारिया की किताब लेट मी से इट नाउ। ट्विटर

पूर्व पुलिस आयुक्त मारिया ने कहा, आतंकी अजमल आमिर कसाब के जिंदा पकड़े जाने से फेल हो गए पाकिस्तान के नापाक मंसूबे

लूटपाट के लिए लश्कर में गया था कसाब : मारिया ने किताब में कहा है- वह लगभग रोजाना कसाब से पूछताछ करते थे। वह लूटपाट करने के लिए लश्कर में शामिल हुआ था, उसका जिहाद से लेना-देना नहीं था। भारत में हमले के लिए भेजने से पूर्व लश्कर ने उसे सवा लाख रुपये और एक हफ्ते के लिए घर जाने की छुट्टी दी थी। रुपये उसने बहन की शादी के लिए परिजनों को सौप दिया था।

लोगों को नमाज पढ़ते देख हैरान था पेज>>3

जम्मू-कश्मीर में पंचायत उपचुनाव स्थगित

जम्मू : जम्मू-कश्मीर में पंचायत उपचुनाव को लेकर मंगलवार सुबह हुई सर्वदलीय बैठक और नेशनल कांफ्रेंस द्वारा अपने नेताओं की रिहाई की शर्त के बाद तेजी से बदले घटनाक्रम के बीच रात को चुनाव स्थगित कर दिया गया। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर जारी अधिसूचनाओं को वापस ले लिया गया है। कुमार ने 13 फरवरी को जम्मू में पत्रकार वार्ता कर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में रिक्त पड़े 1011 सरपंच और 11639 पंच हलकों के चुनाव दलीय आधार पर करवाने का एलान किया था। उसके साथ ही अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी कि मतदान आठ चरणों में करवाया जाएगा। पहले चरण का मतदान पांच मार्च और अंतिम चरण का मतदान 20 मार्च को होना तय किया था। (पेज-6)

रिपोर्ट

क्राई ने किशोरों में इंटरनेट के उपयोग पर जारी की रिपोर्ट, इंटरनेट उपयोग करने वाले 80 फीसद लड़कों और 59 फीसद लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए बेहतर निगरानी तंत्र बनाने की अपील

इंटरनेट के बुरे अनुभव का शिकार हर तीसरा किशोर

माला दीक्षित, नई दिल्ली

वर्तमान समय में इंटरनेट जरूरत बनने के साथ चुनौती भी पेश कर रहा है। विशेषकर बच्चों व किशोरों के लिए। दिल्ली-एनसीआर के लगभग आधे किशोरों को इंटरनेट की लत है। इतना ही नहीं इंटरनेट का उपयोग करने वाला हर तीन में से एक किशोर नकारात्मक अनुभव से गुजरा है। इस बात का पता चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) संस्था द्वारा किए गए अध्ययन से चलता है। क्राई ने इंटरनेट के बढ़ते उपयोग को देखते हुए ऑन लाइन सेफ्टी एंड इंटरनेट एडिक्शन पर जारी अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन दुनिया को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने को बेहतर निगरानी तंत्र की जरूरत पर बल दिया है। इसमें माता-पिता, संरक्षक व शिक्षक की भागीदारी के अलावा कानूनी उपाय की जरूरत बताई गई है।

गैर सरकारी संस्था क्राई ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट जारी की। दिल्ली-एनसीआर के

प्रतीकात्मक फोटो

13 से 18 साल की आयु के बीच के 600 से ज्यादा बच्चों पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि किशोरों, किशोरियों की इंटरनेट तक आसान पहुंच है। 93 फीसद किशोर किशोरी अपने घर का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 60 फीसद लड़कों और 40 फीसद लड़कियों के पास अपना मोबाइल फोन है। 80 फीसद लड़कों और 59 फीसद लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट थे। लेकिन उनमें से करीब तीन चौथाई को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए जरूरी न्यूनतम आयु की सही जानकारी नहीं थी। हर पांच में से दो इंटरनेट उपयोगकर्ता दोस्तों के दोस्त या पूरी तरह अजनबी का फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं, जिससे वे साइबर खतरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं।

क्राई की क्षेत्रीय निदेशक सोहा मोइत्रा ने कहा कि कम उम्र में साइबर स्पेस के व्यापक संपर्क और उपयोग गंभीर चिंता पैदा करते हैं। भारत में वयस्कों और बच्चों के बीच इंटरनेट का उपयोग पिछले एक दशक में काफी बढ़ा है। वैसे यह वृद्धि बहुत अच्छी है, क्योंकि यह लोगों के लिए रास्ते और अवसर प्रदान करती है लेकिन ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। बच्चों के लिए इसे सुरक्षित बनाए जाने की जरूरत है। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा नीतियों और कानूनी प्रावधानों से सुनिश्चित की जा सकती है।

अध्ययन से पता चला कि 48 फीसद उपयोगकर्ता किसी-न-किसी स्तर की इंटरनेट लत के शिकार थे। हालांकि गंभीर लत सिर्फ एक फीसद में ही देखी गई वो भी ज्यादातर किशोरों में देखने को मिली। इंटरनेट की लत उम्र के साथ बढ़ती गई और उन किशोर, किशोरियों में ज्यादा थी जिनके घर में अपना कमरा, अपना मोबाइल था और माता-पिता दोनों कामकाजी थे। रिपोर्ट में बच्चों को इंटरनेट की लत और खतरों से सुरक्षित रखने के लिए उनको इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की जरूरत बताई गई है। सिर्फ प्राइवेसी सेटिंग या माता-पिता का नियंत्रण काफी नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ इंटरनेट सेफ्टी रूल की जानकारी होना पर्याप्त नहीं है। इसके उपयोग की व्यावहारिक जानकारी भी होनी चाहिए और ऐसा पढ़ाई के दौरान क्लास रूम में हो सकता है। इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इसका प्रशिक्षण होना चाहिए। कहा गया है कि निजता मौलिक अधिकार है। ऐसे में सोशल मीडिया पर उपलब्ध बच्चों के डिजिटल फुटप्रिंट उनके खिलाफ नहीं प्रयोग होने चाहिए।

सरकार की दो टूक, डेबी अब्राहम्स भारत विरोधी मुहिम में शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सांसद डेबी अब्राहम्स का ई-बिजनेस वीजा उनकी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते रद किया गया था। सरकार ने डेबी के भारत आगमन से तीन दिन पहले ही 14 फरवरी को उन्हें इस बारे में जानकारी दे दी थी।

सूत्रों ने कहा, वीजा या इलेक्ट्रॉनिक यात्रा पत्र प्रदान करना, उसे खारिज या निरस्त करना किसी देश का संप्रभु अधिकार है। अब्राहम्स को पिछले साल सात अक्टूबर को ई-बिजनेस वीजा जारी किया गया था, जो कारोबारी बैठकों में भाग लेने के लिए पांच अक्टूबर, 2020 तक वैध था। 'भारत विरोधी गतिविधियों में उनके शामिल होने की वजह से 14 फरवरी, 2020 को उनका ई-बिजनेस वीजा रद कर दिया गया। इस बारे में उन्हें सूचित कर दिया गया।' सूत्रों ने कहा कि अब्राहम्स के पास विगत 18 फरवरी को यहां आइजीआइ एयरपोर्ट पहुंचने पर वैध वीजा नहीं था और इसीलिए उन्हें लौटने को कहा गया। ध्यान रहे कि कश्मीर पर ब्रिटिश संसदीय दल की अध्यक्ष अब्राहम्स को सोमवार को नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। लेबर पार्टी की सांसद ने कहा था कि वैध वीजा होने के बावजूद उन्हें यहां हवाई अड्डे पर उतरने के बाद भारत से वापस लौटा दिया गया।

दुष्प्रचार पर वार

- 14 फरवरी को इसी वजह से ब्रिटिश सांसद का ई-बिजनेस वीजा रद किया था
- सरकार ने कहा-वीजा खारिज करना किसी भी देश का संप्रभु अधिकार

सरकार के फैसले के साथ कांग्रेस पेज>>3

26.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा मंगलवार को राजधानी में, जबकि न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27 एवं 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 19 फरवरी 2020

न्यूज गैलरी

सैंपल पेपर की त्रुटियों को लेकर दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा 12 के अकाउंटेंसी सैंपल प्रश्नपत्रों में त्रुटियों को सुधारने की मांग करते हुए दायर की गई याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका को निम्न स्तर की बताते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने याचिकाकर्ता रविंद्र नाथ दुबे पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुख्य पीठ ने कहा कि परीक्षा पेपर के बजाय आप सैंपल पेपर की बात कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि मॉडल पेपर छात्रों के अभ्यास के लिए होते हैं। याचिकाकर्ता ने जब पीठ के समक्ष दलील पेश करने की कोशिश की तो पीठ ने कहा कि आप पर लगाया गया जुर्माना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते। याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता 26 वर्षों से अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि सीबीएसई की वेबसाइट पर दिए गए सैंपल पेपर में आठ मौलिक और वैचारिक रूप से गलत उत्तरों को हटाने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर छात्र बोर्ड परीक्षाओं में ये गलत उत्तर लिखते हैं तो उनके 7 से 8 अंक काटे जा सकते हैं। (जासं)

एनसीवेब की 125 छात्राओं को मिली नौकरी

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से संबद्ध नॉन कॉलिजिएट वूमेन एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) की तरफ से मंगलवार को दो दिवसीय मेगा प्लेसमेंट कार्यक्रम करवाया गया। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ मिलकर डीयू के नॉर्थ कैंपस स्थित कांफ्रेंस सेंटर में करवाया गया। यहां 23 कंपनियां पहुंची और इन्होंने कार्यक्रम के पहले दिन 125 छात्राओं को नौकरियों के ऑफर दिए। कार्यक्रम में एनसीवेब की निदेशक डॉ. गीता भट्ट, छात्र कल्याण डीन प्रो. राजीव गुप्ता, एनसीवेब के उपनिदेशक डॉ. उमाशंकर व एनसीवेब के श्री अरबिंदो कॉलेज के प्रभारी सहायक प्रोफेसर हंसराज सुमन मौजूद थे। डॉ. गीता भट्ट ने बताया कि एक हजार से ज्यादा छात्राओं ने प्लेसमेंट के लिए पंजीकरण करवाया। इनमें से 125 छात्राओं को प्लेसमेंट मिली। प्लेसमेंट कार्यक्रम के दूसरे दिन बुधवार को भी छात्राओं को प्लेसमेंट के अवसर मिलेंगे। छात्राओं को प्रति महीना 15 हजार से 27 हजार रुपये की नौकरियों के ऑफर मिले। (जासं)

विधायक दल का नेता चुनने के लिए सरोज बनीं केंद्रीय पर्यवेक्षक

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा विधायक दल के नेता चुनने के लिए राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडेय को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दरअसल, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने 70 में से आठ सीटों पर ही जीत हासिल की थी। इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और अभय वर्मा और अन्य पांच विधायकों ने चुनाव में जीत दर्ज की है। इन्हीं आठ में से किसी एक को विधायक दल का नेता बनाया जाना है। वर्ष 2015 में 70 में से तीन सीटें जीतने पर भाजपा ने विजेंद्र गुप्ता को विधायक दल का नेता बनाया था। इससे वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। संभवतः इसी सप्ताह में विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। (जासं)

गार्गी कॉलेज मामले में दो और आरोपित गिरफ्तार

दक्षिणी दिल्ली : गार्गी कॉलेज में जबरन घुसकर छात्राओं से छेड़छाड़ करने के मामले में हौजखास थाना पुलिस ने मंगलवार रात दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपित दिल्ली के रहने वाले छात्र हैं। डीसीपी दक्षिणी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि इनके बाकी साथियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए दोनों आरोपितों से पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज के शिनाख्त कर पुलिस इन दोनों आरोपितों तक पहुंची। गत छह फरवरी को गार्गी कॉलेज में फेस्टिवल के दौरान अज्ञात लोगों की भीड़ ने जबरन प्रवेश कर छात्राओं से न केवल छेड़छाड़ की बल्कि उन्हें धमकी भी दी। (जासं)

द पार्क होटल का लाइसेंस रद, खाली कराने की तैयारी

निहाल सिंह, नई दिल्ली

अग्निशमन विभाग की ओर से द पार्क होटल का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रद किये जाने के बाद नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने भी होटल के ट्रेड व हेल्थ लाइसेंस को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया है। एनडीएमसी ने होटल के जनरल मैनेजर को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। इसके बाद होटल को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। इस ट्रेड व हेल्थ लाइसेंस के निरस्त होने के बाद भी अगर होटल पहले की तरह अतिथियों को ठहराता है या उन्हें कोई अन्य सुविधाएं देता है तो एनडीएमसी इसे कभी भी सील कर सकता है।

पत्र में एनडीएमसी ने बताया है कि अग्निशमन विभाग के एनओसी के आधार पर एनडीएमसी ने 19 मई 2017 को जारी हेल्थ लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही होटल में मौजूद सात रेस्तरां, एक लॉजिंग, एक बैंक्वेंट हॉल व डिस्को का भी लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। एनडीएमसी के अनुसार इस लाइसेंस के बिना इटिंग हाउस, लॉजिंग हाउस को चलाया नहीं जा सकता। इसलिए होटल को सलाह दी जाती है कि जब तक पुनः हेल्थ लाइसेंस नहीं दिया जाता तब तक उक्त गतिविधियों को न कराया जाए। अगर होटल स्टाफ ऐसा करता है तो बिना किसी नोटिस के होटल को सील किया जा सकता है। हालांकि एनडीएमसी ने दोपहर को ही लाइसेंस रद होने का नोटिस होटल को दे दिया था। बावजूद इसके वहां पर अतिथियों का आना जारी था।

वहीं होटल के पब्लिक रिलेशन विभाग से इस बारे में जब संपर्क किया गया तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

द पार्क होटल में अतिथियों की जांच के लिए खड़े सुरक्षाकर्मी। जागरण

दमकल विभाग पार्क होटल को आज जारी करेगा एनओसी

जासं, नई दिल्ली : कनॉट प्लेस स्थित द पार्क होटल ने आग से बचाव की तमाम खामियों को दूर कर लिया है। इस संबंध में होटल प्रबंधन के पत्र के बाद मंगलवार को दमकल विभाग के अधिकारियों ने होटल का निरीक्षण किया। सारी व्यवस्था दुरुस्त पाए जाने पर दमकल विभाग ने होटल को क्लीन चिट दे दी है। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि होटल में विभाग द्वारा आग बुझाने से संबंधित बताए गए सभी उपाए कर लिए गए हैं। लिहाजा बुधवार को विभाग की ओर से होटल को एनओसी जारी कर दी जाएगी। दरअसल गत शनिवार को पार्क होटल के बेसमेंट में आग लग गई थी। दमकल विभाग को होटल में जांच के दौरान 11 खामियां मिली थीं। जिसके बाद विभाग ने होटल को दी गई एनओसी को अस्थाई तौर पर रद कर दिया था। इसके आधार पर दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग ने होटल का लाइसेंस रद कर दिया था। दमकल विभाग ने होटल को कमियां दूर करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। अधिकारियों ने बताया कि होटल सील होने की संभावना के तहत प्रबंधन ने रात-दिन काम कराकर तमाम खामियों को ठीक करा दिया। होटल सब कुछ सही पाए जाने पर दमकल विभाग की टीम ने होटल को दोबारा से एनओसी जारी करने का निर्णय लिया है।

शनिवार को लग गई थी होटल में आग : शनिवार को होटल के बेसमेंट में आग लग गई थी। पहले होटल कर्मियों ने अपने स्तर पर आग को बुझा दिया था, लेकिन कुछ देर बाद आग दोबारा लग गई थी। इस आग का धुआं होटल के कमरों में फैल जाने से वहां रह रहे विदेशी नागरिकों सहित अन्य लोग बीमार हो गए थे। दरअसल होटल में अग्निशमन का वेंटिलेशन सिस्टम ठप होने के अलावा वहां आग से बचाव की 11 अन्य खामियां अग्निशमन विभाग ने पाई थी। इसके आधार पर ही विभाग ने होटल की फायर एनओसी को अस्थायी तौर पर रद कर दिया था। पुलिस ने भी उसका लाइसेंस रद कर दिया था।

17 हजार उद्यमी दिल्ली सरकार के छात्रों से करेंगे चर्चा

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों से अब 17 हजार उद्यमियों को जोड़ा जाएगा। यह सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों से उद्यमिता पर चर्चा करेंगे और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताएंगे। पिछले वर्ष 4 हजार उद्यमियों ने 3,10,309 छात्रों से अपनी उद्यमिता यात्रा की चर्चा की थी। इस वर्ष इसका दायरा और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में शुरू किए गए उद्यमिता पाठ्यक्रम के तहत 17 हजार उद्यमी कक्षाओं में छात्रों के साथ इस विषय पर बात करेंगे।

मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यह फैसला लिया है। उन्होंने उद्यमिता पाठ्यक्रम की मंगलवार को समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), शिक्षा निदेशालय और उद्यमिता पाठ्यक्रम की कोर समिति के सदस्य शामिल हुए थे। साथ ही अगामी अप्रैल व जुलाई महीने से 11वीं व 12वीं के छात्रों के लिए उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देते हुए उनके लिए फील्ड प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इन छात्रों को इसी पाठ्यक्रम के अनुरूप फील्ड प्रोजेक्ट के लिए एक हजार रुपये की सीड मनी भी दी जा रही है।

केजरीवाल कैबिनेट की पहली बैठक आज

नई पारी ▸ गारंटी कार्ड के 10 बिंदुओं पर होगी चर्चा, यमुना व दिल्ली की सफाई भी बड़ा मुद्दा

मुख्यमंत्री सरकार के तीन महीने के एजेंडे पर जानेंगे मंत्रियों से उनकी योजना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली की नवनिर्वाचित केजरीवाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बुधवार को होगी। सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में होनी वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री 'आप सरकार' के गारंटी कार्ड सहित यमुना-सफाई एवं दिल्ली की साफ-सफाई को लेकर अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। सरकार गठन के बाद आयोजित होने वाली इस पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री अपनी सरकार की दस गारंटियों को लागू करने एवं भविष्य में बिना किसी रुकावट के इनके जारी रहने पर भी बात होगी।

दिल्ली सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री हर हाल में सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी सरकार बिना किसी देरी के जनता के हित में काम करे। अधिकारी एवं मंत्री लोगों की समस्याएं एवं जरूरतों के हिसाब से योजनाओं का क्रियान्वयन करें। सरकार की हर योजना का फायदा समाज के निचले तबके तक जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि बुधवार को होने वाली पहली कैबिनेट बैठक में सरकार की दस गारंटियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के प्रति भी सरकार प्रतिबद्ध है। इसीलिए राजधानी की साफ-सफाई व्यवस्था एवं कूड़ा निस्तारण का इंतजाम अत्याधुनिक तरीके से किया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री स्वयं इन चीजों को लेकर गंभीर हैं। यमुना की सफाई एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाना उनकी प्राथमिकता है।

अरविंद केजरीवाल। फाइल

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में सरकार ने बहुत काम कराए हैं। ये काम लगातार जारी रहेंगे। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य की प्रगति का भी जायजा लेंगे। वे संबंधित मंत्री से इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा छात्रों की फ्री बस यात्रा पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सरकार के तीन महीने के एजेंडे पर मंत्रियों से उनकी योजना जानेंगे।

कैबिनेट के बाद होगी शीर्ष अधिकारियों की बैठक : कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बुधवार को शीर्ष अधिकारियों की भी बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक सचिवालय में ही दोपहर को होने वाली इस बैठक के एजेंडे में पेयजल आपूर्ति, सभी बच्चों के लिए शिक्षा, समाज के विभिन्न तबकों के लिए निःशुल्क बस सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सुरक्षा एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली इत्यादि शामिल हैं। बैठक में सभी सचिवों और प्रधान सचिवों को शामिल होने के लिए कहा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर मंगलवार को एक बैठक आयोजित की जिसमें अधिकारियों ने बुधवार की बैठक में रखे जाने वाले विषयों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने की उपराज्यपाल से मुलाकात

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से शिष्टाचार भेंट की। करीब 10 मिनट की यह मुलाकात उपराज्यपाल सचिवालय में ही हुई। बैठक का कोई खास एजेंडा नहीं था। बताया कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल अनौपचारिक तौर पर उनसे मिलने के लिए गए थे।

मालूम हो कि पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच काफी दूरियां थीं, लेकिन नए कार्यकाल की शुरुआत करते ही मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर इस दूरी को कम करने का संदेश दिया है। राजधानी में सेवा विभाग भी उपराज्यपाल के पास ही है जिससे नौकरशाहों के तबादले के अधिकार भी उपराज्यपाल के पास ही हैं। इस लिहाज से मुख्यमंत्री की यह अनौपचारिक मुलाकात भी कई मायनों में अहम मानी जा रही है।

सॉफ्टवेयर को इंटर लिंक करने से बढ़ेगी मालिकाना हक देने की रफ्तार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- डीडीए ने मालिकाना हक पंजीकरण के लिए शुरू किया था पोर्टल
- अब तक 2.21 लाख लोग करा चुके हैं अपना पंजीकरण

पिछले दो माह से भले ही अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक देने का काम धीमी रफ्तार से चल रहा हो, लेकिन जल्द ही इसके रफ्तार पकड़ लेने की संभावना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) इसके लिए अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कराकर उसे इंटरलिंक करवा रहा है। ऐसा होने के बाद आवेदकों को कन्वेंस डीड जारी करने की प्रक्रिया भी जोर पकड़ने लगेगी।

मालिकाना हक का पंजीकरण कराने के लिए डीडीए ने 16 दिसंबर को अपना पोर्टल शुरू किया था। करीब दो महीन में इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या 2.21 लाख के करीब पहुंच गई है। लेकिन कन्वेंस डीड अभी तक केवल 151 लोगों को मिल पाई है। वजह है सर्वे और कागजों के सत्यापन में समय लगना। पोर्टल पर डीडीए के सभी मॉड्यूल भी आपस में लिंक नहीं हैं। मसलन, पहले पोर्टल पर पंजीकरण कराकर अपना आइ डी नंबर लेना पड़ता है। उसके बाद आवेदन जमा कराने के लिए फिर से पोर्टल पर जाना पड़ता है। संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होते हैं। इसके बाद डीडीए के लिए काम कर रही निजी फर्मों की टीम संपत्ति का सर्वे करती है। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन कर आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने पर उसे कन्वेंस डीड जारी की जाती है।

डीडीए अब पोर्टल के सॉफ्टवेयर को अपडेट कराकर इसके सभी मॉड्यूल आपस में इंटर लिंक करवा रहा है। जल्द ही यह कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद मालिकाना हक लेने वालों को बार-बार पोर्टल पर नहीं जाना पड़ेगा। एक ही बार में ज्यादातर काम पूरा हो जाएगा। फिर केवल संपत्ति के सर्वे और कागजी सत्यापन का काम बचेगा। इसके लिए भी डीडीए टीमें बढ़ा रहा है।

केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस मुददे पर डीडीए से नियमित अपडेट लेते हैं। यही वजह है कि डीडीए ने 9,950 संपत्तियों का सर्वे पूरा कर लिया है। इससे करीब 1100 लोगों को कन्वेंस डीड देने का रास्ता भी साफ हो गया है। कन्वेंस डीड के आधार पर ही संबंधित सब रजिस्ट्रार कार्यालय से आवेदक को रजिस्ट्री जारी होती है।

एक वर्ष तक बंद रहेगी एयरपोर्ट को रंगपुरी से जोड़ने वाली सड़क

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

फेज-3-ए विस्तार योजना के तहत ईस्टर्न क्रॉस टैक्सी-वे (ईसीटी) के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग-8 (एनएच-8) पर रंगपुरी से जोड़ने वाली सड़क को बुधवार दोपहर से बंद किया जाएगा। निर्माण कार्य के चलते यह मार्ग एक वर्ष तक बंद रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा स्वीकृत डायवर्जन प्लान के अनुसार, रंगपुरी गोल चक्कर से आने वाले ट्रैफिक को सेंट्रल स्पाइन रोड की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जो महिपालपुर से टर्मिनल-2 और 3 को जोड़ता है। शिव मूर्ति, द्वारका और गुड़गांव से टर्मिनल 2 और 3 पर आने वाले यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने रेडिसन बाईपास को चालू किया है। टर्मिनल 3 के लिए मौजूदा रेडिसन रोड/रंगपुरी की ओर नवनिर्मित डायवर्जन रोड 6-लेन डबल कैरेज-वे रोड है।

रंगपुरी और गुड़गांव से टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 की तरफ आने वाले वाहन सिग्नल-फ्री वेस्टर्न कैरेज-वे का उपयोग करेंगे, जो महिपालपुर गोल चक्कर के पास एनएचएआइ टोल प्लाजा से शुरू होता है और एयरोसिटी मेट्रो स्टेशन के सामने मौजूदा टी-जंक्शन से लगभग 480 मीटर पर सेंट्रल स्पाइन रोड से मिलता है। यह डायवर्जन रोड पूर्वी कैरेज-वे टर्मिनल-2 और 3 से रंगपुरी और गुड़गांव के लिए जाने वाले वाहनों के लिए है। टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 से निकलने वाले यात्री सेंट्रल स्पाइन रोड पर आने के लिए दायीं तरफ मुड़ेंगे। यहां से डायवर्जन रोड पर आने के लिए सिग्नल वाले जंक्शन से दक्षिण की तरफ जाना होगा, जो एनएचएआइ टोल के सामने महिपालपुर गोल चक्कर के पास रेडिसन रोड से मिलता है। सेंट्रल स्पाइन रोड पर नया सिगनलाइज्ड जंक्शन एयरोसिटी मेट्रो स्टेशन के सामने मौजूदा टी-जंक्शन से लगभग 300 मीटर दूर है। डायवर्जन रोड नए बनाए गए मार्ग द्वारा एयरपोर्ट हेल्थ आर्गेनाइजेशन (एपीएचओ) के आने-जाने वाले ट्रैफिक के लिए भी काम करेगा।

डायल ने जगह-जगह लगाए बोर्ड : डायल ने यात्रियों की सुविधा के लिए डायवर्जन के बारे में जगह-जगह सूचना बोर्ड भी लगाए हैं। लोगों को डायवर्जन के कारण आइजीआइ एयरपोर्ट पर सही समय पर आने के लिए 10-15 मिनट का अतिरिक्त समय लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि डायल के अधिकारियों के मुताबिक इस डायवर्जन का कोई असर एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों पर नहीं पड़ेगा।

हिंदू व सिख शरणार्थी परिवार के बच्चों को शिक्षा दिलाएगी डीएसजीपीसी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) द्वारा मजनूं का टीला क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदू व सिख शरणार्थी परिवार के बच्चों को निशुल्क शिक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर संचालित 11 प्रतिष्ठित गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूलों में इन बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। इन बच्चों को गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूलों में प्रवेश दिए जाने के लिए कमेटी ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से अनुमति मांगी है। इस मामले में वह शरणार्थी परिवारों के प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी हस्तक्षेप की मांग करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अप्रैल से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में इन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश मिल जाएगा।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इसके अलावा मेधावी बच्चों को छात्रवृति तथा अन्य प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी इन बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर रही है ताकि कोई वैधानिक विकल्प निकालकर इन बच्चों की पढ़ाई सुचारू रखने का रास्ता जल्द निकाला जा सके।

ओएचई में खराबी से अब मेट्रो का परिचालन नहीं होगा ज्यादा प्रभावित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

तकनीकी खराबी के कारण मेट्रो का परिचालन प्रभावित होने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। परेशानी तब ज्यादा होती है जब ओएचई (ओवर हेड इक्युपमेंट) में खराबी आ जाए। ऐसी सूरत में कई बार घंटे परिचालन प्रभावित होने की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने तीन पुराने मेट्रो कॉरिडोर (रेड, येलो व ब्लू लाइन) पर ट्रैक्शन सिस्टम में बदलाव करने की तैयारी की है। इन तीनों कॉरिडोर पर ऐसे अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे जिससे ओएचई खराब होने पर मेट्रो कॉरिडोर के बड़े हिस्से पर बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इसलिए मेट्रो का परिचालन ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, बल्कि उसका असर कॉरिडोर के कम हिस्से पर होगा।

डीएमआरसी इस योजना पर 33.82 करोड़ खर्च करेगा। डीएमआरसी का कहना है कि ओएचई में खराबी आने पर उस मेट्रो कॉरिडोर के बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति ठप करनी पड़ती है। इस वजह से उस हिस्से पर सिंगल लाइन पर परिचालन करना पड़ता है। इस वजह से परिचालन प्रभावित होने का असर अधिक दिखता है। इस वजह से ट्रैक्शन सिस्टम में बदलाव करने का फैसला किया गया है। इस योजना पर अमल के बाद ओएचई में खराबी होने पर घटना स्थल के आसपास के एक-दो स्टेशनों के बीच ही परिचालन पर असर पड़ेगा। बाकी हिस्से पर परिचालन ठीक हो सकेगा। इससे यात्रियों को असुविधा कम होगी। रेड लाइन (रिठाला-दिलशाद गार्डन), ब्लू लाइन (द्वारका सेक्टर 21-नोएडा सिटी सेंटर-इलेक्ट्रॉनिक सिटी) व येलो लाइन (समयपुर बादली-हुडा सिटी सेंटर) ये तीनों पुराने कॉरिडोर हैं। यह देखा गया है कि ओएचई में खराबी की सबसे ज्यादा घटनाएं इन कॉरिडोर पर ही होती हैं। कई बार तो महत्पूर्ण अवसर पर ओएचई में खराबी के कारण यात्रियों को घंटो परेशान होना पड़ा है। डीएमआरसी की नई पहल से यात्रियों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। हालांकि किस तरह के उपकरण लगाए जाएंगे अभी यह जानकारी डीएमआरसी ने नहीं दी है।

दिल्ली मेट्रो। फाइल

प्रत्यारोपण के योग्य नहीं मिला डोनर, धरी रह गईं एम्स की तैयारियां

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : एम्स में सोमवार को फेफड़ा प्रत्यारोपण की पूरी तैयारी थी। ब्रेन डेड घोषित बुजुर्ग के परिजनों ने फेफड़ा दान की स्वीकृति भी दे दी थी। प्रत्यारोपण के लिए मरीज व डॉक्टरों की टीम भी तैयार थी, लेकिन डॉक्टरों ने ब्रांकोस्कोपी जांच के बाद डोनर का फेफड़ा प्रत्यारोपण के योग्य नहीं माना। इस वजह से एम्स की तैयारी धरी रह गई। हालांकि एम्स प्रशासन का कहना है कि संस्थान फेफड़ा प्रत्यारोपण के लिए तैयार है। उपयुक्त डोनर मिलने पर प्रत्यारोपण शुरू कर दिया जाएगा।

दरअसल, एम्स लंबे समय से इस कोशिश में है कि संस्थान में फेफड़ा प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो। इसके लिए एम्स ने लाइसेंस भी ले रखा है। लेकिन, अभी तक संस्थान में एक भी फेफड़ा प्रत्यारोपण नहीं हुआ है।

अंगदान में अभी हैं कई बाधाएं : एम्स के ऑर्बो की प्रभारी व संस्थान की प्रवक्ता डॉ. आरती विज ने कहा कि हाल के वर्षों में अंगदान के प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। फिर भी अभी कई तरह की बाधाएं हैं। धार्मिक मान्यताएं भी आड़े आती हैं। इसलिए अंगदान के प्रति अभी और जागरूकता की जरूरत है। देश में हर साल करीब दो लाख लोगों को किडनी, 75 हजार मरीजों को लिवर, दो लाख लोगों को कॉर्निया व करीब 10 हजार मरीजों को दिल प्रत्यारोपण की जरूरत होती है।

आयोजन

कश्मीर की संस्कृति से सराबोर हुआ डीयू

मीरास-ए-कश्मीर कार्यक्रम में कलाकारों ने लोकगीतों की प्रस्तुति से बांधा समां, संतूर वादक भजन सोपोरी ने कहा-कश्मीर के सूफीवाद को पूरे भारत को समझना चाहिए

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नॉर्थ कैंपस के सर शंकर लाल कंसर्ट हॉल में कश्मीर की संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए मंगलवार को मीरास-ए-कश्मीर कार्यक्रम करवाया गया। इस कार्यक्रम में कश्मीर के कलाकारों ने लोकगीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में समाजसेवी, कवि व राजनेता डॉ. कर्ण सिंह के साथ जेएनयू के अंतरराष्ट्रीय राजनीति संगठन एवं निरस्त्रीकरण केंद्र के अध्यक्ष प्रो. अमिताभ मट्टू, संतूर के प्रसिद्ध प्रतिपादक व प्रतिष्ठित कलाकार पंडित भजन सोपोरी, डीयू के कुलपति प्रो. योगेश त्यागी और डीयू के पर्यावरण विभाग के प्रो. एमके पंडित उपस्थित हुए। पंडित भजन सोपोरी ने शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया। इसके अलावा दौलत राम कॉलेज की संगीत की सहायक प्रोफेसर डॉ. सपना रायना कचरू, गायक वसीम अहमद भट्ट व गायक मुकेश कुमार ने कश्मीर लोक गीतों को गाकर लोगों को सराबोर कर दिया। यह सभी कलाकर जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं। साथ ही डीयू के संगीत विभाग के पीएचडी के छात्रों ने भी कश्मीर लोकगीतों को गाया।

डीयू के सर शंकर लाल कंसर्ट हॉल में आयोजित मीरास-ए-कश्मीर कार्यक्रम में संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी अपनी प्रस्तुति देते हुए। जागरण

पंडित भजन सोपोरी ने बताया कि कश्मीर की संस्कृति को मिरास कहते हैं। कश्मीर के सूफीवाद व यहां की संस्कृति को पूरे भारत को समझना चाहिए।

कश्मीर की संस्कृति पर की जाए शोध : डीयू कुलपति : वहीं कार्यक्रम में डीयू के कुलपति प्रो. योगेश त्यागी ने कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी है। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति, खान-पान, परंपरा व साहित्य की महत्वता बहुत अधिक है। इसे प्रस्तुत करने के लिए कश्मीर के शिक्षाविद हमारे बीच हैं। उन्होंने छात्रों के साथ ही शिक्षाविदों से आग्रह किया है कि वे उन मुद्दों पर गुणवत्तापूर्ण शोध करें जो दुनिया के सामने कश्मीरी संस्कृति की आंतरिक सुंदरता सामने लाते हैं। उन्होंने बताया कि डीयू के उन शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए एक लाख रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जो कश्मीरी संस्कृति और संगीत पर गुणवत्ता शोध करते हुए अपने लेख अनुक्रमित पत्रिकाओं में प्रकाशित करेंगे।

दो लोगों के अंगदान से सात लोगों को मिला जीवनदान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- एम्स के निदेशक ने दोनों डोनर के परिवार के जज्बे की तारीफ की

एम्स में 48 घंटे के अंदर ब्रेन डेड घोषित दो लोगों के अंगदान से सात लोगों को जीवनदान मिला। इसमें से दो मरीजों को लिवर, चार मरीजों को किडनी व एक मरीज को दिल प्रत्यारोपित हुआ। एम्स के डॉक्टरों ने दोनों लिवर, दो किडनी व दिल का प्रत्यारोपण किया। वहीं दो किडनी आरएमएल अस्पताल में भेजी गई। जहां दो मरीजों को किडनी प्रत्यारोपण हुआ। इसके अलावा अंगदान में मिले चारों कॉर्निया, चार हार्ट वाल्व व हड्डियां सुरक्षित टिश्यू बैंक में रखी गई हैं। इस तरह कई अन्य मरीजों की जिंदगी भी रोशन हो सकेगी।

एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने दोनों डोनर के परिवार के जज्बे की तारीफ की है। एम्स के अनुसार 26 वर्षीय सचिन नामक युवक को 13 फरवरी को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया था। वह उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला था और मजदूरी करता था। दूसरी मंजिल से गिरने के कारण उसे गंभीर चोट लगी थी। 15 फरवरी को उसे डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया। एम्स के ऑर्गेन रीट्रिवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की प्रभारी डॉ. आरती विज ने कहा कि काउंसलिंग के बाद परिजनों ने अंगदान की स्वीकृति दी। इसके बाद देर रात को दिल, लिवर, किडनी व दोनों कॉर्निया दान की प्रक्रिया पूरी हुई। दिल 21 साल के एक युवक को प्रत्यारोपित किया गया। वहीं एम्स में लिवर 43 वर्षीय पुरुष मरीज को व एक किडनी 30 वर्षीय युवती को प्रत्यारोपित की गई। वहीं दूसरी किडनी आरएमएल में 34 वर्षीय युवक को प्रत्यारोपित की गई। वहीं 17 फरवरी की रात 61 वर्षीय अनिल मित्तल ने अंगदान किया। उनका परिवार अंगदान के प्रति जागरूक है। अनिल ने भी दधीचि देहदान समिति में अंगदान के लिए पंजीकरण कराया था। इसलिए उनके ब्रेन डेड होने पर परिवार के लोगों ने उनका हृदय, फेफड़ा, लिवर, दोनों किडनी, कॉर्निया व हड्डी दान की स्वीकृति दी। लेकिन हृदय व फेफड़ा प्रत्यारोपण के लिए योग्य नहीं पाया गया। इसलिए लिवर व एक किडनी दो मरीजों को एम्स में प्रत्यारोपित किए गए।

हिंदू की किडनी से मुस्लिम नवयुवक को मिली जिंदगी : एम्स में अंगदान से सांप्रदायिक सौहार्द की बेहतरीन मिसाल पेश की। आरएमएल अस्पताल के नेफ्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. हिमांशु महापात्रा ने बताया कि एम्स में जिस बुजुर्ग ने अंगदान किया उनकी एक किडनी आरएमएल में 17 वर्षीय नवयुवक को प्रत्यारोपित किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में खास बात यह है कि डोनर हिंदू हैं, जबकि जिस मरीज को किडनी प्रत्यारोपण हुआ वह मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि यह नवयुवक टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित है। इस वजह से उसकी किडनी खराब हो गई और आंख की रोशनी भी जा चुकी है।

415 बड़े रेलवे स्टेशनों पर गूगल की मदद से उपलब्ध कराई जा रही मुफ्त वाईफाई सेवा बंद होने वाली है। हालांकि इससे सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेलटेल देश के 5,600 रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराती रहेगी।

न्यूज गैलरी

मनोहर पर्रीकर के नाम पर होगा रक्षा संस्थान का नाम

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर की 'प्रतिबद्धता और विरासत' के सम्मान में सरकारी थिंक टैंक रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आइडीएसए) का नाम बदलकर मनोहर पर्रीकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान कर दिया है। पर्रीकर नौ मार्च, 2014 से लेकर 14 मार्च, 2017 तक रक्षा मंत्री थे। उन्होंने पठानकोट और उड़ी जैसे हमलों की चुनौती के दौर में रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व किया और साहस के साथ उनका (चुनौतियों का) जवाब दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान सशस्त्र बलों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को लागू करना था। पिछले साल 17 मार्च को कैंसर से उनका निधन हो गया। (प्रेट्र)

पीजीडीएम-एमबीए पाठ्यक्रम साथ नहीं चला सकते विवि

नई दिल्ली : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने कहा है कि सरकारी और निजी विश्वविद्यालय अब एक साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (पीजीडीएम) और एमबीए पाठ्यक्रम नहीं चला सकते। उन्हें दोनों में से किसी एक पाठ्यक्रम का चुनाव करना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा नियामक का कहना है कि पीजीडीएम पाठ्यक्रम सिर्फ भारतीय प्रबंध संस्थान (आइआइएम) जैसे स्वतंत्र संस्थान ही चला सकते हैं जो न तो विश्वविद्यालय हैं और न ही किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। (प्रेट्र)

एजेएल के चेयरमैन मोतीलाल वोरा की याचिका खारिज

चंडीगढ़ : नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के चेयरमैन व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा की एक याचिका को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए वापस लेने की छूट दे दी। मंगलवार को एजेएल की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उसने सक्षम प्राधिकरण के सामने अपील दायर कर दी है। ऐसे में अब वह इस याचिका को यहां जारी नहीं रखना चाहता। (राज्य ब्यूरो)

विजय माल्या की याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शराब कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। इसमें उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने व उसकी संपत्तियां जब्त करने संबंधी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। अर्जी पर मार्च में होली के बाद सुनवाई करेगी। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के प्रत्यर्पण फैसले के खिलाफ ब्रिटिश हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई के बाद गुरुवार को विजय माल्या ने पत्रकारों से कहा था, 'सीबीआइ और ईडी की कार्रवाई अनुचित है। (एएनआइ)

कश्मीरी पंडितों के अच्छे दिन आएंगे

घर वापसी ▶ अमित शाह ने कश्मीर में ससम्मान वापसी का दिया भरोसा

प्रतिनिधिमंडल ने अनुच्छेद 370 व 35ए हटाने के लिए गृहमंत्री का जताया आभार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कश्मीरी पंडितों के खुशहाली भरे पुराने दिन वापस आएंगे। कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह भरोसा दिया है। कश्मीर पंडितों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के दौरान अमित शाह ने कहा कि उन्हें घाटी के उन जिलों में पूरी सुरक्षा के साथ वापस बसाया जाएगा, जहां से उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था। प्रतिनिधिमंडल ने अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के लिए अमित शाह को धन्यवाद दिया।

अमित शाह के साथ करीब एक घंटे तक चली मुलाकात के बाद सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने बताया कि गृहमंत्री ने कश्मीरी पंडितों की ससम्मान घर वापसी का पूरा भरोसा दिया है। शाह ने उन्हें बताया कि सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया कराने के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर प्रशासन में भागीदारी बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इसके तहत कश्मीरी पंडितों के लिए सरकारी नौकरी में प्रवेश की सीमा 50 साल तक करने का प्रावधान किया जा सकता है। दरअसल इन पंडितों को कश्मीर छोड़े लगभग तीस साल हो गए हैं। केंद्र सरकार विस्थापित कश्मीरी पंडितों की अपनी संपत्तियों को वापस हासिल करने में भी मदद करेगी। इसीलिए शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के जिलों में फिर से बसाया जाएगा। इसके साथ ही घाटी में तोड़े गए सभी मंदिरों व धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार भी करेगी, ताकि कश्मीर की साझा संस्कृति को मूल रूप पुनर्स्थापित किया जा सके।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीरी प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सरकार किस तरह कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार सृजन का प्रयास कर रही है। अनुच्छेद 370 और 35ए के निरस्त होने के बाद राज्य की जनता को कई केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके साथ ही सरकार जम्मू-कश्मीर में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल महीने में बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसमें देश-विदेश की कई बड़ी कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद है।

ध्वंस किए सभी मंदिर व धार्मिक स्थलों का किया जाएगा जीर्णोद्धार ताकि कश्मीर की साझा संस्कृति को पुनर्स्थापित किया जा सके

वादे जो करने हैं पूरे

- पूरी सुरक्षा के साथ सरकार का प्रशासन में भागीदारी बढ़ाने का विचार
- सरकारी नौकरी में प्रवेश की सीमा 50 साल तक करने का प्रावधान भी संभव
- विस्थापित पंडितों की संपत्तियां उन्हें वापस दिलाने में भी मदद करेगी सरकार

गृहमंत्री अमित शाह से मंगलवार को नई दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। दल ने अनुच्छेद -370 और 35ए हटाने के लिए गृहमंत्री का आभार जताया। एएनआइ

'कस्टडी की लड़ाई बच्चे हारते हैं और भारी कीमत चुकाते हैं'

▶ तलाक के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कस्टडी की लड़ाई में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पति-पत्नी में से कौन जीतता है, लेकिन इसमें बच्चों की हमेशा ही हार होती है। बच्चे ही इसकी सबसे भारी कीमत चुकाते हैं क्योंकि वे बिखर जाते हैं जब न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अदालत उन्हें माता या पिता में से किसी एक के साथ जाने के लिए कहती है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती फिर भी वे अपने माता-पिता के प्यार-दुलार से वंचित हो जाते हैं।

एक दंपती में लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद पर फैसले के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने की जरूरत है क्योंकि वे माता और पिता दोनों का ही प्यार पाने के अधिकारी हैं। शादी टूटने का मतलब माता-पिता की जिम्मेदारी खत्म हो जाना नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों को कस्टडी के मामलों का निपटारा बच्चों के सर्वाधिक हितों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए जो इस लड़ाई में पीड़ित होते हैं। अगर मध्यस्थता की प्रक्रिया का कोई परिणाम न निकले तो अदालतों को मामले का समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ बच्चा भारी कीमत चुकाता है।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

पीठ ने कहा कि बच्चे की कस्टडी का फैसला करते समय पहली और सर्वोपरि सोच हमेशा बच्चे की बेहतरी होती है और अगर बच्चे की बेहतरी की बात हो तो तकनीकी आपत्तियां बाधा नहीं बन सकतीं। इस मामले में शीर्ष अदालत ने हमेशा सहमति से विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पति-पत्नी का अहंकार आड़े आ गया और उनके दो बच्चों की पीड़ा अंतहीन हो गई है। पीठ ने आगे कहा, 'इस मामले में वैवाहिक विवाद के चलते दादा-दादी न सिर्फ अपने बच्चों बल्कि अपने पोते-पोतियों के प्यार दुलार से भी वंचित हुए और अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। ऐसे बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें जीवन के इस पड़ाव पर यह खुशी मिलती है जहां बुजुर्ग अपने बच्चों और उनके बच्चों के साथ रह पाते हैं।'

मतदाता सूची को आधार से जोड़ने पर बढ़ी बात

चुनाव आयोग की नौ समितियों ने सौंपी सुधार संबंधी सिफारिशें

चुनाव आयोग के अधिकारियों और 20 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की नौ समितियों ने मंगलवार को विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें चुनाव आचार संहिता, निर्वाचक नामावली और व्यय प्रबंधन शामिल हैं। समितियों की सिफारिशें पिछले आम चुनाव और हालिया अन्य चुनावों पर आधारित हैं। समूहों ने अपनी सिफारिशें दो दिवसीय संगोष्ठी के दौरान सौंपी। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि समितियों की सिफारिशों पर गौर किया जाएगा। लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए इन सिफारिशों को सार्वजनिक भी किया जाएगा।

नई दिल्ली, प्रेट्र : चुनाव आयोग ने मंगलवार को चुनाव सुधार की दिशा में सरकार के साथ नए सिरे से पहल की है। इनमें मतदाता सूची को आधार से जोड़ने, पेड न्यूज और फर्जी हलफनामे के मामले में चुने गए प्रतिनिधियों की सदस्यता रद करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। आयोग के प्रशासनिक मामले सीधे तौर पर विधि मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।

चुनाव आयोग की तरफ से जारी बयान के अनुसार, विधि सचिव जी. नारायण राजू के साथ बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और आयुक्त अशोक लवासा तथा सुनील चंद्र ने मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा की।

सूत्रों ने बताया था कि हाल ही में विधि मंत्रालय को लिखे गए पत्र में चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसमें मतदाता सूची में शामिल किए जाने के लिए आवेदन के दौरान तथा सूची में पहले से ही मौजूद लोगों के लिए आधार संख्या अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव शामिल हैं। प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विधि मंत्रालय ने चुनाव आयोग से आधार डाटा को सुरक्षित रखने के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने गलत हलफनामा देकर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की सदस्यता समाप्त करने का भी प्रस्ताव दिया है। फिलहाल, ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वालों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होता है। आयोग ने विधानसभा की तर्ज पर विधानपरिषद चुनाव में भी प्रचार खर्च की सीमा तय करने की पहल की है। आयोग ने मतदाता सूची में शामिल किए जाने के लिए एक जनवरी के अलावा भी अन्य तिथियां निर्धारित करने की मांग की है। फिलहाल एक जनवरी तक 18 साल के होने वाले को ही मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य माना जाता है।

बयान के अनुसार, चुनाव सुधार के लिए सरकार को 40 प्रस्ताव दिए गए हैं। इनमें सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के लिए निर्वाचन नियमों को लैंगिक आधार पर समान बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके तहत आयोग ने महिला सैन्यकर्मियों के पति को भी सर्विस वोटर का दर्जा देने की बात कही है। कानून में इस आशय के संशोधन से जुड़ा विधेयक पिछली लोकसभा में पारित नहीं हो पाने के कारण निष्प्रभावी हो गया था। इसके अलावा आयोग ने विधि मंत्रालय से मुख्य चुनाव आयुक्त की तर्ज पर दो चुनाव आयुक्तों को भी संवैधानिक संरक्षण देने के पुराने प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है।

विधि मंत्रालय के अनुमोदन पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। विधि आयोग ने मार्च 2015 में चुनाव सुधारों पर पेश अपनी रिपोर्ट में दोनों चुनाव आयुक्तों को भी संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था।

33 साल बाद आ रही नई शिक्षा नीति को अब खुद परखेंगे पीएम

▶ प्रस्तावित नीति के अंतिम स्वरूप को लेकर मंत्रालय देगा प्रजेंटेशन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद परखेंगे। 33 साल के बाद इस नीति को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय बुधवार को प्रधानमंत्री के सामने प्रजेंटेशन देगा। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री की सहमति मिली, तो नीति जल्द ही देश के सामने आ सकती है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। फिलहाल मौजूदा समय में इसी नीति को थोड़े बदलावों के बाद आगे रखकर शिक्षा का खाका खींचा जा रहा है।

इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को दिन भर प्रस्तावित नीति के अंतिम रूप को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। इस बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने बैठक को लेकर कुछ ट्वीट भी किए और कहा कि केवल शिक्षा में ही वह क्षमता है, जो किसी राष्ट्र को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। नई शिक्षा नीति नए भारत का निर्माण सुनिश्चित करेगी।

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति का फोकस रोजगारपरक शिक्षा की ओर रखा गया है। वैसे भी भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े होने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत कुशल कामगारों की होगी। इसमें गुणवत्तापरक शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। हालांकि सरकार ने इस दिशा में तेजी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिसके तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री को शिक्षा नीति को लेकर यह प्रजेंटेशन कैबिनेट की बैठक के बाद दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति को फिलहाल यह अंतिम रूप एक लंबे विचार-विमर्श के बाद दिया गया है। इसके तहत अलग-अलग स्तर पर नीति को लेकर लोगों से राय ली गई थी। जिसमें दो लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। हालांकि मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री के सामने नीति के अमल का भी एक पूरा खाका पेश किया जाएगा। मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार की बैठक में इसे लेकर भी चर्चा की है।

'हर काम देश के नाम' के नारे से गांव-गांव पहुंचेगी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास यूं तो एक चुनावी नारा था जिसे लोकसभा से ठीक पहले गढ़ा गया था, लेकिन अब वह सरकार का मंत्र है। इसे और विस्तार देते हुए गुरुवार से 'हर काम देश के नाम' के जरिये गांव-गांव तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश होगी कि केंद्र सरकार हर व्यक्ति के माध्यम से देश को गढ़ने का काम कर रही है। परोक्ष रूप से विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया जाएगा कि विवाद खड़ा कर देश को भटकाने की कोशिश की जा रही है।

20 फरवरी से 31 मार्च तक चलने वाली इस विशेष मुहिम का फीडबैक भी जांचा जाएगा, जिसके आधार पर आगे भी ऐसे ही मेगा ब्रांडिंग कैंपेन चलाने का फैसला लिया जाएगा। केंद्र ने सभी मंत्रालयों को तैयारी करने को कहा है। ऐसी योजनाओं व पहल से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं, जो सरकार की लोकप्रियता को और ऊंचाई दे सके। लोगों के बीच यह संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि वह वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर काम करने में भरोसा रखती है।

लोगों को नमाज पढ़ते देख हैरान रह गया था

प्रथम पृष्ठ से आगे

'लेट मी से इट नाउ' में मारिया ने कहा है कि लश्कर ने कसाब के दिमाग में यह भर दिया था कि भारत में मुस्लिमों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। जेल में रहते हुए उसने जब अजान की आवाज सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। बाद में मेट्रो सिनेमा के पास मस्जिद में उसे ले जाया गया। वहां लोगों को नमाज पढ़ते देख कसाब हैरान रह गया था।

2008 में हमले से दहल गई थी माया नगरी : मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को आतंकी हमला हुआ था। इसमें 166 लोगों की मौत हुई थी और तीन सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान से कसाब के साथ 10 आतंकी हमला करने आए थे। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में नौ आतंकियों को मार गिराया था। कसाब जिंदा पकड़ा गया था जो हमले में पाकिस्तान के हाथ को साबित करने में अहम साबित हुआ था। बाद में उसे फांसी दे गई थी। राकेश मारिया ने अपनी पुस्तक में बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड को लेकर भी कई अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपित पीटर मुखर्जी के शामिल नहीं होने को लेकर उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को कोई गलत जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ यह बताया था कि हत्याकांड के समय पीटर भारत में नहीं थे। मुंबई पुलिस के तत्कालीन संयुक्त आयुक्त (अब एटीएस के एडीजी) देवेन भारती ने उन्हें अंधेरे में रखा था। देवेन भारती पहले से ही पीटर मुखर्जी को जानते थे लेकिन उन्होंने इससे इन्कार किया था। मारिया ने कहा है कि पूछताछ के दौरान जब पीटर मुखर्जी ने बताया कि शीना बोरा के लापता होने के बारे में उन्होंने 2012 में ही 'देवेन' को बता दिया था, तब उन्हें बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि पीटर ने पुलिस अधिकारी को उनके पहले नाम से संबोधित किया था। हालांकि, देवेन भारती ने मारिया के आरोपों को नकारा है और इसे पुस्तक बेचने के लिए प्रचार का हथकंडा करार दिया है। मारिया ने यह भी कहा है कि उनके बाद पुलिस आयुक्त बनाए गए अहमद जावेद भी मुखर्जी परिवार को पहले से जानते थे। जावेद ने ईद पर पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी को बुलाया भी था। शीना बोरा मीडिया मुगल कहे जाने वाले पीटर और इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी। 2012 में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पीटर और इंद्राणी दोनों आरोपित हैं। पीटर पर साजिश रचने का आरोप है। शीना पीटर की सौतेली बेटी थी। इंद्राणी मुखर्जी पर हत्या का आरोप है और वो जेल में बंद है।

हलफनामा मामले में फड़नवीस की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई पूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। इसमें उन्होंने 2014 के चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा नहीं देने पर मुकदमे का सामना करने के शीर्ष अदालत के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था।

फड़नवीस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ के समक्ष कहा कि चुनाव लड़ने वाले अन्य उम्मीदवारों के लिए इस मुद्दे के दूरगामी परिणाम होंगे। अदालत को एक अक्टूबर, 2019 के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने फैसले में बांबे हाई कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने फड़नवीस को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि उनको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कथित अपराध पर मुकदमे का सामना नहीं करना होगा।

बहस के दौरान रोहतगी ने कहा कि किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला दो सूरतों पर चलाया जा सकता है। पहला आरोप तय होने के बाद मामले की जानकारी नहीं देने और दूसरा दोषी ठहराए जाने की जानकारी नहीं देने पर। उन्होंने पीठ से कहा, 'यह एक अहम प्रश्न है, क्योंकि यह अनुच्छेद 21 को प्रभावित करता है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।'

चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों का ब्योरा नहीं देने का आरोप

मुकदमे का सामना करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार का अनुरोध

देवेंद्र फड़नवीस फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सतीश उइके की अपील पर सुनाया था। उन्होंने बांबे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उइके की याचिका पर 23 जुलाई, 2019 को सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि फड़नवीस द्वारा चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी कथित तौर पर नहीं देने पर सुनवाई के दौरान फैसला होगा। अदालत ने कहा था, 'हमारा सरोकार बहुत ही सीमित मुद्दे पर है कि क्या इस मामले में पहली नजर में जन प्रतिनिधित्व कानून का अनुच्छेद 125 लागू होता है या नहीं।' यह अनुच्छेद मूल रूप से गलत हलफनामा दाखिल करने से संबंधित है। यदि कोई प्रत्याशी नामांकन पत्र के साथ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी देने में विफल रहता है या उसे छिपाता है और यह साबित हो जाता है, तो प्रत्याशी को छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

सरकार के फैसले के साथ कांग्रेस

▶ सिंघवी ने कहा कि डेबी सांसद नहीं पाकिस्तान की कठपुतली

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ब्रिटिश सांसद डेबी अब्राहम्स को भारत से वापस भेजे को बहुत जरूरी करार देते हुए कहा कि देश की संप्रभुता पर हमला करने के हर प्रयास को विफल करना होगा। सिंघवी ने ट्वीट कर कहा, 'डेबी अब्राहम्स को भारत से वापस भेजा जाना वाकई जरूरी था क्योंकि वह सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कठपुतली हैं जो पाक सरकार और आइएसआइ के साथ अपनी नजदीकियों के लिए जानी जाती हैं। भारत की संप्रभुता पर हमला करने के हर प्रयास को विफल करना होगा।

अभिषेक मनु सिंघवी। फाइल फोटो

आगमन पर वीजा का प्रावधान नहीं

प्रथम पृष्ठ से आगे

सूत्रों ने कहा कि एयरपोर्ट पर ब्रिटिश नागरिकों के लिए 'आगमन पर वीजा' का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने अब्राहम्स की इस दलील को खारिज किया कि उन्हें 'आगमन पर वीजा' दिया जाना चाहिए था। नियमों के अनुसार व्यापारिक बैठकों के लिए पहले जारी ई-बिजनेस वीजा का इस्तेमाल दोस्तों और परिजनों से मिलने के लिए नहीं किया जाता।

वह उन ब्रिटिश सांसदों के दल में शामिल थीं जिन्होंने पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर चिंता जताते हुए औपचारिक पत्र जारी किए थे। विपक्षी सांसद ने उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब को लिखे पत्र में कहा था, 'हम भारत के गृह मंत्री अमित शाह की इस घोषणा से बहुत चिंतित हैं कि जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 राष्ट्रपति के आदेश से खत्म कर दिया गया है।'

कह के रहेंगे

माधव जोशी

अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन से मांगी माफी

खेद जताया

दोस्ती टूटने के बाद भी अमिताभ बच्चन ने कभी सार्वजनिक रूप से अमर सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अमर सिंह लगातार उनको निशाना बनाते रहे हैं

एंटरटेमेंट ब्यूरो, मुंबई

महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव अमर सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर खेद जताया। अमर सिंह के बच्चन परिवार के साथ करीबी संबंध रह चुके हैं। कुछ साल पहले दोनों के संबंधों में दरार आ गई थी। अमिताभ बच्चन ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अमर सिंह के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अमर सिंह उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। अमर सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि अमिताभ ने उनके साथ दोस्ती खत्म की है और अमिताभ और जया अलग-अलग रह रहे हैं।

अमर सिंह ने ट्विटर पर लिखा, ' आज (मंगलवार को) मेरे पूज्य पिताजी की बरसी थी। इस तिथि पर पिछले एक दशक से लगातार उनकी स्मृति में अमिताभ बच्चन मुझे संदेश भेजते हैं। संबंध जितना अधिक निकट होता है उसके टूट की चुभन भी उतनी तेज होती है। पिछले दस वर्षों से मैं बच्चन परिवार से न सिर्फ अलग रहा, बल्कि यह प्रयत्न किया कि उनके दिल में मेरे लिए नफरत हो। लेकिन आज फिर अमिताभजी ने मेरे पिताजी का स्मरण किया। सिंगापुर में दस साल पहले गुर्दे की बीमारी के लिए मैं और अमित जी दो महीने तक साथ रहे थे। इसके बाद हमारा और उनका साथ छूट सा गया। 10 साल बीत जाने पर भी उनकी निरंतरता में कोई बाधा नहीं आई। वह लगातार अनेक अवसरों पर, चाहे मेरा जन्मदिन हो या पिताजी की पुण्य तिथि, हर दिन का स्मरण कर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने अनावश्यक रूप से ज्यादा उग्रता दिखाई। 60 से ऊपर जीवन की संध्या होती है। एक बार फिर मैं जिंदगी और मौत की चुनौती के बीच से गुजर रहा हूं। वह मुझसे उम्र में बड़े हैं इसलिए उनके प्रति मुझे नरमी रखनी चाहिए थी। जो कटुवचन मैंने बोला है, उसके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए। मेरे मन में कटुता और नफरत से ज्यादा उनके व्यवहार के प्रति निराशा रही, लेकिन उनके मन में न तो कटुता है और न ही निराशा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबको उनके कर्मों के अनुसार यथोचित न्याय दे। हमें सब ईश्वर पर छोड़ना चाहिए बजाय इसके कि हम उसके काम में खुद दखल दें। अमितजी बहुत-बहुत धन्यवाद।'

अमर सिंह ने इसके साथ ही एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें वह बच्चन परिवार के प्रति अपनी बयानबाजी को लेकर खेद जता रहे हैं।

कहा, जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूं, बच्चन परिवार के खिलाफ दिए गए बयान पर खेद है

अमर सिंह अमिताभ बच्चन फाइल फोटो

जाली आदेश पर बांबे हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया

मुंबई, प्रेट्र : जाली आदेश की कॉपी की शिकायत को पर बांबे हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने अज्ञात के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। जस्टिस जीएस पटेल दो वकीलों की ओर से दायर शिकायत की सुनवाई कर रहे थे। वकीलों ने दावा किया है कि एक दस्तावेज को दिसंबर 2019 में न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की तरह बांटा गया।

THE STUDY
प्राचीन भारत
से नया बैच प्रारंभ
-मणिकांत सिंह
OPEN LECTURE
कल 8:00 AM
210, VIRAT BHAWAN, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9
9999516388, 9999278966, 42870015

यह बजट शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए महत्वाकांक्षी बजट है। इससे प्रदेश का संतुलित व समग्र विकास होगा। बजट में सभी वर्गों और क्षेत्रों का ख्याल रखा गया है। गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का विकास, युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार, किसानों की खुशहाली, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और त्वरित न्याय बजट के मुख्य आयाम हैं।

केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री

योगी सरकार का बजट युवाओं के सपनों को नए पंख देने का काम करेगा। सरकार अब सूबे में राष्ट्रनिर्माण के लिए कुशल व सक्षम युवाओं को तैयार करेगी, जो आने वाले समय में देश का मान-सम्मान बढ़ाएंगे। सरकार की मंशा सूबे को शिक्षा का केंद्र बनाने की है। इसके लिए तीन नए राज्य विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं।

डॉ. दिनेश शर्मा, उपमुख्यमंत्री

टॉप-20 विभागों का बजट आवंटन

क्रम	विभाग	धनराशि (करोड़ रु. में)
1.	प्राथमिक शिक्षा	55064.55
2.	ऊर्जा विभाग	33754.48
3.	समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण	31010.09
4.	लोक निर्माण विभाग	27837.89
5.	पुलिस	27286.69
6.	ग्राम्य विकास	20316.33
7.	पंचायती राज	18460.88
8.	नगर विकास विभाग	18211.4
9.	सिंचाई विभाग	16973.04
10.	खाद्य रसद विभाग	16377.25
11.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	15860.33
12.	माध्यमिक शिक्षा	12988.91
13.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	9690.99
14.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन, राहत, राजस्व परिषद)	9384.55
15.	भारी एवं मध्यम उद्योग	7476.99
16.	चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	6460.22
17.	कृषि	6176.27
18.	न्याय विभाग	5368.71
19.	उच्च शिक्षा	3651.67
20.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	3159.27

उत्तर प्रदेश बजट ▶ धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत को सहेजने-संवारने में जुटी योगी सरकार

अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए मिले 500 करोड़

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

पर्यटन के अकूत खजाने से संपन्न उप्र में योगी सरकार धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत को सहेजने-संवारने में जुटी है। 2017 से ही धार्मिक स्थलों पर नजर रखने वाली सरकार ने अपने चौथे बजट में भी पर्यटन के सहारे धर्मध्वजा फहराने के लिए कदम बढ़ाया है।

अयोध्या में प्रस्तावित एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये के अलावा पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 85 करोड़, तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहां स्थित रामगढ़ ताल में वॉटर स्पोर्ट्स के विकास के लिए बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर हेलीपैड निर्माण के अलावा 46 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर को विकसित करने की भी घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि सरकार पहले ही गढ़मुक्तेश्वर को हरिद्वार के हर की पैड़ी के तर्ज पर विकसित करने की घोषणा कर चुकी है।

वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण-सुंदरीकरण परियोजना के तहत विश्वनाथ धाम कारिडोर के समयबद्ध निर्माण को लेकर मंगलवार को जारी बजट ने भी प्रतिबद्धता जता दी। नए वित्तीय वर्ष में इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बाबा दरबार से गंगा तट तक 50 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में 745 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे कारिडोर का निर्माण 31 दिसंबर 2021 तक कर लेने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रथम चरण में मिले 398 करोड़ से 299 भवनों की खरीद की जा चुकी है। दूसरे चरण में निर्माण के लिए स्वीकृत 347 करोड़ रुपये में से 127.50 करोड़ की पहली किस्त पिछले साल अक्टूबर में अधिसूचना के साथ ही जारी कर दी गई थी।

लखनऊ में मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करने के लिए जाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ मे वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना। हृदेश चंदेल

युवाओं की बल्ले-बल्ले, प्रशिक्षण के साथ भत्ता भी मिलेगा

आशीष त्रिवेदी, लखनऊ

राज्य के बजट की गाड़ी इस बार युवाओं के खेमे की ओर घूम गई है। सरकार का जोर प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाने का है, ताकि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़े हो सकें। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं की जेब खाली न रहे, बजट में इसकी चिंता की गई है, जबकि प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार की बड़ी योजना भी सरकार के बजट पिटारे में है।

अप्रशिक्षित युवाओं के लिए बजट का सबसे बड़ा आकर्षण मुख्यमंत्री अप्रेंटिशसिप (शिक्षुता) प्रोत्साहन योजना है, जबकि प्रदेश के हर जिले में युवा हब बनाने की परिकल्पना हुनरमंद युवाओं को स्वरोजगार की राह पर ले जाने की उम्मीदों से भरी है। अप्रेंटिशसिप योजना के जरिए युवाओं के लिए उद्योगों में ऑनजॉब प्रशिक्षण का रास्ता खुल जाएगा। उन्हें प्रशिक्षण के साथ यहां छह से साढ़े नौ हजार रुपये तक का प्रशिक्षण भत्ता भी हर महीने मिलेगा। इस भत्ते के लिए अब तक केंद्र सरकार 1500 रुपये देती थी, जबकि बाकी रकम उद्योगों से मिलती थी लेकिन अब इस भत्ते में राज्य सरकार ने भी अपने एक हजार रुपये शामिल करने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने सौ करोड़ रुपये का बजट रखा है। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने बजट में 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यह रकम युवा उद्यमिता विकास अभियान (युवा) पर खर्च की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के हर जिले में 50 करोड़ रुपये से युवा हब बनाए जाएंगे। यहां अपना उद्यम लगाने के लिए युवाओं को विशेषज्ञों की मदद उपलब्ध होगी। साथ ही एक साल तक वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा उप्र कौशल विकास मिशन के तहत वर्ष 2020-21 में दो लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की तैयारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 25 करोड़ से ओपन जिम बनेंगे।

'भगीरथ' बने मुख्यमंत्री योगी बुझेगी हर गांव की प्यास

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बुंदेलखंड की सूखी धरती से पानी के लिए मिशन मोड पर काम करने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, उस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने का रास्ता तैयार है।

प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 'भगीरथ' बनकर चल पड़े हैं। गांवों की प्यास बुझाने की पर्याप्त भूख सरकार के बजट में नजर आई है। जल शक्ति, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए सरकार ने नौ हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की है।

पेयजल संकट से ग्रामीण क्षेत्रों को उबारने के केंद्र सरकार के प्रयासों को राज्य सरकार ने हाथों-हाथ लेते हुए उसे रफ्तार का रास्ता बजट में बनाया है। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने और अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए तीन हजार करोड़ रुपये की धनराशि रखी है। खेतों की प्यास बड़ी नहर परियोजनाएं बुझा सकती हैं।

उन्हें संपूर्णता की टेल तक पहुंचाने की चिंता और व्यवस्था बजट में है। इसी तरह वर्षा जल संचयन, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और नलकूपों के लिए भी योगी सरकार ने पर्याप्त धन आवंटन किया है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण पर भी फोकस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : 'सबका साथ सबका विकास' के अपने वादे पर योगी सरकार आगे बढ़ते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण पर भी फोकस किया है। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में 111.21 करोड़ रुपये का इजाफा करते हुए कुल 3159.24 करोड़ रुपये दिए हैं। योगी सरकार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में 21 कॉमन सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। योगी सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 783 करोड़ रुपये का बजट दिया है। कब्रिस्तान व अंत्येष्टि स्थल की चहारदीवारी के लिए 100 करोड़ रुपये दिए हैं।

मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए-479 करोड़
अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए-394 करोड़
अरबी-फारसी मदरसों को अनुदान-817.57 करोड़
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए-600 करोड़
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए-190 करोड़

जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ की व्यवस्था

राजीव दीक्षित, लखनऊ

- योगी सरकार ने पेश किया 5.12 लाख करोड़ रुपये का चौथा बजट
- ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ी योगी आदित्यनाथ की सरकार

योगी सरकार ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 5,12,860.72 करोड़ रुपये का बजट पेश कर उप्र की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बजट में 10,967.87 करोड़ रुपये की नई योजनाओं/मदों का एलान किया गया है। ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान (युवा) शुरू करने का बजट में एलान किया गया है। युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान 2500 रुपये मासिक प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाएगा। इसमें 1500 रुपये केंद्र व 1000 रुपये राज्य सरकार और शेष राशि उद्योग की ओर से दी जाएगी। वहीं युवा उद्यमिता विकास अभियान के तहत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने के लिए हर जिले में 50 करोड़ रुपये की लागत से युवा हब स्थापित किया जाएगा।

सात नए विश्वविद्यालयों की स्थापना पर फोकस: युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के अवसर मुहैया कराने के लिए सूबे में सात नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी बजट में एलान हुआ है। रेडीमेड पुलिस अफसर तैयार करने के लिए लखनऊ में पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।

अलीगढ़, आजमगढ़ और सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के अलावा प्रयागराज मे विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए भी संसाधन मुहैया कराए गए हैं।

बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को शीर्ष प्राथमिकता: ढांचागत विकास को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बिजली, सड़कों-सेतु और सिंचाई के लिए सरकार ने 78,565.41 करोड़ रुपये खर्च करने का हौसला दिखाया है। वहीं सूबे में पांच एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का संजाल बिछाने के लिए कुल 5060 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसमें मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित 637 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। डिफेंस एक्सपो की सफलता से उत्साहित सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।

ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तथा आगरा, कानपुर, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए भी धन वर्षा की गई है।

लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल: सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को गति देने के साथ जनसंघ और भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना का भी इरादा जताया है जिसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये दिये गए हैं। पराली प्रबंधन की चिंताओं ने सरकार को इस मद में 300 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए मजबूर किया है।

मेट्रो और एक्सप्रेसवे

दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम- 900 करोड़
आगरा मेट्रो- 286 करोड़
कानपुर मेट्रो- 358 करोड़
गोरखपुर व अन्य शहरों के मेट्रो प्रस्ताव बनाने के लिए- 200 करोड़
मेरठ-प्रयागराज (637 किलोमीटर) गंगा एक्सप्रेसवे- 2000 करोड़

हवाई अड्डे

नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट- 2000 करोड़
अयोध्या एयरपोर्ट- 500 करोड़
रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम- 92.50 करोड़

मथुरा पर मेहरबान रही सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: मथुरा में उत्सवों के आयोजन के लिए 500 लाख रुपये का प्रावधान किया है और वृंदावन व मथुरा में कृष्ण कुटीर आश्रय सदन निर्माण के लिए 60 लाख प्रदान किए है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की बाहरी परिधि में सर्विस रोड निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में सौ बेड वाला महिला छात्रावास निर्माण के लिए 646.99 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। कालेज आफ डेरी साइन्स की स्थापना के लिए 1034.60 लाख प्रदान किए गए है। मेरठ में शूटिंग रेंज स्थापना की स्वीकृति मिली है।

धार्मिक यात्राओं के लिए मदद: धार्मिक पर्यटन को बढ़ा रही सरकार की नजर तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं पर भी है। कैलाश मान सरोवर की यात्रा को अनुदान देने के लिए आठ करोड़ रुपये तो सिंधु दर्शन यात्रा अनुदान मद में दस लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति- 2018 के अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे कोई नई पार्टी, करेंगे 'बात बिहार की'

राज्य ब्यूरो, पटना

प्रशांत किशोर। फाइल

- प्रशांत किशोर ने कहा- चलाएंगे अभियान और बदलाव लाएंगे
- नीतीश शासनकाल पर उठाए सवाल, पिछड़ेपन के आंकड़े दिखाए
- कहा- अगर गांधी की नीतियां पसंद है तो गोडसे समर्थकों के साथ क्यों हैं नीतीश?

अलग-अलग चुनावों में अलग-अलग नीतियों वाली पार्टियों के लिए लुभावने नारे गढ़ने वाले चुनावी प्रबंधक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को एलान किया कि वह कोई नया दल नहीं बनाएंगे। अब बिहार में बदलाव के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने 'पितातुल्य' बताया। कहा, नीतीश ने मुझे अपने बेटे की तरह स्नेह दिया। उनका हर फैसला मंजूर है। उनपर टीका-टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन तुरंत बाद वह पंद्रह साल की कमियां गिनाने लगे। यह भी कह दिया कि वह भाजपा के 'पिछलग्गू' बन गए हैं। पत्रकारों ने जब पूछा कि 5 साल तक तो वह भी नीतीश के साथ थे और 'बिहार में बहार है' जैसे नारे गढ़ रहे थे, तो प्रशांत किशोर जवाब टाल गए और नीतीश से मतभेद की वजहें गिनाने लगे।

20 से शुरू होगा अभियान : प्रशांत किशोर की 18 फरवरी को पटना में प्रेस वार्ता की घोषणा की वजह से देश भर की मीडिया वहां जुटी थी। खबर थी कि वह अलग राजनीतिक फ्रंट खड़ा करेंगे, लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया। कहा अभी वह बिहार की साढ़े आठ हजार पंचायतों के 10 लाख युवाओं के साथ 'बात बिहार की' अभियान करने जा रहे हैं। यह 20 फरवरी से शुरू हो रहा है।

नीतीश का हर निर्णय दिल से स्वीकार है : प्रशांत किशोर ने कहा कि 'नीतीश कुमार से मेरे संबंध आज के नहीं। उन्होंने मेरे साथ हमेशा बेटे जैसा व्यवहार किया और मैं भी उन्हें पिता तरह मानता हूं। जब मैं जदयू में था, तब भी नीतीश कुमार को पितातुल्य ही मानता था। इस वजह से उनके निर्णय पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करूंगा। उनका जो भी निर्णय होगा हृदय से स्वीकार होगा।'

पिछलग्गू हैं नीतीश कुमार : नीतीश कुमार के साथ अपने मतभेद की चर्चा करते हुए प्रशांत ने कहा कि 'लोकसभा चुनाव के वक्त से ही मतभेद शुरू हो गए थे। नीतीश गांधी, जेपी और लोहिया के आदर्श की बात करते हैं, पर गोडसे को समर्थन देने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। मतभेद गठबंधन में पोजिशनिंग और विकास को लेकर है। नीतीश पहले भी भाजपा के साथ थे, लेकिन तब दो सांसदों वाली पार्टी के धूल धुसरित नेता थे। तब नीतीश कुमार दस करोड़ बिहारियों के नेता थे, लेकिन आज 16 सांसदों वाले नीतीश समृद्ध बिहार के नाम पर भाजपा के पिछलग्गू बन गए हैं। भाजपा उनकी बात नहीं सुनती। विशेष राज्य का दर्जा हो या पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की उनकी मांग स्वीकार नहीं हुई।'

नि:शब्द हूं, अभिभूत कर गया स्वागत : मरांडी

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय के बाद मंगलवार को दोपहर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा कार्यालय पहुंचे तो उनका स्वागत किसी हीरो की तरह किया गया। कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी पदाधिकारी और विधायकों तक की मौजूदगी ने बाबूलाल को अभिभूत कर दिया। कार्यक्रम के ठीक बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, निःशब्द हूं।

इसके पूर्व पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा कि 14 वर्षों के बाद प्रदेश कार्यालय आने पर मेरा जिस प्रकार से स्वागत हुआ उससे मैं अभिभूत हूं। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मेरे पास कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट करने के लिए शब्द नहीं हैं। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ पार्टी की सेवा करूंगा।

स्करकार के संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल बहाने बना रही है, कोई काम नहीं कर रही। इसे अपने वायदों पर अमल करना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं की जांच कराने से संबंधित हेमंत सरकार की घोषणा पर कहा कि जांच कराने से किसने रोका है, सरकार जिस स्तर पर चाहे जांच करानी चाहिए।

हिमाचल में बिना शक्तियां लोकायुक्त की सचिव ने अवकाश पर भेजा स्टाफ

रमेश सिंगटा, शिमला

लोकायुक्त की सचिव एवं वरिष्ठ आइएएस अधिकारी ने बिना शक्तियों के स्टाफ को लंबे अवकाश पर भेज दिया है। ऐसा विंटर वेकेशन के नाम पर किया गया है। केवल कार्यालय आदेश से ही 34 में से 32 कर्मचारियों को 22 दिन के लिए अवकाश दे दिया। सूत्रों के अनुसार अवकाश की सूचना राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधान सचिव गृह को नहीं दी गई है।

लोकायुक्त को भी अवकाश राजभवन से स्वीकृत करवाना होता है। प्रशासनिक अधिकारी गृह सचिव हैं, उन्हें भी विश्वास में नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय तक को सूचना देना उचित नहीं समझा गया। हिमाचल में तीन साल से लोकायुक्त का पद रिक्त होने से उनके कार्यालय में कामकाज नाममात्र है। सचिव ने शिमला स्थित लोकायुक्त कार्यालय के रजिस्ट्रार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के स्टाफ को अवकाश दे दिया। ऐसे में कार्यालय में तालाबंदी की नौबत आ गई है। वहां केवल सचिव हैं। रजिस्ट्रार चूंकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रैंक के हैं, इस कारण वह हाईकोर्ट की अनुमति से अधिकृत अवकाश पर हैं। एएसपी भी मेडिकल लीव पर हैं। नए एक्ट में सारी शक्ति लोकायुक्त के पास निहित है। स्टाफ को लंबा अवकाश केवल लोकायुक्त ही दे सकते हैं। लोकायुक्त कार्यालय में अवकाश के मामले में हाईकोर्ट के नियमों का अनुसरण होता है। कोर्ट में अवकाश फुल कोर्ट तय करता है। इसे चीफ जस्टिस की ओर से अधिसूचित किया जाता है।

शिकायतों की जांच, नोटिस व समन जारी करने का अधिकार नहीं

एक्ट के अनुसार सचिव लोकायुक्त की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लोकायुक्त के अभाव में सचिव के पास भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच और नोटिस व समन जारी करने का अधिकार नहीं है। शिकायत रजिस्टर में दर्ज होगी। सचिव के पास वित्तीय और न्यायिक शक्तियां भी नहीं हैं।

मैं कायदे कानून से बाहर जाने वाली नहीं हूं। स्टाफ को अवकाश पर नियमों के तहत भेजा है। लोकायुक्त नहीं होंगे तो क्या कर्मियों का हक छीन लेंगे? एएसपी ने अवकाश मांगा था। उन्हें नहीं मिल सकता था क्योंकि वह मानवाधिकार आयोग के अधिकारी हैं, हमारे यहां तो अतिरिक्त कार्यभार है।

-मधुबाला, सचिव, लोकायुक्त

एक्ट में सारी शक्ति लोकायुक्त के पास हैं। लोकायुक्त अगर सचिव को शक्तियों का हस्तांतरण करेंगे तभी वह स्टाफ को अवकाश पर भेज सकेंगे। मेरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार से जुड़ी करीब 20 शिकायतें आई थीं। सरकार को नए लोकायुक्त की नियुक्ति जल्द करनी चाहिए।

-एलएस पांटा, पूर्व लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश

मैं चिकित्सा अवकाश पर हूं। स्टाफ के अवकाश पर टिप्पणी नहीं कर सकता। **-भूपेंद्र नेगी, एएसपी, लोकायुक्त**

सियासत

सहयोगी दलों ने शरद यादव को आगे करके खोला मोर्चा, महागठबंधन में नूराकुश्ती शुरू

शरद को आगे कर महागठबंधन में बना तीसरा दल

अरुण अशेष, पटना

शरद यादव। फाइल

- मुख्यमंत्री पद के चेहरे और सीटों के तालमेल को लेकर राजद पर दबाव बनाने का प्रयास

वाम के सवाल पर बोली कांग्रेस

इधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा. मदन मोहन झा ने कहा कि भाजपा को परास्त करने के लिए समान विचारधारा के सभी दल एक मंच पर आ जाएं तो अच्छी बात है। इस पर महागठबंधन के किसी दल को संभवत: एतराज न हो।

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को चुनौती देने से पहले ही महागठबंधन में नूराकुश्ती शुरू हो गई है। राजद के बढ़ते वर्चस्व और तेजस्वी के बढ़े कद के कारण खुद का वजूद बचाए रखने के लिए सहयोगी दलों ने शरद यादव को आगे करके मोर्चा खोल दिया है। रालोसपा, हम और विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) जैसे दल वाम मोर्चा को साथ लाकर एक मंच तैयार कर रहे हैं।

ताकि मुख्यमंत्री पद के चेहरे और सीटों के तालमेल को लेकर राजद पर दबाव बनाया सके। हालांकि कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे तमाशा देख रही है। इन दलों के संश्रय से महागठबंधन में एक दबाव समूह बन गया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य सबसे बड़े दल राजद को बराबरी पर लाकर बिठाना है। बेशक, विधानसभा चुनाव में एनडीए को परास्त करना अंतिम लक्ष्य है। फिलहाल यह प्राथमिकता सूची में दूसरे नंबर पर है। मालूम हो कि तीन दिन पहले रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हिन्दुस्तानी अवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने शरद से मुलाकात कर नेतृत्व का विवाद सुलझाने का आग्रह किया था। इसके बाद शरद रांची गए। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद मुलाकात हुई। लेकिन,नेतृत्व का विवाद सुलझ नहीं पाया।

कुशवाहा, मांझी और सहनी का कहना था कि उन्हें तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। शरद खुद महागठबंधन का नेतृत्व करें। प्रस्ताव तो यह भी था कि महागठबंधन शरद को ही विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य चेहरे के तौर पर पेश करे। खबर है कि लालू प्रसाद इसके लिए तैयार नहीं हुए। शरद उसी शाम दिल्ली लौटे। लेकिन, ये तीन दल अपने एजेंडे पर काम करते रहे। अगले दिन गांधी मैदान में धरना का कार्यक्रम था। उसमें इन दलों के अलावा वाम दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने बैठक में कहा था कि महागठबंधन में वाम दलों को शामिल करने से मजबूती मिलेगी। इस तर्क से मांझी और सहनी भी सहमत हुए।

फिलहाल, वाम दलों के साथ महागठबंधन के गैर राजद दल दोस्ती जारी रखेंगे। मकसद यह है कि एनडीए और राजद से अलग राज्य में तीसरे मोर्चे का ढांचा तैयार हो जाए। ताकि राजद से मोलजोल करने में सहूलियत हो। राजद और एनडीए से अलग राय रखने वालों को इससे जोड़ा जाए। लेकिन, यह सब मोलजोल की क्षमता बढ़ाने के लिए ही होगा। तीसरा मोर्चा के नाम पर अलग चुनाव अंतिम या मजबूरी का विकल्प होगा। वैसे, राजद का एक हिस्सा पूरी कवायद को शरद यादव की राज्यसभा में वापसी के उपाय से अधिक कुछ नहीं मान रहा है।

प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने पर पीसीसी मौन

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में अप्रैल में राज्यसभा की रिक्त होने वाली तीन सीटों में से एक सीट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उतारे जाने की अटकलों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) ने मौन साध रखा है। पार्टी के विधायक, पीसीसी पदाधिकारी जरूर प्रियंका को प्रदेश से राज्यसभा भेजे जाने के पक्ष में हैं, लेकिन ऊपर क्या चल रहा है, इसकी किसी को भनक तक नहीं है। यह अवश्य कहा जा रहा है कि कांग्रेस को प्रदेश से मिलने जा रही दो राज्यसभा सीटों में से एक पर प्रदेश के बाहर के किसी नेता को भेजा जा सकता है।

दो महीने बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर तीन दिन से प्रियंका गांधी के नाम की अटकलें हैं। पीसीसी के संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर ने इस बारे में टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि अभी तक पीसीसी को एआइसीसी की तरफ से कोई पत्र नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि प्रियंका गांधी को प्रदेश से राज्यसभा भेजे जाने के मद्देनजर बयानबाजी की शुरुआत कमलनाथ सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की मांग से हुई। इसके बाद सोमवार को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी ट्वीट कर मैदान में उतरे। उन्होंने प्रियंका को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजे जाने को सामयिक बताते हुए लिखा कि इससे राज्यसभा में फांसीवादी विचारधारा के खिलाफ जमीनी संघर्ष की धार को और अधिक तीखा किया जा सकेगा। कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने भी प्रियंका को मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में उतारे जाने की मांग की है। दूसरी तरफ पीसीसी के महामंत्री महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि वे हाईकमान से प्रयंका को यहां से राज्यसभा का टिकट देने की मांग करेंगे।

700 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी टाटा पावर अगले दो वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। कंपनी पहले ही तेजी से चार्ज करने वाले 100 स्टेशन स्थापित कर चुकी है।

अहमदाबाद एयरपोर्ट से हटेंगे उद्यमियों के चार्टर्ड प्लेन

▶ ट्रंप की गुजरात यात्रा का असर, रोड शो के मार्ग पर दुकानें भी बंद रहेंगी

▶ ताजनगरी में 24 को आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, तैयारियां जोरों पर

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गुजरात यात्रा को लेकर जहां सरकार जोर-शोर से तैयारियां कर रही है, वहीं सामान्य नागरिकों, दुकानदारों से लेकर कॉरपोरेट घरानों तक को सुरक्षा कारणों के चलते परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप की यात्रा के दौरान जहां पूरे दिन रोड शो रुट की दुकानें बंद रहेंगी, वहीं औद्योगिक घरानों के चार्टर्ड प्लेन भी एयरपोर्ट से हटाने पड़ेंगे।

अहमदाबाद के सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से गांधी आश्रम तक और गांधी आश्रम से मोटेरा स्टेडियम तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए पहुंचेंगे। 24 फरवरी को उनकी यात्रा के दौरान सुरक्षा कारणों से अहमदाबाद पुलिस आयुक्त ने रोड शो के रुट की दुकानें बंद रखने को कहा है। इस दौरान देश के नामी उद्यमियों को भी ट्रंप की गुजरात यात्रा से परेशानी हो सकती है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अदाणी समूह के तीन, निरमा समूह का एक, कैडिला फार्मा का एक सहित करीब दो दर्जन चार्टर्ड प्लेन खड़े रहते हैं जिन्हें अन्य शहरों और राज्यों के एयरपोर्ट पर भेजा जा रहा है। बता दें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट का पार्किंग चार्ज प्रति हजार किलो 3.50 रुपये प्रति घंटे है, जबकि मुंबई के जीवीके छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक दिन का किराया 75 हजार रुपये तक वसूलता है। इसके चलते भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में प्लेन पार्क किए जाते हैं।

इस बीच, चांदखेड़ा, सरदारपुरा, मोटेरा सहित अहमदाबाद के कई इलाकों में पुलिस ने एक अभियान चलाकर बिना पुलिस मंजूरी किराए पर रह रहे 18 किराएदार पकड़े हैं और मकान मालिकों के खिलाफ आइपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। गांधी आश्रम और सुभाष ब्रिज के आसपास की सोसायटियों के लोगों को निर्देश दिया गया है कि रोड शो के दौरान सड़क पर खड़े रहने के लिए पुलिस पंजीकरण करा लें। सड़क के दोनों ओर खड़े रहने वाले लोगों के हाथों में भारतीय और अमेरिकी ध्वज दिए जाएंगे। इन लोगों को ध्वज सौंपने का काम शिक्षकों को दिया गया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगरा दौरे से पहले मंगलवार को अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने भारत के सीआइएसएफ बल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्यों के साथ ताजमहल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। प्रेट्र

झुग्गीवासियों को जगह खाली करने का नोटिस

अहमदाबाद, प्रेट्र : अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के पास झुग्गी बस्ती में रह रहे करीब 45 परिवारों को अहमदाबाद नगर निगम ने सात दिन में जगह खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों को ट्रंप की यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, निगम के डिप्टी इस्टेट ऑफिसर (वेस्ट जोन) चैतन्य शाह ने कहा कि इन नोटिसों का 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम से कोई लेना-देना नहीं है। जनवरी में साइट सर्वे कराया गया था और पाया गया कि उक्त भूखंड पर अतिक्रमण किया गया है।

स्वागत ऐसा हो, जिसे दुनिया याद करे : योगी

जागरण संवाददाता, आगरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 24 फरवरी को आगमन के मद्देनजर मंगलवार को उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया, लेकिन वह व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं थे। मुख्यमंत्री ने कई जगह पर्याप्त रोशनी न होने पर नाराजगी जताई तो ताजमहल के पास बदबू आने पर उन्होंने छह दिन विशेष सफाई अभियान चलाने का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐसा स्वागत हो, जिसे दुनिया याद करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार शाम 4.15 बजे खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे और अधिकारियों से अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। कोठी मीना बाजार मैदान में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद सीएम ट्रंप के प्रस्तावित रूट की ओर बढ़ गए। माल रोड, फतेहाबाद रोड होते हुए होटल अमर विलास पहुंचे। जहां गोल्फ कार्ट से ताज के पूर्वी गेट पहुंचे। सीएम ने ताज में भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा संबंधी सवाल भी पूछे। ताज के रॉयल गेट तक गए। यहां के बाद सर्किट हाउस आकर अमेरिका की एडवांस टीम के साथ बैठक की। खेरिया एयरपोर्ट से ताज महल तक सीएम को कई जगह अव्यवस्थाएं मिलीं। कई जगह धूल उड़ने पर उन्होंने वहां पानी का छिड़काव करने को कहा। शहर में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि विदेशी मेहमान को महसूस हो कि वह ताज के शहर में गए थे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए।

शरजील का भाषण सुनकर ही लोग हुए थे हिंसक

कार्रवाई ▶ जामिया व एनएफसी हिंसा मामले में दो महीने बाद आरोप पत्र दायर

जामिया के एक भी छात्र को नहीं बनाया गया आरोपित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधित कानून (सीएए) के खिलाफ गत 15 दिसंबर को दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी (एनएफसी) और जामिया नगर में शरजील इमाम के भाषण को सुनकर ही लोग आक्रोशित हुए थे और करीब आठ घंटे तक सड़कों पर जमकर हिंसक उपद्रव किया था। इस मामले में 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में 18 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

दोनों जगहों पर हुए भीषण हिंसक उपद्रव में जामिया विश्वविद्यालय समेत अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में शामिल थे, लेकिन फिलहाल आरोप पत्र में क्राइम ब्रांच ने उनके भविष्य को देखते हुए एक को भी आरोपित नहीं बनाया है। वहीं, आरोप पत्र में शरजील के बारे में बताया गया है कि उसी के भड़काऊ भाषण के बाद छात्रों व स्थानीय लोग उत्तेजित हो गए थे और उन्होंने हिंसक उपद्रव किया था। आरोप पत्र घटना के करीब दो महीने बाद दायर किया गया है। आरोप पत्र में देशद्रोह के आरोपित जेएनयू के शोध छात्र शरजील इमाम समेत 18 उपद्रवियों को आरोपित बनाया गया है।

शरजील इमाम की फाइल फोटो। प्रेट्र

अब तक

18 आरोपितों की दो केसों में हो चुकी है गिरफ्तारी

04 आरोपित अभी तिहाड़ जेल में, बाकी जमानत पर बाहर

04 95 लोग उपद्रव में हुए थे घायल, 6 डीटीसी बसों में लगा दी थी आग

04 100 से अधिक लोगों को बनाया गया है गवाह

क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है। मामला संवेदनशील व राजनीतिक होने के कारण क्राइम ब्रांच के अधिकारी कुछ भी बताने से बचते रहे। गोपनीय तरीके से 13 फरवरी को आरोप पत्र दायर कर दिया गया। जामिया व एनएफसी मामले में शरजील समेत 18 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनएफसी और जामिया में 9-9 आरोपित गिरफ्तार किये गए थे। जिनमें शरजील को छोड़कर बाकी सभी स्थानीय ही है। चार आरोपित अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं, बाकी जमानत पर बाहर हैं।

आरोप पत्र में बड़ी संख्या में सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल से बनाए गए वीडियो व आरोपितों के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल का रिकॉर्ड रखा गया है। 100 से अधिक लोगों को गवाह बनाया गया है। दोनों जगहों पर हुए हिंसक उपद्रव में 95 लोग घायल हो गए थे, जिनमें 47 पुलिस अधिकारी व कर्मी शामिल थे। दंगे के दौरान उपद्रवियों ने डीटीसी की 6 बसें व तीन निजी वाहनों में आग लगा दी थी। आरोप पत्र में प्वाइंट 32 बोर की पिस्टल से गोली चलने की बात भी कही गई है। आरोप पत्र में कहा गया है कि कई दंगाइयों की तस्वीरें मिल गई हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हुई है। पहचान के लिए विज्ञापन दिए गए हैं।

केंद्रीय अपर परिवहन सचिव के खिलाफ जमानती वारंट

जासं, नैनीताल: उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों के बकाया वेतनमान मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने केंद्रीय अपर परिवहन सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर नैनीताल एसएसपी को कार्रवाई सुनिश्चत करने का निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिवहन संपत्तियों के बंटवारे के मामले में केंद्रीय अपर परिवहन सचिव को मंगलवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। इस पर हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करते हुए 24 फरवरी को उन्हें तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कर्मचारी संघ ने याचिका में बताया कि सरकार न तो उन्हें नियमित वेतन दे रही है और न ही अस्थायी कार्मिकों को नियमित किया जा रहा है। रिटायर कर्मचारियों का भी भुगतान नहीं किया गया है। आंदोलन करने पर सरकार ने उन पर एस्मा लगाने की चेतावनी देती है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मध्य परिसम्पत्तियों का बंटवारा नहीं होने से उत्तराखंड परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम को करीब 64 करोड़ की धनराशि नहीं दी है। इसके अलावा उत्तराखंड परिवहन निगम के उत्तर प्रदेश सरकार पर 800 करोड़ रुपये बकाया हैं जो आज तक नहीं मिले। याचिका में कहा गया है कि अगर निगम को यह धनराशि मिल जाती है तो कई समस्याएं हल हो जाएंगी।

शाहीन बाग में मध्यस्थों के पहुंचने को लेकर असमंजस में रहे प्रदर्शनकारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थता तय किए जाने के बाद से प्रदर्शनकारियों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शन में किसी आधिकारिक व्यक्ति या संस्था का न होना लोगों को अखर रहा है। प्रदर्शनकारियों के सवालों के जवाब देने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में लगातार 65 से अधिक दिनों से सड़कों पर बैठे प्रदर्शनकारी परेशान हैं। मंगलवार सुबह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मध्यस्थों के शाहीन बाग पहुंचने की सूचना पर असमंजस की स्थिति रही। बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त तीन वार्ताकार बुधवार को दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के प्रदर्शनकारियों को मनाने के लिए चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे। बैठक टीम के सदस्य संजय हेगड़े के घर पर होगी, जिसमें साधना रामचंद्रन और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह प्रदर्शनकारियों को एक वैकल्पिक स्थान पर आंदोलन करने के लिए मनाने के लिए बातचीत की रूपरेखा तय करेंगे। शीर्ष अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय की है।

यह है मामला : नंद किशोर गर्ग और अमित साहनी द्वारा जनहित याचिका दायर कर कालिंदी कुंज के पास शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए केंद्र और अन्य सक्षम संस्थाओं को निर्देशित करने की अपील की गई थी। याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करके शाहीन बाग में लोग अवैध रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 17 फरवरी को तीन वार्ताकारों को लोगों से सड़क खाली करने के लिए बातचीत करने के लिए नियुक्त किया है।

नेतृत्व विहीन प्रदर्शन, कौन करेगा बात : शाहीन बाग में चल रहे धरना प्रदर्शन में कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है जिसके कारण प्रदर्शनकारियों के मन में यह सवाल है कि वार्ताकारों से बात करेगा कौन? लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद खुशी जताई थी, लेकिन नेतृत्व न होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति वार्ताकारों से बात करना चाहता है।

शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन में मंगलवार को बहुत कम लोग पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्ग अवरुद्ध करने पर की गई टिप्पणी के बाद अब भीड़ छंटने लगी है। जागरण

पूछ रहे लोग, शाहीन बाग में कब होगी कार्रवाई

जासं, नई दिल्ली : अब दिल्ली पुलिस को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस पिछले दो माह से रोजाना फेसबुक और ट्विटर पर लोगों को कालिंदी कुंज रोड 13ए बंद होने की जानकारी देती है। इसके बाद लोग फेसबुक पर अपने गुस्से का इजहार करना शुरू कर देते हैं। अब तो लोगों ने सोशल मीडिया पर ही पूछना शुरू कर दिया है कि आखिर धरने पर बैठे लोगों पर कार्रवाई कब की जाएगी। दिल्ली पुलिस लोगों की सुविधा के लिए ज्यादा व्यस्त या ट्रैफिक जाम की सूचना फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से जनता को देती है। इसी क्रम में पुलिस कालिंदी कुंज मार्ग बंद होने और मथुरा रोड पर औसतन ज्यादा ट्रैफिक रहने की सूचना फेसबुक के जरिये रोजाना देती है। शुरुआती दिनों में लोगों ने पुलिस को इसके लिए धन्यवाद दिया, लेकिन पिछले दो सप्ताह से लोग पुलिस की इस पोस्ट पर सवाल उठा रहे हैं।

नक्सल प्रभावित जिलों में सड़कों के लिए 1636 करोड़ मंजूर

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित आठ जिलों में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (आरसीपीएलडब्ल्यूई) योजना के तहत सड़क और पुल निर्माण के लिए तीन चरणों में कुल 1635 करोड़ 96 लाख रुपये को मंजूरी दी गई है। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि इस राशि का उपयोग कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और राजनांदगांव में बेहतर कनेक्टिविटी और सुदूर ग्रामीण अंचलों को जोड़ने के लिए किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय इन जिलों की 240 किलोमीटर लंबाई की सड़क निर्माण के लिए 638 करोड़ रुपये की सहमति दी है। इसके अलावा इस योजना के तहत प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाकर 97 कार्यों (72 सड़क और 25 पुल) कुल लंबाई 1238 किलोमीटर के लिए 997 करोड़ 96 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन सड़कों के निर्माण में भारत सरकार का 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का 40 प्रतिशत भागीदारी है।

झारखंड पुलिस की गुंडागर्दी, 18 किमी तक महिला डॉक्टर का पीछा कर मचाया बवाल

जेएनएन, रांची

▶ डॉक्टर के चालक को एके-47 के बट से पीटा, गाड़ी में तोड़फोड़

झारखंड में गरिडीह पुलिस की स्मॉल एक्शन टीम (सैट) के जवानों ने सोमवार की रात गुंडागर्दी की हद पार कर दी। रिम्स की एक महिला डॉक्टर अदिति कश्यप की कार का घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 18 किलोमीटर तक पीछा किया। ओवरटेक कर गाड़ी रोकी, डॉक्टर के चालक को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और एके-47 की बट से मारकर जख्मी कर दिया। बीचबचाव करने पर महिला चिकित्सक से भी दुर्व्यवहार किया। जवान सादे लिबास में थे और सफेद स्कार्पियो में स्कूटी का नंबर लगाकर चल रहे थे। इस घटना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गंभीरता से लिया है। मंत्रियों ने दो टूक कह दिया है कि ऐसी पुलिसिंग यहां नहीं चलेगी। दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश मिलने के बाद एसपी गिरिडीह सुरेंद्र कुमार झा ने सैट के दोषी दो जवानों राजेंद्र कुमार व कुमार वरदराज भास्कर को मंगलवार को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर एसपी गिरिडीह को कार्रवाई का आदेश दिया। एसपी ने रीट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी दी है।

> मुझे अब तक प्राथमिकी का नंबर नहीं मिला है। गिरिडीह पुलिस अपने विभाग के जवानों को बचाने की कोशिश में जुटी है। न्याय की उम्मीद कम लग रही है।
> -डा. अदिति कश्यप, पीड़िता

डॉ. अदिति कश्यप ने गिरिडीह के टाउन थाने में इस पूरे मामले में लिखित शिकायत की हैं। उन्होंने आवेदन में बताया है कि वह अपने ड्राइवर शहंशाह सिंह के साथ सोमवार की शाम रांची से देवघर के लिए अपनी टाटा नेक्सान कार से रवाना हुई थीं। गिरिडीह के डुमरी में दो ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। उनकी कार किसी तरह वहां से निकली और एक बलेनो व एक स्कार्पियो को ओवरटेक कर आगे बढ़े। इसके बाद से ही स्कार्पियो ने उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। घनघोर जंगल क्षेत्र में स्कार्पियो सवार गाड़ी के समानांतर आकर गाली देते हुए गाड़ी रोकने को कह रहे थे। डॉक्टर डर गईं और चालक से बोलीं कि जहां पुलिस दिखे, वहीं गाड़ी रोके, क्योंकि जगह सुरक्षित नहीं है। इसी बीच डॉक्टर ने स्कार्पियो का नंबर भी नोट किया। जब उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया तो वह नंबर स्कूटी का निकला।

उन्होंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी किसी भी कीमत पर नहीं रोकनी है। करीब 18 किलोमीटर की भागमभाग के बाद गिरिडीह के कोलडीहा पेट्रोल पंप पर पहुंचे और फिर स्कार्पियो को पास दी। इसके बाद ही स्कार्पियो पर सवार एके-47 से लैस सादे लिबास में 10-12 लोग उतरे और गाली देते हुए मारपीट व तोड़फोड़ शुरू कर दी। चालक के गले से सोने की चेन भी लूट ली गई।

नापाक हरकत को विफल करने के लिए सतर्क और तैयार रहें कमांडर : भदौरिया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

▶ वायुसेना अध्यक्ष ने कमांडरों को समझाई रणनीति

▶ दस एयर फोर्स स्टेशन के कमांडर तीन दिवसीय सम्मेलन में कर रहे शिरकत

प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान मुख्यालय बमरौली में दस एयरफोर्स स्टेशनों के कमांडरों के सम्मेलन में वायुसेना की रणनीति पर बात की गई। मंगलवार को सम्मेलन का उद्घाटन कर वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया ने कमांडरों को मुस्तैद रहने का मंत्र दिया। कहा कि सभी कमांडर शत्रु की किसी भी नापाक हरकत को विफल करने के लिए सतर्क एवं तैयार रहें। उन्होंने एयरो स्पेस, साइबर और सूचना क्षेत्र में सर्वोच्च प्रशिक्षण मानक अपनाने को कहा। साथ ही बदले दौर की आधुनिक सुरक्षा प्रणाली अपनाने का भी निर्देश दिया। कहा कि डिजाइन एवं विकास में अधिकतर स्वदेशीकरण को तरजीह दिया जाय।

तीन दिवसीय सम्मेलन में वायुसेना अध्यक्ष ने मध्य वायु कमान के परिक्षेत्र में आने वाली यूनिटों और स्टेशनों की ऑपरेशनल तैयारी के साथ ही कमान में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद सम्मेलन में कमांडरों को सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना की रणनीति को स्पष्ट किया।

सम्मेलन के बाद उन्होंने मध्य वायु कमान के वायु योद्धाओं एवं असैन्य कार्मिकों से मुलाकात की। भारतीय वायु सेना के मूल सिद्धांत अभियान, सत्यनिष्ठा एवं उत्कृष्टता को और आगे बढ़ाने में उनके कठिन कार्य व समर्पण भावना की सराहना की। वह बुधवार को भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

इन स्टेशनों से आए हैं कमांडर : मध्य वायु कमान के परिक्षेत्र में बरेली, ग्वालियर, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, दरभंगा और बिहटा एयरफोर्स स्टेशन के कमांडर सम्मेलन में आए हैं।

सनसनी के अलावा भी किताब में बहुत कुछ है : अहलूवालिया

नईदुनिया, भोपाल : संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के वक्त केंद्रीय योजना आयोग (अब नीति आयोग) के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि उनकी किताब 'बैकस्टेज : द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ ईयर्स' में सनसनी के अलावा भी बहुत कुछ है। किताब में पर्दाफाश किया गया है कि 2013 में राहुल गांधी के अध्यादेश फाड़ने की घटना से वह (पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह) आहत थे और इस्तीफा भी देना चाहते थे। सिंह ने कहा कि किताब में देश के कई महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा है। मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य के पास वित्तीय संसाधन सीमित होते हैं और अधिकार भी, ऐसे में इनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल होना चाहिए।

मुख्यमंत्री कमलनाथ के बुलावे पर 'वैकल्पिक वित्त व्यवस्था' विषय पर मार्गदर्शन देने मंगलवार को भोपाल आए सिंह ने नईदुनिया से विशेष बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग सनसनी निकाल लेते हैं और बड़ा भाग छोड़ देते हैं। किताब में बहुत कुछ है।

रखी बात

लखनऊ स्थित लोहिया विधि विश्वविद्यालय के आंबेडकर सभागार में एकल अभियान परिवर्तन महाकुंभ के समापन समारोह को रक्षा मंत्री ने किया संबोधित

धर्मांतरण महापाप, जनजागरण से ही रुकेगा : राजनाथ

जागरण संवाददाता, लखनऊ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि लालच और डरा धमकाकर किसी का धर्म परिवर्तन करा देना महापाप है। इसको कानून और सख्ती के जरिये रोकना आसान नहीं है। इस मुद्दे पर एकल अभियान जैसे जनजागरण अभियान ही कुछ कर सकते हैं। नक्सली, आतंकवाद प्रभावित और सीमावर्ती इलाकों में एकल विद्यालय शानदार काम कर रहे हैं, जो धर्मांतरण रोकने में भी मददगार साबित हो रहे हैं।

राजनाथ सिंह लखनऊ स्थित लोहिया विधि विश्वविद्यालय के आंबेडकर सभागार में एकल अभियान परिवर्तन महाकुंभ- 2020 के समापन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एकल अभियान से राष्ट्र का उत्थान हो रहा है। मेरा विश्वास पक्का हुआ कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। बिना वेतन प्राप्त किए लगातार काम करना बड़ी बात है।

वनवासी इलाकों में रहना बहुत कठिन तपस्या : आदिवासी और वनवासी इलाकों में रहना बहुत कठिन तपस्या है। नक्सली इलाकों में बड़े-बड़े दिलेर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन इलाकों में भी एकल अभियान चल रहा है। देश में एक लाख एकल विद्यालय हैं और 28 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। यह बड़ी बात है। आप जिस जगह काम करते हैं, वहां धर्मांतरण का संकट है। जो जिस धर्म का पालन कर रहा है, उसे आजादी है, मगर प्रलोभन और डराकर धर्म परिवर्तन कराने वाले महापाप कर रहे हैं। यह अभियान ही धर्मांतरण रोक पाएगा। कहा कि बहुत सारी विदेशी ताकतें हमको तोड़ना चाहती हैं, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं। लोगों को डराना उद्देश्य नहीं है।

लखनऊ में मंगलवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया विवि में एकल अभियान द्वारा आयोजित परिवर्तन कुंभ के समापन के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जागरण

सैनिक से कम नहीं शिक्षक का काम : रमेश भाई ओझा

कार्यक्रम में प्रख्यात कथावाचक रमेश भाई ओझा ने कहा कि आप सभी एकल योद्धा हैं। देश में एक सर्वे किया गया कि आपकी दृष्टि में समाज में सबसे आदरणीय कौन है। आप सबसे अधिक किसको चाहते हैं, जिसमें पता चला कि सबसे ज्यादा आदर पूर्वक लोग अध्यापक और सैनिक को मानते हैं। एक सीमा पर लड़ रहा है। अध्यापक अपने विद्यालय में अज्ञान के खिलाफ लड़ता है।

हमको अध्यात्म ने बचाया : कृष्ण गोपाल

आरएसएस के सह संचालक कृष्ण गोपाल ने देश की एकता और आध्यात्मिकता की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भक्ति का ये भाव ही जोड़ रहा है। भारत अध्यात्म के आधार पर संकटों का सामना करता है। कभी हम विश्व में नंबर एक थे, मगर बुरे काल का प्रभाव एक हजार साल तक रहा। इतने संघर्ष हुए, लेकिन दुनिया में केवल हम ही हैं जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रख सके।

हिंदुओं को प्रतिक्रियावादी नहीं होना चाहिए : भागवत

▶ देश भर के 70 स्तंभकारों के साथ संघ प्रमुख ने किया संवाद

▶ कानून नापसंद हो तो बदलाव की मांग करें, बसें न जलाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि खुलापन हिंदुओं की पहचान है, जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। भागवत के मुताबिक हिंदुओं के जागरण की आवश्यकता है, लेकिन यह किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को प्रतिक्रियावादी नहीं होना चाहिए।

संघ प्रमुख ने दिल्ली के छतरपुर में पूरे देश के 70 स्तंभकारों के साथ संवाद किया। यह बंद दरवाजे के भीतर हुई बैठक थी। भागवत की कोशिश संघ के प्रति लोगों के मन में व्याप्त कतिपय भ्रांतियों को दूर करने की थी। बैठक में मौजूद रहे कई स्तंभकारों ने बताया कि तमाम विषयों पर यह संवाद अर्थपूर्ण और फलदायी रहा।

एक स्तंभकार के मुताबिक, संघ प्रमुख ने खुलेपन संबंधी हिंदू समुदाय की विशेषताओं पर जोर दिया। भागवत ने कहा, हम किसी का वर्गीकरण नहीं करते। किसी पर हमें कोई संदेह नहीं है।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और इसके खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर भागवत ने कहा कि किसी भी कानून को नापसंद किया जा सकता है और उसमें बदलाव की मांग की जा सकती है, लेकिन इसके नाम पर न तो बसें जलाई जा सकती हैं और न ही सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद किया जा सकता है। भागवत ने कहा, बसों को जलाना लोकतंत्र नहीं है। अब वही लोग भारत का झंडा लहरा रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं।

भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो कौन बदल रहा है? कौन जीत रहा है? भागवत ने गत वर्ष देश में काम कर रहे विदेशी मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की थी।

4000 नमूने खाद्य पदार्थों की असुरक्षित पाए गए देश में पिछले साल। एक लाख छह हजार खानपान के नमूनों की जांच हुई थी। इनमें 3.7 फीसद नमूने असुरक्षित पाए गए।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 19 फरवरी 2020

न्यूज गैलरी

श्रीनगर की बरीक मंजूर को इग्नू से गोल्ड मेडल

जम्मू : नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के 33वें दीक्षा

समारोह में बरीक मंजूर को राष्ट्रीय स्तर पर बीकॉम परीक्षा में अव्वल आने पर गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वह श्रीनगर के रैनावारी की रहने वाली हैं। मंजूर अहमद मीर की बेटी बरीक को दीक्षा समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने कश्मीर में चुनौतियों के बीच पढ़ाई को जारी ही नहीं रखा, बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन कर पहला स्थान हासिल कर दिखा दिया है कि कड़ी मेहनत से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। (राब्यू)

फिर सैयद अली शाह गिलानी की मौत की अफवाह

श्रीनगर : लंबे समय से बीमार चल रहे अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत की अफवाहों से घाटी के कई इलाकों में फिर से तनाव फैल गया। अलबत्ता गिलानी के परिजनों ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि गिलानी की हालत स्थिर है। बीते कुछ दिनों से गिलानी की मौत की खूब अफवाहें चल रही हैं। हालांकि, प्रशासन ने भी इनका संज्ञान लेकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। (संवाद सहयोगी)

सेना ने आम लोगों के जान-माल व सम्मान को प्राथमिकता दी

प्रथम पृष्ठ से आगे

लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो ने कहा कि सेना की मुख्य जिम्मेदारी आतंकियों को एलओसी और घाटी के भीतरी इलाकों से दूर रखना है। एलओसी पर लगातार चौकसी, मजबूत घुसपैठ रोधी तंत्र, पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब और घाटी के भीतरी इलाकों में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर प्रभावी आतंकरोधी अभियानों के चलते ही स्थिति में सुधार हुआ है। हमने आम लोगों के जान माल व सम्मान को प्राथमिकता देते हुए आतंकरोधी अभियान चलाने की रणनीति अपनाई है। इससे आम लोग इन अभियानों की सफलता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने यह भी कि हमें गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आतंकवाद के समूल नाश में जुटे हैं।

ढिल्लो की जगह लेंगे बीएस राजू : सेना की 15वीं कोर को चिनार कोर भी कहा जाता है। पिछले वर्ष फरवरी में चिनार कोर की कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो अगले चंद दिनों में दिल्ली स्थित सैन्य मुख्यालय में सैन्य सचिव के तौर पर अपनी नयी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। वहीं, ढिल्लो की जगह बीएस राजू एक मार्च को चिनार कोर कमांडर के रूप में काम संभालेंगे।

जम्मू-कश्मीर में स्थगित किए गए पंचायत उपचुनाव

फैसला ▶ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा का हवाला दे वापस लीं सभी अधिसूचनाएं

पांच से 20 मार्च तक आठ चरणों में होने थे बची हुई सीटों पर चुनाव

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर में पंचायत उपचुनाव को लेकर मंगलवार सुबह हुई सर्वदलीय बैठक के बाद तेजी से बदले घटनाक्रम के बीच रात को चुनाव स्थगित कर दिया गया। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर जारी की गईं सारी अधिसूचनाओं को वापस ले लिया गया है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 13 फरवरी को जम्मू में पत्रकार वार्ता कर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में रिक्त पड़े 1011 सरपंच और 11639 पंच हलकों के चुनाव दलीय आधार पर करवाने का एलान किया था। उसके साथ ही अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी कि मतदान आठ चरणों में करवाया जाएगा। पहले चरण का मतदान पांच मार्च और अंतिम चरण का मतदान 20 मार्च को होना तय किया था।

> सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसी जानकारियां हासिल हुई हैं, जिसे देखते हुए पूरी व्यवस्था की दोबारा समीक्षा करने की जरूरत महसूस हुई है। लिहाजा चुनाव को लेकर जारी सभी अधिसूचनाएं वापस ले ली गई हैं। अगले दो-तीन सप्ताह में हालात की फिर से समीक्षा करके नए सिरे से अधिसूचना जारी की जाएगी।
> -शैलेंद्र कुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

क्या विपक्ष के दबाव के बाद लिया गया फैसला : सूत्र दावा कर रहे हैं कि पंचायत उपचुनाव स्थगित करने का फैसला विपक्षी पार्टियों के सरकार पर दवाब के कारण लिया गया है। पंचायत उपचुनाव की घोषणा के बाद से विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया था। नेशनल कांफ्रेंस के नेता रतन लाल गुप्ता ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि नेकां चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन पहले उनके नेताओं की रिहाई की जाए। उन्होंने कहा था कि जब नेता ही नजरबंद है तो उम्मीदवार कैसे तय किए जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रधान जीए मीर ने भी कहा था कि जब हमारे नेताओं पर पाबंदियां लगी हुई है, तो फिर चुनाव कैसे हो सकते हैं।

सुबह सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने रखी थी नेताओं की रिहाई की शर्त : पंचायत चुनाव के लिए पार्टियों का सहयोग मांगने के लिए जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने मंगलवार सुबह ही अपने कार्यालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और भाजपा और पैंथर्स पार्टी के नेताओं ने भाग लिया था। बैठक में पीडीपी नेताओं ने कहा था कि उनके नेता ही नजरबंद है तो उनकी पार्टी चुनाव में कैसे भाग ले सकती है। यह कहते हुए उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस, पैंथर्स ने भी पहले नेताओं को रिहा करने और उन पर लगी पाबंदियां हटाने को कहा था। वहीं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा था कि वह सरकार के समक्ष मुद्दा रखेंगे।

पाक सेना ने घुसपैठ के लिए एलओसी पर लगाई आग, गोलाबारी भी की

जागरण संवाददाता, पुंछ : पाकिस्तानी सेना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई आग एलओसी पार कर पुंछ के बालाकोट सेक्टर में एक से डेढ़ किलोमीटर तक फैल गई है। इससे अब तक सीमा पर बिछाई गई करीब 15 बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो चुका है। सेना के दमकल कर्मी और जवान आग पर काबू पाने में जुटे हैं।

इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को पुंछ के शाहपुर किरनी सेक्टर में भारी गोलाबारी की। पाकिस्तानी सेना आग और गोलाबारी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहती है, लेकिन भारतीय सेना करारा जवाब देकर हर साजिश को नाकाम बना रही है।

जानकारी के अनुसार, दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने शाहपुर किरनी सेक्टर में एकाएक सेना की अग्रिम चौकियों के साथ रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर गोलाबारी शुरू कर दी। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है।

कई बार सीमा पर आग लगा चुका है पाक : बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान कई बार सीमा पर आग लगा चुका है। सूत्रों के अनुसार, अब पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगी है। पाकिस्तान चाहता है कि रास्ते खुलने के बाद अधिक से अधिक आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में धकेला जाए, इसलिए सीमा पर भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए आए दिन साजिश रच रहा है।

लश्कर के दो गाइडों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- गुलाम कश्मीर के हैं रहने वाले, पिछले साल गुलमर्ग में पकड़े थे
- सैन्य ठिकानों की रेकी और आतंकियों को हथियार देने के लिए घुसे थे

उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग रिसार्ट गुलमर्ग में पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा के दो गाइडों के खिलाफ मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। यह दोनों पिछले साल 21 अगस्त को पकड़े गए थे। इनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम और इग्रेस एंड इंटर्नल मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

यह दोनों गाइड भारतीय सेना के ठिकानों की रेकी करने और आतंकियों के लिए जरूरी साजो सामान की खेप पहुंचाने के लिए एलओसी के इस तरफ आए थे। इनके नाम खलील अहमद कयानी और मोहम्मद नाजिम हैं। यह दोनों ही गुलाम कश्मीर में खुर्शिदाबाद तहसील के पास टेडबन गांव के रहने वाले हैं। इन दोनों को सेना के गश्तीदल ने सीमा के 700 मीटर अंदर गुलमर्ग इलाके में नीलकंठ नाले के पास पकड़ा था। बाद में इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद मामले की जांच एनआइए को दी गई थी।

पाक सेना के अधिकारियों से संपर्क में थे

एनआइए के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों के खिलाफ मंगलवार को जम्मू स्थित एनआइए अदालत मे आरोपपत्र दायर किया गया है। इन दोनों की निशानदेही पर जंगल में एक जगह छिपाकर रखे गए हथियार, गोला-बारूद, दवाएं, ग्रेनेड, आइईडी बनाने का सामान, डेटोनेटर, पाकिस्तान निर्मित दवाएं और खाने-पीने का सामान भी बरामद किया गया। यह दोनों गुलाम कश्मीर में बैठे पाकिस्तानी सेना के आलाधिकारियों व अपने हैडलरों के साथ लगातार संपर्क में थे। यह आतंकियों के लिए सामान को पहले से तय जगह पर छिपाते थे। आतंकी बाद में इस सामान को प्राप्त कर जम्मू कश्मीर में विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए उसका इस्तेमाल करते थे।

'आर्थिक, मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक संकट से जूझ रहा जम्मू-कश्मीर'

- महबूबा की बेटी बोलीं, शेष भारत से कश्मीर के भावनात्मक जुड़ाव का जरिया था अनुच्छेद 370

नई दिल्ली, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से राज्य आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संकट से जूझ रहा है।

एक संवाददाता सम्मेलन में इल्तिजा ने कहा कि अनुच्छेद 370 शेष भारत से कश्मीर के भावनात्मक जुड़ाव का जरिया था और इसे बड़ी कीमत पर हटाया गया है। उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ महबूबा मुफ्ती की बेटी के तौर पर नहीं बल्कि एक चिंतित कश्मीरी के तौर पर भी बोल रही हूं। हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से क्या हो रहा है। मुझे वास्तव में लगता है कि सरकार दुष्प्रचार कर रही है। कश्मीर आने वाले देश के शेष हिस्सों के लोगों और राजनयिकों को बताया गया कि हमें समान अधिकार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम अभी कश्मीर में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। मेरे मन में भी अन्य लोगों की तरह प्रधानमंत्री के लिए सम्मान है। लेकिन मुझे दुख होता है कि उन्हें या तो गुमराह किया जा रहा है या वह जानबूझकर देश को गुमराह कर रहे हैं। अभी कश्मीरियों के

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस की। एएनआइ

पास क्या अधिकार हैं?' इल्तिजा ने 1989 में कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से पलायन पर अफसोस भी जताया। साथ ही कहा कि देश 'हिंदू पाकिस्तान' बनने की राह पर है और वर्तमान समय में सिर्फ संविधान ही 'पवित्र पुस्तक' है।

राजौरी में मिले भड़काऊ नारे लिखे झंडे, क्षेत्र में तनाव

जागरण संवाददाता, राजौरी : जम्मू के राजौरी में सीमावर्ती धरासंवला गांव में मंगलवार को हिंदू समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लिखे काले रंग के तीन झंडे मिलने से तनाव फैल गया। पुलिस और सेना ने मौके पर पहुंचकर झंडों को जब्त कर लिया। पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन अभी पता नहीं चल सका कि यह किसकी शरारत है।

सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने काले रंग के तीन झंडे पानी के कुएं के पास टंगे हुए देखे। इन झंडों पर आपत्तिजनक नारे लिखे थे। लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत पास में तैनात सेना के अधिकारियों व जवानों को दी। इसके साथ पुलिस पोस्ट चटियार को भी सूचित किया गया। सूचना मिलते ही सेना व पुलिस के जवानों ने इन झंडों को उतार कर जब्त कर लिया। इसके बाद काफी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों ने इस तरह की हरकत की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि क्षेत्र में शांति का माहौल बना रहे। इस घटना के बाद पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ भी की।

जम्मू-कश्मीर में युद्ध की भावी चुनौतियों से निपटेगा अलग थियेटर कमान

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- रक्षा विशेषज्ञ बोले- आज के समय की चुनौतियों की तैयारी है अहम

कूटनीतिक व सामरिक तौर पर जम्मू-कश्मीर की अपनी चुनौतियां हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे में जम्मू-कश्मीर में अलग से थियेटर कमान की स्थापना पाकिस्तान ही नहीं चीन की तरफ से आने वाली चुनौतियों से निपटने में अहम होगी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से सटे दोनों पड़ोसी देश अतीत में भी देश के लिए कई तरह की चुनौतियां पैदा करते रहे हैं।

कारगिल युद्ध के बाद से भारतीय सेना पहाड़ों पर युद्ध के लिए निरंतर तैयार हो रही है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वायुसेना की भी चुनौतियां मैदानी इलाकों से अलग रहती हैं। थियेटर कमान में सशस्त्र सेनाओं के सभी अंगों का एकसाथ प्रशिक्षण होगा और उन्हें युद्धक्षेत्र की चुनौतियों का सामने करने में दक्ष बनाया जाएगा। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का कहना है कि भविष्य के युद्ध आधुनिक तकनीक से लड़े जाएंगे। सशस्त्र सेनाओं के हर अंग के पास अलग तकनीक, साधन व अनुभव हैं। ऐसे में अगर तीनों सेनाएं मिलकर लड़ेंगी तो जीत की राह आसान होगी। थियेटर कमान में नियंत्रण किसी एक के पास होगा। थियेटर कमांडर के नेतृत्व में योजना बनेगी व ऑपरेशनल कमांडर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्रवाई को अंजाम देंगे। इससे संसाधनों व मानव संसाधनों की भी बचत होगी। मौजूदा व्यवस्था में तीनों सशस्त्र सेनाएं शस्त्र भंडार से लेकर जरूरी साजो सामान का अलग-अलग भंडारण करती हैं। ब्रिगेडियर गुप्ता के अनुसार इससे संसाधनों व उपकरणों का भंडारण भी एक साथ होगा। इसके साथ ही बेहतर संचार व्यवस्था व अन्य तकनीकी सहयोग सुनिश्चित होगा।

मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल का कहना है कि 21वीं सदी के युद्ध का स्वरूप अलग होगा। अलग थियेटर कमान आधुनिक वारफेयर की दिशा में एक कदम है। यह सशक्त होकर दुश्मन को नाकाम बनाने की दिशा में कार्रवाई है।

जम्मू-कश्मीर व लद्दाख की सुरक्षा का जिम्मा सेना की उत्तरी कमान के साथ पश्चिमी कमान के पास भी है। पश्चिमी कमान जम्मू के अखनूर तक 202 किलोमीटर में से 192 किलोमीटर अंतराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात है। वहीं, उत्तरी कमान अखनूर से पश्चिमी लद्दाख के सियाचिन तक 740 किलोमीटर नियंत्रण रेखा व पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी करीब एक हजार किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा संभाल रही है। इन मोर्चों पर सेना पाकिस्तान के साथ चार युद्ध लड़ चुकी है।

दो दशक पूर्व हुए कारगिल युद्ध के बाद अलग थियेटर कमान की जरूरत महसूस की गई थी। युद्ध के शुरुआती दौर में सेना व वायुसेना में बेहतर समन्वय की जरूरत महसूस की गई थी। थियेटर कमान में एक कमांडर के नेतृत्व में सेना, वायुसेना और नौसेना एक इकाई के रूप में काम करते हुए दुश्मन पर त्वरित व सटीक कार्रवाई कर सकते हैं। चीन ने 2016 में थियेटर कमान व्यवस्था स्थापित कर दी थी। ऐसे में पाकिस्तान के साथ चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए भी थियेटर कमान स्थापित करना आवश्यक हो गया था।

घाटी में हालात बिगाड़ने की साजिश में जुटे 200 शरारती तत्व चिह्नित

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- सोशल साइट के दुरुपयोग करने का मामला दर्ज, वीपीएन का प्रयोग कर चला रहे सोशल साइट

कश्मीर घाटी में लगातार सुधरते हालात के बीच इंटरनेट का दुरुपयोग कर हालात बिगाड़ने की साजिश में जुटे करीब 200 शरारती तत्वों को चिह्नित किया गया है। इन सभी के खिलाफ आइटी अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर साइबर पुलिस स्टेशन ने गत सोमवार को सरकारी आदेश की अवहेलना कर इंटरनेट की सोशल साइट का दुरुपयोग करने वाले तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इस बीच, संबंधित सूत्रों ने बताया कि घाटी में सिर्फ पांच से दस फीसद उपभोक्ता ही वीपीएन के जरिए हालात बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वीपीएन का इस्तेमाल करने वाले 90 से 95 फीसद उपयोगकर्ताओं की आयु 30 साल से कम है और वे वीडियो गेम्स खेलने के लिए ही ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग वाट्सएप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें से 99 फीसद किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री को अपलोड करने से बचते हैं।

केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर राज्य प्रशासन ने 14 जनवरी को जम्मू-कश्मीर में 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा को बहाल करते हुए सभी प्रकार की सोशल साइटों को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके साथ ही प्रशासन ने करीब 450 अनुमोदित वेबसाइट की सूची भी जारी की।

पाबंदी के बावजूद चलाई सोशल साइटें : प्रशासन के निर्देश और पाबंदियों के बावजूद घाटी में कई लोगों ने अपने मोबाइल पर वीपीएन के जरिए सोशल साइटों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। घाटी में सक्रिय आतंकियों और उनके समर्थकों ने भी वीपीएन के जरिए सोशल एप पर सरहद पार बैठे अपने आकाओं से संपर्क बहाल कर लिया है।

वीपीएन प्रयोग कर फैला रहे अफवाह : बीते कुछ दिनों से घाटी में अलगाववादियों के समर्थक भी वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया पर लगातर सक्रिय नजर आ रहे थे। उन्होंने कश्मीर बंद, गिलानी की तबीयत व अन्य कई मुद्दों पर वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए अफवाहों को आगे बढ़ा हालात बिगाड़ने का प्रयास किया। इसी के चलते बीते सप्ताह तो पुलिस को एक दिन के लिए 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा को फिर बंद करना पड़ा था।

शरारती तत्वों ने अफवाह फैलाई, भड़काऊ पोस्ट किए : साइबर सेल पुलिस स्टेशन और एसओजी श्रीनगर के प्रभारी एसपी ताहिर अशरफ ने बताया कि शरारती तत्व सोशल मीडिया को एक बड़ा हथियार बनाए हुए हैं। वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया पर शरारती तत्वों द्वारा फैलाई गई अफवाहों और उनके भड़काऊ पोस्ट का संज्ञान लेते हुए ही एक एफआइआर दर्ज की गई है।

पत्थर छोड़ भविष्य की नींव रख रहे कश्मीरी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- सेना के स्नो गेम्स में अपनी प्रतिभा को निखार रहे युवक और युवतियां
- उत्तरी कश्मीर में अलगाववादियों का गढ़ सोपोर अब तेजी से बदल रहा

उत्तरी कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकियों का गढ़ सोपोर अब तेजी से बदल रहा है। यहां युवाओं की अब वह भीड़ नहीं दिखती जो कभी अलगाववादियों और आतंकियों के समर्थन में रैलियां निकाली थीं या फिर सुरक्षाबलों पर पत्थर फेंकती थी। बदलाव के बीच अब ये युवा सेना द्वारा आयोजित स्नो गेम्स में नजर आते हैं। बर्फ के बीच ये अपना दमखम दिखा ही रहे हैं साथ ही अपने भीतर छिपी प्रतिभा को भी निखार रहे हैं। हालांकि, जीत की खुशी से कहीं ज्यादा इन युवाओं के चेहरे पर जिहादियों के दुष्प्रचार में अपनी प्रतिभा और आगे बढ़ने के मौकों को गंवाने का मलाल नजर आता है।

स्थानीय युवाओं को जिहादी तत्वों से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाने के लिए ही सेना की किलो फोर्स के अंतर्गत परिबल टेकरी राष्ट्रीय राइफल बटालियन ने सोपोर, राजपोरा, रामपोरा और साथ सटे अन्य इलाकों के नौजवानों के लिए स्नो गेम्स फेस्टिवल आयोजित किया। स्नो गेम्स के साथ साथ स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। स्नो गेम्स में करीब 170 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। रोप स्नो टैग, स्नो मैन बिल्डिंग रेस, स्नो मैन हैटट्रिक, फुट प्रिंट टैग रेस और स्नो रग्बी में स्थानीय खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। स्नो गेम्स फेस्टिवल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया।

स्नो गेम्स में जोर आजमाइश करते स्थानीय युवाओं का यह नजारा उत्तरी कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकियों का गढ़ कहे जाने वाला सोपोर का है। अनु.370 हटने और केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। राज्य के हालात सामान्य हो रहे हैं। सौजन्य : पीआरओ डिफेंस

आफिया ने कहा मैं कभी कभार स्कूल में या फिर अपने घर के आंगन में बर्फ की आकृतियां बनाती थी। पहली बार मैंने ऐसी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। मेरी जैसी और भी कई लड़कियां थी, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। मैंने एक स्नो मैन और स्नो साइकिल बनाई। रस्साकशी में उपविजेता रही टीम के सदस्य इरशाद ने कहा कि सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल है हमने कुछ किया। आजकल स्नो गेम्स खूब लोकप्रिय हैं। हमें लगता है कि हम इनमें अपना कैरियर बना सकते हैं। मैंने स्नो शू रेस में भी हिस्सा लिया है, उसमें दूसरे नंबर पर रहा हूं।

कर्नल रैंक के एक अधिकारी ने बताया कि बीते दिनों पत्थरबाजी के सिलसिले में पकड़े गए कुछ युवकों से बातचीत और स्थानीय लोगों के आग्रह पर ही हमने इन खेलों का आयोजन किया है। लोगों में स्नो गेम्स को लेकर काफी जोश है। हम तो यहां मौजूद भीड़ से हैरान हैं। बुजुर्ग अख्तर रशीद ने कहा कि हमारे बच्चों को इस तरह के मौके नहीं मिलते थे, इसलिए वह आपको नारे लगाते नजर आते थे। हमारे बच्चे वतनपरस्त हैं, बस इन्हें सही राह और मौका चाहिए।

बदलाव

आइएचबीटी स्थानीय किसानों को तकनीक व अन्य सहायता उपलब्ध कराएगा, देश ही नहीं विदेशों में भी महकेगी बर्फीले रेगिस्तान के फूलों की खुशबू

लद्दाख में फूलों की खेती से खुशहाल होंगे किसान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

बर्फीला रेगिस्तान लद्दाख... जहां मीलों तक बंजर रेतीली जमीन नजर आती हैं, में गुलाब और गेंदा की लंबी-लंबी क्यारियां होंगी। फूलों की खुशबू से सिर्फ लद्दाख ही नहीं महकेगा, बल्कि यहां के फूलों की महक देश-दुनिया को भी महकाएगी। सुनने में यह अटपटा लग सकता है, लेकिन यह सब हकीकत बनने जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी (आइएचबीटी) इसके लिए स्थानीय किसानों को तकनीक व अन्य सभी सहायता उपलब्ध कराएगा। इस खेती के जरिये किसानों का जीवन खुशहाल करने की योजना पर काम चल रहा है।

केंद्र शासित लद्दाख राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों के विपरीत कृषि अनुकूल नहीं हैं। यहां अत्यधिक ठंड होती है। सर्दी में अधिकांश समय बर्फ रहती है और गर्मी में धूल भरी आंधियां चलती हैं। इससे

प्रतीकात्मक

पेड़ पौधों को पनपने का मौका नहीं मिलता है। लद्दाख सब्जियों, दालों व खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह बाहर से आपूर्ति पर ही निर्भर है। स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति देश के अन्य इलाकों के किसानों से बहुत कमजोर है। शेरे कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर में वैज्ञानिक डॉ. संदीप ने कहा कि मैं लद्दाख में काम कर चुका हूं। हमने वहां फलोरीकल्चर और बागवानी को लेकर कई अनुसंधान किए हैं। वहां कई नकदी फसलें विशेषकर फूलों के उत्पादन की खूब संभावना है। लद्दाख में फूलों के कई ऐसे पौधे उगा सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्फीति या फिर तिब्बत में नहीं हो सकते। इसके लिए किसानों को जागरूक करना और आवश्यक तकनीक व सुविधाओं की जरूरत है जो अब उपलब्ध होने जा रही है।

इत्र, तेल के लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लगेंगी : लद्दाख फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स कापोरेटिव लिमिटेड (एलएफपीसीएल) लेह एंड लद्दाख ने हाल ही में आइएचबीटी पालमपुर के साथ एक समझौता किया है। आइएचबीटी स्थानीय किसानों को गुलाब, गेंदा, लेवेंडर जैसे फूलों और मिंट की खेती के लिए तकनीक उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा इन फूलों से अर्क, इत्र और तेल तैयार करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लद्दाख में लगाए जाएंगे। इनमें से एक यूनिट रणबीरपुरा थिक्से में स्थापित की जा रही है।

शुरुआत में 5500 हेक्टेयर में होगी खेती : सीएसआइआर आइएचबीटी के निदेशक डॉ. संजय कुमार के मुताबिक, लद्दाख के विभिन्न हिस्से में दमिश्क गुलाब, चमेली, गेंदा और केसर को पैदा किया जा सकता है। इसलिए हमने लद्दाख फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स कारपोरेटिव लिमिटेड के साथ सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किया है। यह परियोजना जिसे अरोमा मिशन प्रोग्राम कहते हैं, पर दो साल पहले काम शुरू हुआ था। इस मिशन के तहत शुरुआत में 5500 हेक्टेयर जमीन पर गुलाब, चमेली, गेंदा, मिंट उगाया जाएगा। हम किसानों को न सिर्फ इन फसलों के लिए बीज प्रदान करेंगे, बल्कि उन्हें इन्हें लगाने और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के तौर तरीके भी सिखाएंगे। एलएफपीसीएल के सीईओ एमएल मंटु ने कहा कि लद्दाख में पैदा होने वाले गुलाब, चमेली, गेंदा की खुशबू और औषधीय गुण भी बेहतर होंगे।

दुश्मनों की हरकतों का कड़ा जवाब दें जवान : सेना अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- जनरल नरवाने ने जम्मू के नगरोटा में फील्ड कमांडरों से बैठक की

नियंत्रण रेखा पर पाक की ओर से गोलीबारी से उपजे हालात के बीच थलसेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकंद नरवाने मंगलवार को जम्मू में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सेना की 16 कोर मुख्यालय नगरोटा में फील्ड कमांडरों के साथ बैठक की। उन्होंने जम्मू संभाग में सुरक्षा परिदृश्य, राजौरी, पुंछ जिलों में गोलाबारी से उपजे हालात व सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम बनाने के प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने सेना को कड़ी सर्तकता से दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाने के निर्देश दिए हैं।

थलसेना अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद जनरल नरवाने का सेना की उत्तरी कमान में यह तीसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने 9 जनवरी को सियाचिन और 22 जनवरी को उत्तरी कमान मुख्यालय ऊधमपुर का दौरा किया था। आर्मी चीफ जल्द कश्मीर का दौरा भी कर सकते हैं। सैन्य सूत्रों के अनुसार उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सीमा पार से होने वाली किसी भी प्रकार की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जम्मू-कश्मीर में इस समय आतंकवादियों के खिलाफ सेना की मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। नए वर्ष में अब तक प्रदेश में 28 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके साथ तीन दर्जन के करीब आतंकवादी व उनके ओवरग्राउंड वर्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में थलसेना अध्यक्ष की बैठक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की मौजूदा चुनौतियों व उनसे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा हुई।

1 अप्रैल से विदेशी यात्रा महंगी हो सकती है। इस दिन से विदेशी टूर पैकेज खरीदना और विदेश में कोई भी फंड खर्च करना महंगा हो जाएगा।

गुम जवाबों के बीच अब डीएनए इलेक्ट्रोफेराग्राम गुम!

सीएफएसएल, कोलकाता ने कहा कि उसके पास नहीं है नेताजी के स्वजनों के साथ गुमनामी बाबा के डीएनए मिलान का इलेक्ट्रोफेराग्राम

आरटीआइ के तहत मांगी गई थी सीएफएसएल से जानकारी

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और फैजाबाद (वर्तमान में अयोध्या) के गुमनामी बाबा। क्या ये दोनों एक ही थे? नेताजी के रहस्यमय ढंग से लापता होने की जांच के लिए गठित जस्टिस मुखर्जी आयोग और जस्टिस सहाय आयोग, गुमनामी बाबा की थ्योरी को खारिज कर चुके हैं, हालांकि आरटीआइ कार्यकर्ता सायक सेन द्वारा सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (सीएफएसएल), कोलकाता ने जो जवाब दिया है, उसने एक बार फिर इस सवाल को नए सिरे से जन्म दे दिया। सायक सेन ने सीएफएसएल, कोलकाता से गुमनामी बाबा के दांतों के नेताजी के परिवार के सदस्यों के साथ किए गए डीएनए मिलान के 'इलेक्ट्रोफेराग्राम' (रिपोर्ट) के बारे में जानकारी मांगी थी। इलेक्ट्रोफेराग्राम रिपोर्ट डीएनए टेस्ट के विश्लेषण का मूल अवयव है। सीएफएसएल कोलकाता के सीपीआइओ बीपी मिश्रा की तरफ से आरटीआइ का जवाब देते हुए कहा गया कि उनके पास इलेक्ट्रोफेराग्राम रिपोर्ट मौजूद नहीं है। इसके बाद से ही इस रिपोर्ट के लापता होने की बात कही जा रही है।

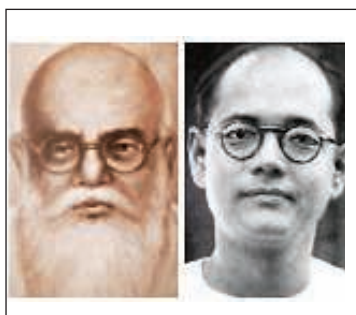

गुमनामी बाबा (बाएं) और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइल फोटो।

इलेक्ट्रोफेराग्राम रिपोर्ट अब भी गुप्त

नेताजी के गायब होने पर 20 वर्षों से शोध कर रहे लेखक अनुज धर ने दावा किया कि इलेक्ट्रोफेराग्राम रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। कहा, जहां मुझे जानकारी है, इसे मुखर्जी आयोग को भी नहीं सौंपा गया। 'नेताजी- रहस्य गाथा' नामक किताब लिख चुके धर ने कहा कि दो साल पहले जब इलेक्ट्रोफेराग्राम रिपोर्ट को लेकर आरआइटी आवेदन किया गया था, उस वक्त सीएफएसएल ने जानकारी देने तक से इन्कार कर दिया था और अब रिपोर्ट नहीं होने की बात कही है।

अनुज धर जागरण

सच्चाई जानने को लगाई आरटीआइ

आरटीआइ लगाने वाले सायक सेन ने बताया कि उन्होंने इलेक्ट्रोफेराग्राम रिपोर्ट की सच्चाई जानने के लिए आरटीआइ आवेदन किया था। अगर इलेक्ट्रोफेराग्राम रिपोर्ट की प्रति मिल जाती तो उसकी अन्य विशेषज्ञों से जांच कराकर सच्चाई का पता लगाया जा सकता था। यह भी पता चल जाता कि वाकई डीएनए टेस्ट हुआ था भी कि नहीं। सायक ने कहा- नेताजी को लेकर मुख्यत: तीन थ्योरी है। पहला विमान हादसे में उनकी मौत, दूसरा उनके रूस चले जाने वाली बात और तीसरी गुमनामी बाबा। इनमें गुमनामी बाबा वाली थ्योरी सबसे मजबूत है। नेताजी और गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग बिलकुल एक थी। गुमनामी बाबा से मिलने नेताजी के बेहद करीबी लोग आया करते थे। गुमनामी बाबा और नेताजी के परिवार के लोगों का डीएनए नहीं मेल खाना संदेह पैदा करता है।

सायक सेन जागरण

मैं डीएनए टेस्ट कराने को तैयार

नेताजी के पड़पोते चंद्र कुमार बोस ने दैनिक जागरण से कहा- गुमनामी बाबा के नेताजी होने की थ्योरी आधारहीन है। कुछ लोगों ने अपनी दुकान चलाने को इसे गढ़ा है। जो भी हो रहा है, बहुत गलत है। मेरे दोनों चाचा सुब्रत बोस व डीएन बोस का गुमनामी बाबा के दांतों के साथ डीएनए मिलान कराया गया था, जो बेमेल रहा। कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट हुआ ही नहीं था। अगर ऐसा है तो फिर से डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। मैं गुमनामी बाबा के संरक्षित करके रखे गए दांतों के साथ अपना डीएनए टेस्ट कराने को तैयार हूं।

चंद्र कुमार बोस की फाइल फोटो। जागरण

'दैनिक जागरण' ने सच्चाई का पता लगाने के लिए कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में मौजूद सीएफएसएल का रुख किया। सीएफएसएल, कोलकाता के निदेशक बी बडोनिया ने कहा- हमें जिस एजेंसी से भी जांच का जिम्मा मिलता है, हम जांच पूरी करके रिपोर्ट उसे सौंप देते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही किया गया। अगर इलेक्ट्रोफेराग्राम रिपोर्ट की बात कही जा रही है तो वह मुखर्जी आयोग के पास होगी, हमारे यहां नहीं। इसलिए रिपोर्ट के गुम होने का सवाल ही नहीं है। वहीं सीपीआइओ बीपी मिश्रा ने कहा- आरटीआइ एक्ट के तहत जो पूछा गया था, हमने उसका जवाब दे दिया है। इसके इतर मैं कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं। बता दें कि गुमनामी बाबा फैजाबाद में रहने वाले रहस्यमय शख्स थे, जिन्हें 1970-80 में नेताजी बताया जा रहा था। उनकी आवाज, हैंडराइटिंग समेत विभिन्न शारीरिक गुणों के नेताजी से मिलने के कारण बोस होने का दावा किया जा रहा था। 16 सितंबर, 1985 को उनका निधन हुआ था।

पीरियड्स को लेकर गुजरात के धर्मगुरु का विवादित बयान

- कहा, पीरियड्स में पति के लिए खाना पकाने वाली महिला कुत्ते का जन्म लेगी
- ऐसी पत्नी का पकाया खाना खाने वाला पति अगले जन्म में बैल होगा
- इसी स्वामी के पंथ से जुड़े कॉलेज ने पीरियड्स चेक करने के लिए उतरवाए गए थे छात्राओं के कपड़े

अहमदाबाद, प्रेट्र : पीरियड्स को लेकर गुजरात के एक धर्मगुरु ने विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पीरियड्स के दौरान पति के लिए खाना पकाने वाली महिला का पुनर्जन्म कुत्ते के रूप में होगा, जबकि उसका बनाया खाना खाने वाला पति अगले जन्म में बैल के रूप में पैदा लेगा।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि जिस स्वामी कृष्णस्वरूप दासजी ने यह टिप्पणी की है, वह स्वामीनारायण मंदिर के 'नर-नारायण देवगड़ी' पंथ से जुड़े हैं। स्वामीनारायण मंदिर ही भुज में श्री सहजानंद गर्ल्स इंस्टीट्यूट (एसएसजीआइ) चलाता है, जिसकी प्रिंसिपल और महिला कर्मचारियों ने 11 फरवरी को यह जांच करने के लिए 60 छात्राओं के कपड़े उतरवा दिए थे कि कहीं वो पीरियड्स में तो नहीं हैं। कॉलेज के हॉस्टल के मेस में पीरियड्स वाली छात्राओं को दूसरी छात्राओं के साथ बैठकर खाना नहीं खाने दिया जाता। प्रिंसिपल रीता रनिंगा और महिला कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

स्वामी कृष्णस्वरूप ने कहा कि यह निश्चित है कि जो पुरुष पीरियड्स वाली महिलाओं के हाथ का पका हुआ खाना खाता है, उसका बैल के रूप में पुनर्जन्म होगा। उन्होंने यहां तक कह दिया, 'मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपको मेरे विचार पसंद हैं या नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने यह सब लिखा हुआ है। अगर कोई महिला पीरियड्स के दौरान अपने पति के लिए खाना पकाती है तो निश्चित रूप से अगले जन्म में वह कुत्ते के रूप में पैदा होगी।' स्वामी कृष्णस्वरूप के इस प्रवचन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि, यह वीडियो कब का और कहां का है यह स्पष्ट नहीं पाया है।

स्वामी ने महिलाओं को इस बात के लिए फटकार भी लगाई है कि वे पीरियड्स को लेकर लापरवाह रहती हैं। उन्होंने कहा, 'महिलाओं को यह एहसास नहीं होता कि पीरियड्स का समय तपस्या के समान है। यह हमारे शास्त्रों में लिखा है। मैं यह सब कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आपको सावधान करना था। पुरुषों को खाना पकाना सीखना चाहिए... इससे आपको मदद मिलेगी।'

न्यूज गैलरी

पीलीभीत में बरात के दौरान हर्ष फायरिंग, युवक घायल

पीलीभीत : बरात के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से युवक घायल हो गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लाइसेंसी बंदूक कब्जे में ले ली है। बरेली जिले के फरीदपुर निवासी श्रीपाल के बेटे की बरात सोमवार रात पतरसिया गांव आई थी। बरातघर में समारोह चल रहा था। इसी बीच शाहजहांपुर जिले के चिरचिरा गोटिया गांव निवासी नत्थूलाल ने लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग कर दी। गोली बदायूं जिले के बीरमपुर गांव निवासी विजय कुमार के बाएं हाथ में लगी। नत्थूलाल भाग गया, जबकि बरातियों ने उसकी लाइसेंसी बंदूक छीन ली। पुलिस ने घायल विजय कुमार को जिला अस्पताल भेजा। विजय के साले बरेली जिले के महमूदापुर गांव निवासी देवेंद्र पाल ने आरोपित नत्थूलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एसपी अभिषेक दीक्षित ने बताया कि नत्थूलाल को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक बरामद कर ली गई है। आरोपित का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने के लिए शाहजहांपुर के जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट जल्द ही भेजी जाएगी। (जासं)

शिमला में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके

शिमला : हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार दोपहर 12.48 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र शिमला से उत्तर पूर्व दिशा में 53 किलोमीटर दूर था। इसकी गहराई पांच किलोमीटर थी। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। कम तीव्रता होने से लोगों को भूकंप का अधिक अहसास नहीं हुआ। भूकंप से जान माल का भी नुकसान नहीं हुआ है। (जासं)

1.6 किलो चरस समेत पंजाब व उत्तराखंड के दो लोग गिरफ्तार

मंडी : मंडी पुलिस के विशेष जांच दल (एसआइयू) व औट पुलिस ने दो लोगों से 1.6 किलोग्राम चरस बरामद की है। एक आरोपित पंजाब व दूसरा उत्तराखंड का रहने वाला है। औट पुलिस ने मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार देर शाम मुख्य आरक्षी यशपाल सिंह की अगुआई में थलौट में पुलिस थाना के समीप वाहनों की जांच के लिए नाका लगाया था। कुल्लू की तरफ से आई एक निजी बस को रोक कर सवारियों के सामान की तलाशी ली तो बेनेखेड़ा बजपुर (जिला काशीपुर, उत्तराखंड) के सोनू के बैग से 508 ग्राम चरस मिली। एक अन्य मामले में मनाली से कांगड़ा की तरफ जा रही निजी बस को रोक कर सवारियों के सामान की तलाशी लेने पर पंजाब के भाबुर से एक किलो 154 ग्राम चरस मिली।(जासं)

बिहार में होमगार्ड की हत्या, शव फेंका

तेतरिया (पूर्वी चंपारण) : पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र में नारायणपुर बाजार के पास एक होमगार्ड का शव मिला है। जवान की हत्या कर शव को यहां फेंक दिया गया था। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया। शव की शिनाख्त राजेपुर पंचायत के फुलवरिया गांव निवासी रामेश्वर सहनी के रूप में की गई। वह मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाने में तैनात था। चार दिन पहले ड्यूटी से घर लौटा था। बताया गया कि सोमवार शाम किसी ने मोबाइल पर कॉल कर उसे बुलाया। रात में घर नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। इस बीच मंगलवार की सुबह शव बरामद होने की सूचना मिली। जवान की बाइक घटनास्थल से थोड़ी दूर पर बरामद की गई। (जासं)

दिल्ली का मोस्ट वांटेड डेढ़ लाख का इनामी मुठभेड़ में ढेर

जागरण संवाददाता, मेरठ

मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र में दिल्ली का मोस्ट वांटेड डेढ़ लाख का इनामी शिव शक्ति नायडू मंगलवार को पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। फायरिंग में गोली लगने से सीओ दौराला भी घायल हो गए। वह शिव शक्ति वैष्णो धाम कालोनी में रह रहे इंस्पेक्टर और प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के लिए अपने साथियों संग आया था। इसके अलावा दिल्ली के एसीपी ललित मोहन की भी हत्या की तैयारी कर चुका था। मारे गए बदमाश के पास से एक कारबाइन और एक बंदूक बरामद हुई है।

सोमवार को सरधना क्षेत्र में बदमाशों ने फॉरच्यूनर गाड़ी लूटी थी। इसके बाद ये बदमाश कंकरखेड़ा स्थित आरके सिटी कालोनी में एक फौजी के खाली पड़े फ्लैट में रह रहे थे। कंकरखेड़ा पुलिस ने लूटी हुई फॉरच्यूनर फ्लैट के बाहर खड़ी देखी, जिसके बाद सीओ दौराला जितेंद्र कुमार ने टीम के साथ फ्लैट की घेराबंदी की। मंगलवार शाम साढ़े चार बजे बदमाश शिव शक्ति नायडू बिजनौर में तैनात इंस्पेक्टर और प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की साजिश रच रहा था। बदमाश से फॉरच्यूनर, नाइन एमएम की कारबाइन और 12 डीबीएल बंदूक बरामद हुई है। फरार बदमाशों की तलाश में कांबिंग की जा रही है।

-प्रशांत कुमार, एडीजी जोन।

फ्लैट में मौजूद थे। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फ्लैट के अंदर से फायरिंग की। 30 मिनट तक हुई फायरिंग में दिल्ली के मोस्ट वांटेड बदमाश शिव शक्ति नायडू के सीने में गोली लग गई, जबकि उसके साथी रवि उर्फ भूरा एवं अन्य मौके से भाग गए। फायरिंग में एक गोली सीओ की पीठ पर भी लग गई। शक्ति नायडू और सीओ को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान शिव शक्ति नायडू निवासी मदनगीर अंबेडकर नगर साउथ दिल्ली ने दम तोड़ दिया। सीओ की हालत खतरे से बाहर है। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि नायडू पर दिल्ली से पचास हजार और मेरठ से एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।

राम मंदिर के लिए दानदाताओं की लगी कतार

रघुवरशरण, अयोध्या

- मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट का खाता खुलने से पूर्व ही हो चुकी है करोड़ों की राशि देने की घोषणा

राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास भले प्रतीक्षित हो पर प्रस्तावित मंदिर के लिए दान देने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। गत नौ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के साथ ही दानदाता भी सामने आने लगे थे। पटना स्थित महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव पूर्व आइपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने रामलला के हक में फैसला आते ही प्रस्तावित मंदिर के लिए पांच किस्तों में 10 करोड़ रुपये देने का एलान कर दिया था और इसी घोषणा के अनुरूप पहली किस्त के रूप में गत सप्ताह वह दो करोड़ का चेक लेकर पटना से अयोध्या पहुंचे।

हालांकि जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने स्पष्ट किया कि मंदिर निर्माण के लिए गठित श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का खाता खुलने के बाद ही उनका चेक स्वीकार किया जा सकेगा। फैसला आते ही रामलला के मंदिर के लिए दान की घोषणा करने वालों में देश के अतिसमृद्ध धार्मिक केंद्र भी रहे। इन संस्थाओं ने भी मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों रुपये देने का एलान कर रखा है। समझा जाता है कि ट्रस्ट का खाता खुलने के साथ ये संस्थाएं अपनी घोषणा पर अमल करेंगी। वर्ल्ड पीस सेंटर आलंदी महाराष्ट्र के संस्थापक अध्यक्ष एवं दिग्गज समाजसेवी डॉ. विश्वनाथ कराड तो राममंदिर के लिए चार हजार करोड़ रुपये देने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में जहां वह रामनगरी के संपर्क सूत्रों से वार्ता कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री सहित मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। व्यापार अधिकार मंच के संयोजक एवं स्थानीय कारोबारी सुशील जायसवाल भी राममंदिर के लिए पांच लाख का चेक तैयार कर चुके हैं। दंतधावनकुंड पीठाधीश्वर महंत नारायणाचारी ने भी मंदिर निर्माण के लिए एक लाख रुपये दान देने की घोषणा कर रखी है। उनका कहना है कि ट्रस्ट का खाता खुलने दीजिए और शिलान्यास की तारीख मुकर्रर होने दीजिए, तब देखिए मंदिर के लिए एकत्रित होने वाली राशि एक लाख करोड़ से कम नहीं होगी।

दान की घोषणा करने वालों में मुस्लिम भी

मंदिर निर्माण के लिए दान की घोषणा करने वालों में मुस्लिम भी शामिल हैं। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने रामलला के पक्ष में निर्णय आने के कुछ ही दिन बाद 51 हजार रुपये की राशि देने का एलान किया तो लायंस क्लब रुदौली के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन एवं जाने-माने समाजसेवी डॉ. नेहाल रजा ने 11 हजार का चेक तैयार कर रखा है। ट्रस्ट का खाता खुलते ही वह चेक बैंक में जमा कर देंगे।

सिंहासन और गर्भगृह स्वर्ण मंडित कराने का प्रस्ताव

किशोर कुणाल प्रस्तावित मंदिर में रामलला का सिंहासन और गर्भगृह की दीवारों को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। इस संबंध में वह जल्द ही रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों से बात करेंगे। निर्णय आने के बाद से वह रामलला के हजारों दर्शनार्थियों को प्रतिदिन मुफ्त भोजन भी कराते हैं।

विहिप के मॉडल पर बन सकता है मंदिर

प्रथम पृष्ठ से आगे

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर के पक्ष में फैसला देने व मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के आदेश पर 5 फरवरी को केंद्र सरकार ने ट्रस्ट का एलान किया था। इसके साथ ही उप्र सरकार ने मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन भी आवंटित कर दी थी। माना जा रहा है कि 2024-25 तक अयोध्या में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भव्य राममंदिर मूर्त रूप ले लेगा। वैसे, ट्रस्ट को यह आजादी है कि वह मंदिर निर्माण का नया नक्शा तैयार करा सकता है, लेकिन यह माना यह जा रहा है कि मंदिर आंदोलन की अगुआ विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा चंद्रकांत सोमपुरा से तैयार कराए गए मॉडल को ही यथास्थिति में रखा जा सकता है। यह मॉडल भगवान विष्णु के पसंदीदा अष्टकोणीय आकार में होगा। नागर शैली में पूर्णतया पत्थरों से बनने वाले दो मंजिला मंदिर में पांच प्रखंड होंगे।

रवीना, फराह व भारती की गिरफ्तारी की मांग

बीड, प्रेट्र : पिछले साल अभिनेत्री रवीना टंडन, फिल्म निर्देशक फराह खान और हास्य कलाकार भारती सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले आशीष शिंदे ने सभी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने तीनों पर एक टीवी शो के दौरान ईसाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। शिंदे ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सभी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मंगलवार को एक अर्जी सौंपी। शिकायतकर्ता एक स्थानीय एनजीओ के प्रमुख हैं। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने बीड शहर के शिवाजी नगर थाने में तीनों फिल्मी हस्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि टंडन एवं अन्य ने एक क्विज शो बैकबेंचर्स में ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। यह शो क्रिसमस के मौके पर प्रसारित किया गया था। इससे पहले एक पुलिस अधिकारी ने कहा था कि यह मामला मुंबई के मलाड थाने में स्थानांतरित किया गया है। इसी थाने की सीमा में आरोपित रहते हैं। अपनी अर्जी में शिंदे ने कहा है कि मामले में आरोपितों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया है।

उड़ान भरते समय पक्षी टकराने से गोएयर विमान के इंजन में लगी आग

- एयरलाइन ने बताया, विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित
- तीन बच्चों समेत 131 यात्री सवार थे विमान में

मुंबई, प्रेट्र : अहमदाबाद से बेंगलुरु के लिए सोमवार को उड़ान भरने वाले गोएयर विमान के इंजन में पक्षी टकराने से आग लग गई। इसके कारण उसके टेकऑफ को बीच में ही रोकना पड़ा। एयरलाइन ने बताया कि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। विमान को रनवे से हटा दिया गया है। गोएयर के अधिकारियों ने बताया कि जब यह हादसा हुआ तब विमान में चालक दल के अलावा तीन बच्चों समेत 131 यात्री सवार थे।

एयरलाइन के प्रवक्ता की तरफ से जारी बयान के अनुसार, 'अहमदाबाद से बेंगलुरु जा रहे गोएयर की उड़ान संख्या जी8-802 के दाएं इंजन में किसी बाहरी वस्तु (एफओडी) से नुकसान हुआ। इसके कारण उसके इंजन में मामूली आग लग गई।' दरअसल, विमान से पक्षी टकरा गया था। विमान को आगे की जांच के लिए खड़ा कर दिया गया है।

यात्रियों को दूसरे विमान से किया गया रवाना : प्रवक्ता ने बताया कि हादसे के बाद आपातकालीन व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं पड़ी। यात्रियों को बदले हुए समय पर दूसरे विमान से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। करीब साढ़े तीन घंटे के विलंब से उड़ान को दोपहर 1:30 बजे रवाना किया गया।

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान भरते समय इंजन से पक्षी टकराने से आग लगने के बाद गोएयर के विमान को बीच में ही रोकना पड़ा। प्रेट्र

'सायनाइड' मोहन को हत्या के 19वें मामले में उम्रकैद

- गिरफ्तारी के बाद आरोपित ने 20 महिलाओं की हत्या की बात की थी कुबूल

मेंगलुरु, प्रेट्र : कुख्यात सीरियल किलर 'सायनाइड' मोहन को हत्या के 19वें मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2006 का यह मामला केरल के कासरगोड जिला निवासी एक 23 वर्षीय महिला की हत्या से जुड़ा है।

मेंगलुरु (कर्नाटक) के छठे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सइदुनिशा ने सोमवार को मोहन को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जज ने कहा कि सजा की शुरुआत तब होगी जब वह दूसरे मामलों में भी सजा काटना शुरू करेगा। मोहन पर हत्या के कुल 20 मामले दर्ज हैं। वह महिलाओं से दोस्ती करने के बाद उनके साथ दुष्कर्म करता था और सायनाइड खिलाकर उनकी हत्या कर देता था। इससे पहले उसे पांच मामलों में मौत की सजा और तीन मामलों में उम्रकैद हो चुकी है। हालांकि, बाद में दो मामलों में मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी गई थी।

हालिया मुकदमे में दाखिल आरोपपत्र के अनुसार, मोहन महिला से तब मिला था जब वह मेंगलुरु स्थित एक फैक्ट्री में काम करने जा रही थी। महिला से दोस्ती करने और शादी का झांसा देने के बाद वह तीन जनवरी, 2006 को उसे मैसुरु ले गया। वहां वह बस स्टैंड के पास महिला के साथ लॉज में रुका। सुबह उसने महिला से सारे गहने उतरवा लिए। इसके बाद दोनों बस स्टैंड गए। वहां उसने महिला को गर्भनिरोधक बताते हुए एक कैप्सूल दिया और खाने को कहा। महिला बाथरूम में गई और उसे खाते ही गिर पड़ी। लोग उसे पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कैप्सूल के भीतर सायनाइड था। पहले की अन्य वारदातों की तरह मोहन लॉज लौटा और वहां से महिला के सारे गहने समेटकर फरार हो गया। मोहन को वर्ष 2009 में कर्नाटक के बंटवाल से गिरफ्तार किया गया था। तब उसने 20 महिलाओं की हत्या की बात स्वीकार की थी।

कार-बस हादसे के मृतकों में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़े दो प्रत्याशी भी

जागरण संवाददाता, कानपुर

- बस-फार्च्यूनर भिड़ंत में जान गंवाने वाले छह लोगों की शिनाख्त

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बिल्हौर के मकनपुर में सोमवार रात हुई वॉल्वो बस और फार्च्यूनर की भिड़ंत में जान गंवाने वाले छह लोगों की मंगलवार तड़के पहचान हुई। कार सवारों में दिल्ली में पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े सुरजीत सिंह, त्रिलोकपुरी से प्रत्याशी रहे विक्रम के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के जज के ड्राइवर समेत कुल पांच लोग थे। सभी प्रतापगढ़ से एक शादी से लखनऊ होकर लौट रहे थे। मृत बस चालक की पहचान कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के रक्कड़ अलोह चनब्याला गांव के जतींद्र सिंह के रूप में हुई।

सोमवार रात साढ़े 12 बजे कौशांबी (गाजियाबाद) से बिहार रोडवेज की वॉल्वो बस करीब 40 यात्रियों को लेकर लखनऊ जा रही थी। एक्सप्रेस वे पर मकनपुर में बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में सामने से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर को टक्कर मारते हुए सर्विस लेन पर जा गिरी थी। हादसे के बाद देर रात गैस कटर से फॉर्च्यूनर की बॉडी काटकर पांचों शव निकाले गए। पुलिस ने मृतकों के मोबाइल से दिल्ली में घर वालों को सूचना दी।

सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र ने बताया कि कार सवारों में दिल्ली मयूर विहार फेज वन स्थित चिल्ला गांव निवासी सुरजीत सिंह, उनके दोस्त डीडी जनता फ्लैट निवासी विक्रम, पटपड़गंज स्थित आचार्य निकेतन निवासी तीस हजारी कोर्ट के अर्दली और हाई कोर्ट जज के ड्राइवर मुकेश ठाकुर, सुरजीत के ड्राइवर सन्नी खत्री और चिल्ला गांव स्थित डीडी जनता फ्लैट निवासी पान कारोबारी रमाशंकर थे। सुरजीत के मैनेजर सुनील सिंह ने बताया कि 16 फरवरी को उनके बेटे की शादी थी। सभी साथ गांव आए थे। 17 की सुबह शगुन देकर लखनऊ चले गए। वहां उन्हें खेल मंत्री चेतन चौहान से मिलना था। देर शाम सभी दिल्ली लौट रहे थे।

निर्दलीय चुनाव लड़े थे दोनों दोस्त

चचेरे भाई राजेंद्र ने बताया कि सुरजीत और विक्रम ने दिल्ली विधानसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था। दोनों हार गए थे। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद सुरजीत के घर वाले पांचों शव दिल्ली ले गए।

पाइपलाइन में लीकेज, पांच हजार लीटर डीजल बहा

जागरण टीम, फुलवारीशरीफ

- नमामि गंगा योजना के लिए निर्माण एजेंसी एलएंडटी कर रही थी खोदाई

पटना बाईपास के नजदीक सिपारा के 70 फीट इलाके में बरौनी-कानपुर तेल पाइपलाइन में लीकेज से लगभग पांच हजार लीटर डीजल बह गया। मंगलवार सुबह 5 बजे नमामि गंगा योजना के तहत सीवरेज के लिए एलएंडटी कंपनी मशीन से ड्रीलिंग (खोदाई) कर रही थी। इसी बीच जमीन के अंदर दबी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) की बरौनी-कानपुर तेल पाइपलाइन में एक जगह लगभग तीन इंच का लीकेज हो गया। देखते ही देखते लगभग 200 मीटर के इलाके में डीजल ही डीजल फैल गया। घनी आबादी के बीच तेज धार में डीजल बहता देख एलएंडटी कर्मी वहां से फरार हो गए। आसपास के मकानों में सोए हुए लोगों को जब इसकी भनक लगी तो वे भी घर छोड़कर भागने लगे। इस कारण काफी देर तक इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति रही। लोगों की सूचना पर बेउर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आइओसीएल के अफसरों को जैसे ही लीकेज की सूचना मिली, पहले पटना सिपारा स्थित डीपो और फिर बरौनी से तेल की आपूर्ति रोकी गई। हालांकि तब तक हजारों लीटर डीजल बह चुका था। लगभग 15 घंटे की मशक्कत के बाद रात आठ बजे के करीब इंजीनियरों ने पाइपलाइन की मरम्मत कर दोबारा आपूर्ति शुरू की। आइओसीएल के मुख्य महाप्रबंधक केके चौधरी ने बताया कि बुडको को यह कहकर खोदाई की अनुमति दी गई थी कि सीवरेज पाइप डालने के लिए मैनुअल खोदाई होगी और आइओसीएल के इंजीनियर की निगरानी में खोदाई करवाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुडको ने खोदाई का जिम्मा एलएंडटी कंपनी को सौंप दिया। कंपनी ने आइओसीएल की अनुमति की अवहेलना करते हुए बिना सूचना के खोदाई की। मशीन से खोदाई कराई गई जिससे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से काफी नुकसान हुआ है। आइओसीएल नुकसान का कुल अनुमान लगाकर बुडको के खिलाफ शिकायत करेगा। इस बाबत बुडको के एमडी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि इंडियन ऑयल की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने की जिम्मेवारी से बुडको पीछे नहीं हटेगा। क्षतिपूर्ति के दावों पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि निर्माण एजेंसी एलएंडटी के वित्त प्रशासन प्रबंधक मो. मुस्ताक ने आइओसीएल को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि खोदाई की अनुमति के दौरान आइओसीएल के अधिकारी ने पाइप जमीन से दो मीटर नीचे होने की सूचना दी थी। कंपनी की ओर से चार मीटर नीचे मशीन से छेद किया जा रहा था, लेकिन तेल पाइपलाइन दो की जगह चार मीटर नीचे था, जिससे हादसा हुआ। आइओसीएल के इंजीनियर की निगरानी में खोदाई की बात पर उन्होंने कहा कि कंपनी ने पहले ही घनी आबादी होने के कारण रात या फिर अहले सुबह खोदाई का समय मांगा था और आइओसीएल को इंजीनियर भेजने की सूचना दी थी लेकिन अधिकारी टाल-मटोल करते रहे।

दैनिक जागरण

हृदय में आस्था हो तभी हम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं

आर्थिक मोर्चे पर नया संकट

कोरोना वायरस किस तरह मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी संकट बन गया है, इसका ही प्रमाण है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया कि कोरोना वायरस के चलते आयात एवं निर्यात प्रभावित हुआ है। माना जा रहा है कि ऑटो, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, फॉर्मा आदि कहीं अधिक प्रभावित होने वाले सेक्टर हैं। वास्तव में वे सभी उद्योग कठिनाई का सामना करेंगे जो कच्चे माल अथवा उपकरणों के लिए चीन पर निर्भर हैं या फिर जो अपने उत्पाद चीन भेजते हैं। इस मामले में जो स्थिति भारत की है वही दुनिया के अन्य अनेक देशों की भी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि भारत सरकार कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? आवश्यकता केवल इसकी ही नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के असर से बचाने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं, बल्कि यह जरूरी सबक सीखने की भी है कि उद्योग-व्यापार के मामले में किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ठीक नहीं। यदि भारत ने आयात-निर्यात के मामले में चीनी बाजार का कोई विकल्प तलाश रखा होता तो संभवतः आज संकट कहीं अधिक कम होता। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि भारतीय उद्योग जगत अपनी जरूरतों के लिए किसी एक देश पर आश्रित न रहे।

यदि चीन जल्द ही कोरोना वायरस के असर से उबरता नहीं तो खुद उसकी अर्थव्यवस्था तो और गोता लगाएगी ही, विश्व अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। एक ऐसे समय जब विश्व अर्थव्यवस्था पहले से ही सुस्ती का शिकार है तब चीन में फैला कोरोना वायरस किसी मुसीबत से कम नहीं। यह समय की मांग है कि विश्व समुदाय चीन के समक्ष यह स्पष्ट करे कि इस मुसीबत की जड़ में उसकी लापरवाही और उसके तानाशाही भरे तौर-तरीके ही जिम्मेदार हैं। यदि चीन ने कोरोना वायरस को लेकर अपने लोगों और साथ ही विश्व समुदाय को समय पर सही सूचना दी होती तो शायद हालात कुछ और होते। जब चीन का संकट पूरी दुनिया के लिए संकट बन गया है तब कम से कम उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तो चीनी प्रशासन से जवाबदेही लेनी ही चाहिए जो वहां पर काम कर रही हैं। यह ठीक नहीं कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने आर्थिक हितों के लोभ में चीनी शासन के तानाशाही भरे व्यवहार की परवाह नहीं की। बेहतर होगा कि चीनी शासन भी यह समझे कि वह लोकतांत्रिक परिपाटी की अनदेखी कर न तो अपना हित कर सकता है और न ही अन्य किसी का।

यात्रा की चुनौतियां

मौसम की चुनौतियों से जूझ रहे उत्तराखंड में इन दिनों भले ही राहत महसूस की जा रही हो, लेकिन अभी आने वाले दिनों में मौसम फिर परीक्षा ले सकता है। इस बार प्रदेश में रिकार्ड बर्फबारी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार हिमपात का यह क्रम बना रह सकता है। विशेषकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मार्च तक बर्फबारी आश्चर्य में नहीं डालती। जाहिर है चार धाम यात्रा की तैयारियों में जुटे विभागों के लिए यह वक्त किसी चुनौती से कम नहीं है। बदरीनाथ और केदारनाथ में आठ से दस फीट बर्फ जमा है। गंगोत्री और यमुनोत्री का हाल भी अलग नहीं है। स्थिति यह है कि बदरीनाथ हाईवे पर बदरीनाथ के पास और गंगोत्री व यमुनोत्री हाईवे पर करीब चार से पांच फीट बर्फ जमा है। हालांकि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की टीम सड़क से बर्फ हटाने में जुटी है, लेकिन बढ़ते तापमान के बीच हिमखंड टूटने का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा भारी मात्रा में जमा बर्फ को हटाने में भी समय लगेगा। केदारनाथ में हिमपात का आलम यह है कि पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे श्रमिकों को वहां से वापस बुलाना पड़ा। पिछले दिनों प्रशासन ने हालात का जायजा लेने एक टीम केदारनाथ भेजी, मगर बर्फ इतनी ज्यादा थी कि टीम आधे रास्ते से ही लौट आई। धामों के कपाट खुलने की तिथियां घोषित करने का सिलसिला जारी है। बदरीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल और गंगोत्री-यमुनोत्री के कपाट 26 अप्रैल को खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि महाशिवरात्रि के पर्व पर घोषित की जाएगी। जाहिर है प्रशासन के पास करीब दो माह का समय ही तैयारियों के लिए है। मौसम कब तक राहत देगा कहा नहीं जा सकता। केदारनाथ में पैदल मार्ग पूरी तरह से बर्फ से पटा हुआ है। इसके अलावा वहां पुनर्निर्माण कार्यों और फ्रेब्रिकेटेड हट आदि को भी बर्फबारी से भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। हालांकि असल स्थिति का आकलन तो बाद में ही हो पाएगा। पिछले साल की यात्रा के उत्साह को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार भी यात्रा कुछ ऐसी ही रहेगी। तब रिकार्ड संख्या में यात्री चारों धाम पहुंचे। जाहिर है ऐसे में सरकार, शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।

संरक्षणवादी नीति के नुकसान

विवेक कौल

या तो सरकार अधिक संरक्षणवादी बन सकती है या फिर निर्यात को बढ़ावा दे सकती है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते

अवधेश राजपूत

दुनिया की दिग्गज कंपनी एपल और उसके उत्पाद किसी परिचय के मोहताज नहीं। एपल आइफोन सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन माना जाता है। चूंकि एपल अमेरिकी कंपनी है तो अधिकांश लोग आइफोन को भी अमेरिकी उत्पाद ही मानते हैं जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। इस सिलसिले में फिलिप कॉगन अपनी नई किताब 'मोरः द 10,000 ईयर राइज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी' में इस पहलू से पर्दा उठाते हैं। इस किताब के अनुसार आइफोन का डिस्प्ले जापान और दक्षिण कोरिया में, सेंसर्स ताइवान में और कई अन्य कलपुर्जे जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड में बनते हैं। इन पुर्जों को बनाने में कच्चा माल अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से आता है। इन सभी को इकट्ठा कर आइफोन की असेंबलिंग चीन में होती है। इतना कुछ होने के बावजूद आइफोन को व्यापक रूप से अमेरिकी उत्पाद ही माना जाता है।

आप शायद इस बात पर अचंभित हों कि हम एकाएक आइफोन की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए, क्योंकि चीन की चमत्कारिक सफलता की कहानी आइफोन जैसे उत्पादों की असेंबलिंग से ही जुड़ी है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं।

हालिया प्रकाशित आर्थिक समीक्षा में एपल आइपॉड की चर्चा है। आइफोन के माफिक आइपॉड के पुर्जे भी दुनिया के अलग-अलग कोनों से चीन पहुंचते थे। वर्ष 2008 में एक आइपॉड की फैक्ट्री गेट कीमत 144 डॉलर थी, लेकिन इसमें से केवल चार डॉलर ही चीनी वैल्यू एडिशन में शामिल होते। यह इस कीमत का महज तीन प्रतिशत हिस्सा था। हालांकि इससे यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि आइपॉड असेंबलिंग से चीन को कोई फायदा नहीं हो रहा था। अगर कुल आंकड़ों को देखें तो चीन में तकरीबन 5.483 करोड़ आइपॉड असेंबल हुए जिससे उसे 21.9 करोड़ डॉलर का वैल्यू एडिशन मिला।

कमोबेश यही स्थिति आइफोन के मामले में है। एक आइफोन असेंबलिंग में चीन को 8.46 डॉलर ही मिलते हैं जो कुल लागत का केवल 3.6 प्रतिशत है। यह देखने में भले ही कम लगे, लेकिन 2018 में दुनिया भर में बिके कुल 21.8 करोड़ आइफोन की बिक्री से चीन को मिले फायदे का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

बहरहाल आइफोन या आइपॉड तो महज दो मिसाल हैं। वास्तव में चीन ऐसे हजारों उत्पादों की असेंबलिंग का गढ़ बना हुआ है। इनके निर्यात से जहां चीन ने भारी कमाई की तो अपने लाखों-करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित किए। आखिर हम इन पहलुओं की चर्चा क्यों कर रहे हैं? असल में इस सवाल का जवाब वर्ष 2013 की वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट में छिपा है। इस रिपोर्ट के अनुसार दो-तिहाई से अधिक विश्व व्यापार अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उसके आपूर्तिकर्ताओं के बीच होता है। इसे देखते हुए यदि भारत भी इस मोर्चे पर बढ़त बनाना चाहता है तो उसे इस वैश्विक आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। अच्छी बात यही है कि अब सरकार भी इसकी जरूरत समझकर इस दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा भी कि 'भारत को नेटवर्क वाले उत्पादों के विनिर्माण की आवश्यकता है। इससे भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन जाएगा। परिणामस्वरूप अधिक निवेश होगा और फलतः रोजगार के अवसर भी अधिक सृजित होंगे।'

जहां तक भारत की बात है तो कारों का निर्यात उसके लिए एक बड़ी कामयाबी रही है। देश में तैयार की गई कारों का बड़े पैमाने पर निर्यात किया गया और धीरे-धीरे देश वैल्यू चेन के मोर्चे पर आगे बढ़ता गया। यही बात आर्थिक समीक्षा में भी लिखी गई है। इसके अनुसार वर्ष 2001 में जहां भारत से 22.5 करोड़ डॉलर मूल्य की जो कारें निर्यात की गई थीं, वह आंकड़ा वर्ष 2017 में बढ़कर 880 करोड़ डॉलर हो गया। इसी अवधि में कार के कलपुर्जों का निर्यात भी 40.8 करोड़ डॉलर से बढ़कर 550 करोड़ डॉलर हो गया। इससे एक बड़ी सीख यह मिलती है कि घरेलू कंपनियां पहले निम्न प्रौद्योगिकी से शुरुआत करके वैल्यू चेन को आगे बढ़ाती हैं। इसमें कारों की असेंबलिंग से आरंभ करके धीरे-धीरे अन्य घटकों के निर्माण की ओर बढ़ती हैं। सरकार अब यही चाहती है कि ऐसे अन्य उत्पादों का निर्यात बढ़ाया जाए। इसी सिलसिले में सीतारमण ने बजट में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर निर्माण को प्रोत्साहन देने वाली एक योजना का एलान किया। हालांकि अभी इस योजना का खाका तैयार नहीं हुआ, लेकिन यह निश्चित ही अच्छी पहल है।

हालांकि ऐसी कोई योजना दस-पंद्रह साल पहले ही आ जानी चाहिए थी। इस बीच सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जहां भारत अपना निर्यात बढ़ाना चाहता है वहीं संरक्षणवादी नीतियां भी अपना रहा है। पिछली सदी के आखिरी दशक से ही सरकारें सीमा शुल्क घटाती आ रही थीं, लेकिन अब इस नीति में बदलाव आ रहा है। इसी का नतीजा है कि देश दोबारा आयात प्रतिस्थापन की ओर अग्रसर है। बजट में सरकार ने 37 वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाया। इसके अतिरिक्त 10 अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया भी गया है।

वर्ष 1991 से पहले भारत आयात प्रतिस्थापन की नीति पर चलता रहा। तब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की भी यही रणनीति थी, लेकिन उन्होंने यह रुख बदलते हुए निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया जिसका उन्हें लाभ भी मिला। वहीं भारत अपनी इस नीति का लगातार खामियाजा भुगतता रहा और 1991 से पहले की आर्थिक विकास दर इसका जीता-जागता सुबूत थी जो अमूमन चार प्रतिशत से कम रहती थी।

बात सीधी है। जब कंपनियां वैश्विक बाजार के लिए उत्पादन करती हैं तो उनका मुकाबला सर्वश्रेष्ठ कंपनियों से होता है। इसमें जीतकर ही वे वैश्विक बाजारों में सफल हो पाती हैं। यदि भारतीय कंपनियों को वैश्विक वैल्यू चेन का हिस्सा बनना है तो उन्हें विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा क्षमताएं हासिल करनी होंगी। ऐसे में सरकार की सीमा शुल्क बढ़ाने वाली नीति विरोधाभासी होगी, क्योंकि इससे कंपनियां घरेलू बाजार के लिए उत्पादन पर जोर देंगी। तब वे विदेशी कंपनियों के साथ कैसे मुकाबला कर पाएंगी। वैश्विक वैल्यू चेन का हिस्सा बनने की उनकी कवायद भी अधूरी रह जाएगी। ऐसे में या तो सरकार अधिक संरक्षणवादी बन सकती है या फिर निर्यात को बढ़ावा दे सकती है। यह दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। यह समझना बहुत जरूरी है।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

नेहरू-पटेल के रिश्तों में कटुता तो थी

अवधेश कुमार

महान मनुष्यों में भी मानवजनित दोष होते हैं और जवाहरलाल नेहरू इसके अपवाद नहीं थे

पिछले कुछ समय से सरदार वल्लभभाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के संबंध लगातार बहस और विवाद का विषय बने हुए हैं। विवाद का एक बड़ा पहलू यह भी है कि नेहरू के अंदर पटेल को लेकर असम्मान और द्वेष का भाव था। इस समय नारायणी बसु द्वारा लिखी किताब वीपी मेनन को लेकर विवाद है। इसमें बताया गया है कि नेहरूजी की पहली मंत्रिपरिषद की सूची में पटेल का नाम नहीं था। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इसका उल्लेख करने के साथ ही नेहरूजी के समर्थक टूट पड़े और कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करने में जुट गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 14 अगस्त 1947 का एक पत्र ट्वीट करते हुए कहा कि पटेल नेहरू के बाद कैबिनेट में नंबर दो थे। दरअसल हम किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बना लेते हैं कि वह इतना महान है या था कि उसमें कोई दोष हो ही नहीं सकता। महान मनुष्यों में भी मानवजनित दोष होते हैं और नेहरूजी अपवाद नहीं थे। पटेल से उनके गहरे मतभेद के इतने तथ्य हैं कि उन पर मोटी-मोटी पुस्तकें लिखी जा सकतीं हैं। जयराम रमेश ने जो प्रमाण दिए वे भी सच हैं, किंतु वे बाद के हैं। नेहरू को मंत्रिमंडल का गठन करने और उसके सदस्यों की सूची भेजने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी प्रथम सूची में सरदार पटेल को स्थान नहीं दिया था। उनके हाथों से लिखी यह सूची उपलब्ध है। बात गांधी जी तक पहुंची और फिर पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यह ध्यान रहे कि गांधी जी का सम्मान करते हुए सरदार पटेल ने 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था, जबकि 15 प्रांतों की कांग्रेस समितियों में से 12 ने उनके नाम का अनुमोदन कर दिया था। वह आसानी से प्रधानमंत्री बन सकते थे। अनेक नेताओं ने पटेल के अपना दावा छोड़ने के रवैये पर असंतोष प्रकट किया था। मध्य प्रांत के तत्कालीन गृहमंत्री डीपी मिश्र ने पटेल को पत्र लिखकर कहा, 'आपके कारण ही कांग्रेसी नेताओं ने चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लिया।'

पटेल ने 16 जनवरी 1948 को गांधीजी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उन्हें पद से मुक्त कर दिया जाए। इससे पूर्व 6 जनवरी 1948 को नेहरू ने गांधीजी को लिखे पत्र में कहा कि या तो पटेल को अपना पद छोड़ना होगा, नहीं तो मैं स्वयं त्यागपत्र दे दूंगा। नेहरू द्वारा उठाए गए मामलों पर पटेल ने गांधी जी को फिर पत्र लिखकर कहा कि नेहरू की नीतियों को स्वीकार कर लिया जाए तो देश में प्रधानमंत्री की भूमिका एक तानाशाह की हो जाएगी। गांधी जी की हत्या के बाद की स्थितियों में दोनों ने मतभेद दूर कर काम करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1948 को नेहरू ने सरदार पटेल को लिखा कि बापू के निधन के बाद अब सब कुछ बदल गया है। पुराने मतभेदों का अब कोई महत्व नहीं रहा और मुझे लगता है कि हमें एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। पटेल ने इसका उत्तर दिया, हमें आपसी बातचीत के लिए समय निकालना होगा ताकि हम मतभेदों को दूर कर सकें। क्या इसके बाद भी कुछ कहने की आवश्यकता है?

वीपी मेनन वाली पुस्तक में ही मेनन के हवाले से लिखा गया है कि जब सरदार का निधन हुआ तो उनकी स्मृतियों को मिटाने का बड़ा अभियान शुरू हुआ। सरदार पटेल सोसाइटी के संस्थापक एस निजलिंगप्पा ने अपनी जीवनी 'माइ लाइफ एंड पॉलिटिक्स' में लिखा है कि मैं बार-बार अनुरोध करता रहा कि इस सोसायटी को उचित स्तर की इमारत दी जाए, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। नेहरूजी के इर्द-गिर्द कुछ ऐसे नेता इकट्ठे थे जो पटेल के खिलाफ उनके कान भरते थे और गांधी जी तक शिकायतें पहुंचाई जातीं थी। गांधी जी को पटेल के खिलाफ इतनी शिकायतें मिलीं कि कुछ समय के लिए वह भी प्रभावित हो गए। उन्होंने पटेल को लिखा, मुझे तुम्हारे खिलाफ कई शिकायतें सुनने को मिली हैं। लोग तो कह रहे हैं कि तुम किसी भी स्थिति में पद पर बने रहना चाहते हो। पटेल ने 7 जनवरी 1947 को गांधीजी को लिखे जवाब में कहा कि नेहरू ने उन्हें पद छोड़ने के लिए दबाव डालते हुए धमकी दी थी जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इससे कांग्रेस की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। आरोपों के संदर्भ में पटेल ने गांधीजी को बताया कि ये अफवाहें मृदुला द्वारा ही फैलाई गई होंगी जिन्होंने मुझे बदनाम करने को अपना शौक बना लिया है।

पटेल की मृत्यु के प्रसंग की चर्चा से उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा जो यह मानने को तैयार नहीं कि नेहरूजी के अंदर उनको लेकर गहरी वितृष्णा थी। 15 दिसंबर 1950 को सरदार की मृत्यु हुई। मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम वाल्यूम-2 के पृष्ठ संख्या 289-290 पर लिखा है कि नेहरू ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दाह संस्कार में न जाएं। एनवी गाडगिल, सत्यनारायण सिन्हा और वीपी मेनन ने निर्देशों पर ध्यान न देते हुए अंतिम संस्कार में भाग लिया। वरिष्ठ पत्रकार दुर्गा दास ने, जिनके नेहरू, पटेल और आजाद से संबंध थे, अपनी पुस्तक इंडिया फ्राम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के पृष्ठ 305 पर लिखा है कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह को अपने लिए बाध्यकारी नहीं माना।

यह सच है कि स्वयं नेहरू पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, पर उन्होंने अन्य लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसमें वह विफल रहे। वास्तव में इस देश में इतिहास के ऐसे तथ्यों को दबाकर रखा गया है जिससे नेहरूजी को महापुरुष मानने पर किसी तरह का प्रश्न खड़ा किया गया हो, किंतु सच यही है कि नेहरू पटेल को अच्छी नजर से नहीं देखते थे, अन्यथा अंतिम संस्कार में जाने से लोगों को रोकना और उनकी स्मृति में कुछ भी बड़ा न करने का कोई कारण नहीं हो सकता।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आह्लाद ही शिवत्व

भगवान शंकर की महिमा का वर्णन करते हुए शिव-महिम्न स्त्रोत में उल्लेख है कि यदि काले पर्वत को स्याही, समुद्र को दवात, कल्पवृक्ष को लेखनी, पृथ्वी को कागज बनाकर स्वयं सरस्वती भोलेनाथ की महिमा लिखें तो भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। इस श्लोक के निहितार्थ यह हैं यदि शिवजी का उपासक अपने जीवन की कठिनाइयों के पर्वत जैसे हालातों को आत्मविश्वास एवं नेक इरादों की दवात में घोलकर दृढ़ इच्छाशक्ति की लेखनी से अपने जीवनपथ के कागज पर बुद्धि में निवास करने वाली ज्ञानशक्ति (सरस्वती) से लिखे तो उसके जीवन पथ पर आनंद प्रदाता शिवजी दिखाई पड़ने लगेंगे। उसकी समस्याएं धीरे-धीरे दूर हो जाएंगी।

शिव की उपासना से यह प्रेरणा मिलती है कि भिन्न-भिन्न प्रकृति और अभिरुचि के लोगों को एक साथ करना ही सार्थक जीवन पद्धति है। लोगों में एकता स्थापित करने से बड़ा काम दूसरा नहीं है। शिवजी के सिर में जल रूप में गंगा और ऊर्जा के रूप में चंद्रमा, गले मे सर्प और पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर, मां पार्वती का वाहन शेर और खुद उनका वाहन नंदी (बैल) आपस में एक दूसरे के बैरी होने के बावजूद एक साथ एक परिवार में रहते हैं। इससे एक संदेश यह भी जाता है कि जीवन की प्रतिकूलताओं के जहर को पीने के बाद भी प्रसन्नता मिलती है। अर्थात विपरीत परिस्थितियों से विचलित होने के बजाय उसके साथ तालमेल बनाने की क्षमता प्राप्त होती है शिव जी की सच्ची पूजा से।

इसके अलावा शिवजी के अर्धनारीश्वर स्वरूप पर दृष्टि डालने से जहां दाहिना हिस्सा शिवजी के रूप में कर्मपक्ष का परिचय देता है वहीं वाम भाग भाव पक्ष का स्वरूप है। यह बताता है कि दोनों पक्ष के संयोग से कोई कार्य किया जाएगा तो सफलता जल्द मिलेगी। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।

सलिल पांडेय

भोजन की बर्बादी पर लगे अंकुश

सुधीर कुमार

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पूरी दुनिया में सलाना करीब 1.3 बिलियन टन खाद्य सामग्री बर्बाद हो जाती है

भोजन की बर्बादी की प्रवृत्ति सामाजिक कुसंस्कृति का रूप ले रही है। शादियों, उत्सवों तथा त्योहारों में आवश्यकता से अधिक भोजन लेना और उसे आधा-अधूरा खाकर छोड़ना फैशन बन चुका है। भोजन की बर्बादी नैतिक अपराध है। इस बात को हम कब समझेंगे? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक पूरी दुनिया में सलाना करीब 1.3 बिलियन टन खाद्य सामग्री बर्बाद हो जाती है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में करीब 50 हजार करोड़ की कीमत का अन्न हर साल बर्बाद होता है। इतना अन्न बिहार जैसे राज्य की कुल आबादी को एक साल तक भोजन उपलब्ध करवा सकता है। 2017 की सीएसआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इंग्लैंड में भोजन की जितनी खपत होती है, उतना हम बर्बाद कर देते हैं। भारत में हर साल प्रति व्यक्ति 51 किलोग्राम खाने की बर्बादी करता है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है, लेकिन वैश्विक भूख सूचकांक-2019 में भारत दुनिया के सबसे ज्यादा भूख पीड़ित देशों की सूची में 102वें स्थान पर रहा। देश में भोजन की बर्बादी रोकने के संबंध में कोई कानून नहीं है और न ही इसे रोकने के प्रति नागरिकों में पर्याप्त सजगता का भाव ही निहित है। क्या भोजन की बर्बादी पर बिना अंकुश लगाए तथा कुपोषण और भुखमरी जैसी बुनियादी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से निपटे बिना भारत विकसित व ताकतवर देशों की श्रेणी में शामिल हो पाएगा?

भोजन का जो अंश हम अपनी थाली में जूठन के रूप में छोड़ देते हैं, उसके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा किए गए शोध के मुताबिक खाने की बर्बादी की वजह से ग्रीन हाउस गैसों में आठ फीसद का इजाफा होता है। इसकी वजह से एक तरफ जहां ग्लोबल वॉर्मिंग की समस्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ यह अनाजोत्पादन को भी प्रभावित कर रहा है। भोजन की बर्बादी को रोके बिना खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करना भी मुमकिन नहीं होगा।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण खाना बर्बाद करने वाले होटलों और शादीघरों पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है। इस बीच अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की एक पहल ने सबका ध्यान खींचा है। वहां के होटलों में भोजन न छोड़ने वाले ग्राहक को बिल पर पांच फीसद की छूट दी जा रही है। उधर तेलंगना के एक होटल में थाली में जूठा छोड़ने वालों से 50 रुपये जुर्माना लगाने की शुरुआत हुई है। भोजन की बर्बादी पर अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे इस तरह के प्रयोग एवं प्रयास सराहनीय हैं। हालांकि नागरिकों में सामाजिक चेतना जागृत करके ही इस समस्या से पिंड छुड़ाया जा सकता है।

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

मेलबाक्स

सुविधा को मुफ्तखोरी की संज्ञा क्यों?

दिल्ली मॉडल की चुनौतियां शीर्षक से लिखे अपने लेख में विकास सारस्वत ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के सामने राजस्व के मोर्चे पर आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया है। इसमें लेखक ने केजरीवाल सरकार द्वारा आमजन को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं के दुष्प्रभाव तो गिना दिए, लेकिन जो राज्य अपने नागरिकों को ऐसी सुविधाएं नहीं देते वे आखिर क्यों अपने सरकारी खजाने के खाली होने का रोना रोते हैं? क्यों कर्ज लेते हैं? अन्य सरकारें आमजन से विभिन्न रूपों में जो टैक्स वसूलती हैं, क्या वे मात्र मंत्रियों या सरकार बाबुओं को मोटी सैलरी देने के लिए ही हैं, आमजन को मूलभुत सुविधाएं देने के लिए नहीं? पंजाब के जालंधर में मेयर ने पार्षदों के वेतन लगभग पचास हजार रुपये करने का फैसला लिया है। बेशक अभी सरकार ने इसे शायद मंजूरी नहीं दी है, लेकिन जब जालंधर की आम जनता नगर निगम से मूलभूत सुविधाएं की मांग करती है, तब वह अपना खजाना खाली होने का रोना रोता है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें अपने राजस्व का उचित प्रयोग करें तो देश के हर राज्य के आमजन को दिल्ली की तरह मूलभूत सुविधाएं दी जा सकती हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

ऐतिहासिक फैसला

यह पत्र 'महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने का सुप्रीम आदेश' के संदर्भ में है। यह एक अत्यंत ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले से पुरुष और महिला अधिकारियों के बीच की खाई पाटने में मदद मिलेगी। निःसंदेह आज न केवल सरकार को, बल्कि पूरे समाज को अपनी विचारधारा बदलने की जरूरत है। महिला अधिकारियों को स्थायी कमिशन का विकल्प मिलना चाहिए। साथ ही पेंशन जैसी सुविधाएं जिनसे अभी वे वंचित हैं उसका अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। वह समय गया जब महिलाएं कमजोर होती थीं, आज वह कई क्षेत्रों में पुरुषों को भी पीछे छोड़ चुकी हैं। कैप्टन तान्या शेरगिल हाल ही में पहली महिला अधिकारी बनी हैं, जिन्होंने सेना की परेड की कमान संभाली। इसलिए हमें खुले दिल से महिलाओं को समाज हर क्षेत्र मे आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए।

बाल गोविंद, नोएडा

प्रदर्शन नहीं जगह से परेशानी

'राह रोकने वाला धरना' संपादकीय पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना या विरोध करना वाजिब है, लेकिन जिस प्रदर्शन या विरोध से आम जन को परेशान होती है तो वह प्रदर्शन ठीक नहीं है। विरोध करने से पहले लोगों को यह चयन करना होगा कि उनके ऐसा करने से किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी। यही सही तरीका भी है। जब सत्ताधारियों के समर्थक इस प्रकार के प्रदर्शन करते हैं तो सत्ता नरम रुख अपना लेती है। यह न्याय सिद्धांत को प्रभावित करने वाला होता है। चाहे अपने हो या परए, आम हो या खास अगर वह विरोध करने का गलत तरीका अपना रहा है तो उसके साथ भी सख्ती होनी चाहिए। शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाले विरोधियों को ऐसी जगह बैठ कर विरोध करना चाहिए जहां किसी को कोई परेशानी न हो। यही अदालत की मूल भावना है, जिसे समझना होगा।

hemahariupadhyay@gmail.com

दिल्ली को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा

विकास सारस्वत द्वारा लिखित लेख 'दिल्ली मॉडल की चुनौतियां' में उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार के दिल्ली मॉडल को आगे तक बरकरार रखने को लेकर चुनौतियां पेश की हैं। उन्होंने अपने लेख में बढ़ते राजकोषीय घाटे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिती में केजरीवाल सरकार क्या करेगी जब राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा है? वह अपने दिल्ली मॉडल को कैसे आगे बढ़ाएगी? यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल पाना है। केंद्र सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे कर जनता का पूरा सहयोग करे ताकि दिल्ली मॉडल की चुनौतियों को कम किया जा सके।

पवन कुमार मुरली, गुरुग्राम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1.5 करोड़ लोग ही आयकर देते हैं देश के 130 करोड़ लोगों में से। इसके अलावा देश के केवल तीन लाख लोगों ने ही अपनी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक घोषित की है।

जाहिद खान
स्वतंत्र पत्रकार

आजकल

लैंगिक समानता की दिशा में अहम कदम

पुरुषों की तरह महिलाएं भी सेना के हर क्षेत्र में काम कर सकती हैं, बस जरूरत उन्हें और अधिक मौका देने की है। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का शीर्ष अदालत का फैसला लैंगिक समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। अदालत ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देकर सेना में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया है। इससे आधी-आबादी को उन क्षेत्रों में भी आगे आने की प्रेरणा मिलेगी, जिनमें पुरुषों का विशेषाधिकार माना जाता है

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अधिकारों और समानता को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उसने कहा है कि अगर कोई महिला अफसर स्थायी कमीशन चाहती है तो उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। भले ही उनकी नौकरी 14 साल से अधिक हो गई हो। उन सभी महिला अफसरों को तीन महीने के अंदर सेना में स्थायी कमीशन दिया जाए जो यह विकल्प चुनना चाहती हैं। महिलाओं को शारीरिक आधार पर स्थायी कमिशन न देना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। अदालत ने इसके लिए मार्च, 2019 के बाद सेना से जुड़ने की सरकारी शर्त भी हटा दी है। अदालत ने स्थायी कमिशन देने के हाईकोर्ट के आदेश पर एक दशक तक अमल न करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू नहीं किया। अदालत ने केंद्र सरकार की इन दलीलों कि सेना में ज्यादातर जवान ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और महिला अधिकारियों से फौजी हुक्म लेना उनके लिए सहज नहीं होगा तथा महिलाओं की शारीरिक स्थिति और पारिवारिक दायित्व जैसी बहुत सी बातें उन्हें कमांडिंग अफसर बनाने में बाधक हैं को खारिज करते हुए कहा कि सरकार अपने दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव लाए। उसकी यह सोच, अतार्किक और समानता के अधिकार के खिलाफ है। महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने से इन्कार पूर्वाग्रह का उदाहरण है। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। महिला अधिकारी पराक्रम में कहीं से भी कम नहीं हैं।

अदालत ने अपने इस अहम फैसले में बाकायदा देश की उन 11 महिला सैन्य अधिकारियों जिसमें कैप्टन तानिया शेरगिल, ले. कर्नल सोफिया कुरैशी और मेजर मधुमिता शामिल हैं, की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां गिनाई हैं, जिन्होंने अपने बहादुरी भरे कारनामों से देश का सम्मान बढ़ाया है और उन्हें सेना पदक समेत कई वीरता पदक मिल चुके हैं। लिहाजा सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं के योगदान को शारीरिक संरचना के आधार पर कमतर आंकना गलत है। महिला होने के आधार पर उनकी क्षमता पर सवाल उठाना न सिर्फ उनकी महिला होने की गरिमा का निरादर है, बल्कि भारतीय सेना के सदस्य का भी निरादर है। अदालत के इस फैसले से सेना में महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। थलसेना में उन्हें स्थायी कमीशन और कमांड पोस्टिंग दिए जाने का रास्ता खुलेगा। फैसले से सेना में सेवारत 1,653 महिला सैन्य अधिकारियों को फायदा होगा।

सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के तहत 14 साल की सेवा दे चुके पुरुष सैनिकों को ही स्थायी कमीशन का विकल्प मिलता रहा है। महिला सैनिकों को इसके लिए हकदार नहीं माना जाता था, जबकि वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन मिलता रहा है। अपने साथ हो रही इस नाइंसाफी को महिलाओं ने अदालत में चुनौती दी। जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2010 में उनके हक में फैसला दिया। सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी थी। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। हाईकोर्ट के फैसले के नौ साल बाद फरवरी 2019 में सरकार ने सेना के 10 विभागों में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने की नीति बनाई, लेकिन साथ में यह शर्त भी जोड़ दी कि इसका फायदा मार्च 2019 के बाद से सर्विस में आने वाली महिला अफसरों को ही मिलेगा। इस तरह वे महिलाएं स्थायी कमीशन पाने से वंचित रह गईं, जिन्होंने इस मसले पर लंबे अरसे तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी। मामला फिर अदालत में पहुंचा और अब सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने की इजाजत दे दी है।

सेना में महिलाओं की भर्ती की प्रक्रिया साल 1993 में शुरू हुई थी। साल 2008 में सेना की दो ब्रांच में उन्हें स्थायी कमीशन दिया गया। जिसमें जज एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कोर शामिल हैं। शीर्ष अदालत के हालिया फैसले के बाद अब महिला अधिकारियों को 10 ब्रांच में स्थायी कमीशन मिलेगा। जिनमें आर्मी एविएशन कोर, सिग्नल, इंजीनियरिंग, आर्मी एयर डिफेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस और इंटेलीजेंस शामिल हैं। महिलाएं अब सेना में पूर्णकालिक रूप से कर्नल या उससे ऊपर रैंक पर पदस्थ हो सकती हैं। एक महिला कर्नल अब 850 पुरुषों की एक बटालियन की कमान संभाल सकती है। महिलाएं योग्यता के आधार पर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और सैद्धांतिक रूप से सेना प्रमुख के पद तक बढ़ सकती हैं। अलबत्ता महिलाओं को कॉम्बेट रोल यानी युद्धक भूमिका देने का फैसला अदालत ने सरकार और सेना पर छोड़ दिया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि युद्धक भूमिका में महिलाओं की तैनाती नीतिगत विषय है। इस पर संबंधित अधिकारियों को निर्णय लेना चाहिए।

महिला अधिकारियों को कॉम्बेट रोल न देने के पीछे अक्सर यह दलील दी जाती है कि शारीरिक तौर पर वे पुरुषों के मुकाबले कमतर हैं। वे असाधारण स्थितियों को सामना नहीं कर सकतीं। महिलाएं 20 दिन पेट्रोलिंग ड्यूटी पर नहीं जा सकतीं, सियाचिन जैसी जगहों में वे ड्यूटी नहीं कर सकतीं। महिलाओं को पुरुष जवानों के साथ रहने में परेशानी होगी। यह दलील भी दी जाती है कि अगर महिला अफसर को युद्धबंदी बना लिया गया तो फिर क्या होगा? जाहिर है कि ये सारी दलीलें ऐसी हैं, जिनमें कोई दम नहीं। सच बात तो यह है कि लैंगिक भेदभाव की ही वजह से महिलाएं पुरुषों से पीछे रही हैं। वरना उनकी काबिलियत में कहीं कोई कमी नहीं। सेना में कॉम्बेट भूमिका भी वे बेहतर तरीके से निभा सकती हैं। सेना में कई बार ऐसे मौके आए हैं, जब महिलाओं ने अपनी काबिलियत बेहतर तरीके से दिखलाई है। वायुसेना में जब उन्हें कॉम्बेट भूमिका मिली, फाइटर विमान उड़ाने का मौका मिला तो उन्होंने यहां भी अपने आप को साबित कर दिखाया। पुरुषों की तरह महिलाएं भी सेना के हर क्षेत्र में काम कर सकती हैं, बस जरूरत उन्हें मौका देने की है। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का शीर्ष अदालत का फैसला लैंगिक समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। अदालत ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देकर सेना में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया है। इससे लड़कियों को उन क्षेत्रों में भी आगे आने की प्रेरणा मिलेगी, जिनमें पुरुषों का विशेषाधिकार माना जाता है।

लड़ाकू भूमिका में कब आएंगी महिलाएं

मनीषा सिंह

महिलाओं को सेना में अब लड़ाकू की भूमिका भी दी जानी चाहिए। कहा जाता रहा है कि कुछ ऐसी बाधाएं हैं, जिनके रहते सेना में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका नहीं दी जा सकती है, लेकिन यहां कुछ सवाल उठते हैं। क्या सेना में पुरुष जवानों का काम आसान होता है। उन्हें बेहद कम संसाधनों वाले इलाकों में तैनात किया जाता है, हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और इसका अहसास उन्हें सेना में भर्ती होने से पूर्व ही होता है। गर्मी में तपते रेगिस्तान से लेकर हड्डियां जमा देने वाले सियाचिन जैसे इलाकों में तैनात होने वाले ये पुरुष जवान अपने किसी कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे में यह भला क्यों मान लिया जाता है कि महिलाएं ऐसे दुर्गम इलाकों में तैनाती नहीं चाहेंगी, वे हमेशा पीस-पोस्टिंग की ही मांग करेंगी। यह असल में एक किस्म का मानसिक भेदभाव है जिसमें महिलाओं को कोई चुनौती देने और उसमें अपना पराक्रम साबित करने से पहले ही पुरुषों के मुकाबले कमजोर और कमतर ठहराने की कोशिश की जाती है और फिर उनके बारे में एक अलग राय बना ली जाती है। ऐसी ही धारणाओं पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया है कि आखिर मौका देने से पहले से महिलाओं को किसी चुनौती की कसौटी पर खरा उतरने का विकल्प क्यों छीना जा रहा है?

गौरतलब है कि महिलाएं अभी सेना में हैं, पर लड़ाकू भूमिका में नहीं। हालांकि यह सच है कि हर साल सशस्त्र सुरक्षाबलों की तीनों शाखाओं में करीब 3300 महिलाओं की भर्ती होती है, लेकिन वे चिकित्सा, लीगल, शिक्षा, सिग्नल और इंजीनियरिंग शाखाओं में काम करती हैं, सीधे दुश्मन से नहीं भिड़ती हैं। उल्लेखनीय है कि लड़ाकू जवान के रूप में एक सैनिक की भूमिका छावनी क्षेत्र और सैन्य प्रतिष्ठानों में पुलिसिंग की होती है। सैनिकों को नियम कायदों को तोड़ने से रोकना, सैन्य मूवमेंट, युद्ध बंदियों को संभालना और जरूरत पड़ने पर सिविल पुलिस की मदद का काम भी सेना के जवानों को करना होता है। हालांकि इससे इतर भूमिकाएं महिलाओं को हमारे देश में दी जा चुकी हैं। जैसे वर्ष 2016 में इंडियन एयरफोर्स ने तीन महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में शामिल किया था। ये तीन महिलाएं:- अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह फाइटर पायलट के रूप में काम कर रही हैं। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) में भी महिला अफसरों की नियुक्ति की पहलकदमी की जा चुकी है। अभी भी महिलाओं को सीआरपीएफ और सीआइएसएफ में अफसर की वर्दी पहनने का मौका मिलता है, लेकिन वहां भी वे मोर्चे पर दुश्मन फौज का सीधा मुकाबला नहीं करतीं, क्योंकि इन दोनों सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा की होती है।

जहां तक लड़ाकू सैनिक के रोल की बात है तो फिलहाल जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन और इजरायल में ही महिलाएं इस भूमिका में काम कर रही हैं। अब समय आ गया है जब भारत भी अपने महिला सैनिकों को लड़ाकू भूमिका दे।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

खरी-खरी

चिंतक नियरे राखिए!

नंदकिशोर बर्वे

मेरा फलसफा तो यही कहता है कि जो हमेशा चिंतित रहते हैं, वे चिंतक होते हैं। चिंता से उपजा चिंतन ही सार्थक होता है। कहने का मतलब यह है कि चिंता ही वह उर्वरा भूमि है, जिस पर चिंतन की फसल लहलहा सकती है। चिंतन की मात्रा चिंता के सीधे-सीधे अनुपात में होती है। यानी जिसकी चिंता जितनी बड़ी, वह उतना ही बड़ा चिंतक।

हमारे पड़ोस में भी ऐसे ही एक चिंतक रहते हैं। वे जन्मजात चिंतक हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि अभावों में लालन-पालन ने उनको होश संभालते ही रोजी-रोटी चिंता से रूबरू करा दिया था। यह चिंता हमेशा उनके समक्ष मुंह बाए ही रहती थी और इसका असर यह हुआ कि वे दूध के दांत टूटते-टूटते एक चिंतक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब जबकि वे चिंतक के रूप में खड़े हो गए हैं तो आगे भी बढ़ेंगे। सो वे सदैव अपने उत्थान की चिंता में लगे रहते हैं। चिंता से आक्रोश उत्पन्न होता है और आक्रोश से क्रोध का जन्म होता है। किसी विषय पर यही क्रोध जब धाराप्रवाह मुखारविंद से भाषणों के रूप में प्रवाहित होता है, तब व्यक्ति घोषित रूप से चिंतक हो जाता है।

सो वे घोषित चिंतक हो गए। अब चिंतन है तो वाद भी होगा और विवाद भी। सो वे वाद के अनुयायी हैं। क्या कहा, कौन से वाद के? अरे भई कोई भी वाद हो, क्या फर्क पड़ता है? सभी वादों का अंतिम उद्देश्य एक ही होता है, किसी भी तरह खुद को सही सिद्ध करना। जो ओहदेदार होते हैं, वे प्रायः चिंतकों पर निर्भर रहते हैं। जो जितना बड़ा ओहदेदार, उसके चिंतक उतने बड़े। बिना चिंतकों के भी कोई ओहदेदार होता सकता है भला! बिना दूल्हे के भी कोई बारात होती है कभी!

बाबा कबीर के जमाने में निंदक नियरे रखने का चलन था। इसलिए विद्वान समाज सुधारक ने निंदक को नियर रखने का दर्शन दिया, लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज के दौर में निंदक अपरिहार्य नहीं रहा। अब वह त्याज्य भी है और मर्दन योग्य भी। इसलिए यह युग निंदकों के लिए नहीं, चिंतकों के लिए मुफीद है। चिंतक अपने स्वामी के प्रति वफादार रहते हैं। सो उन्हें ही नियर रखने की परंपरा हो गई है। अब चिंतक नियर भी है और डियर भी। वह स्टेटस सिंबल है। भले ही वह रसातल की दिशा में क्यों न सोचता हो।

ट्वीट-ट्वीट

-26/11 कसाब फर्जी हिंदू पहचान और हाथ में कलावा के साथ पकड़ा गया।
-17/12 अंतुले ने संसद में संकेत किया कि मुंबई हमले के पीछे हिंदू हो सकते हैं।
-20/07/09 राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत से कहा, इस्लामिक आतंक से बड़ा खतरा है हिंदू आतंक।
-28/12/2010 दिग्विजय सिंह ने '26/11: आरएसएस की साजिश' नामक किताब रिलीज की।

विक्रांत@vikrantkumar

जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह भाजपा के तमाम बैनरों-पोस्टरों से गायब हो गए हैं। क्या कांग्रेस में आप राहुल गांधी के बिना ऐसा कोई बैनर-पोस्टर देख सकते हैं जबकि राहुल गांधी फिलहाल किसी पद पर भी नहीं हैं। एक वंशवादी पार्टी और जमीन से जुड़े दल में यही फर्क है।

संदीप घोष@SandipGhose

इमरान खान की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे सूची में बना हुआ है। पाकिस्तान को एक बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि जब कारगर कदम नहीं उठाए जाएं तो कोई तिकड़म काम नहीं आती। इमरान खान को भी समझना होगा कि आतंक को पालने-पोसने से भला नहीं होने वाला।

इम्तियाज हुसैन@hussain_imtiyaz

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आम आदमी पार्टी के उभार से अन्य भाजपा विरोधी दलों के लिए चुनौती बढ़ गई है?

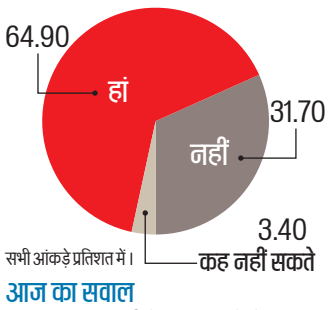

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या बाबूलाल मरांडी के वापस आने से झारखंड में भाजपा मजबूत होगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

राहत कैसे मिल सके जब काले हैं कर्म,
आप निभाते जाइए बस आतंकी धर्म।
बस आतंकी धर्म लिस्ट 'ग्रे' में ही रहिए,
यही एक स्थान आप जैसों को चहिए।
तेरे कारण रोज पड़ोसी होता आहत,
फिर कैसे इमरान मिलेगी तुझको राहत!

- ओमप्रकाश तिवारी

ओमप्रकाश तिवारी
ब्यूरो प्रमुख, मुंबई

महाराष्ट्र डायरी

शरद पवार की खीझ!

शरद पवार को यलगार परिषद मामले की जांच राज्य पुलिस के हाथ से निकलकर एनआइए के हाथ में जाने का बड़ा अफसोस होता दिख रहा है। इसके लिए वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी कोस रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हैं कि छाछ भी फूंक-फूंककर पी रहे हैं। वह ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते कि भविष्य में कांग्रेस-राकांपा से बात बिगड़ने पर उन्हें पछताना पड़े। दरअसल शरद पवार 31 दिसंबर, 2017 की शाम को पुणे में हुए 'यलगार परिषद' मामले को भी 'मालेगांव' बनाने की राह पर चल चुके थे। उस मामले को हिंदू आतंकवाद का रंग भी महाराष्ट्र पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अलीबाग में हुई उस बैठक के बाद ही दिया था, जिसे संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा था कि आतंक के हर मामले में एक वर्ग को ही निशाना बनाया जाना उचित नहीं है। उसके बाद ही एटीएस ने 'दूसरे वर्ग' को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया। यह बात और है कि एनआइए द्वारा मालेगांव कांड की जांच करने के बाद एटीएस की जांच में आरोपी बनाए गए सभी लोगों को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन तब तक कई लोग कई वर्ष की जेल काट चुके थे।

यलगार परिषद मामले में आरोपी बनाए गए सभी 17 लोग वाम रुझान के कार्यकर्ता हैं। 31 दिसंबर, 2017 की शाम पुणे में पेशवाओं का निवास रहे शनिवारवाड़ा के बाहर इस परिषद का आयोजन सीपीआइ (एम) की मदद से हुआ था। पुलिस का आरोप है कि इस परिषद में दिए गए भड़काऊ भाषणों के फलस्वरूप ही अगले दिन एक जनवरी, 2018 को भीमा-कोरेगांव में हिंसा शुरू हुई। इस हिंसा में एक व्यक्ति की जान गई और लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के फलस्वरूप शुरू हुई जांच

के तार सीपीआइ (एम) एवं इससे जुड़े कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। इनमें वाम रुझान वाले सुधीर धवले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, सोमा सेन, अरुण परेरा, वरनन गोंजाल्विस, सुधा भारद्वाज एवं वरवर राव जैसे नाम शामिल हैं।

पुलिस का कहना है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या जैसी किसी बड़ी घटना की साजिश रच रहे थे। इसी कड़ी में दो नाम आनंद तेलतुंबड़े एवं गौतम नौलखा के भी हैं, जिनकी अग्रिम जमानत की अर्जी मुंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। वाम रुझान वाले इन्हीं कार्यकर्ताओं की पहचान देश में अर्बन नक्सल के रूप में होती है। माना जाता है कि यही वर्ग गहन वनों में रहनेवाले आदिवासियों को नक्सली समूहों के रूप में प्रेरित-पोषित करता है। गौतम नौलखा पर तो कश्मीरी आतंकवादियों से भी मिले होने का आरोप है। यलगार परिषद मामले की जांच एनआइए के हाथ में जाने के बाद अब न सिर्फ गौतम नौलखा पर शिकंजा कस सकता है, बल्कि नक्सल-आतंकी संबंधों की गुत्थी भी सुलझ सकती है।

राज्य में सरकार बदलने के बाद से ही यलगार परिषद के समर्थक राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे। कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद से ही यलगार परिषद मामले की जांच फिर से करवाने की मांग उठनी शुरू हो गई थी। इसी मांग का समर्थन करते हुए राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर यलगार परिषद मामले की एसआइटी से जांच कराने की सिफारिश की, लेकिन उद्धव ने उस पत्र पर कोई टिप्पणी नहीं लिखी। कुछ दिन बाद केंद्रीय जांच एजेंसी एनआइए ने यलगार परिषद मामले की जांच अपने हाथ में लेने की पहल कर दी। अब शरद पवार के पास खीझ उतारने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा है। उनका कहना है कि किसी अपराध की जांच राज्य सरकार के दायरे में आती है। महाराष्ट्र सरकार का यलगार परिषद मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपना संवैधानिक रूप से गलत है। पवार का सीधा प्रहार उद्धव ठाकरे पर है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि यलगार परिषद मामले की जांच एनआइए द्वारा अपने हाथ में लिए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पवार की खीझ का एक बड़ा कारण यह भी है कि साझे की सरकार में गृहमंत्रालय उनकी पार्टी के पास रहते हुए भी यह मामला उनकी मर्जी के विरुद्ध एनआइए के हाथ में चला गया। जबकि इस साझा सरकार के शिल्पकार भी वही माने जाते हैं। उनकी पार्टी ने सोच समझकर ही गृहमंत्रालय अपने पास रखा था। इसके बावजूद कुछ न कर पाने की हताशा इस सरकार को कब तक चैन से चलने देगी, कहा नहीं जा सकता।

सुधार

कर सरलीकरण की राह

सरकार कर व्यवस्था के सरलीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही है, ताकि लोगों का कर प्रशासन के प्रति विश्वास पुख्ता हो। इससे कर संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी

डॉ. जयंतीलाल भंडारी
अर्थशास्त्री

हाल में एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश प्रत्यक्ष कर सुधार (डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म) की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में कर प्रणाली को पिछले 4-5 वर्षों से लगातार सरल बनाया जा रहा है। करदाताओं के अधिकारों को स्पष्टता से परिभाषित करने वाला करदाता चार्टर भी शीघ्र ही लागू करने की योजना है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही आयकर देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम यह देखें कि हालिया दौर में प्रत्यक्ष कर सुधार का सिलसिला तेज हुआ है। विगत 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट में प्रत्यक्ष कर सुधार की दिशा में तीन अहम बातें उल्लेखनीय रहीं। एक, प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना। दो, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए उपभोग खर्च बढ़ाने वाली आयकर की नई व्यवस्था। तीन, करदाताओं के अधिकारों के लिए करदाता चार्टर को लागू करना।

गौरतलब है कि देश में कर सुधार के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत वित्तमंत्री ने बजट में विभिन्न न्यायाधिकरणों में अटके 4,83,000 प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए योजना की घोषणा की। इसी तारतम्य में उन्होंने प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान की विवाद से विश्वास योजना को लागू करने हेतु 5 फरवरी को लोकसभा में एक विधेयक भी पेश किया। फिर अब उसे आकर्षक और व्यापक दायरे वाली योजना बनाने के लिए 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष कर विवादों के मामलों में 30 नवंबर, 2019 तक 9.32 लाख करोड़ रुपये का कर फंसा हुआ है। ऐसे में प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना से आर्थिक सुस्ती से निपटने की डगर पर आगे बढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था को जहां एक बड़ी धनराशि उपलब्ध होगी और मुकदमों पर सरकार का खर्च घटेगा, वहीं चूककर्ता करदाताओं को भी बिना किसी भेदभाव के फॉर्मूला आधारित समाधान मिलेगा और उनके कर भुगतान संबंधी तनाव में कमी आएगी।

इस कर समाधान योजना के तहत करदाता अपनी पिछली अतिरिक्त आय का खुलासा कर सकेंगे। नई प्रत्यक्ष कर समाधान योजना के तहत कमिश्नर अपील, आयकर अपील न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों के साथ-साथ मध्यस्थता एवं ऋण वसूली पंचाटों में लंबित मुकदमों तथा कर संशोधन और जब्ती के छोटे मामले भी शामिल किए गए हैं। इनके निपटान में ब्याज, जुर्माने और अभियोजन की छूट की पेशकश की गई है। यह योजना 30 जून, 2020 तक जारी रहेगी। आगामी 01 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ देश के इतिहास में पहली बार करदाता चार्टर भी लागू हो जाएगा। ज्ञात हो कि वर्ष 2020-21 के बजट में आयकर अधिनियम में एक नई धारा 119ए जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। यह धारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को एक करदाता चार्टर अपनाने एवं घोषित करने के लिए अधिकृत करती है। आयकर अधिनियम में नई धारा जोड़े जाने के बाद सीबीडीटी के पास आयकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश और आदेश जारी करने की शक्ति मिल जाएगी।

उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में 40 से अधिक देशों में ऐसे करदाता चार्टर बने हुए हैं। भारत को अमूमन घरेलू एवं विदेशी करदाता एक आक्रामक कर नियमन वाले देश के रूप में देखते रहे हैं। ऐसे में इस करदाता चार्टर से कर प्रशासन के प्रति करदाताओं का भरोसा बहाल करने में मदद मिलेगी। यहां पर यह बात भी महत्वपूर्ण है कि नए करदाता चार्टर को तैयार करते समय कानून-निर्माताओं

को करदाताओं के प्रति एक तरह की जवाबदेही दिखानी होगी। करदाता चार्टर में कर विवरण सूचना की निजता, कारोबार संबंधी आंकड़ों की गोपनीयता और औपचारिक समाधान प्रक्रिया से इतर एक शिकायत निपटान प्रणाली को भी शामिल किया जाना उचित होगा। एक करदाता चार्टर भले ही करदाता को अधिकार दे देगा, लेकिन उसके प्रभावी अमल के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव तथा कर अधिकारियों के भीतर जवाबदेही की भावना लाने की भी जरूरत है।

निःसंदेह वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अपने पहले बजट में अप्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान हेतु जिस सबका विश्वास योजना को लागू किया था, उसकी बदौलत अप्रत्यक्ष करों से संबंधित करीब 1,89,000 विवादित मामलों का निपटान किया गया है और इससे करीब 35 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिला है। अब यह नई विवाद से विश्वास योजना भी सबका विश्वास योजना की तरह सफलता की पूरी संभावनाएं रखती है। अभी समय है कि चूककर्ता आयकरदाता इसका लाभ उठा सकते हैं। इस क्रम में इस योजना से जो बड़ी धनराशि जमा होगी, उससे अर्थव्यवस्था को सुस्ती से उबारने में मदद मिल सकती है।

हम आशा करें कि कर सरलीकरण की डगर पर आगे बढ़ रहे हमारे देश में तमाम करदाता भी ईमानदारी से कर चुकाने की ओर प्रोत्साहित होंगे।

2010 में भारत में बाघों की संख्या 1,411 थी जो अब 2,967 हो गई है। भारत में 60 प्रतिशत एशियाई हाथी हैं, देश में 30 हाथी संरक्षण वन हैं। गुजरात एशियाई शेरों का घर है, आज इनकी आबादी सर्वाधिक 523 तक पहुंच गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 19 फरवरी 2020

जम्मू-कश्मीर

सियासी इंसाफ

जम्मू कश्मीर के परिसीमन की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग के लिए चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को प्रतिनिधि नामित कर दिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द जम्मू कश्मीर का परिसीमन हो सकता है। जम्मू संभाग के लोग मुख्य चुनाव आयुक्त के इस कदम से खुश नजर आ रहे हैं। लोगों की राय है कि कश्मीर केंद्रित सरकारों के कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन में जम्मू संभाग नजरअंदाज हुआ है। अब उम्मीद है कि नए सिरे से परिसीमन होगा तो कश्मीर के मुकाबले जम्मू में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी। पुरानी गलतियों को सुधार कर जम्मू से राजनीतिक इंसाफ करने का यही सफल तरीका माना जा रहा। पूर्व में अगर नियमों के आधार पर परिसीमन होता तो कश्मीर के मुकाबले जम्मू में अधिक विधानसभा क्षेत्र होते। सत्ता में कश्मीर का पलड़ा भारी रहे, इसके लिए ही पूर्व में कश्मीर को अधिक महत्व दिया गया।

जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से पहले जम्मू कश्मीर में 87 विधानसभा क्षेत्र थे। कश्मीर में 46 और जम्मू में 37। अब चार विधानसभा क्षेत्र लद्दाख के अलग होने से कम हो गए। 24 विधानसभा क्षेत्र अथवा सीटें गुलाम कश्मीर के लिए अलग से आरक्षित हैं। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन में स्पष्ट किया है कि विधानसभा सीटों को 107 से बढ़कर 114 किया जाएगा। गुलाम कश्मीर की 24 सीटें ही कायम रहेंगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के तहत केवल विधानसभा की सीटों का परिसीमन होगा। यह परिसीमन 2011 की जनसंख्या के आधार पर ही होगा।

जम्मू और कश्मीर के बीच विवाद की जड़ रहे विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना एक अच्छी पहल है, लोग इसे जम्मू से इंसाफ करने की दिशा में कदम बता रहे हैं

वर्तमान में स्थिति यह है कि कश्मीर के एक विधानसभा क्षेत्र का औसत 344 वर्ग किलोमीटर तो जम्मू में 710 वर्ग किलोमीटर औसतन क्षेत्रफल है। कश्मीर की नौ विधानसभा सीटें अधिक होने के कारण जम्मू के राजनीतिक दल चाहकर भी अपने बलबूते पर सरकार बनाने की सोच नहीं पाते। यही जम्मू और कश्मीर के बीच विवाद की भी जड़ रही है। ऐसे में लगातार मांग उठ रही थी कि विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए। दोनों संभागों को बराबर सीटों में बांटा जाए, लेकिन कश्मीर केंद्रित सरकारों के कार्यकाल में ऐसा संभव नहीं था। अब केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करवाने की दिशा में अच्छी पहल हुई है।

राज्य में अंतिम परिसीमन 1995 में हुआ था। तब राज्य में सीटों की संख्या बढ़ाकर 75 से 87 की गई थी। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर परिसीमन पर रोक लगा दी थी। 2002 के चुनावों में कश्मीर और लद्दाख के मुकाबले जम्मू में मतदाताओं की संख्या अधिक थी। इसके बावजूद कश्मीर में सीटों की संख्या अधिक रही और लगातार कश्मीरी दल ही राज्य की सत्ता पर काबिज रहे। यही वजह है कि कश्मीरी दल परिसीमन नहीं होने देना चाहते थे।

बंगाल

इंटरनेट बंद कर नकल रोकने का प्रयास

परीक्षा में नकल एक बड़ा अभिशाप है। यह विडंबना ही है कि साल-दर-साल कठिन परिश्रम करने वाली मेधा प्रतिस्पर्धा में नकलचियों से पिछड़ जाती है। पढ़ाई के दौरान होने वाली परीक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार बंगाल के कई जिलों में जड़ जमाए हुए है। इससे प्रतिभाओं का हक तो मारा ही जाता है, परीक्षा प्रणाली की शुचिता और पवित्रता भी खतरे में पड़ जाती है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती परीक्षाओं में इसी नकल को रोकने की है। अब तक हुई परीक्षाएं इस बात का प्रमाण हैं कि नकल माफिया की घुसपैठ को खत्म नहीं किया जा सका है। इसीलिए ममता सरकार नकल रोकने के लिए इस बार गंभीर नजर आ रही है। हालांकि अभिभावकों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। यदि अभिभावक खुद यह निश्चय कर लें कि वे नकल की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देंगे तो कोई दो राय नहीं कि परीक्षाओं से यह कलंक स्वतः मिट जाएगा और परीक्षाएं शुचिता, पारदर्शिता की ऐसी मिसाल बनेंगी, जो पूरी दुनिया के लिए नजीर होगी।

ममता सरकार ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए छह जिलों के 42 विकास खंडों में इंटरनेट सेवा बंद रखने की पहल की है। परीक्षा के दौरान इन अंचलों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी और इसके अलावा स्मार्ट फोन, स्मार्ट घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या विशेष संसाधनों को परीक्षा रूम में ले जाने से

प्रतीकात्मक फोटो

रोका जाएगा।

निःसंदेह राज्य सरकार ने इस व्यवस्था के जरिये दसवीं बोर्ड की परीक्षा में नकल और प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने का इंतजाम किया है। यह इंतजाम कितना पुख्ता है, यह तो भविष्य तय करेगा, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इससे नकल कराने वाले तंत्र का मनोबल टूटेगा। यद्यपि इंटरनेट सेवा बाधित करने से आम आदमी के जन जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। चूंकि इस समय बैंक सेवा से लेकर यातायात, संवाद और हर क्षेत्र में इंटरनेट का महत्वपूर्ण स्थान है इसलिए रोक लगने से आमजन को असुविधा का सामना करना ही पड़ेगा, पर यह भी सही है कि पहले से इंटरनेट सेवा बाधित किए जाने की समयबद्ध घोषणा से लोग अपना इंतजाम भी कर लेंगे। दरअसल सरकार ने पिछले वर्ष वाट्सएप पर प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से यह कदम उठाया है। 18 फरवरी से 27 फरवरी के बीच परीक्षा के दौरान दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। इससे मालदा, मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, उत्तर एवं दक्षिण दिनाजपुर एवं जलपाईगुड़ी जिले के 42 ब्लॉक प्रभावित होंगे। गौर करें तो नकल तंत्र के लिए ये इलाके कुख्यात हैं।

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की सघन छानबीन और निगरानी के साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। राज्य में इस दफा दसवीं की परीक्षा में दस लाख 15 हजार से अधिक छात्र-छात्रा बैठेंगे। निःसंदेह इनमें बहुत से मेधावी छात्र हैं और अगर नकल पर अंकुश लगा तो उनकी प्रतिभा का सही ढंग से मूल्यांकन हो सकेगा। बंगाल के भविष्य और बेहतरी के लिए नकल पर अंकुश जरूरी भी है। 2839 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा की ओर सबकी निगाहें लगी हैं। राज्य सरकार का यह प्रयोग सफल हुआ तो औरों के लिए भी सबक होगा।

झारखंड

मरीजों की जान से खिलवाड़

आयुष्मान योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि उन लोगों को इलाज से वंचित न होना पड़े जिनके पास पैसे नहीं हैं। साथ ही इसका बेजा इस्तेमाल न हो, यह तो बेहद जरूरी है। ऐसा न हो कि रकम के लिए मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए और बीमारी बरकरार रहे। पिछले दिनों धनबाद में ऐसा ही एक वाकया हुआ। एक बड़े नर्सिंग होम में मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया, मगर उसकी बीमारी दूर नहीं हो सकी। इस मरीज को पेट में दर्द की समस्या थी। उसके यूरिनरी ब्लाडर में पथरी थी। नर्सिंग होम में जांच करवाने पर कहा गया कि ऑपरेशन करना होगा। आयुष्मान कार्डधारी मरीज का ऑपरेशन किया गया। उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।

मगर कुछ ही दिनों बाद उसके पेट में फिर दर्द होने लगा। फिर उसे नर्सिंग होम ले जाया गया। जांच हुई तो पता चला कि 10 एमएम की पथरी है, जबकि ऑपरेशन के पहले जब जांच की गई थी तो 9.5 एमएम की पथरी बताई गई थी। जब इलाज पर

प्रतीकात्मक फोटो

सवाल उठा और मरीज के परिजनों ने नर्सिंग होम में हंगामा किया तो ऑपरेशन करनेवाले डॉक्टर ने यह कह कर पल्ला झाड़ा कि इस बारे में पहले ही बता दिया गया था। बड़ी पथरी निकालने की यहां व्यवस्था नहीं, इसके लिए दूसरी जगह जाना होगा। अब सवाल उठता है कि जब नर्सिंग होम में पथरी निकालने की व्यवस्था नहीं थी तो ऑपरेशन क्यों किया गया, जबकि सोनोग्राफी में तो पता चल ही गया था कि मर्ज क्या है। एक बार ऑपरेशन करा चुके मरीज से यह कहना कहां तक जायज माना जा सकता है कि वो दोबारा ऑपरेशन करा ले।

यह तो उसकी जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा हुआ। ऐसे मामले सिर्फ धनबाद नहीं, राज्य के कई हिस्सों में भी सामने आए हैं। बड़े-बड़े नर्सिंग होम में खेल चलता है। डॉक्टरों का काम मरीज की जान बचाना है, उनसे फायदा उठाना नहीं। उनके पास तो मरीज ठीक होने की आस में ही जाता है। मगर ऐसे डॉक्टर रहेंगे और ऐसा इलाज मिलेगा तो क्या उम्मीद की जा सकती है। आयुष्मान योजना या किसी भी मरीज की जान की कीमत पर ऐसे खेल की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुक्मरानों को इस तरह की कुव्यवस्था पर नजर रखनी होगी। नर्सिंग होम की मनमानी पर अंकुश लगाना होगा।

हिमाचल प्रदेश

हादसे की प्रयोगशाला

प्रयोगशाला हादसों के लिए नहीं, प्रयोगों के लिए होती है। यह दुखद है कि शिमला जिला की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मतियाना में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने न केवल विद्यार्थियों और शिक्षकों अपितु समूचे स्कूल की सुरक्षा को प्रश्नांकित कर दिया है। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रेक्टिकल के दौरान धमाका होने से चार विद्यार्थी घायल हो गए। दो विद्यार्थियों को पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर किया गया है। हालांकि इनकी हालत में सुधार है और उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। पुलिस ने जांच के लिए प्रयोगशाला को सील कर दिया है। इस मामले में कई व्यवस्थागत कमियां सामने आ सकती हैं। इस प्रकार का प्रयोग दोबारा न हो, इसके लिए आवश्यक है कि जिन्हें छोटी बातें समझकर नजरअंदाज किया जाता है, उनके बड़े असर को समझा जाए। प्रयोगशाला में बच्चों के लिए लैब कोट के साथ दस्ताने एवं आंखों की सुरक्षा के लिए लैंस अनिवार्य होते हैं, लेकिन बहुत कम स्कूलों में इनकी अनिवार्यता देखी जाती है। लैब कोट तो कई स्कूलों में बच्चे पहनते हैं, लेकिन दस्ताने एवं आंखों की सुरक्षा शायद ही किसी स्कूल की प्राथमिकता में हो। बड़ी खामी यह भी है कि स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक तो हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जिन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं मिला है। पदोन्नति बुरी नहीं, लेकिन प्रशिक्षण भी हो। यह भी दिलचस्प है कि जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र आदि सबके लिए एक ही योग्यता है। अध्यापक हो या सहायक, सच यह है जब स्कूल में प्रेक्टिकल होता है तो सभी पर नजर रखना किसी के लिए संभव नहीं है। प्रयोगशाला में प्रयोगशाला का ही परिवेश रहे तो बेहतर है। विद्यार्थी शरारती हों तब भी एक संस्कृति का विकास करने पर रसायन अपने आप एक दूसरे में नहीं मिल सकते। बेशक यह जांच का विषय है कि स्कूल में वास्तव में हुआ क्या है। किसी रसायन को आवश्यकता से अधिक गर्म किया गया है या कुछ और। सुखद यह कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगली गलती का आरंभ वहीं से होता है जब पिछली गलती को भुला दिया जाए। वैसे भी यह घटना एक ऐसे दौर में हुई है जब विज्ञान से जुड़े विषयों को लेकर छात्रों में कुछ हद तक उदासीनता का रुख भी देखने को मिल रहा है। ऐसे हादसे विज्ञान में छात्रों की अभिरुचि को और प्रभावित कर सकते हैं। यह न तो छात्रों के हित में होगा और न ही समाज और देश के, क्योंकि यदि नई पीढ़ी विज्ञान से विमुख होने लगे तब उस राष्ट्र के विकास की संभावनाएं भी निश्चित रूप से प्रभावित होंगी।

शिमला के मतियाना स्कूल की प्रयोगशाला में धमाका कई सवाल छोड़ गया। ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए आवश्यक है कि जिन्हें छोटी बातें समझकर नजरअंदाज किया जाता है, उनके बड़े असर को समझा जाए

उम्मीद है कि शिक्षा विभाग इस मामले को गंभीरता से लेगा और जांच को सार्वजनिक करेगा ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ ही प्रयोगशाला सहायकों को प्रशिक्षण मिले, विद्यार्थियों में अनुशासन संस्कृति हो, यह जरूरी है। कहना न होगा, शिक्षकों से यह अपेक्षा तो रहती ही है कि वे भी प्रेक्टिकल के दौरान विद्यार्थियों की हर गतिविधि पर नजर रखें। स्कूल प्रमुख का दायित्व है कि वह चौकस रहे।

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में जल्द नियुक्त होंगे नए विशेषज्ञ

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज

- पुराने विशेषज्ञों को हटाने की शुरू हुई प्रक्रिया, वेबसाइट के जरिये पहली बार मांगा जा रहा है आवेदन

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने अपने विशेषज्ञों को बदलने का अहम निर्णय लिया है। आयोग जल्द नए विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा। इसके मद्देनजर आयोग की वेबसाइट में अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों से आवेदन मांगा गया है। यह पहला मौका है जब आयोग की वेबसाइट में आवेदन का प्रारूप अपलोड करके विशेषज्ञों से आवेदन मांगा जा रहा है। इसके पहले आयोग में बनी अलग-अलग समितियों के द्वारा विशेषज्ञों की नियुक्ति होती थी।

उप्र लोकसेवा आयोग की कार्यप्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता लाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यापक बदलाव किए गए हैं। परीक्षा में आने वाले पेपर के स्तर, आरक्षण व्यवस्था व अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर आयोग पहले ही बदलाव कर चुका है। अब विशेषज्ञों की टीम नए सिरे से तय करने की तैयारी है। इसके पीछे बीती परीक्षाओं में होने वाला विवाद प्रमुख कारण माना जा रहा है। पीसीएस, आरओ-एआरओ सहित कई परीक्षाओं का पेपर लीक होने, कापियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी जैसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें विशेषज्ञों की भूमिका संदिग्ध मिली है। कई मामलों की जांच सीबीआइ द्वारा की जा रही है। इसके मद्देनजर विशेषज्ञों की टीम नए सिरे से गठित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है।

नई टीम जारी करेगी उत्तरकुंजी : यूपीपीएससी ने पीसीएस 2019 प्री परीक्षा का रिजल्ट सोमवार की रात घोषित कर दिया। इस बार नियम में बदलाव करते हुए उसकी संशोधित उत्तरकुंजी जारी नहीं की गई। जबकि अभी तक रिजल्ट के साथ संशोधित उत्तरकुंजी भी जारी होती थी। माना जा रहा है कि आयोग नए विशेषज्ञों की जल्द नियुक्ति करके उन्हीं से पीसीएस 2019 की उत्तरकुंजी जारी कराएगा।

यह है विशेषज्ञों का काम : यूपीपीएससी से जुड़ने वाले विशेषज्ञों की भूमिका अहम होती है। वह पेपर बनाने, परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन करते हैं। आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू विशेषज्ञ ही लेते हैं।

पंजाब में 25 हजार करोड़ की सीसीएल पर संकट के बादल

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

- अमरिंदर सरकार ने केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के समक्ष उठाया यह मुद्दा
- आरबीआइ ने कहा, पहले 2018-20 तक के लिए दी गई सीसीएल क्लीयर की जाए

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने पंजाब को अप्रैल माह में 120 लाख टन गेहूं को खरीदने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) देने से मना कर दिया है। आरबीआइ का कहना है कि जब तक पंजाब 2018-20 तक के लिए दी गई सीसीएल का भुगतान नहीं कर देता तब तक नई सीसीएल नहीं दी जाएगी। अमरिंदर सरकार ने पत्र लिखकर यह मामला केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के समक्ष उठाया है।

केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति सचिव रविकांत ने दो दिन पहले केंद्रीय वित्त सचिव (खर्च) डॉ. टीवी सोमनाथन को पत्र लिखकर यह मामला आरबीआइ के समक्ष उठाने को कहा है। उन्होंने पंजाब सरकार के पत्र का हवाला भी दिया जिसमें इस बात पर आपत्ति जाहिर की गई है कि पिछले साल का गेहूं 38 लाख मीट्रिक टन अब भी केंद्र सरकार ने नहीं उठाया है। ऐसे में कैश क्रेडिट लिमिट कैसे बंद हो सकती है? पत्र में केंद्रीय सचिव ने यह भी लिखा है कि 2017-18 का स्टॉक भी पड़ा है। बारिश होने के कारण गेहूं खरीद में राहत दी गई थी।

पत्र में कहा गया है कि गेहूं की पैदावार करने वाले राज्यों में पैदावार ज्यादा होने और खपत वाले राज्यों में मांग कम होने के कारण स्टॉक को भेजने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में पंजाब को 2018-19 की सीसीएल बंद करने में दिक्कत आ रही है। इसका प्रभाव 2020-21 की सीसीएल लेने पर पड़ रहा है। आगामी सीजन में करीब 120 लाख टन गेहूं मंडियों में पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के सचिव ने कहा कि ऐसी स्थिति में गेहूं की खरीद करनी मुश्किल होगी। इसलिए यह मुद्दा रिजर्व बैंक के पास उठाया जाना चाहिए ताकि 2020-21 के लिए मांगी गई सीसीएल को क्लीयर किया जा सके।

इसलिए आ रही दिक्कत : ज्ञात हो आरबीआइ के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों से कहा था कि जब तक पिछली सीसीएल क्लीयर नहीं होतीं तब तक आगे की सीसीएल न दी जाए। उसी के चलते 17 दिसंबर 2019 को आरबीआइ ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर पिछली सीसीएल क्लीयर करने की हिदायत दी थी।

अनाज ले जाना केंद्र की जिम्मेदारी

पंजाब चूंकि सबसे ज्यादा सीसीएल लेने वाले राज्यों में है, इसलिए यहां संकट सबसे ज्यादा है। पंजाब के फूड एंड सप्लाई विभाग के मंत्री भारत भूषण आशु ने कहा कि हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं है। हम अनाज की खरीद केंद्र के लिए करते हैं और अनाज को दूसरे राज्यों में ले जाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे पास पिछले दो सालों का स्टॉक पड़ा हुआ है। केंद्र इसे ले जाए और हमारी सीसीएल क्लीयर हो जाएगी।

उत्तराखंड में भूमि परिवर्तन संबंधी अध्यादेश में पेच

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- बजट सत्र घोषित होने के बाद अब अध्यादेश के बजाए विधेयक लाने की कसर में जुटी सरकार
- सीवर ट्रीटमेंट प्लांट समेत सरकारी योजनाओं को कृषि भूमि का गैर कृषि में भू-उपयोग परिवर्तन

उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं को तय वक्त पर पूरा करने के लिए कृषि भूमि के उपयोग में बदलाव (गैर कृषि कार्यों के लिए) के मामले में फिलहाल पेच फंस गया है। बजट सत्र की घोषणा होने के बाद उक्त संबंध में लाए जा रहे संशोधित भूमि अध्यादेश के स्थान पर अब विधेयक लाया जाएगा। सरकार अब इस कवायद में जुटी है।

कैबिनेट की बीती 30 जनवरी को हुई बैठक में भू-कानून की धारा-143 में संशोधन कर अध्यादेश लाए जाने को हरी झंडी दिखाई गई थी। उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन और उपांतरण आदेश 2001) (संशोधन) अधिनियम की धारा-143 में संशोधन के फैसले के बाद अध्यादेश लाने की तैयारी पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। दरअसल, अब अध्यादेश लाने का औचित्य सरकार को समझ नहीं आ रहा है। विधानसभा सत्र घोषित होने के बाद इस अध्यादेश को बतौर विधेयक पेश करने की बाध्यता है।

लिहाजा अब विधेयक लाने की कसरत चल रही है। सरकार इस मामले में हीलाहवाली नहीं करना चाहती। दरअसल धारा-143 में कृषि भूमि के अन्य कार्यों में इस्तेमाल के लिए भू-उपयोग परिवर्तन कराना अनिवार्य है। औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि का इस्तेमाल होने पर धारा-143 में खुद परिवर्तन मानने का प्रविधान है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रेंचिंग मैदान, सुलभ शौचालय, बस अड्डा, पार्क, बहुद्देश्यीय भवन आदि के लिए भूमि को कृषि से अकृषि करने में दिक्कतें हैं। इसमें काफी वक्त जाया हो रहा है।

ऐसी दशा में कार्यों को समय पर पूरा करने में वक्त लग रहा है। इसे देखते हुए धारा-143 में संशोधन कर धारा-143 (ख) के प्रविधान से संबंधित भू-कानून में संशोधन को अब विधेयक लाया जाएगा। राजस्व सचिव सुशील कुमार ने कहा कि बजट सत्र में उक्त संबंध में विधेयक लाया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।

फोर्स ने दी सुरक्षा तो नक्सलगढ़ में 15 साल बाद पहुंची बिजली

अनिल मिश्रा, जगदलपुर

- कभी वनोपज का बड़ा केंद्र था गोलापल्ली, नक्सलियों ने उजाड़ दिया था यह इलाका

छत्तीसगढ़ के जिस क्षेत्र से कभी ट्रकों में इमारती लकड़ी निकलती। महुआ, चिरौंजी, तेंदूपत्ता, साल बीज से वनवासी मालामाल होते थे। वही गांव अंधेरे में ऐसा डूबा कि लोग उसका नाम तक भूल गए। अब फोर्स की मदद से इस गांव को दोबारा रोशन किया जा रहा है। अब इस क्षेत्र में तेलंगाना के रास्ते बिजली पहुंची है।

छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित इस गांव का नाम है गोलापल्ली। जानकार बताते हैं कि यह इमारती गोलों का सबसे बड़ा केंद्र था। शायद इसीलिए गांव का नाम गोलापल्ली पड़ा। वन विभाग के लिहाज से महत्वपूर्ण होने की वजह से यहां रेंज दफ्तर भी खोला गया। इमारती लकड़ी का डिपो भी यहां है। वन कर्मियों के आवास व दफ्तर के अलावा थाना इस गांव की पहचान रहे। लेकिन नक्सली हावी हुए तो सब उजड़ गया। गोलापल्ली रेंज का दफ्तर अब नाम भर को वहां है। साप्ताहिक बाजार वनोपजों के संग्रह का केंद्र था। उसे भी नक्सलियों ने उजाड़ दिया। सरकारी भवनों को तोड़ दिया। स्कूल, अस्पताल सब बंद हो गए। गांव के लोग नक्सलियों की मनमर्जी

बस्तर के सुदूर अंचल गालापल्ली में चल रही बिजली विस्तारीकरण का कार्य। नईदुनिया

के गुलाम हो गए। बिजली तब भी थी। समस्या तब आई जब दक्षिण बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान सलवा जुडूम शुरू हुआ। 2005 में जुडूम शुरू हुआ था। गांव के गांव नक्सलियों के खिलाफ खड़े होने लगे। उन्होंने इसका बदला बिजली काटकर दिया। तब से गोलापल्ली अंधेरे में डूबा है। लेकिन अब फोर्स पहुंची तो बिजली लाइन भी पहुंच गई। ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। इसी हफ्ते गोलापल्ली रोशनी से नहाएगा।

ऐसे बिछी लाइन : यह समूचा इलाका अति नक्सल प्रभावित है। बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता जेकब केरकेट्टा ने बताया कि केंद्र और राज्य की कई योजनाओं से ऐसे गांवों को बिजली दी जा सकती है पर जहां विद्युत कर्मियों की जान दांव पर हो, पर वहां कैसे काम करते? डीजीपी डीएम अवस्थी ने विश्वास, सुरक्षा और विकास की रणनीति बनाई। जिस पर बस्तर पुलिस ने तत्परता से काम किया। तेलंगाना के कोत्तगुडम जिले में 11 केवी की लाइन से बिजली ली। बॉर्डर के पुलिस कैंप पइलीगुडम से होते हुए रामगुडम, तारलागुडम के रास्ते लाइन खींची गई। फोर्स ने पूरी सुरक्षा दी। बिजली पहुंच चुकी है। ट्रांसफार्मर लगते ही घरों में कनेक्शन दे दिए जाएंगे।

बीजापुर में सात नक्सली गिरफ्तार किए गए

नईदुनिया, बीजापुर : जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने मंगलवार को सात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। बासागुड़ा से जिला बल एवं सीआरपीएफ की संयुक्त टीम सर्चिंग पर रवाना हुई थी। मुखबिर की सूचना पर तर्रेम के जंगल से उइका शंभू निवासी तर्रेम थाना बासागुड़ा, पुनेम बुधु निवासी तर्रेम थाना बासगुड़ा, पुनेम मोटू निवासी कोरसागुड़ा थाना बासागुड़ा, सेमला पोदिया निवासी कोरसागुड़ा और एक अन्य को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए नक्सलियों पर 22 नवंबर 2019 को पुलिस पार्टी को निशाना बना कर सारकेगुड़ा और तर्रेम के मध्य विस्फोट करने की वारदात में शामिल होने का आरोप है। पकड़े गए उइका शंभु के बयान पर तर्रेम जंगल से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है।

गोलापल्ली ही नहीं, इस तरह के सभी इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। जहां कैंप खुलेंगे वहां समन्वित विकास केंद्र बनाया जाएगा।

– सुंदरराज पी, आइजी, बस्तर रेंज

छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध मावली मेला आज से

मो. इमरान खान, नारायणपुर

अबूझमाड़िया आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध मावली मेला बुधवार से शुरू हो रहा है। इसका इतिहास करीब 800 साल पुराना है। महाशिवरात्रि से पहले बुधवार को हर साल आयोजित होने वाले बस्तर के सबसे पुराने मेले में अबूझमाड़िया संस्कृति को करीब से देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी आते हैं।

मेले में नौ परगना के ग्रामीणों के साथ करीब 80 गांवों के देवी-देवता शिरकत करते हैं। मेला स्थल की ढाई परिक्रमा के बाद मेला आयोजन की अनुमति देवी-देवताओं द्वारा दी जाती है। ढोल नगाड़ों की थाप पर माता मंदिर से लेकर मेला स्थल तक देवी-देवताओं की सवारी मुख्य आकर्षण होती है। लेखक शिवकुमार पांडेय बताते हैं कि माता मावली मेला राजा अन्नमदेव के पूर्व से है। बस्तर के लोग कालखंड की गिनती प्रसिद्ध घटना से करते हैं। उन्होंने बताया कि यहां मेला मड़ई नल और नागवंशीय शासनकाल से है। राजा अन्नमदेव के आने से पूर्व का इतिहास जनश्रुति और किस्से कहानी में ही समाहित है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला

मावली मेले में देवी-देवताओं को गाजे बाजे के साथ लेकर पहुंचते आदिवासी। नईदुनिया

आ रहा है। ऐसे में लोग इसे 800 साल पुराना मेला बताते हैं।

कभी बस्तर को कहा जाता था चक्रकोट : लेखक पांडेय बताते हैं कि मावली माता बस्तर की आराध्य देवी माता दंतेश्वरी का ही रूप हैं। अन्नमदेव से पूर्व बस्तर को चक्रकोट कहा जाता था। उस समय चक्रकोट की आराध्य देवी माता मावली हुआ करती थी। माता को मणिकेश्वरी नाम से जाना जाता था। माता मणिकेश्वरी का संक्षिप्त नाम माता मावली है। मावली शब्द संस्कृत के मौली धातु से उद्धृत है जिसका शाब्दिक अर्थ मूल में होता है। नारायणपुर क्षेत्र में अबूझमाड़िया, मुरिया और हल्बा जनजाति निवास करती है। इन जनजातियों की माता मावली ईष्ट देवी हैं। नारायणपुर के विश्व प्रसिद्ध मावली मड़ई में झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के आदिवासियों का आगमन होता है। मेला आदिवासियों को समझने का सबसे उपयुक्त स्थान होता है। यही कारण है कि आदिवासियों के विषय में जानने इस मेले में पर्यटक और शोधार्थी भी आते हैं। इनमें विदेशी भी होते हैं।

2.4 हिस्सा भारत के पास है दुनिया के कुल क्षेत्रफल का। देश के भौगोलिक विस्तार में 21.67 फीसद भूभाग हरियाली से आच्छादित है। 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनों से ढका है।

तीस साल के श्रम से चंदन वन बन गया ढाई किमी का बंजर

मिसाल ▶ 80 साल के लाल सिंह ठाकुर के जज्बे और जुनून की कहानी, मिला मेहनत का फल, हरियाली से संवर उठा पूरा क्षेत्र

बिलासपुर में चट्टानों को काटकर तैयार किया बगीचा और चंदन का जंगल

राजेश्वर ठाकुर, बिलासपुर

हिम्मत, जुनून और मेहनत के पसीने से पूर्व सैनिक ने बंजर जमीन को सींचा और फलदार बगीचे के साथ-साथ करीब ढाई किलोमीटर तक चंदन के पेड़ उगा दिए। अब इनकी खुशबू से क्षेत्र महक रहा है। कहानी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से है, जहां पूर्व सैनिक 80 वर्षीय लाल सिंह ठाकुर की तारीफ हर कोई कर रहा है।

पर्यावरण संरक्षण

बिलासपुर जिले के घुमारवी के बाड़ी मझेहड़वा में लालसिंह द्वारा उगाया गया जंगल। जागरण

ऐसे बदली बंजर की तकदीर...

लाल सिंह ठाकुर के बेटे विजय सिंह ठाकुर ने बताया कि पिताजी ने 1990 में चट्टानों को तोड़ना शुरू किया था ताकि इन पर पानी ठहर सके। इसके लिए चट्टानों में सुराख कर छोटे-छोटे गड्ढे बनाए। इन गड्ढों में बारिश का पानी रुकना शुरू हुआ और मिट्टी भी। चट्टानों पर घासफूस उगाने के लिए खास तरह की बेलें भी रोपी, जो खूब फैलीं। खाद डालने और बारिश का पानी रुकने के कारण इनमें फलदार पौधे आम, किन्नू, लीची, कटहल, चीकू इत्यादि लगाना शुरू कर दिया। लगभग 45 बीघा जमीन में कुछ ही वर्ष में चट्टानों पर समृद्ध बगीचा तैयार हो गया। फिर धीरे-धीरे ढाई किमी के दायरे में बड़ा क्षेत्र हरियाली से भर गया, जो पहले बंजर था।

लाल सिंह बताते हैं कि उनके पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन कृषि योग्य बहुत कम। अधिकांश जमीन चट्टानी और बंजर थी। ऐसे में उनका जुनून था कि इस क्षेत्र में हरियाली लाकर बंजर का दंश मिटा दें। इसके लिए उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद मिली अच्छी नौकरी भी त्याग दी। बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल स्थित पट्टा पंचायत के गांव बाडी मझेडवा निवासी लाल सिंह ठाकुर ने अपनी जमीन से चट्टानों को छेनी व सब्बल से काटकर इस योग्य बनाया कि इसमें पौधे पनप सकें। फलदार बगीचा लगाने के साथ ही चंदन के हजारों पौधे भी रोपे।

लाल सिंह 1979 में भारतीय सेना की सिग्नल कोर से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने बीएसएफ में सेवाएं दीं, लेकिन दो वर्ष के बाद ओएनजीसी में नौकरी की। तीन वर्ष बाद इस नौकरी को भी छोड़ दिया। कहते हैं, अपनी 55 बीघा जमीन में कृषि-बागवानी करना चाहता था। इसमें से महज दस बीघा जमीन ही कृषि योग्य थी। बाकी जमीन में चट्टानें थीं। चट्टानों को काटकर फलदार पौधे रोपे और बगीचा तैयार किया।

इसके बाद मैसूर (कर्नाटक) से चंदन के पौधे लाया और रोपना शुरू किया। इसी बीच नौणी स्थित बागवानी विश्वविद्यालय के निदेशक करतार सिंह वर्मा से अपनी बात साझा की और फिर इस बंजर इलाके को हरियाली से भर देने की ठानी...। अब करीब ढाई किलोमीटर क्षेत्र में हजारों चंदन के पेड़ हैं। लाल सिंह अब 80 की उम्र पार कर चुके हैं। कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में राज्य सरकार ने उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

हर किसी को पौधे लगाने चाहिए। जरूरी नहीं कि अपनी ही जमीन में लगाएं, मकसद अपने आसपास हरियाली को बरकरार रखना हो। बंजर पर लगाएं, सड़कों के किनारे लगाएं, खाली पड़ी जमीन पर लगाएं, सरकारी जमीन में भी लगाएं, क्योंकि इससे धरती पर सभी का भला है।

- लाल सिंह ठाकुर, बागवान

पूर्व सैनिक लाल सिंह ठाकुर। जागरण

पर्यटकों के लिहाज से सुगम नहीं है धर्मनगरी बनारस

डा. श्रीराम त्रिपाठी, वाराणसी : धर्म-संस्कृति के शहर बनारस में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटक भी खूब आते हैं लेकिन उनके लिए समुचित सुविधाओं का अभाव है। एक से 29 फरवरी तक देश के 118 शहरों में चल रहे जीवन सुगमता सूचकांक सर्वेक्षण के तहत लीड इंडिया, आइआइटी बीएचयू व स्मार्ट सिटी लिमिटेड की साझा रिपोर्ट में फिलहाल यह सच सामने आया है। इसे देशभर से विभिन्न क्षेत्रों के 26 विशेषज्ञों की टीम ने तैयार कर नगर आयुक्त गौरांग राठी को सौंपा है। इसे वह महीने के अंत में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को देंगे।

लीड इंडिया, आइआइटी बीएचयू और स्मार्ट सिटी लिमिटेड की रिपोर्ट

जीवन सुगमता सूचकांक के तहत किए गए अध्ययन में यह पाया गया है कि तमाम विकास परियोजनाओं के संग बहुत सी चीजों का अभाव है। रिपोर्ट में पर्यटक सूचना संकेतक को प्रमुख चौराहों पर लगाने और यातायात को बेहतर बनाने के लिए रेट्रो फिटिंग ई-रिक्शा को और चलाने पर बल दिया गया है। बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन में जनता की भागीदारी के साथ ही नीति और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की भी बात है।

दरअसल, कैंट रेलवे स्टेशन स्थित पर्यटक सूचना केंद्र के अलावा पर्यटकों को जानकारी लेने के लिए शहर में कहीं अन्यत्र सुविधा नहीं है। किसी चौराहे या अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी को नहीं दर्शाया गया है। इसके अलावा यातायात सुविधा का भी समुचित विकास नहीं हो सका है।

स्वच्छता को शिक्षा में शामिल करने का सुझाव

टीम ने स्वच्छता शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का भी सुझाव दिया ताकि बच्चों में घरेलू स्वच्छता, सामान्य कचरा और पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े।

शहर से सटे गांवों में बढ़े हरियाली

टीम ने शहर के बाहर स्थित बस्तियों में हरियाली को बढ़ावा देने व परिवहन से जोड़ने की बात कही है ताकि लोग शहर से अपने को दूर न समझे।

वाराणसी में विकास की आपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को भेजकर सुविधाओं के विकास के लिए मदद मांगी जाएगी। यह रिपोर्ट कई विभागों के लिए एक रोडमैप है।

- गौरांग राठी, नगर आयुक्त

'प्रॉडिकल साइंस' कहने वाले टॉपर अब नहीं मिलते बिहार में

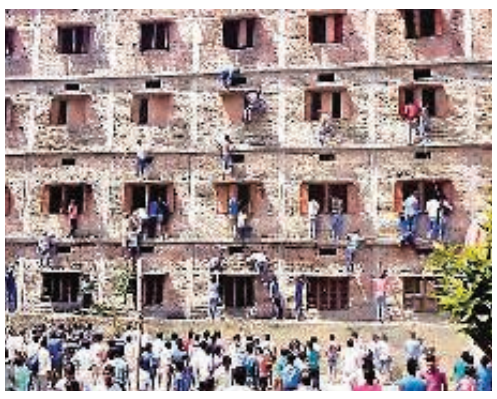

बिहार के हाजीपुर के स्कूल की 2015 की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में परीक्षा में नकल को लेकर बिहार को बदनाम किया था। आज सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार में अब ऐसी तस्वीर नहीं दिखती। (पूरी दुनिया में वायरल तस्वीर)

जयशंकर बिहारी, पटना

- **तकनीक के इस्तेमाल से नकल पर लगी नकेल, परीक्षा से मूल्यांकन तक में है सीसीटीवी से निगरानी**
- **शिक्षा माफिया खा रहे जेल की रोटी, पैरवी और पैसे के बल पर अब नहीं बनाए जाते टॉपर**

बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में नकल (कदाचार) नहीं होती। दशकों तक बिहार में सामूहिक नकल की तस्वीरें देखने के अभ्यस्त दूर के राज्यों के लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यही सच है। तकनीक के इस्तेमाल से परीक्षा से लेकर मूल्यांकन तक की पद्धति बदल गई। यूं कहें कि बिहार बोर्ड की पूरी कार्यपद्धति ही बदल गई है। यही वजह है कि अब बिहार में पॉलिटिकल साइंस को 'प्रॉडिकल साइंस' कहने वाले टॉपर नहीं मिलते।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में तकनीक का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल कर फिजा बदल दी है। 2016 में टॉपर घोटाले के बाद बोर्ड प्रशासन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने के बाद त्रुटियों को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने आइटी टीम के साथ स्थानीय समस्याओं एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर तैयार करवाया। इसमें बोर्ड अध्यक्ष के आइआइटी कानपुर के पूर्ववर्ती छात्र होने का भी लाभ मिला। तकनीक ने परीक्षा संचालन और रिजल्ट प्रकाशन को आसान कर किया। बिहार बोर्ड को देश के टॉपर बोर्ड बनाने में इन कदमों की भूमिका अहम रही।

कॉपी पर फोटो सहित पूरा विवरण रहता है प्रिंट : बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को जो कॉपी उपलब्ध कराता है, उस पर संबंधित परीक्षार्थी की फोटो, नाम, रोल नंबर, रोल कोड सहित सभी जानकारी प्रिंट रहती है। इससे मूल्यांकन व रिजल्ट में त्रुटि की संभावना कम हो गई।

डमी रजिस्ट्रेशन व एडमिट कार्ड : रजिस्ट्रेशन और प्रवेशपत्र में किसी भी स्तर पर त्रुटि नहीं रहे, इसके लिए बोर्ड ने डमी रजिस्ट्रेशन व एडमिट कार्ड जारी करना प्रारंभ किया। त्रुटि में सुधार के लिए परीक्षार्थियों को कई मौके दिए जाते हैं।

सीसीटीवी से निगरानी : 2015 में वैशाली जिले के एक परीक्षा केंद्र के चौथे तल की खिड़की से लटककर अपने-अपने अभ्यर्थी को नकल कराते हुए लोगों की फोटो काफी वायरल हुई थी। अब बाहरी लोगों पर नजर सीसीटीवी व मजिस्ट्रेट की निगरानी में कंट्रोल रूम से रखी जाती है। परीक्षार्थियों के बीच प्रश्नपत्रों के 10 सेट वितरित किए जाते हैं। इससे ताकझांक की गुंजाइश भी खत्म हो गई।

लिथो और बार कोड युक्त कॉपी : परीक्षार्थियों की कॉपी पर लिथो और बार कोड, रोल नंबर, कोड नंबर, नाम, केंद्र सहित 28 तरह की जानकारी प्रिंट रहती है। पांच माध्यम से कॉपी में दर्ज सूचनाओं की जांच की जा सकती है। फीडबैक के आधार पर बदलाव किए जाते हैं।

बिहार बोर्ड पिछले तीन साल से अपनी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित कर रहा है। इसके साथ ही बोर्ड के कामकाज को डिजिटलाइज्ड कर दिया गया। इस कारण फाइलों के पीछे दौड़ लगाने की बजाय, चंद मिनटों में ई-मेल और वाट्सएप से जानकारी साझा की जा रही है।

बिहार बोर्ड ने गलतियों से सीख लेते हुए खुद की जरूरतों के अनुसार सॉफ्टवेयर और तकनीक ईजाद की। हर साल फीडबैक के आधार पर इसमें बदलाव कर ज्यादा सहज बनाया गया। पूरी प्रक्रिया तकनीक आधारित व ऑनलाइन करने से कार्य निष्पादन में काफी बदलाव आया।

- आनंद किशोर, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे सभी ऑनलाइन कोर्स

जागरण विशेष ▶ आइआइटी दिल्ली के दो छात्रों ने तैयार की वेबसाइट एडवाइजर .कॉम

राहुल मानव, नई दिल्ली

एडवाइजर.कॉम नामक वेबसाइट बनाने वाले दिल्ली आइआइटी से पासआउट इन छात्रों का कहना है कि बीमा पॉलिसी या होटल-रेस्तरां खोजने के लिए इंटरनेट पर अनेक विकल्प, कई वेबसाइट, कई एप मौजूद हैं, लेकिन ऐसा कोई विकल्प छात्रों के लिए नहीं था कि वे अपनी जरूरत के मुताबिक ऑनलाइन कोर्स को ऐसे किसी एक प्लेटफॉर्म पर या किसी एक ही जगह पर खोज और चुन सकें। इसके अलावा, ऑनलाइन कोर्स को चुनते समय अकसर यह दुविधा रहती है कि कोर्स कितना बेहतर या परिणाममूलक है? क्या उसे करने पर कुछ लाभ होगा? मौजूद हजारों में से कौन सा कोर्स चुनना फायदेमंद होगा? कौन सा कोर्स करने से करियर के क्या विकल्प मिलेंगे? इन्हीं सब का जवाब हम अपनी इस बेवसाइट पर लेकर आए हैं...।

आइआइटी दिल्ली से पासआउट वैभव श्रीवास्तव (बाएं) और मिलन रॉय। जागरण

विश्लेषण और रेटिंग के आधार पर कर सकते हैं चयन...

मिलन रॉय ने बताया कि वेबसाइट में जितने भी ऑनलाइन कोर्स को करने के लिए बताया जा रहा है, उन सभी को छह पैमानों पर परखा गया है, जिसके आधार पर इन्हें रेटिंग भी दी जाती है। कोर्स के असाइमेंट को परखा जाता है कि इसमें दिए गए असाइमेंट कितने अच्छे हैं। कॉन्टेंट और शिक्षकों का स्तर कैसा है, जैसी बुनियादी बातों को परख कर विशलेषण किया जाता है और फिर इन्हें रेटिंग दी जाती है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली से 2019 में केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक कर चुके वैभव श्रीवास्तव और मिलन रॉय बताते हैं कि उनकी इस बेवसाइट पर छात्रों को एक लाख से अधिक ऑनलाइन कोर्स को चुनने का अवसर मिलेगा। किसी को डेटा साइंस में ऑनलाइन कोर्स करना है या किसी को मैनेजमेंट में, तो उन्हें इसके सभी बेहतर विकल्प एक ही जगह पर मिल जाएंगे।

वैभव ने बताया, जब मैं और मिलन केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तब हमें कंप्यूटर साइंस में भी कुछ बेहतर ऑनलाइन कोर्स करने की आवश्यकता महसूस हुई। कई कोर्स गूगल पर ऑनलाइन ढूंढे, इसमें बड़ी कठिनाई पेश आई। कौन सा कोर्स अच्छा और लाभदायक होगा, यह पता करने में भी काफी उलझन आई। बेहतर कोर्स का चयन न कर पाने के कारण हमें समय और पैसे जाया करना पड़ा। तब यह आइडिया आया कि यह समस्या हमारी तरह दूसरे छात्रों को भी पेश आती होगी। गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन कोर्स के बारे में एक ही प्लेटफॉर्म पर छात्रों को सब जानकारी मिल जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप के तहत वेबसाइट हमने तैयार की जिसमें दुनियाभर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं। वैभव ने बताया कि देश भर के बड़े शिक्षण संस्थानों में उनके प्रतिनिधि इस वेबसाइट के बारे में छात्रों को जानकारी दे रहे हैं। वेबसाइट के जरिये कोर्स के बारे में सभी सूचनाएं दर्ज हैं, जबकि वेबसाइट से केवल उन्हीं कोर्स के लिए सीधे आवेदन किया जा सकता है, जिनसे संबंधित शिक्षण संस्थानों के साथ इसके लिए हमने साझेदारी की है।

वैभव ने बताया कि स्नातक या स्नातकोत्तर के छात्र जब अंतिम वर्ष में होते हैं तो उन्हें नौकरी की चिंता रहती है और वह खुद को अपडेट रखने के लिए कुछ कोर्स को करने के लिए भी सोचते हैं। हमारी वेबसाइट में यह भी विकल्प इन छात्रों को मिलेगा कि वह अपनी क्षमताओं के आधार पर खुद का विशलेषण करने के बाद ऐसे कोर्स को चुन सकते हैं। इन सब के लिए एलगोरिदम तैयार किया गया है। जिसमें वह अपने विभिन्न मानदंडों को डालेंगे और उन्हें उनकी क्षमता व कौशल के तहत ऑनलाइन कोर्स को चुनने का मौका मिल जाएगा। 400 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक के ऑनलाइन कोर्स इस वेबसाइट से छात्र कर सकते हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

93 वर्ष की उम्र में ली मास्टर की डिग्री

पढ़ने के लिए कोई उम्र नही होती। यह बात 93 वर्ष की उम्र में मास्टर डिग्री लेकर कोयंबटूर के सीआई शिवसुब्रमण्यम ने सच साबित की है। शिवसुब्रमण्यम को सोमवार को दिल्ली के मानिक शाह ऑडिटोरियम में आयोजित इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) के 33वें दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान की गई। वे इग्नू के सबसे बुजुर्ग छात्र हैं। उनका इरादा आगे कुछ शॉर्ट कोर्स करते हुए पढ़ाई जारी रखने का है। पढ़ाई के प्रति उनके इस जज्बे को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सलाम किया है। प्रेट्र

पलायनग्रस्त 245 गांवों की बदलेगी तस्वीर

- **सात जिलों के 19 ब्लाकों के इन गांवों में है 50 फीसद से ज्यादा पलायन**
- **तमाम विभागों की योजनाएं मनरेगा से जोड़कर यहां की जाएंगी संचालित**

प्रतीकात्मक।

केदार दत्त, देहरादून

पलायन से त्रस्त इन गांवों पर फोकस

जिला	गांवों की संख्या
अल्मोड़ा	69
पौड़ी	54
चंपावत	43
पिथौरागढ़	29
उत्तरकाशी	26
टिहरी	22
चमोली	02

पलायन की मार से प्रभावित पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के सात जिलों के 19 ब्लाकों के 245 गांवों की एक अप्रैल से तस्वीर संवरने लगेगी। 50 फीसद से ज्यादा पलायन वाले इन गांवों में विभिन्न विभागों की योजनाओं को मनरेगा से जोड़कर संचालित किया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन गांवों में पात्र लोगों को हर हाल में 100 दिन का रोजगार मिले। साथ ही प्रोजेक्ट उन्नति के तहत उन्हें न सिर्फ निश्शुल्क प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि 100 दिन के बराबर दिहाड़ी भी मिलेगी। जिन कंपनियों के जरिए ट्रेनिंग कराई जाएगी, उनमें प्लेसमेंट भी कराया जाएगा। शासन इन दिनों यह कार्ययोजना तैयार करने में जुटा है। नए वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से इसे लागू कर दिया जाएगा।

उत्तराखंड में गांवों से निरंतर हो रहा पलायन बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। पलायन आयोग की रिपोर्ट ही बताती है कि 500 से ज्यादा गांवों में 50 फीसद से ज्यादा पलायन हो चुका है। इस सबको देखते हुए सरकार ने पलायन को थामने के मद्देनजर कमर कसी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत राज्य रोजगार गारंटी परिषद की हालिया बैठक में प्रथम चरण में पलायन से सर्वाधिक प्रभावित 245 गांवों की तस्वीर संवारने का निर्णय लिया गया था।

इस सिलसिले में मनरेगा के तहत कार्ययोजना तैयार हो रही है। काफी हद तक इसका खाका खींच लिया गया है। राज्य परियोजना समन्वयक (मनरेगा) मुहम्मद असलम के अनुसार, मनरेगा में विभिन्न विभागों को जोड़कर कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। 245 गांवों में सभी पात्र लोगों को हर हाल में सौ दिन का रोजगार सुनिश्चित कराया जाएगा। जिन लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, उन्हें प्रोजेक्ट उन्नति में भी निश्शुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाने के साथ ही सौ दिन के बराबर दिहाड़ी भी दी जाएगी।

मुहम्मद असलम के अनुसार, रोजगारपरक प्रशिक्षण दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड कौशल विकास योजना व आरसेटी में दिया जाएगा। ये प्रविधान किया जा रहा कि जो भी कंपनी इन गांवों के लोगों को प्रशिक्षण देगी, वह उन्हें प्लेसमेंट भी देगी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं के समूह भी बनाए जाएंगे और उन्हें रोजगारपरक कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा।

50 फीसद से ज्यादा पलायन वाले 245 गांवों के लिए मनरेगा के तहत कार्ययोजना तैयार हो रही है। इसमें रोजगार व स्वरोजगार पर खास फोकस है। एक अप्रैल से इन गांवों में कार्ययोजना को धरातल पर उतारने की मुहिम शुरू हो जाएगी।

- उदयराज सिंह, अपर सचिव मनरेगा, उत्तराखंड

महाशिवरात्रि पर विशेष

महाशिवरात्रि पर काशी में निकाली जाती है अनूठी शिव बरात, तैयारियां जोरों पर, काशी-महाकाल एक्सप्रेस में महाकाल के लिए बर्थ रिजर्व करने पर बवाल क्यों...

लोक आस्था में काशी और उज्जैन के राजा हैं महादेव

जागरण टीम, नई दिल्ली

आइये पहले बनारस चलते हैं, फिर उज्जैन चलेंगे...। काशी में हाजी बदरुद्दीन महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर व्यस्त हैं। इस दिन उन्हें शिव बरात में दुल्हन बनना है। पेशे से चश्मा व्यापारी हैं, लेकिन पूरे शहर में ऐसा कपड़ा खोज रहे हैं जो दुल्हन पर फबे। 65 साल के इस दुल्हन के दूल्हा बनेंगे 83 साल के सुदामा तिवारी उर्फ सांड बनारसी। यह आयोजन लोक आस्था का जीवंत उदाहरण है। यह दिखाता है कि जाति-धर्म से ऊपर उठ कर हर बनारसी अपने राजा के लिए दी गई जिम्मेदारी को तत्परता से निभाता है।

लोक आस्था का ऐसा ही उदाहरण उज्जैन में भी दिखता है। यहां विराजमान महाकाल को अवंतिकाराज के रूप में सदियों से पूजा जाता आया है। स्टेट के समय तत्कालीन सिंधिया राजवंश के सदस्य महाकाल की अंवतिकानाथ के रूप में पूजा किया करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस परंपरा का निर्वहन जिला कलेक्टर करने लगे। हर साल श्रावण-भादौ मास की

मध्यप्रदेश के उज्जैन में महाकाल को पुलिस के जवान सलामी देते हैं। फाइल फोटो

सवारी में जिलाधिकारी भगवान महाकाल की पूजा-अर्चना कर पालकी को नगर भ्रमण के लिए रवाना करते हैं। मंदिर के मुख्यद्वार पर मध्यप्रदेश पुलिस की सशस्त्र बल की टुकड़ी राजाधिराज को सलामी देती है। हर साल श्रावण-भादौ और कार्तिक-अगहन मास में उज्जयिनी के राजा महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। सवारी का स्वरूप भी राजा-महाराजाओं के लाव-लश्कर की तरह होता है।

महाशिवरात्रि पर भी कलेक्टर करेंगे पूजा : महाशिवरात्रि पर भगवान महाकाल के शासकीय पूजन की परंपरा है। इस बार भी 21 फरवरी को दोपहर 12 बजे शासन की ओर से डीएम महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे। शाम 4 बजे सिंधिया व होलकर राजवंश की ओर से भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी।

थाने की कुर्सी पर काशी के कोतवाल : देवाधिदेव महादेव भोले बाबा काशी के पुराधिपति तो बाबा कालभैरव उनकी नगरी के कोतवाल। उनकी महिमा का प्रताप शहर के पहले थाने कोतवाली में नजर आता है जिसमें मुख्य कुर्सी पर बाबा खुद विराजते हैं और थानेदार समीप दूसरी कुर्सी से थाना चलाता है। कोतवाली प्रभारी महेश पांडेय ने बताया कि बीते साल सावन के आखिरी सोमवार को कुर्सी संभालने आया तो हैरान रह गया जो नजारा सामने पाया। कुर्सी पर विराजमान बाबा कालभैरव की छवि जिन्हें पुलिसकर्मियों ने काशी कोतवाल बताया, उनका दर्शन पूजन कर जिम्मेदारी संभाली। अब तो इससे ही दिन की शुरुआत होती है।

बाबा महाकाल के नाम बर्थ : बाबा भोले शंकर लोक आस्था के राजा ठहरे तो भला उनसे जुड़े दो नगरों को जोड़ने वाली ट्रेन उन्हें क्यों न मुदित कर जाए। काशी विश्वनाथ की नगरी से जब यात्रियों का पहला जत्था महाकाल की नगरी के लिए निकला तो भक्तों ने बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने बाबा को कोच बी-5 की 64 नंबर बर्थ पर विराजमान कराया। साथ में शिव परिवार और देव मंडल की झांकी सजाई और पूजा आरती कर वातावरण को शिवमय बनाया। आइआरसीटीसी ने भी इसके पीछे की मंशा से पर्दा हटाया और बताया कि कारपोरेट ट्रेन के उद्घाटन सफर में माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक बनाने के लिए यह कवायद की गई। ट्रेन के अंदर ध्वनि विस्तारक यंत्रों से भजन गूंजे और रेल अफसरों व उनके स्वजनों के अलावा विशेष अतिथियों ने भी भजन-कीर्तन करते रास्ता बिताया।

(इनपुट-उज्जैन से नई दुनिया के राजेश वर्मा और वाराणसी से शाश्वत मिश्रा)

राष्ट्रीय संस्करण
बुधवार 19 फरवरी 2020
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर हो सकता है मंहगा

नई दिल्ली : अब उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले कुकिंग गैस (एलपीजी) सिलेंडर पर अधिक दाम चुकाने पड़ सकते हैं। सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों को एलपीजी सिलेंडर के दाम में हर महीने इजाफा करने की इजाजत देने पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि अभी बढ़ाई जाने वाली राशि तय नहीं की गई है। लेकिन यह हर महीने चार से पांच रुपये प्रति सिलेंडर हो सकती है। (आइएएनएस)

सबका विश्वास योजना से अप्रत्यक्ष कर के 95 फीसद मामले हल हुए हैं। विवाद से विश्वास योजना से भी ऐसे ही परिणाम की उम्मीद है।

— अनुराग ठाकुर
वित्त राज्यमंत्री

सेंसेक्स	40,894.38	निफ्टी	11,992.50	सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 41,865	चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 47,584	डॉलर	₹ 71.54
	▼ 161.31		▼ 53.30		▲ ₹ 239		▲ ₹ 296		▲ ₹ 0.22

क्रूड (ब्रेंट)	$ 56.43
	प्रति बैरल

अर्थव्यवस्था को कोरोना की मार से बचाने को तैयार सरकार

कसी कमर ▶ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत एवं विशेषज्ञों से स्थिति को लेकर किया विमर्श

बुधवार को वित्त समेत कई अहम मंत्रालयों के सचिवों की होगी बैठक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने में जुटी केंद्र सरकार के सामने चीन के कोरोना वायरस ने नई चिंता पैदा कर दी है। सरकार ने भी इस चुनौती को बेहद गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने मौजूदा हालात की समीक्षा की। बुधवार को फिर एक बैठक बुलाई गई है। पीएमओ भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संभव है कि दो से तीन दिनों के भीतर कई उपायों का एलान किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया, 'इस सप्ताह चीन से आयात प्रभावित होने से जिन उद्योगों पर असर पड़ रहा है, उनके लिए कई उपायों पर विचार किया जा रहा है। हम इस बारे में पीएमओ से भी विमर्श कर रहे हैं। बुधवार को वित्त मंत्रालय के सचिव एवं अन्य मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की जाएगी।' वित्त मंत्री के साथ मंगलवार को हुई बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के अलावा देश के प्रमुख उद्योग चैंबरों व कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

आयात और निर्यात के सप्लाई चेन में चुनौतियां और अवसर को लेकर सोमवार को नई दिल्ली में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित किया। प्रेट्र

▶ कोरोना के असर पर पीएमओ भी लगातार बनाए हुए है नजर

असर का अभी आकलन नहीं किया गया

वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, इसका आकलन अभी नहीं किया गया है। चीन से सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से फिलहाल उत्पादकों की लागत बढ़ने की बात सामने नहीं आई है। बैठक में वित्त सचिव के साथ राजस्व सचिव और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन भी मौजूद रहे।

सरकार ने सीआइआइ, फिक्की को यह निर्देश दिया कि वह महामारी के संभावित असर पर रिपोर्ट सरकार को दें। इन रिपोर्टों में स्थिति को लेकर सतर्क किया जाएगा। वित्त मंत्री ने दो दिन पहले ही यह संकेत दिया था कि बजट के बाद भी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। कोरोना के असर को लेकर जिस तरह आशंका जताई जा रही है, वह माथे पर बल डालता है। यही वजह है कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है।

सरकार भारतीय मैन्यूफैक्चरर्स के लिए चीन से आने वाले इंटरमीडिएट गुड्स की सप्लाई चेन को किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होने देना चाहती है। भारतीय मैन्यूफैक्चरर्स 15.21 फीसदी इंटरमीडिएट गुड्स का आयात चीन से करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की सप्लाई बाधित होने से भारतीय निर्यात में गिरावट के साथ घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग पर विपरीत असर पड़ सकता है।

चीन से आयात पर निर्भरता के चलते स्थिति हुई गंभीर

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

भारत के लिए चीन कारोबारी साझेदार देश ही नहीं है बल्कि फार्मास्युटिकल्स, रसायन समेत कई उत्पादों की वैश्विक उत्पादन श्रृंखला में दोनों देश अहम हिस्सेदार हैं। दोनों देशों के बीच 90 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार है। भारत के कई उद्योगों के लिए चीन सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। जिन 20 उत्पादों का भारत सबसे ज्यादा आयात करता है, उनमें चीन की हिस्सेदारी 43 फीसद है। भारत अपनी जरूरत का 90 फीसद सोलर पैनल चीन से लेता है जबकि कुल बल्क ड्रग्स आयात का भी दो तिहाई से ज्यादा हिस्सा चीन से आता है।

उद्योग चैंबर सीआइआइ के महासचिव चंद्रजीत बनर्जी का कहना है कि कोरोना ने देश के कई महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी पैदा कर दी है। यह छोटे कारोबारियों और रोजगार के अवसरों पर काफी विपरीत असर दिखा सकता है। सरकार व उद्योग जगत के बीच एक संयुक्त समिति बनाने की जरूरत है ताकि बिना किसी देरी के हालात से निपटने के लिए कदम उठाए जा सकें। हालात चिंताजनक हैं लेकिन इसे संभाला जा सकता है। सीआइआइ ने कोरोना से भारतीय इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर को लेकर एक अध्ययन किया है जिसमें बताया गया है कि चीन से आयातित उत्पादों पर भारत इस तरह से निर्भर हो गया है कि उसे चीन से आपूर्ति बाधित होने पर भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है।

देश के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 30 फीसद के करीब है। इलेक्ट्रॉनिक आयात में चीन का 45 फीसद, सोलर पैनल में 90 फीसद, ऑटोमोटिव पार्ट्स में 25 फीसद, बल्क ड्रग्स में 70 फीसद, मोबाइल फोन पार्ट्स में 90 फीसद चीन का हिस्सा है।

निर्यात पर भी असर : आयात के साथ निर्यात पर भी भारी असर पड़ने लगा है। भारत से होने वाले निर्यात में चीन का स्थान तीसरा है। समुद्री मछली, कपास, रसायन, प्लास्टिक, लौह अयस्क का सबसे ज्यादा निर्यात चीन को ही होता है। ये सेक्टर देश के किसानों व मछुआरों से लेकर बड़े उद्योगों के हितों से जुड़े हुए हैं। कोरोना वायरस भारत से 50 फीसद कपास निर्यात को प्रभावित कर सकता है। देश के मोबाइल फोन बाजार पर दो तिहाई से ज्यादा हिस्सा चीन की कंपनियों का है और भारत में इनकी फैक्ट्री होने के बावजूद ये 85-90 फीसद सामान चीन से लाती हैं। आमतौर पर ये भारत में फोन की असेंबलिंग करती हैं। सीआइआइ के मुताबिक जनवरी-मार्च में इस वजह से स्मार्टफोन की बिक्री में 15 फीसद की गिरावट होगी।

क्या हैं चिंता की वजहें

- सबसे ज्यादा आयातित 20 उत्पादों में चीन का 43 फीसद हिस्सा
- 90 फीसद सोलर पैनल चीन से होता है आयात
- जरूरत का दो तिहाई से ज्यादा बल्क ड्रग्स चीन से आता है
- एक चौथाई ऑटो पार्ट्स चीन से लेती हैं भारतीय कंपनियां

तर्कसंगत कदम उठाए भारत

मंगलवार को भारत में चीन के राजदूत सून वीडोंग ने परोक्ष तौर पर कहा कि भारत या दूसरे देशों को चीन से लोगों के आने-जाने या कारोबार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि भारत कारोबार व लोगों के आने-जाने के मामले में तर्कसंगत व ठंडे दिमाग से फैसला करेगा व दोनों देशों के बीच कारोबार फिर से शुरू करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने भी माना है कि सामान्य जनता के आवागमन व कारोबार को रोकने की कोई जरूरत नहीं है।'

दवाओं की आपूर्ति के लिए एयरलिफ्ट भी किया जाएगा कच्चा माल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

यूं तो कोरोना का असर मैन्यूफैक्चरिंग के हर सेक्टर पर दिखने लगा है और सरकार सक्रिय भी हो गई है, लेकिन बड़ी चिंता फार्मा सेक्टर को लेकर है। सरकार और उद्योग संगठन फिक्की के अनुसार अभी दवाओं के कच्चे माल का दो-तीन महीने का स्टॉक है, लेकिन कुछ जरूरी दवाओं के दाम बढ़ने की खबरें आने लगी हैं। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वस्त किया है कि चीन में फैले कोरोना के कारण भारत में किसी भी हाल में दवाइयों की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो सरकार दवा निर्माण के लिए कच्चे माल को एयरलिफ्ट करा लेगी। सरकार दवा उत्पादन से जुड़े कच्चे माल पर लगने वाले आयात शुल्क में भी कमी कर सकती है। देश में दवाइयों की किल्लत को रोकने के उपायों पर फैसला लेने के लिए बुधवार को नीति आयोग की भी बैठक होगी।

भारत दवा उत्पादन के लिए 70 फीसद कच्चे माल का निर्यात चीन से करता है। चीन से सप्लाई चेन पर पड़ने वाले असर पर उद्योग जगत के साथ बैठक के बाद सीतारमण ने बताया कि देश में फार्मा उद्योग के लिए कच्चे माल का फिलहाल कोई संकट नहीं है। देश में मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता है, कच्चा माल भी उपलब्ध है। सरकार चीन के अलावा अन्य देशों से या अन्य माध्यमों से कच्चे माल की आपूर्ति पर विचार कर रही है। लाइफ सेविंग ड्रग्स (जीवन रक्षक दवाओं) का जायजा लिया जा रहा है और फिलहाल बाजार में किसी भी दवाई की कमी नहीं है।

उद्योग संगठन फिक्की की तरफ से वित्त मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फार्मा उद्योग 70 फीसदी कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फार्मा उद्योग के पास कच्चे माल का दो से तीन माह का स्टॉक है। फार्मा उद्योग का कहना है कि फिलहाल दवा उद्योग पर कच्चे माल को लेकर कोई संकट नहीं है, लेकिन कोरोना संकट गहराने पर व सप्लाई चेन आगे कुछ और समय के लिए बाधित रहने पर दवा उद्योग का संकट गहरा सकता है।

प्रतीकात्मक फोटो

फायदा उठाने में जुटीं कुछ कंपनियां

दवाओं के कच्चे माल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है लेकिन कुछ छोटे निर्माता इस परिस्थिति का फायदा उठाकर कीमतों में वृद्धि करने से नहीं चूक रहे हैं। देश की बड़ी दवा निर्माता कंपनी एलंबिक के प्रतिनिधि ने कहा कि देश की बड़ी कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक है। चीन में इस हालात के और लंबा खिंचने की वजह से थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन हायतौबा जैसी हालत नहीं है। रिचर थेमिस फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश शाह आनंद का कहना है कि कच्चे माल की कम आपूर्ति का बहाना बनाकर कुछ लोग फायदा कमाने की कोशिश कर सकते हैं। एलंबिक के कार्यकारी निदेशक आरके पांडेय ने जोर देकर कहा कि ज्यादातर जेनरिक दवाएं छोटी कंपनियां ही बनाती हैं और उनके पास सामान्यतया कच्चे माल का स्टॉक रखने की क्षमता कम होती है। लिहाजा आपूर्ति कम होते ही वे इसका लाभ उठाने से नहीं चूकती हैं।

कुछ दवाओं का कच्चा माल हो रहा खत्म

फिक्की की इसी रिपोर्ट के मुताबिक 20 से अधिक ऐसी दवाएं भी हैं जिनके कच्चे माल का स्टॉक फरवरी में समाप्त हो रहा है। पैरासिटामाल और आइबूप्रोफेन जैसी दवाएं भी इनमें शामिल हैं। ऐसे में, इन दवाइयों की किल्लत देश में हो सकती है। कुछ दवाओं के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है। सरकार पर दबाव होगा कि इनकी किल्लत न होने दे।

न्यूज गैलरी

ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने लांच किए बिजली बचाने वाले पंखे

नई दिल्ली : सीके बिड़ला ग्रुप की कंपनी ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने आइ-सिरीज वाले पंखे लांच किए हैं। कंपनी का दावा है कि आम पंखों के मुकाबले इनमें 50 फीसद तक कम बिजली की खपत होती है। इस सिरीज में आइ-फ्लोरल, हेक्टर 500 और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आइओटी) की खूबी व आवाज से नियंत्रित होने वाले आइ-फ्लोट पंखे शामिल हैं। कंपनी के एमडी व सीईओ राकेश खन्ना ने कहा कि कंपनी लगातार इनोवेटिव उत्पाद विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है। बिजली की खपत कम करने वाले उत्पाद समय की जरूरत हैं। ये पंखे किफायती दाम पर विश्वस्तरीय टेक्नोलॉजी मुहैया कराने में भी मददगार होंगे। (वि.)

ईईएसएल लगाएगी 1,000 चार्जिंग स्टेशन

नई दिल्ली : एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को लेकर बीएसएनएल से करार किया है। ईईएसएल देशभर में बीएसएनएल के 1,000 केंद्रों पर चरणबद्ध तरीके से चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। (प्रेट्र)

चालू सीजन में 10.62 करोड़ टन होगी गेहूं की पैदावार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ 29 करोड़ टन के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेगी खाद्यान्नों की पैदावार

मानसून की शानदार बारिश से मिट्टी की नमी और अनुकूल जलवायु के चलते रबी सीजन की सबसे बड़ी फसल गेहूं की पैदावार में रिकॉर्ड वृद्धि का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू सीजन में 10.62 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होगा। खाद्यान्नों की कुल पैदावार 29 करोड़ टन के पार पहुंच सकती है।

पिछले साल गेहूं का उत्पादन 10.3 करोड़ टन था। चालू सीजन में उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। दो महीने में नई फसल की कटाई शुरू होगी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, जून-सितंबर में मानसून की अच्छी बारिश से रबी सीजन शानदार होगा। इस बार मानसून में अनुमान से 10 फीसद अधिक बारिश हुई, जिससे मिट्टी में पर्याप्त नमी रही है। इसका लाभ गेहूं जैसी फसल में मिल रहा है। चालू सीजन में 3.36 करोड़ हेक्टेयर रकबा में गेहूं की बोआई की गई है। जबकि पिछले साल 2.9 करोड़ हेक्टेयर में गेहूं की खेती हुई थी।

दूसरे अग्रिम अनुमान में बताया गया है कि सभी फसलों में पिछले साल के मुकाबले पैदावार अधिक होगी। खाद्यान्न की कुल पैदावार 29.19 करोड़ टन होगी, जो पिछले साल के 28.52 करोड़ टन के मुकाबले अधिक है। बीते खरीफ सीजन में कुल 14.24 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। रबी सीजन में 14.96 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान है। खाद्यान्नों में गेहूं, चावल, मोटे अनाज और दलहनी फसलें प्रमुख हैं। अनुमान के मुताबिक चालू फसल वर्ष में चावल की कुल पैदावार 11.75 करोड़ टन होगी, जबकि पिछले साल यह 11.64 करोड़ टन थी। दालों की पैदावार में इस बार फिर वृद्धि का अनुमान है। पिछले साल के 2.21 करोड़ टन के मुकाबले इस बार 2.3 करोड़ टन दलहनी फसलों की पैदावार होगी। तिलहनी फसलों में भी बढ़त दर्ज होगी। 2019-20 में 3.4 करोड़ टन के तिलहन उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले साल 3.1 करोड़ टन रहा था।

'विवाद से विश्वास' करेगी 90 फीसद विवादों का हल : ठाकुर

इंदौर, प्रेट्र : 'विवाद से विश्वास' योजना की सफलता को लेकर सरकार आश्वस्त नजर आ रही है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस योजना के जरिये पहले से लटके हुए 90 परसेंट प्रत्यक्ष कर विवादों का निपटारा संभव हो सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट में पेश की गई इस योजना का मकसद अलग-अलग अदालतों और ट्रिब्यूनल में लंबित 4.8 लाख मामलों का समाधान करना है। इनमें करीब 9.32 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। ठाकुर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि विवाद से विश्वास योजना के तहत कम से कम 90 परसेंट मामलों का समाधान कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ईमानदारी से टैक्स चुकाने वाले कारोबारियों के हितों का ख्याल रखने और टैक्स भुगतान में धोखाधड़ी से निपटने की कोशिश कर रही है। ठाकुर ने टैक्स अधिकारियों से कहा है कि कारोबारियों को तंग नहीं किया जाए। उन्होंने बताया कि अप्रत्यक्ष कर विवादों के लिए लाई गई सबका विश्वास योजना के जरिये पिछले दो महीने के दौरान 95 परसेंट विवादों का निपटारा किया गया है।

संवेदनशील डेयरी क्षेत्र में अमेरिकी घुसपैठ को लेकर संशय में सरकार

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

▶ अमेरिका के दबाव में खुल सकता है पोल्ट्री के लिए सीमित बाजार

▶ भूमिहीन व छोटे किसानों के हितों को नजरअंदाज करना आसान नहीं

भारत के दुग्ध उत्पाद और पोल्ट्री बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए अमेरिका दबाव बना रहा है। हालांकि घरेलू राजनीति में डेयरी क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार संशय में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को देखते हुए यह चर्चा फिर जोर पकड़ रही है। माना जा रहा है कि उनके दबाव में सरकार पोल्ट्री उत्पादों का सीमित बाजार खोल सकती है।

अमेरिकी डेयरी व पोल्ट्री उद्योग क्षेत्र लंबे समय से गंभीर संकट के दौर में है। राष्ट्रपति ट्रंप पर इन क्षेत्रों का जबर्दस्त दबाव है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डेयरी व पोल्ट्री उत्पादों के लिए भारत एक बड़ा बाजार बन सकता है। अगले सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आएंगे। उनके साथ दोनों सेक्टरों के निवेशक व उद्योगपति भी भारत पहुंच रहे हैं।

अमेरिकी कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1975 में जहां प्रति व्यक्ति दूध की खपत 247 पौंड (112 किलो) थी, वह 2018 में घटकर 146 पौंड (66 किलो) रह गई है। इस दौरान उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वहां के लोगों में डेयरी वाले दूध के बजाय सोया, बादाम, नारियल और काजू वाले दूध की मांग बहुत बढ़ गई है। इससे डेयरी वाले ताजा दूध का उत्पादन खपत से ज्यादा हो गया है, जो मुश्किलों का सबब बनने लगा है।

अमेरिका पोल्ट्री से जुड़े उत्पादों के लिए भी बाजार खोलने का दबाव बना रहा है। भारत में पोल्ट्री उद्योग भी आमतौर पर लघु उद्यमी अथवा छोटे किसानों के हाथ में है और असंगठित है। इसकी गुणवत्ता को लेकर घरेलू स्तर पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अमेरिका कई मर्तबा पोल्ट्री बाजार को खोलने की मांग कर चुका है। हालांकि भारत के लिए इन उत्पादों का बाजार खोलना आसान नहीं है। घरेलू कृषि क्षेत्र पहले से ही दबाव में है, जिसे उबारने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में पशुपालन और डेयरी कारोबार में छोटे व मझोले किसानों के साथ भूमिहीन पशुपालक लगे हुए हैं। उनके हितों को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता रही है।

गुणवत्ता की भी चुनौती : अमेरिकी डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। दरअसल, अमेरिकी गायों को दिया जाने वाला चारा और उनके दुग्ध उत्पादों के भारतीय खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने में संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस विषय की राजनीतिक संवेदनशीलता भी सरकार के लिए परेशानी का कारण है।

पहले स्थान पर है भारत : दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का नंबर एक देश है। यहां 18.8 करोड़ टन दूध पैदा हो रहा है। डेयरी क्षेत्र को और समृद्ध व संगठित बनाने के लिए सरकार ने अलग मंत्रालय का गठन किया है, जिससे दूध की उचित प्रोसेसिंग हो सके। देश में अब भी दूध का बड़ा हिस्सा स्थानीय स्तर पर खप जाता है। तीन वर्षों की सुस्ती के बाद इस साल डेयरी क्षेत्र में तेजी का रुख बना है।

हालात

लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार, सेंसेक्स 161 अंक और निफ्टी 53 अंक गिरा

टेलीकॉम सेक्टर पर संकट से दबाव में रहे घरेलू बाजार

मुंबई, प्रेट्र : एजीआर बकाया को लेकर टेलीकॉम सेक्टर पर छाए संकट का असर घरेलू शेयर बाजारों पर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को देश के प्रमुख शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। इस दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 161.31 अंकों की गिरावट के 40,894.38 के स्तर पर बंद हुआ। इन्ट्रा-डे के दौरान इसमें 444 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी। एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 12 हजार के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे चला गया। दिन की समाप्ति पर यह 53.30 अंक गिरकर 11,992.50 के स्तर पर रहा।

सेंसेक्स पैक में एयरटेल के शेयरों में सबसे ज्यादा तीन परसेंट तक की गिरावट देखने को मिली। इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा स्टील के शेयर भी गिरावट के साथ बंद हुए। इसके विपरीत एसबीआइ, इन्फोसिस, पावरग्रिड, टेक महिंद्रा और टीसीएस के शेयरों में बढ़त का रुख रहा। बीएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में टेलीकॉम स्टॉक्स सबसे ज्यादा चार परसेंट तक लुढ़क गए। मेटल, ऑटो और रियल्टी कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली।

प्रतीकात्मक फोटो

सोना-चांदी के भाव में सुधार

नई दिल्ली, प्रेट्र : मंगलवार को स्थानीय सराफा बाजारों में तेजी का रुख रहा। इस दौरान सोना 239 रुपये चढ़कर 41,865 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। चांदी के भाव में भी 296 रुपये की तेजी दर्ज की गई। यह 47,584 रुपये प्रति किलोग्राम भाव पर बिकी। जानकारों के मुताबिक सोने की ग्लोबल कीमत में इजाफा और डॉलर के मुकाबले रुपये के भाव में गिरावट के चलते सोने के भाव में बढ़त देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में सोना 1,588 डॉलर और चांदी 17.88 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के भाव पर बिके।

इन शेयरों में रही गहमागहमी

वोडाफोन आइडिया : एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद वोडाफोन आइडिया का घरेलू कारोबार संकट में नजर आ रहा है। इससे कंपनी के शेयरधारकों में बेचैनी देखने को मिल रही है। मंगलवार को कंपनी के शेयर 11 परसेंट तक टूटकर बंद हुए। बीएसई में इस टेलीकॉम कंपनी के शेयर 11.40 परसेंट की गिरावट के साथ 3.03 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिके। वहीं एनएसई में इनमें 10.29 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। यहां ये 3.05 रुपये के भाव पर बंद हुए।

आरआइएल : मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को नेटवर्क-18 के साथ जोड़ने की खबर के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) के शेयरों में 0.83 परसेंट की गिरावट देखी गई। बीएसई में कंपनी के शेयर 1,466.10 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिके। हालांकि इस दौरान नेटवर्क-18 एंड इन्वेस्टमेंट के शेयरों में 4.89 परसेंट का उछाल देखने को मिला।

एयरटेल : एजीआर का दबाव इस अग्रणी टेलीकॉम कंपनी पर भी देखने को मिला। मंगलवार को कंपनी के शेयरों में तीन परसेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली। बीएसई में कंपनी के शेयर 3.05 परसेंट गिरकर 547.15 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिके। वहीं एनएसई में यह 2.81 परसेंट तक लुढ़ककर 549 रुपये पर बंद हुए।

जानकारों का मानना है कि एजीआर के कारण पैदा हुई असमंजस की स्थिति से निवेशकों का मनोबल कमजोर हुआ है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद टेलीकॉम सेक्टर की कुछ कंपनियों पर इन्सॉल्वेंसी की तलवार लटक रही है। इससे टेलीकॉम सेक्टर का संकट तो बढ़ा ही है, बैंकिंग सेक्टर पर भी दबाव बना है। इस दौरान वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल स्तर पर कोरोना वायरस लगातार शेयर बाजारों को डरा रहा है। दुनियाभर में इससे मरने वालों की संख्या बढ़ने से ग्लोबल स्टॉक मार्केट दबाव में हैं। मंगलवार को एशिया के प्रमुख शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए।

नियंत्रण में रहेगा राजकोषीय घाटा : शक्तिकांत दास

नई दिल्ली, प्रेट्र : अगले वित्त वर्ष (2020-21) में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5 फीसद पर सीमित रखने का लक्ष्य सरकार हासिल कर लेगी। इस संदर्भ में शक की कोई वजह नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक साक्षात्कार में यह भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सरकार अब भी बजट घाटे को लेकर राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समिति की तरफ से तय सीमा के भीतर है।

आरबीआइ गवर्नर की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब सरकार लगातार तीसरे साल घाटे के मामले में बजट में तय लक्ष्य से चूक गई है। मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2019-20 में राजकोषीय घाटा 3.3 फीसद स्तर पर सीमित रखने का लक्ष्य था, जो बढ़कर 3.8 फीसद पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 3.5 फीसद पर सीमित रखने का लक्ष्य तय किया गया है। दास ने कहा कि अगले वित्त वर्ष का बजट महज एक पखवाड़ा पहले संसद में पेश किया गया है और इसके लक्ष्यों व आंकड़ों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रेटिंग एजेंसियों ने भी बजट के आंकड़ों पर भरोसा जताया है। इस महीने की शुरुआत में फिच रेटिंग्स ने कहा था कि नॉमिनल ग्रोथ 10 फीसद रहने और राजस्व में 9.2 फीसद इजाफे का अनुमान विश्वसनीय हैं। हालांकि इन मामलों में लक्ष्य चूकने का थोड़ा जोखिम बना रहेगा।

▶ आरबीआइ गवर्नर के मुताबिक राजकोषीय लक्ष्य हासिल करने को लेकर संदेह नहीं

▶ राजकोषीय प्रबंधन के मामले में सरकार अब भी एफआरबीएम की सिफारिशों के दायरे से बाहर नहीं

छोटी बचत से होगी भरपाई : रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, 'जहां तक राजकोषीय प्रबंधन का सवाल है, सरकार एफआरबीएम की सिफारिशों के दायरे में बनी हुई है। इस लिहाज से अतिरिक्त राजकोषीय घाटा 0.5 फीसद तक सीमित रखा गया है। सरकार इस सीमा से बंधी हुई है और अगले साल राजकोषीय घाटे का एक बड़ा हिस्सा छोटी बचत से आएगा।'

700 लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया तुर्की में मंगलवार को। इसमें सेना और कानून मंत्रालय से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इस कार्रवाई को 2016 में तख्तापलट की कोशिशों से जुड़े नेटवर्क पर लगाम कसने के तौर पर देखा जा रहा है।

कोरोना वायरस से वुहान के अस्पताल के निदेशक की मौत

आफत ▶ वायरस से अब तक छह चिकित्सा कर्मियों की मौत हो चुकी है और 1,716 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए , कुल मरने वालों की संख्या 1868 हुई, 72,436 कुल संक्रमित

बीजिंग, एजेंसियां : चीन में फैली महामारी के केंद्र वुहान स्थित एक अस्पताल के निदेशक की मंगलवार को कोरोना वायरस से मौत हो गई। चीन के सरकारी मीडिया सीसीटीवी ने यह जानकारी दी। खबर के अनुसार, वुचांग अस्पताल के निदेशक लिउ झिमिंग की जान बचाने के सारे प्रयास विफल हो गए और उनकी मौत हो गई। लिउ से पहले कोरोना वायरस के कारण अस्पताल के निदेशक स्तर के किसी व्यक्ति के मरने की खबर नहीं आई थी। उधर, कोरोना वायरस से चीन में मरने वालों की संख्या 1868 हो गई है। जबकि इससे संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 72,436 हो गई है।

लिउ की मौत की खबर सबसे पहले चीनी मीडिया और ब्लागरों ने मंगलवार आधी रात के बाद दी थी, लेकिन फिर इस खबर को हटा लिया गया था। तब बताया जा रहा था कि डॉक्टर बीमार लिउ को बचाने के प्रयास में लगे हैं। लिउ की मौत को वुहान के नेत्र चिकित्सक ली वेन लियांग की मौत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नेत्र चिकित्सक ली वेन लियांग को दिसंबर के आखिर में कोरोना वायरस के खतरे के प्रति आगाह करने के लिए चीन की पुलिस ने सजा दी थी।

ली की मौत पर देशभर में रोष के साथ ही लोगों ने सरकारी व्यवस्था पर वायरस के खतरे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। लोगों ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिउ के साथ ली को भी याद किया। बता दें कि चीन में कोरोना वायरस से अब तक छह चिकित्सा कर्मियों की मौत हो चुकी है और 1,716 कर्मी इससे संक्रमित हुए हैं।

वुहान में मास्क की कमी झेल रहे डॉक्टर : वुहान में डॉक्टरों के पास मास्क और रक्षात्मक बॉडीसूट की कमी है। कुछ डॉक्टर तो कामचलाऊ मास्क और सूट पहनकर लगातार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि कुछ डॉक्टरों में सांस संबंधी समस्या के लक्षण नजर आ रहे हैं, लेकिन चिकित्सा कर्मचारियों की कमी की चलते उन्हें लगातार काम करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में दिखाई दे रहा है। यहां पर अब तक 1800 लोगों की मौत हो चुकी है।

जापान में फंसे क्रूज में 88 और संक्रमित : जापान में फंसे क्रूज में 88 और लोगों के संक्रमित होने का पता चला है। हालांकि जिन 65 लोगों के रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, उनमें अभी भी संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं।

जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिप में मौजूद नागरिकों को एक पत्र भेजकर उन्हें 19 से 21 फरवरी के बीच निकालने की बात कही है। बता दें कि यह क्रूज पांच फरवरी को जापान के योकोहामा बंदरगाह पहुंचा था। हालांकि उस समय इस शिप में कोई वायरस संक्रमित व्यक्ति नहीं था, लेकिन हांगकांग में उतरे एक व्यक्ति का रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद क्रूज को तट पर ही रोक लिया गया है।

जापान ने एचआइवी दवाओं का क्लीनिक ट्रायल शुरू करने की योजना बनाई : अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान ने कोरोना के इलाज के लिए एचआइवी दवाओं के क्लीनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बनाई है। हालांकि दवा के उपयोग को मंजूरी देने में कितना समय लगेगा, इस विषय में कुछ नहीं बताया गया है। उधर, थाइलैंड में डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें फ्लू और एचआइवी दवाओं के संयोजन के उपयोग से वायरस के कुछ गंभीर मामलों के इलाज में सफलता मिली है।

तिमाही राजस्व में आएगी गिरावट: एपल कोरोना के खतरे का असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि अभी तक दो दर्जन से अधिक ट्रेड फेयर और इंडस्ट्रियल कांफ्रेंस को रद किया जा चुका है। ताजा खबर फोन निर्माता कंपनी एपल की तरफ आई है। उसने कहा है कि चीन में आइफोन उत्पादन में कमी और कमजोर मांग के चलते वह चालू तिमाही के राजस्व को प्राप्त नहीं कर सकेगी। मंगलवार को इस घोषणा के बाद विश्व के शेयर बाजारों में गिरावट दिखाई दी। कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन ने कहा कि अर्थव्यवस्था एक आपातकालीन स्थिति में है और मांग बाधित होने के चलते आवश्यक प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

सिंगापुर ने 32 हजार करोड़ का प्रावधान किया : सिंगापुर ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने के लिए 4.6 अरब डॉलर (32 हजार करोड़ रुपये से अधिक) का प्रावधान किया है। बता दें कि कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था को नुकसान होने के साथ ही और मंदी की आशंका जताई गई है। सिंगापुर में अभी तक संक्रमण के 77 मामले सामने आ चुके हैं। व्यापार और पर्यटन इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अभी नुकसान का पूरा आकलन किया जाना बाकी है। उम्मीद है कि स्थितियां हमारे अनुमान से कहीं अधिक खराब हो सकती हैं।

यूएन महासचिव ने कोरोना के संक्रमण पर चिंता जताई: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि संक्रमण ना केवल नियंत्रण से बाहर है, बल्कि यह काफी खतरनाक स्थिति पर जा पहुंचा है। चार दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान आए गुतेरस ने एक साक्षात्कार में कहा कि खतरे बहुत ज्यादा हैं और हमें इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर तैयारी करनी होंगी।

... **आखिरकार कोरोना को दे दी शिकस्त:** चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस के इलाज के लिए बने एक नए अस्पताल से मरीजों को छुट्टी दी जाने लगी है। यह तस्वीर अस्पताल से छुट्टी पाई 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला की है। अस्पताल से बाहर आकर उन्होंने कोरोना को शिकस्त देने की खुशी में अपनी मुट्ठी भींची। एएफपी

पाकिस्तान अब दूतावास के अधिकारियों को भेजेगा वुहान

चीन में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस के खतरे के बीच पाकिस्तान ने अपने दो अधिकारियों को वुहान में तैनात करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने बीजिंग स्थित अपने दूतावास के दो अधिकारियों को वुहान में तैनात करने का फैसला किया है ताकि वे वहां विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे पाकिस्तानी छात्रों से मुलाकात कर सकें। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान की हुकूमत की गुजारिश को स्वीकार करते हुए इस कदम को मंजूरी दे दी है। चीन में लगभग 28,000 पाकिस्तानी छात्र विभिन्न संस्थानों में पढ़ रहे हैं।

चीन में कोई भारतीय कोरोना से संक्रमित नहीं : वीडोंग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ऐसे समय जब भारत वुहान से अपने नागरिकों के एक और दल को स्वदेश लाने की तैयारी में है, चीन के राजदूत सून वीडोंग ने कहा है कि उनके देश में कोई भी भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि चीन में भारतीयों का वैसा ही ख्याल रखा जा रहा है, जैसे अपने नागरिकों का रखा जाता है। मुश्किल की इस घड़ी मे मिले साथ और सहयोग के लिए उन्होंने भारत का आभार भी जताया है और सार्स महामारी के दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस की तरफ से मिली मदद को भी याद किया है। चीन ने कोरोना वायरस यानी 'कोविड 19' को हरा देने का विश्वास भी जताया है चीन में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में वीडोंग ने कहा कि खास तौर पर हुबेई प्रांत के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के स्वास्थ्य व अन्य जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने वहां से वापस आए भारतीय छात्रों से भी कहा कि अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो अपने विवि से संपर्क करें।

न्यूज गैलरी

ईरान और जर्मनी ने रिहा किए एक-दूसरे के कैदी

तेहरान: ईरान और जर्मनी ने अपने यहां जेल में बंद एक-दूसरे के एक-एक कैदी को रिहा कर दिया। ईरान न्यायपालिका के प्रवक्ता ने कहा कि उसके नागरिक अहमद खलीली को जर्मनी ने रविवार को रिहा किया। इसके बदले में ईरान ने अगले दिन जर्मनी के एक नागरिक को जेल से रिहा कर दिया। जर्मन नागरिक की रिहाई इस शर्त पर की गई कि खलीली को अमेरिका प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। खलीली को अमेरिकी नियमों के उल्लंघन में तो जर्मन नागरिक को बिना अनुमति तस्वीर लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। (एएफपी)

अफगानिस्तान में तालिबान ने की जज की हत्या

काबुल: अफगानिस्तान के पश्चिमी हिस्से के हेरात प्रांत में तालिबान आतंकियों ने एक प्राइमरी कोर्ट के जज की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता जेलानी फरहद ने कहा कि आतंकियों ने सोमवार रात जज अब्दुल रहीम आजमी को निशाना बनाया। आतंकियों ने इसी सप्ताहांत कंधार प्रांत में दो पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। (आइएएनएस)

बैरी ओ फैरेल होंगे भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त

मेलबर्न, : ऑस्ट्रेलिया ने न्यू साउथ वेल्स सरकार के पूर्व प्रमुख बैरी ओ फैरेल को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। मंगलवार को एक आधिकारिक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई। ओ फैरेल हरिंदर सिद्धू का स्थान लेंगे, जो 2016 से भारत में ऑस्ट्रेलिया की उच्चायुक्त रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मराइज पायने ने ट्वीट किया, 'बैरी ओ फैरेल भारत में गणराज्य में अगले उच्चायुक्त होंगे। (प्रेट्र)

दुबई में इमारत से गिरने पर भारतीय इंजीनियर की मौत

दुबई : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई शहर में एक ऊंची इमारत से गिरने पर भारतीय इंजीनियर सबील रहमान की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के रहने वाले 25 वर्षीय सबील की मौत उनके कार्यस्थल के समीप एक इमारत से गिरने के कारण हुई। वह दुबई में 2018 से रह रहा था। मौत के पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिजनों को भी सबील के मौत की वजह नहीं दिख रही है। शव भारत भेजे जाने की तैयारी है। (प्रेट्र)

पाक के 'ग्रे लिस्ट' में बने रहने के आसार

- एफएटीएफ अंतिम फैसला शुक्रवार को करेगा
- आतंकी फंडिंग को लेकर कटघरे में हो पड़ोसी देश

नई दिल्ली, प्रेट्र : वैश्विक आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था एफएटीएफ ने मंगलवार को पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' में बनाए रखने की सिफारिश की है। उसने पाया कि पाकिस्तान आतंकी फंडिंग पर काबू करने में विफल रहा है। हालांकि पाकिस्तान पर अंतिम फैसला 21 फरवरी यानी शुक्रवार को किया जाएगा।

इस संबंध में पेरिस में चल रही एफएटीएफ की अंतरराष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह (आइसीआरजी) की बैठक में सिफारिश की गई है कि पाकिस्तान फिलहाल ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। उसे काली सूची में डालने के आसार अभी नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान पर अंतिम फैसला तीन दिन बाद तब लिया जाएगा जब एफएटीएफ अपनी अहम बैठक करेगा। फिलहाल उसकी बैठकें एक हफ्ते से जारी हैं। इसी दौरान अपने बचाव में पाकिस्तान ने आतंकी सरगना हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग के दो मामलों में कुल 11 साल कैद की सजा सुना दी है। पाकिस्तानी अदालत का यह दिखावटी फैसला एफएटीएफ और पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए लिया गया है।

भारत ने पिछले कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह स्थापित कर दिया है कि पाकिस्तान नियमित रूप से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मुहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को हर तरह की मदद करता है। यह सभी आतंकी संगठन पाकिस्तान की ही शह पर भारत के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए भारत ने एफएटीएफ से अपील की है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती बरते।

पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में एफएटीएफ को यह भी बताया है कि जैश का संस्थापक मसूद अजहर और उसका परिवार लापता हैं। पड़ोसी देश ने दावा किया है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकी घोषित केवल 16 आतंकी पाकिस्तान में हैं। इनमें से सात की मौत हो चुकी है। और जो नौ आतंकी जिंदा हैं उनमें से सात ने संयुक्त राष्ट्र से वित्तीय और यात्रा संबंधी प्रतिबंध हटाने की अपील की हुई है।

काली सूची से बचने को और तीन देशों का समर्थन चाहिए : पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' से बाहर निकल कर व्हाइट लिस्ट में आने के लिए कुल 39 में से 12 वोटों की जरूरत पड़ेगी। जबकि काली सूची में डाले जाने से बचने के लिए उसे और तीन देशों का समर्थन चाहिए होगा। पिछले महीने एफएटीएफ की बैठक बीजिंग में हुई थी। पाकिस्तान ने एफएटीएफ के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अब तक अपने यहां की गई कार्रवाई की सूची सौंपी थी। लेकिन अक्टूबर 2019 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान से कहा था कि उसने 27 लक्ष्यों में से केवल पांच को पूरा किया है।

फरवरी तक का अल्टीमेटम हो रहा है खत्म

एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वह फरवरी, 2020 में अपनी कार्ययोजना को पूरा कर ले। पाकिस्तान जून, 2018 से ग्रे लिस्ट में शामिल है। और उसे अक्टूबर, 2019 तक एक कार्ययोजना को अंजाम देने को कहा था। अन्यथा उसे काली सूची में डाला जाएगा। उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश पहले से काली सूची में हैं।

नाइजर में खाने के लिए भगदड़, 20 की मौत

नियामी, एएफपी : अफ्रीकी देश नाइजर में खाने-पीने की सामग्री के वितरण के दौरान शरणार्थियों के बीच मची भगदड़ में 20 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 15 महिलाएं व पांच बच्चे हैं।

सोमवार को नाइजर के दिफ्फा शहर में यह घटना तब घटी, जब खाद्य पदार्थ समेत अन्य राहत सामग्री लेने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम एक साथ उमड़ पड़ा। हादसे की जगह पड़ोसी मुल्क नाइजीरिया व चाड से लगती सीमा पर स्थित है, जहां लाखों की संख्या में लोग शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं।

दिफ्फा के सांस्कृतिक केंद्र में सोमवार को खाद्य सामग्री, कपड़े और पैसा वितरित होने की खबर सुनकर एक साथ हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। बहुत सारे लोग तो 100 किलोमीटर दूर से पैदल चल कर आए थे। आतंकवाद व गृह युद्ध से त्रस्त होकर नाइजर के इस शहर में लाखों की संख्या में लोगों ने शरण ले रखी है।

इनमें पड़ोसी मुल्क के लोग भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। दिफ्फा प्रांत के गवर्नर इस्सा लेमिने ने बताया कि एक दिन पहले राहत सामग्री का वितरण सफलतापूर्वक किया गया था।

करांची में जहरीली गैस के रिसाव से 11 की मौत

पाकिस्तान के करांची शहर में जहरीली गैस के रिसाव की चपेट में आए लोगों को चिकित्साकर्मियों और ईदी फाउंडेशन के सदस्यों ने अस्पताल पहुंचाया। एएफपी

करांची, प्रेट्र : पाकिस्तान के करांची शहर में किसी रहस्यमय जहरीली गैस की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई। यह अभी साफ नहीं हो सका कि यह किस तरह की गैस थी और इसका रिसाव कैसे हुआ। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने कराची के आयुक्त से घटना की रिपोर्ट मांगी है। डॉन अखबार में मंगलवार को छपी खबर के अनुसार, कराची के केमरी इलाके में गैस रिसाव के चलते कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जियाउद्दीन अस्पताल के प्रवक्ता अमीर शहजाद ने कहा कि गत दो दिनों में नौ लोगों की मौत हुई। जबकि पुलिस के अनुसार, दो मौत कुटियाना अस्पताल में हुई। शहर के कई अस्पतालों में दर्जनों लोगों को भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के इस तटीय शहर के आयुक्त इफ्तिखार शालवानी ने कहा कि एक जहाज से सोयाबीन या इसी तरह के पदार्थ के चलते जहरीली गैस का रिसाव हो सकता है। कराची के पुलिस प्रमुख गुलाम नबी मेमन ने कहा, 'घटना के कारणों का अभी पता चल नहीं सका है।'

करतारपुर साहिब पहुंचे गुतेरस, सिख बच्चे ने किया स्वागत

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने मंगलवार को करतारपुर साहिब गलियारे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गलियारा खोलने के कदम की सराहना की।

लाहौर से करीब 125 किलोमीटर दूर करतारपुर साहिब पहुंचने पर गुतेरस को एक सिख बच्चे ने बुके भेंटकर स्वागत किया। इस मौके पर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। गुतेरस को करतारपुर गलियारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते की जानकारी दी गई।

- यूएन महासचिव ने की गलियारे को खोलने की सराहना

गुरुद्वारा दरबार साहिब पाकिस्तान के करतारपुर में है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने यहीं पर अपनी जिंदगी के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबा यह गलियारा गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के गुरुदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। गलियारा गत नवंबर में खोला गया था।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने मंगलवार को कतरतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में शीश नवाया। उन्होंने दुनिया में अमन और शांति की कामना की। रायटर

अमेरिका व तालिबान की वार्ता पर नजर रख रहे यूएन महासचिव

यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस अमेरिका और तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता पर करीब से नजर रख रहे हैं। अफगानिस्तान में 19 वर्षों से जारी खूनी संघर्ष को खत्म करने के प्रयास में दोनों पक्ष जल्द ही किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। महासचिव के प्रवक्ता द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, 'गुतेरस ने इस्लामाबाद की यात्रा के दौरान वार्ता सफल होने की कामना की है।' गत शनिवार को यह खबर आई थी कि अमेरिका और तालिबान 29 फरवरी को समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

सदस्य देशों के यूएन का बकाया भुगतान नहीं करने से भारत चिंतित

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के शांति मिशनों में बढ़-चढ़कर भाग लेने वाले भारत ने सदस्य देशों द्वारा बकाया भुगतान नहीं करने पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही कहा है कि शांति मिशनों के फंड का इस्तेमाल अन्य प्रयोजन के लिए करना विश्वास को ठेस पहुंचाने जैसा है। बता दें कि भारत उन देशों में है, जिसने संयुक्त राष्ट्र को अपने हिस्से के 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 272 करोड़ रुपये) का समय से पहले ही भुगतान कर दिया है। खास बात यह है कि मार्च 2019 तक किसी भी देश द्वारा शांति मिशन के लिए दी गई यह सबसे ज्यादा रकम है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैय्यद अकबरूद्दीन ने विशेष समिति में शांति अभियान के मुद्दे पर भारत की प्राथमिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की वित्तीय स्थिति विशेष रूप से सैनिकों

- कहा, शांति मिशन फंड का अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करना विश्वास को ठेस पहुंचाने जैसा

को भुगतान में विलंब जैसे मुद्दे चिंता का कारण बने हुए हैं। पिछले साल कुछ उपाय किए गए थे, लेकिन इसका अस्थायी असर ही हुआ। भुगतान में देरी की प्रवृत्ति एक बार फिर वापस आ रही है। उन्होंने बंद हो चुके शांति अभियानों का भुगतान नहीं करने पर भी चिंता व्यक्त की।

अकबरूद्दीन ने कहा कि शांति मिशनों की समाप्ति के सालों बाद भी भुगतान नहीं करना यह सुनिश्चित करता है कि इस मामले को छोड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे शांति अभियानों के धन का उपयोग करना ना केवल खराब ऑडिट का उदाहरण है बल्कि यह विश्वास को ठेस पहुंचाने वाला है।

अशरफ गनी अफगानिस्तान के दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित

काबुल, एजेंसियां : अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा के साथ ही सियासी संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को घोषित अंतिम नतीजों में अशरफ गनी दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। लेकिन उनके मुख्य प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने चुनाव नतीजों को मानने से इन्कार करते हुए समानांतर सरकार बनाने का एलान किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पिछले साल 28 सितंबर को मतदान कराए गए थे। मतदान में घोर अनियमितता के आरोप लगे थे। भारी हिंसा भी हुई थी।

स्वतंत्र चुनाव आयोग (आइईसी) ने कहा है कि अशरफ गनी को 50.64 फीसद मत मिले हैं। जबकि, अब्दुल्ला को 39.52 फीसद मत प्राप्त हुआ है। चुनाव आयोग ने दिसंबर में प्रारंभिक चुनाव नतीजों की घोषणा की थी, जिसमें विश्व बैंक के कर्मचारी रहे गनी मामूली अंतर से विजयी हुए थे। लेकिन अब्दुल्ला ने चुनाव नतीजों में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनकी पूरी समीक्षा की मांग की थी। बता दें कि 2014 के चुनाव में भी धोखाधड़ी का आरोप लगा था। बाद में अमेरिका के बीच बचाव के बाद गनी राष्ट्रपति और अब्दुल्ला उनके सीईओ बने थे।

दावा

आतंकी संगठन अलकायदा की पत्रिका नवा-ए-अफगान ने किया दावा, मुशर्रफ की आलोचना की थी और अलकायदा से भी था जुड़ाव

लापता पाक जनरल शाहिद की दो साल पहले हो गई थी मौत

रियाद, एएनआइ : रहस्यमय परिस्थितियों में पिछले कुछ वर्षों से लापता पाकिस्तान के सेवानिवृत्त जनरल शाहिद अजीज की दो साल पहले ही मौत हो चुकी है। यह दावा आतंकी संगठन अलकायदा की पत्रिका नवा-ए-अफगान जिहाद ने किया है। पत्रिका ने पहली बार यह भी दावा किया कि अलकायदा से अजीज के करीबी संबंध थे। उन्होंने एक किताब में पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की आलोचना की थी।

अजीज 2005 में पाकिस्तान की सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। मुशर्रफ जब सेना प्रमुख थे, तब वह सैन्य अभियानों के महानिदेशक थे। 2013 में लिखी एक किताब में उन्होंने मुशर्रफ की नीतियों की आलोचना की थी। वर्ष 2018 में जब उनके लापता होने और निधन की खबरें आई थीं, तब उनके रिश्तेदारों ने इन खबरों को अफवाह करार दिया था। उन्होंने यह दावा किया था कि वह धार्मिक जुड़ाव के साथ निजी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नवा-ए-अफगान पत्रिका ने अपने फरवरी के अंक में दावा किया कि अलकायदा के सदस्यों से

शाहिद अजीज। फाइल

अजीज के करीबी संबंध थे। इस पत्रिका का प्रकाशन अलकायदा इन द इंडियन सबकांटिनेंट (एक्यूआइएस) करता है। 2014 में अलकायदा के सरगना अयमान अल-जवाहिरी ने भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश की सरकारों से मुकाबले के मकसद से एक्यूआइएस की स्थापना की थी।

हाफिज सईद के फंडिंग के दो मामले लाहौर ट्रांसफर

लाहौर, प्रेट्र : मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद के आतंकी फंडिंग के दो मामलों को आतंकवाद रोधी अदालत ने मंगलवार को लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसा आतंकी सरगना हाफिज सईद की अपील पर किया गया। संयुक्त राष्ट्र में एक करोड़ डॉलर के ईनामी आतंकी हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग के मामले में 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। 70 वर्षीय इस आतंकी को कोट लखपत की कड़ी सुरक्षा में बंद किया गया था।

लाहौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ममून राशिद शेख ने हाफिज सईद की याचिका पर सुनवाई के साथ ही उसके करीबी जफर इकबाल के खिलाफ भी सुनवाई हुई। इकबाल अल-अनफाल ट्रस्ट का सचिव भी है। कोर्ट ने हाफिज सईद की याचिका स्वीकार कर ली और 12 फरवरी को सईद और इकबाल को आतंकी फंडिंग

हाफिज सईद। फाइल

के दो मामलों में सजा सुनाई गई। यह दोनों मामले लाहौर और गुजरनवाला शहरों में दर्ज थे। आतंकवाद रोधी कोर्ट के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने सईद और इकबाल को दोनों मामलों में साढ़े पांच साल की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इनकी कुल सजा 11 साल कैद की होगी। सईद के वकील इमरान फैजल गिल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को एफएटीएफ मामले पर दबाव के चलते दोषी ठहराया गया है।

डॉक्टर बोले, असांजे को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं

लंदन, आइएएनएस : 100 से अधिक डॉक्टरों ने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। द लैंसेट मेडिकल जर्नल में सोमवार को प्रकाशित इस पत्र में 18 देशों के डॉक्टरों ने हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि असांजे फिलहाल ब्रिटेन की अत्यधिक सुरक्षा वाले बेलमार्श जेल में बंद है।

पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि जेल में असांजे को पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा है। जिसके चलते उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उनके अनुसार, असांजे के खराब स्वास्थ्य का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गत वर्ष अक्टूबर में जब एक मामले की सुनवाई के दौरान उसे कोर्ट में पेश किया गया था तो उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। चलने-फिरने में असमर्थ असांजे यह भी नहीं समझ पा रहा था कि अदालत में क्या चल रहा है।

पत्र में हस्ताक्षर करने वालों में से अधिकांश डॉक्टर वही हैं, जिन्होंने नवंबर में इसी तरह के एक पत्र के माध्यम से असांजे को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की थी। पत्र में डॉक्टरों ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उचित इलाज मिलना उसका मौलिक अधिकार है और राजनीति को इस मामले में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 'डॉक्टर ऑफ असांजे ग्रुप' से ताल्लुक रखने वाले इन डॉक्टरों ने अन्य डॉक्टरों से भी अपनी इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया है। डॉक्टरों का कहना है कि मूलभूत चिकित्सा सिद्धांतों का राजनीतिकरण करना गंभीर चिंता का विषय है।

असांजे का मामला एक खतरनाक मिसाल है, जिसमें चिकित्सा के पेशे को एक राजनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।

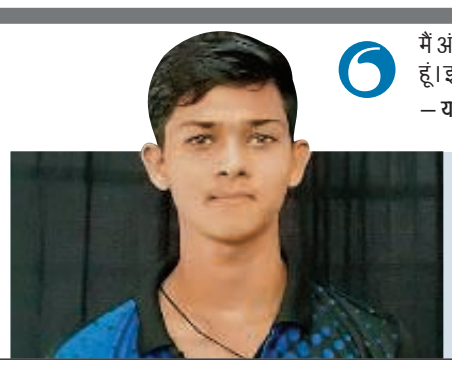

मैं अंडर-19 विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनकर खुश हूं। इस पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है।
— यशस्वी जायसवाल, अंडर-19 क्रिकेटर

कोहली पांच करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर वाले पहले भारतीय

नई दिल्ली, आइएएनएस : विराट कोहली इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय बन गए हैं। कोहली के इस एप पर पांच करोड़ फॉलोअर हो गए हैं। कोहली की अभी तक इंस्टाग्राम पर 930 पोस्ट हैं और वह खुद 480 लोगों को फॉलो करते हैं। कोहली के बाद प्रियंका चोपड़ा सबसे ज्यादा फॉलोअर वाली दूसरी भारतीय हैं। उन्हें 4.99 करोड़ लोग फॉलो करते हैं।

नौ साल में 14 आइसीसी टूर्नामेंट

वनडे और टी-20 प्रारूप में चैंपियंस कप नाम से दो नए टूर्नामेंट का रखा आइसीसी ने प्रस्ताव

2011 वनडे विश्वकप ट्रॉफी के साथ महेंद्र सिंह धौनी ● फाइल फोटो, ग्रेट्र

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली हाल ही में व्यस्त कार्यक्रम की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। न्यूजीलैंड में मौजूद कोहली की इस खबर के बाद नींद उड़ना तय है जिसमें आइसीसी ने अपने अगले कैलेंडर (2024-31) में वनडे विश्व कप, टी-20 विश्व कप और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा दो नए टूर्नामेंट का प्रस्ताव रख दिया है। यह प्रस्ताव अगर लागू हुआ तो दुनिया भर की पुरुष टीमें 2023 से 2031 तक 14 आइसीसी टूर्नामेंट खेलेंगी। इसके अलावा अन्य द्विपक्षीय सीरीज, प्रत्येक देशों की अपनी ग्लोबल लीग और अन्य टूर्नामेंट अलग हैं। आइसीसी के प्रस्तावित कैलेंडर से पहले की बात करें तो इस साल ऑस्ट्रेलिया में और अगले साल भारत में टी-20 विश्व कप होना है। अगले साल इंग्लैंड में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। वहीं 2023 में वनडे विश्व कप भी भारत में होना पहले से ही तय है।

चैंपियंस कप का प्रस्ताव : टी-20 चैंपियंस कप में 10 देश भाग लेंगे और इसमें कम से कम 48 मैच खेले जाएंगे। इतने ही मैच इंग्लैंड में 2019 में हुए वनडे विश्व कप में खेले गए थे। यह टूर्नामेंट आइसीसी के 2024 से 2031 कैलेंडर के लिए प्रस्तावित सबसे बड़ा विवादित टूर्नामेंट है। आइसीसी का यह प्रस्तावित कैलेंडर सामने आया है और अब यह आइसीसी और उसके अमीर बोर्ड सदस्य के बीच एक नया विवाद खड़ा कर सकता है, क्योंकि पहले ही कई देश कैलेंडर में द्विपक्षीय सीरीज और लीग के लिए रिक्त समय रखने के लिए कह चुके हैं।

अक्टूबर में हुई थी सुगबुगाहट : इस प्रस्ताव को सबसे पहले आइसीसी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में सामने रखा था और तब से बोर्ड और आइसीसी के बीच इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। इसके तहत 2024 और 2028 में टी-20 चैंपियंस कप और 2025 और 2029 में वनडे चैंपियंस कप होगा। 2026 और 2030 में टी-20 विश्व कप और 2027 और 2031 में वनडे विश्व कप होगा।

चैंपियंस ट्रॉफी की तरह वनडे चैंपियंस कप: टी-20 चैंपियंस कप के अलावा वनडे चैंपियंस कप, चैंपियंस ट्रॉफी की ही तरह एक छोटा टूर्नामेंट होगा जिसमें छह टीम के बीच 16 मैच होंगे। वहीं टी-20 चैंपियंस कप मैचों के लिहाज से एक नए विश्व कप की तरह होगा, जिसमें नियमित टी-20 विश्व कप से सिर्फ सात ही मैच कम होंगे। वहीं वनडे विश्व कप में तो 48 ही मैच होते हैं।

15 मार्च तक लगाओ बोली : सदस्य देशों को 2023-2031 के बीच होने वाले आइसीसी टूर्नामेंट के लिए बोली डालने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया गया है। हालांकि यह समयसीमा आइसीसी की मार्च के आखिर में होने वाली बैठक तक बढ़ाई जा सकती है। इसका कारण यह है कि इस प्रस्ताव का अभी आधिकारिक करार होना है, क्योंकि यह अभी सिर्फ प्रस्ताव आया है।

ये बोर्ड हटे थे पीछे : आइसीसी और इसके मुख्य कार्यकारी मनु सवानी ने कहा था कि कैलेंडर के प्रत्येक वर्ष में एक आइसीसी टूनामेंट होना चाहिए जिससे नियमित रूप से बड़ी रकम मिलेगी और उसको छोटे देशों में खेल के उत्थान के लिए उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, बीसीसीआइ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इस प्रस्ताव से कदम पीछे हटा लिए थे। उनका मानना था कि इससे द्विपक्षीय सीरीज में असर पड़ेगा और वह ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि इससे उनके बोर्ड की कमाई कम हो जाएगी।

आइसीसी सदस्यों की अलग राय : बोर्ड सदस्यों का मानना है कि इन टूर्नामेंट के लिए काफी दिनों की आवश्यकता होगी और यह टूर्नामेंट द्विपक्षीय वनडे व टी-20 सीरीज के अलावा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए होनी वाली द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज का भी समय खा जाएंगे। टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के बाद 2025, 2027, 2029 और 2031 में होनी है। वहीं दूसरी ओर बीसीसीआइ ने भी इस बार आइपीएल के समय को बढ़ा दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बीबीएल और वेस्टइंडीज के सीपीएल जैसे घरेलू टी-20 टूर्नामेंट भी हैं। वहीं इंग्लैंड भी इसी वर्ष से द हंडेड टूर्नामेंट शुरू करने जा रहा है।

ओलंपिक में पहुंचा क्रिकेट तो : इसके अलावा एक अन्य मामला और है जिसकी वजह से आइसीसी का यह प्रस्तावित कैलेंडर खारिज हो सकता है। वह है क्रिकेट को ओलंपिक तक पहुंचाने की पहल। पिछले वर्ष अगस्त में ही एमसीसी की विश्व क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन माइक गैटिंग ने कहा था कि मनु ने इशारा किया है कि लॉस एंजिलिस में होने वाले 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रस्ताव के मुताबिक इस वर्ष टी-20 चैंपियंस कप भी खेला जाएगा।

महिला क्रिकेट में भी प्रस्ताव : टी-20 और वनडे के चैंपियंस कप का प्रस्ताव महिला क्रिकेट कार्यक्रम में भी जोड़ा गया है। दोनों टूर्नामेंट में छह टीम के बीच 16 मैच खेले जाएंगे। वित्तीय नजरिये से देखा जाए तो जो भी देश इन टूर्नामेंट के लिए बोली लगाएगा वह टिकट, हॉस्पिटेलिटी और कैटरिंग से कमाई करेगा, जबकि आइसीसी अन्य व्यावसायिक और प्रसारण करार से कमाई करेगा।

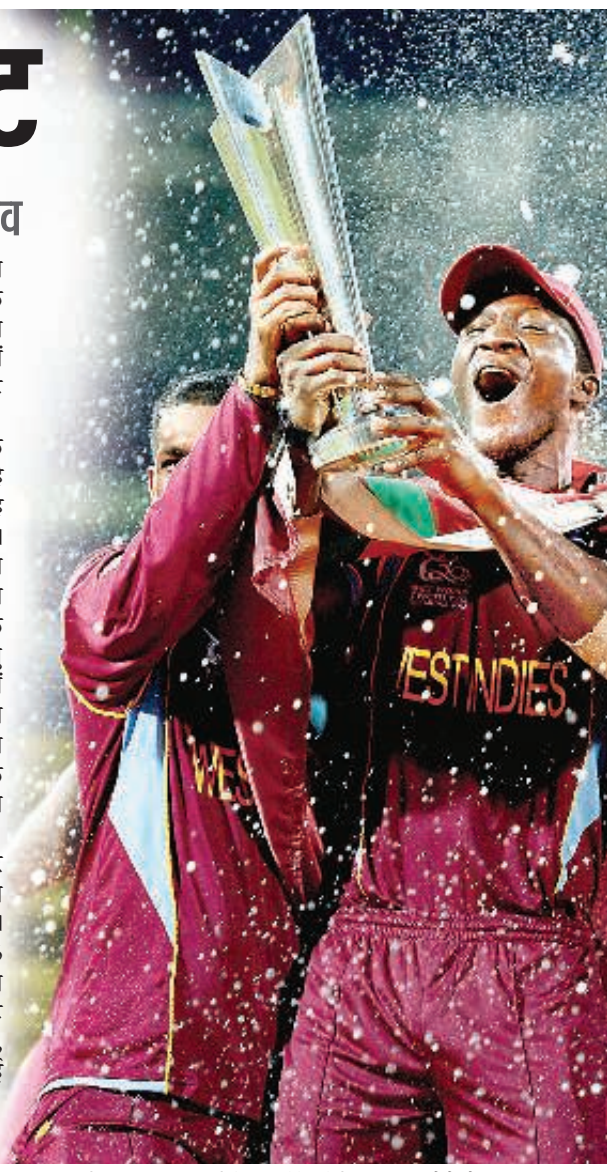

2016 टी-20 विश्वकप ट्रॉफी के साथ डेरेन सैमी ● फाइल फोटो, ग्रेट्र

चैंपियंस ट्रॉफी का विकल्प

नई दिल्ली : आइसीसी ने 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से वनडे क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए पहली बार विश्व कप जैसे ही टूर्नामेंट की शुरुआत की। यह प्रत्येक दो वर्ष बाद आयोजित किया जाता रहा। 2006 में भारत में चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित हुई। इसके बाद पहली बार इस टूर्नामेंट को तीन साल बाद 2009 में आयोजित किया गया। इस बीच टी-20 क्रिकेट ने दुनिया में अपने पैर पसार लिए थे। यही वजह रही कि 2009 के बाद यह प्रत्येक चार वर्ष बाद 2013 और 2017 में आयोजित हुआ। 2017 में आइसीसी ने इस टूर्नामेंट को समेटने का फैसला कर लिया। यही वजह है कि 2021 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी उसको टी-20 विश्व कप में तब्दील कर दिया गया। अब टी-20 और वनडे प्रारूप में अलग-अलग चैंपियंस कप का प्रस्ताव लाया है।

पुरुष क्रिकेट का प्रस्तावित कार्यक्रम

वर्ष	आइसीसी टूर्नामेंट	
2024	टी-20 चैंपियंस कप	
2025	विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल	वनडे चैंपियंस कप
2026	टी-20 विश्व कप	
2027	विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल	वनडे विश्व कप
2028	टी-20 चैंपियंस कप	
2029	विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल	वनडे चैंपियंस कप
2030	टी-20 विश्व कप	
2031	विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल	वनडे विश्व कप

पहले से तय कार्यक्रम

वर्ष	कार्यक्रम	देश
2020	टी-20 विश्व कप	ऑस्ट्रेलिया
2021	टी-20 विश्व कप	भारत
2021	विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल	इंग्लैंड
2023	वनडे विश्व कप	भारत
2023	विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल	तय नहीं

महिला क्रिकेट का प्रस्तावित कार्यक्रम

2023	वनडे चैंपियंस कप
2024	टी-20 चैंपियंस कप
2025	वनडे विश्व कप
2026	टी-20 विश्व कप
2027	वनडे चैंपियंस कप
2028	टी-20 चैंपियंस कप
2029	वनडे विश्व कप
2030	टी-20 विश्व कप

तो 2021 के बाद 2026 में टी-20 विश्व कप

नई दिल्ली : आइसीसी टी-20 विश्व कप हर दो साल में कराता रहा है। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के कारण 2020 और 2021 में लगातार दो टी-20 विश्व कप होंगे। आइसीसी के प्रस्ताव के मुताबिक इसके बाद 2026 में टी-20 विश्व कप होगा। आइसीसी के कैलेंडर को पुनर्निधारित करने के लिए ऐसा किया गया है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप

इसमें सभी देश दो वर्ष तक अपने घर और विरोधी टीम के घर विश्व चैंपियनशिप के तहत द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज खेलते हैं। 2019 में इसकी शुरुआत हुई। अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली दो टीम फाइनल में पहुंचेंगी। इसका पहला फाइनल 2021 में लंदन में खेला जाएगा। हर दो साल में यह आयोजन होगा।

वनडे विश्व कप

1975 में इंग्लैंड में पहला विश्व कप खेला गया। 1987 विश्व कप तक इसमें आठ और 1992 में नौ टीमें खेलीं। 1992 और 2019 को छोड़कर सभी विश्व कप ग्रुप स्तर पर खेले गए। 1999 में सुपर-6 फॉर्मेट आया। 2007 में इसमें सबसे ज्यादा 16 टीमें खेलीं। 2023 में भारत में होने वाले विश्व कप में 10 टीमें होंगी। 2019 वनडे विश्व कप में 48 मैच खेले गए।

वनडे चैंपियंस कप

इस नए प्रस्तावित टूर्नामेंट में शीर्ष छह टीमों के बीच कुल 16 मैच खेले जाएंगे।

टी-20 चैंपियंस कप

एक तरह से यह नए विश्व कप की तरह होगा। यह टी-20 विश्व कप से छोटा होगा। इसमें 10 देश भाग लेंगे और कम से कम 48 मैच खेले जाएंगे।

टी-20 विश्व कप

2007 में शुरू हुए सबसे छोटे फॉर्मेट के विश्व कप को हर दो साल में आयोजित होना था लेकिन आइसीसी के कार्यक्रमों के अनुसार इसे इधर-उधर किया जाता रहा। 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 और 2016 के बाद इस साल ऑस्ट्रेलिया में यह आयोजित होगा। 2021 में यह भारत में पहले से ही होना तय है। 2020 टी-20 विश्व कप में इसमें कुछ 16 टीमें हैं। मेजबान ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान रैंकिंग के आधार पर सीधे सुपर-12 में क्वालीफाई कर चुके हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी, आयरलैंड, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान में से चार टीमें दो ग्रुपों में आपस में भिड़कर सुपर-12 में क्वालीफाई करेंगी। इस टूर्नामेंट में 45 मैच होंगे।

कंबाला में अब सबसे आगे निकले निशांत

सूर्य चंद्र कंबाला रेस के दौरान निशांत शेट्टी ● ट्विटर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भैंसा दौड़ (कंबाला) में उम्दा प्रदर्शन की बदौलत पैडी श्रीनिवास गौड़ा स्टार बन गए लेकिन अब उनसे भी तेज एक पैडी सामने आया है। खबरों के मुताबिक, वेनुर में सूर्य चंद्र कंबाला में निशांत शेट्टी नाम के एक पैडी ने 9.52 सेकेंड में ही 100 मीटर की दूरी तय कर दी, जो गौड़ा से करीब .03 सेकेंड कम है।

सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाले श्रीनिवास गौड़ा ने कंबाला दौड़ के दौरान 100 मीटर की दूरी केवल 9.55 सेकेंड में तय की थी। इसके बाद उन्हें केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी बेंगलुरु साई सेंटर में ट्रायल के लिए कहा था। हालांकि उन्होंने इससे इन्कार कर दिया। हग्गा-हीरिया कैटिगरी में निशांत ने 143 मीटर की दूरी 13.61 सेकेंड में पूरी की जिसमें शुरुआती 100 मीटर तो 9.52 सेकेंड में ही पूरे कर लिए।

कोहली को आउट करने का इंतजार : बोल्ट

तैयारी

- वापसी को यादगार बनाना चाहते हैं कीवी गेंदबाज
- शुक्रवार से शुरू हो रही है भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज

वेलिंगटन, पेट्र : न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने फिटनेस हासिल करने के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाई लेकिन शुक्रवार से यहां शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान वह भारतीय कप्तान विराट कोहली का विकेट चटकाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी को यादगार बनाना चाहते है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था जिसके बाद वह भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे। छह सप्ताह तक टीम से बाहर रहने के बाद वापसी करने वाले इस तेज गेंदबाज ने शुरुआती टेस्ट से पहले अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया।

पहले टेस्ट के लिए यहां पहुंचने के बाद उन्होंने भारतीय कप्तान को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जब भी मैं खेलता हूं तो मेरी कोशिश कोहली जैसे बल्लेबाज को आउट कर खुद को साबित करने की होती है। मैं उनको आउट करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन वह कमाल के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड को पिछली टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से हराया था और उनके लिए भारत भी कठिन चुनौती पेश करेगा। बोल्ट ने कहा कि भारत मजबूत टीम है और आइसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में शीर्ष पर है। वे इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि उन्हें कैसे खेल खेलना है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे लिए मुश्किल समय था। यह देख कर अच्छा लग रहा है कि हम वापसी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के लिए 65 टेस्ट में 256 विकेट लेने वाले 30 साल के इस खिलाड़ी ने कहा कि मैं अच्छे विकेट के हिसाब से तैयारी कर रहा हूं। आमतौर पर यहां कि पिच अच्छी होती है और मैच आखिर (पांच दिन) तक चलता है। मैं मैच शुरू होने का इंतजार कर रहा हूं।

दूसरी टीमें भी बुमराह के खिलाफ अपनाएंगी पारंपरिक तरीका

वेलिंगटन : न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बांड ने कहा कि उनकी टीम ने जिस तरह से भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का पारंपरिक तरीके से सामना किया उससे दूसरी टीमें सीख लेंगी। बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में एक भी विकेट नहीं ले सके थे। सीरीज में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहने पर बुमराह को आलोचना का सामना करना पड़ा लेकिन बांड ने उनका बचाव किया। बांड ने कहा कि जब आपके पास जसप्रीत बुमराह की तरह का गेंदबाज हो तो जाहिर है उससे काफी उम्मीदें होंगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने उन्हें खतरा माना और उनका सामना सही तरीके से किया। उन्होंने उसका सामना पारंपरिक तरीके से किया। बुमराह के साथ टीम में अनुभवहीन गेंदबाज नवदीव सैनी और शार्दुल ठाकुर थे, जिसका फायदा न्यूजीलैंड को हुआ। उन्होंने कहा कि अब हर टीम उन्हें खतरे की तरह देखेगी और दूसरे गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएंगी। बांड ने हालांकि कहा कि भारतीय टीम वनडे सीरीज 0-3 से हार गई लेकिन बुमराह की गेंदबाजी बुरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप मैच में अच्छा करना चाहते हैं। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन कई बार आपको विकेट नहीं मिलता। आइपीएल में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच के तौर पर बुमराह के साथ समय बिताने वाले बांड ने कहा कि यह भारतीय गेंदबाज दो टेस्ट की आगामी सीरीज में 'काफी प्रभाव' डालेगा।

मनप्रीत सिंह की अगुआई में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत

नई दिल्ली, जेएनएन : विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 और 22 फरवरी को खेले जाने वाले एफआइएच प्रो लीग मुकाबले के लिए हॉकी इंडिया ने मनप्रीत सिंह की अगुआई में मंगलवार को 24 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले के लिए हरमनप्रीत सिंह टीम के उपकप्तान होंगे।

हाल ही में विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंची भारतीय टीम ने एफआइएच प्रो लीग के पिछले मुकाबले में विश्व चैंपियन बेल्जियम को पहले मैच में 2-1 से हराया था जबकि दूसरे मुकाबले में उसे 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। 24 सदस्यीय टीम में गोलकीपर पीआर श्रीजेश और कृष्ण पाठक के अलावा अमित रोहिदास, सुरेंद्र कुमार, बीरेंद्र लकड़ा, हरमनप्रीत सिंह, वरुण कुमार, गुरिंदर सिंह और रूपिंदर पाल सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने कहा कि विश्व चैंपियन के खिलाफ करीबी मुकाबले खेलने के बाद हम एक और मजबूत टीम से भिड़ेंगे। हमने फिर से टीम में मजबूत खिलाड़ियों को जगह दी है जो हमें पूरे मैच में अच्छा संतुलन प्रदान करने के साथ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक का मुकाबला करने में हमारी मदद कर सकते हैं।

भारतीय टीम-पी आर श्रीजेश, केबी पाठक, अमित रोहिदास, सुरेंदर कुमार, बीरेंद, हरमनप्रीत सिंह (उपकप्तान), वरुण कुमार, गुरिंदर, रूपिंदर, मनप्रीत सिह (कप्तान), विवेक, हार्दिक सिंह, चिंगलेनसाना, राज कुमार, आकाशदीप, सुमित, ललित, गुरसाहिबजीत, दिलप्रीत, सुनील, जरमनप्रीत, सिमरनजीत, नीलाकांता शर्मा, रमनदीप सिंह।

27 साल बाद ग्रीको रोमन में स्वर्ण

एशियन कुश्ती चैंपियनशिप

योगेश शर्मा ● नई दिल्ली

भारत का यहां केडी जाधव स्टेडियम में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में आगाज शानदार तरीके से हुआ जब 27 साल के बाद देश को ग्रीको रोमन में स्वर्ण पदक मिला। ग्रीको रोमन में भारत का प्रदर्शन हर टूर्नामेंट में खराब ही रहा है, लेकिन मंगलवार को सुनील कुमार ने इसे बदलते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने 87 किग्रा में फाइनल में किर्गिस्तान के सालिदिनोव को एकतरफा अंदाज में 5-0 से शिकस्त देकर अपने पिछले साल की टीस को पूरा किया। सुनील पिछले साल भी इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। इससे पहले ग्रीको रोमन में 1993 में भारतीय पहलवान पप्पू यादव ने स्वर्ण पदक जीता था।

पलट दी बाजी : इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल में हारी हुई बाजी को भी पलट दिया था। वह कजाखिस्तान के अजामत कुस्तुबायेव के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 1-8 से पिछड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने लगातार 11 अंक बनाकर कर शानदार वापसी की और मुकाबले को 12-8 से अपने नाम किया। उन्होंने रोम रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में भी रजत पदक जीता था।

अर्जुन को मिला कांस्य : इससे पहले भारत के अर्जुन हालाकुर्कि (55 किग्रा) ने कांस्य पदक जीता। यह उनका सीनियर अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पहला पदक है। वहीं, अन्य भारतीय पहलवान मेहर सिंह को अंतिम चार के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कोरिया के मिंसेओक किम ने 9-1 से हराया। दिन के पहले क्वालीफिकेशन बाउट में साजन के हारने से भारतीय उम्मीदों को झटका लगा। साजन को पदक का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन किर्गिस्तान के अंडर-23 एशियाई चैंपियन रेनत इलियाजुलु ने उन्हें 9-6 से हराया। सचिन राणा (63 किग्रा) को एलमरत तस्मुरादोव एकतरफा मुकाबले में 8-0 से हराया। रेपेचेज दौर में भी उन्हें निराशा मिली जहां कजाखिस्तान का यर्नूर फिदाखमेटोव को चुनौती नहीं दे सके और 6-3 से हार गए।

कोरोना के डर से मास्क में दिखे पहलवान

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के संक्रमण का असर भारत में चल रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भी दिख रहा है जहां दूसरे देशों के पहलवानों और अधिकारियों ने मास्क लगा रखे थे लेकिन उनका कहना था कि वे अहतियात के तौर पर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के कारण भारत सरकार ने चीन के खिलाड़ियों को वीजा जारी नहीं किया जिससे वहां के पहलवान इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। कोरियाई टीम के चिकित्सा सदस्य सीयेओन ली ने कहा, 'हमारे दल में 28 खिलाड़ी है और उसमें से कुछ खिलाड़ियों और पहलवानों ने मास्क लगाए हैं। हमें पता है कि यहां वह वायरस नहीं है और यह जगह सुरक्षित है लेकिन फिर भी जोखिम क्यों उठाना।' कुश्ती की विश्व संस्था (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) के डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजर को भी यहां मास्क में देखा गया। उन्होंने कहा, 'यह वायरस एशियाई देशों में फैल रहा है इसलिए मेरा परिवार चिंतित है। हमें पता है कि यहां वायरस नहीं है क्योंकि चीन के खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया है।' कुछ खिलाड़ियों के लिए दिल्ली का वायु प्रदूषण चिंता की बात है। जापान टीम के एक सदस्य ने कहा कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अब भी सही नहीं है।

उपलब्धि प्रशंसकों के समर्थन से तेंदुलकर को सबसे ज्यादा मत मिले, सचिन से जुड़े लम्हे को कैरीड ऑन द शोल्डर्स ऑफ ए नेशन' शीर्षक दिया गया

सचिन को लॉरेस का 'सर्वश्रेष्ठ खेल लम्हे' का पुरस्कार

बर्लिन, प्रेट्र: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 2000 से 2020 तक के लॉरेस सर्वश्रेष्ठ खेल लम्हे के पुरस्कार के लिए चुना गया।

भारतीय प्रशंसकों के समर्थन से तेंदुलकर को इस पुरस्कार के लिए सबसे ज्यादा मत मिले। भारत की 2011 विश्व कप में जीत के संदर्भ में तेंदुलकर से जुड़े लम्हे को 'कैरीड ऑन द शोल्डर्स ऑफ ए नेशन' शीर्षक दिया गया था। टेनिस के महान खिलाड़ी बोरिस बेकर ने इस पुरस्कार की घोषणा की जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर स्टीव वॉ ने तेंदुलकर को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। लगभग नौ साल पहले तेंदुलकर अपने छठे विश्व कप में खेलते हुए विश्व खिताब जीतने वाली टीम के सदस्य बने थे।

भारतीय टीम के सदस्यों ने इसके बाद तेंदुलकर को कंधे में उठाकर मैदान का 'लैप ऑफ ऑनर' दिया था और इस दौरान इस दिग्गज बल्लेबाज की आंखों से आंसू निकल रहे थे। भारत ने विश्व कप फाइनल में जीत तेंदुलकर के घरेलू मैदान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दर्ज की थी। पुरस्कार के लिए सूची में पहले 20 दावेदारों को शामिल किया गया था लेकिन वोटिंग के बाद सिर्फ पांच दावेदारों को सूची में जगह मिली थी जिसमें तेंदुलकर विजेता बने।

ट्रॉफी लेने के बाद तेंदुलकर ने कहा, 'यह शानदार है। विश्व कप जीतने की भावना को शब्दों में बयान करना संभव नहीं था। यह कितनी बार होता होगा जब किसी प्रतिक्रिया में लोगों की भावनाएं मिलीजुली न होती हों। ऐसा तो बहुत ही कम होता है जब पूरा देश जश्न मनाता हो। यह इस बात की भी याद दिलाता है कि खेल कितना सशक्त माध्यम है और यह हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाता है। अब भी मैं उस लम्हे के बारे में सोचता हूं और वही अहसास होता है।'

तेंदुलकर के ट्रॉफी हासिल करने के बाद बेकर ने उनसे अपनी भावनाओं को साझा करने को कहा तो इस भारतीय खिलाड़ी ने कहा, 'मेरी यात्रा (क्रिकेट) की शुरुआत तब हुई थी जब मैं 10 साल का था। भारत ने विश्व कप जीता था। मुझे उस समय उसके महत्व के बारे में पता नहीं था। चूंकि हर कोई जश्न मना रहा था तो मैं भी उस में शामिल हो गया। लेकिन कहीं न कहीं मुझे पता था कि देश के लिए कुछ अच्छा हुआ है और मैं भी एक दिन इसका अनुभव करना चाहता था और यहीं से मेरा सफर शुरू हुआ। यह (विश्व कप जीतना) मेरी जिंदगी का सबसे गौरवान्वित करने वाला पल था। मैंने 22 साल तक इसका पीछा किया लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारा। मैं सिर्फ अपने देश की तरफ से ट्रॉफी उठा रहा था।'

मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि लॉरेस ट्रॉफी हासिल करना मेरे लिए बेहद ही सम्मान की बात है। इस मौके पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के आंदोलनकारी नेता और पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के प्रभाव को भी साझा किया। तेंदुलकर जब मंडेला से मिले थे तब इस क्रिकेटर की उम्र केवल 19 साल थी। उन्होंने कहा, 'उनके द्वारा दिए गए कई संदेशों में से मुझे सबसे महत्वपूर्ण यह लगा कि खेल में सभी को एकजुट करने की शक्ति है।'

बर्लिन में आयोजित हुए लॉरेस स्पोर्ट्स अवॉर्ड में खेल के बेहतरीन लम्हे का पुरस्कार जीतने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ● एएफपी

मेसी और हैमिल्टन बने लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर

बर्लिन, प्रेट्र : ब्रिटिश एफ वन रेसर लुइस हैमिल्टन और विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में से एक लियोन मेसी को सोमवार को संयुक्त रूप से लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। दोनों ही खिलाड़ियों को समान वोट मिले। इन पुरस्कारों के 20 वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। ज्यूरी मेसी और हैमिल्टन में से किसी एक को स्पष्ट विजेता तय नहीं कर पाई। छह बार के फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेसी यह पुरस्कार पाने वाले पहले टीम खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही वह दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स, कीनिया के मैराथन एथलीट एलिंड किपचोगे, टेनिस दिग्गज राफेल नडाल और मोटोजीपी चैंपियन मार्क मार्केज को पछाड़कर इस पुरस्कार के हकदार बने।

प्रतिष्ठित लॉरेस सर्वश्रेष्ठ खेल लम्हे का पुरस्कार जीतने के लिए सचिन पाजी को बधाई। हमारे राष्ट्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि और गर्व का क्षण। – **विराट कोहली,** कप्तान, भारत

पूर्व नंबर एक क्लाइस्टर्स की निराशाजनक वापसी

बीजिंग, आइएएनएस : चार बार की ग्रैंडस्लैम विजेता बेल्जियम की किम क्लाइस्टर्स की टेनिस में वापसी निराशाजनक रही और उन्हें मंगलवार को यहां दुबई चैंपियनशिप में पहले ही मैच में स्पेन की गरबाइन मुगुरुजा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। पूर्व विश्व नंबर-1 क्लाइस्टर्स ने 2012 में टेनिस से संन्यास ले लिया था। उन्होंने अब वापसी की है और उन्हें पहले राउंड में ही मुगरुजा के खिलाफ 2-6, 6-7 से हार गई।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज में जोस बटलर का फॉर्म में लौटना उनके टेस्ट करियर के लिए अच्छा है। - **क्रिस सिल्वरवुड, इंग्लैंड के कोच**

नवी मुंबई में होगा फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप फाइनल

फुटबॉल डायरी ▶ दो नवंबर से गुवाहाटी से होगी टूर्नामेंट की शुरुआत, टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेंगी और 32 मैच खेले जाएंगे

ग्रुप चरण के मैच अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और कोलकाता में खेले जाएंगे

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

भारत में पहली बार होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का फाइनल 21 नवंबर को नवी मुंबई में होगा। आयोजन समिति ने मंगलवार को यहां घोषणा की।

इस प्रतियोगिता के मैच देश के पांच शहरों अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत दो नवंबर से गुवाहाटी से होगी। क्वार्टर फाइनल मुकाबले 12 और 13 नवंबर जबकि सेमीफाइनल 17 नवंबर को होंगे। टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेंगी और इस दौरान कुल 32 मैच खेले जाएंगे। इस अवसर पर खेल मंत्री किरन रिजिजू ने कहा, 'भारत जबकि एक अन्य फीफा प्रतियोगिता की मेजबानी की तैयारियों में जुटा है, मैं इसकी शानदार सफलता के लिए सारे देशवासियों से समर्थन की अपील करता हूं। हमारी भारतीय अंडर-17 महिला टीम पहली बार फीफा टूर्नामेंट में खेल रही है।' ग्रुप चरण के मैच चार शहरों अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और कोलकाता में खेले जाएंगे। इस दौरान टूर्नामेंट का आधिकारिक स्लोगन किक ऑफ द ड्रीम का भी अनावरण किया गया है। वहीं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) और स्थानीय आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा, 'इस टूर्नामेंट के बाद हमारी नजरें अंडर-20 विश्व कप और क्लब विश्व कप पर लगी हुई हैं। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का ड्रॉ सितंबर में निकाला जा सकता है।'

फीफा अंडर-17 विश्व कप कार्यक्रम के दौरान (बायें से) एएफआइ अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, खेल मंत्री किरन रिजिजू, सारांई बैरमैन और रॉबर्टो ग्रासी। एएनआइ

एआइएफएफ को एएफसी की ब्रांज लेवल सदस्यता मिली : एआइएफएफ को एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) की 'ग्रासरूट चार्टर ब्रांज लेवल' सदस्यता मिली है जिससे यह राष्ट्रीय महासंघ अपनी आधारभूत प्रतियोगिताओं को एएफसी से मान्यता प्राप्त के रूप में बढ़ावा दे सकता है। एएफसी ग्रासरूट चार्टर की शर्तों के अनुसार, अब एआइएफएफ अपनी जमीनी स्तर की प्रतियोगिताओं और गतिविधियों को एएफसी के सहयोग और मान्यता प्राप्त के रूप में बढ़ावा दे सकता है।

मैनचेस्टर युनाइटेड ने चेल्सी को हराया

लंदन, रायटर : मैनचेस्टर युनाइटेड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) के मैच में चेल्सी को 2-0 से हरा दिया। यह मुकाबला 2-2 से ड्रॉ हो सकता था, लेकिन चेल्सी द्वारा किए गए दो गोल वार के कारण खारिज कर दिए गए और चेल्सी को स्टेमफोर्ड ब्रिज स्टेडियम में हार मिली। चेल्सी के मैनेजर फ्रैंक लैंपार्ड अपने कोचिंग दिनों के सबसे बुरे समय से गुजर रहे हैं। अपने गोलकीपर केपा अरिजावालागा को बेंच पर बिठाना भी उनके लिए कारगरा साबित नहीं हुआ और इस हार ने उनकी टीम को एक नए निचले स्तर पर पहुंचा दिया।

दोनों टीमों की तरफ से एक जोरदार मुकाबला देखने को नहीं मिला जबकि मैच में वार और खराब अंपायरिंग भी इस मैच में चर्चा का विषय रही। मैनचेस्टर युनाइटेड ने कुछ गलतियां की। इसके बावजूद वे गोल करने में सफल रहे लेकिन इसके लिए उसे पहले हाफ के अंत का इंतजार करना पड़ा। फ्रांस के एंथोनी मार्टियल ने 45वें मिनट में शानदार गोल करते हुए अपनी टीम का खाता खोल दिया। एरॉन वान बिसाका ने मार्टियल को शानदार क्रॉस दिया। मार्टियल ने डिफेंडर आंद्रेस क्रिस्टेनसेन को छकाते हुए अपने हेडर से गेंद को नेट में डाल अपनी टीम का खाता खोला। ब्रेक के बाद चेल्सी के डिफेंडर कुर्ट जाउमा ने बराबरी का गोल कर दिया था लेकिन वार ने इस गोल को नकार दिया। चेल्सी के लिए दूसरी बुरी खबर तब आई जब 66वें मिनट में हैरी मेगयुइरे ने कॉर्नर किक पर हेडर से गोल कर दिया। मैच में यहां से भी काफी समय बचा था लेकिन इस दौरान भी सिर्फ मेजबान टीम को निराशा ही मिली। 77वें मिनट में एक बार फिर लंदन स्थित क्लब ने गोल कर दिया था लेकिन वार ने इसे ऑफ साइड करार दे दिया। इस जीत के साथ मैनचेस्टर युनाइटेड ने 38 अंकों के साथ सातवां स्थान हासिल किया और वह अब चौथे स्थान पर मौजूद चेल्सी से तीन अंक पीछे है।

बावुमा ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले टी-20 मैच से बाहर

जोहानिसबर्ग, आइएएनएस : दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज टेम्बा बावुमा हार्मस्ट्रिंग चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले पहले टी-20 मैच से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने मंगलवार को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर बताया कि बावुमा को रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे और अंतिम टी-20 मैच में फील्डिंग करते समय चोट लग गई थी। इस चोट से उबरने में अब उन्हें सात से 10 दिन तक का समय लगेगा। सीएसए ने बताया कि बावुमा टीम के साथ बने रहेंगे और इस दौरान उनका उपचार जारी रहेगा, ताकि वह रविवार के पोर्ट एलिजाबेथ में रविवार को होने वाले दूसरे टी-20 मैच में टीम में लौट सके। टीम प्रबंधन ने फिलहाल उनके स्थान पर किसी और खिलाड़ी के नाम की घोषणा नहीं की है। दक्षिण अफ्रीका को 21, 23 और 26 फरवरी को जोहानिसबर्ग, पोर्ट एलिजाबेथ और केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलनी है।

दक्षिण अफ्रीका टी-20 टीम : क्विंटन डिकॉक (कप्तान व विकेटकीपर), डुप्लेसिस, डुसेन, मिलर, बिल्जोन, प्रिटोरियस, फेलुकवायो, स्मट्स, रबादा, शम्सी, नगिदी, फोर्टुइन, नॉर्त्जे, स्टेन।

वार्नर, स्मिथ ने इंग्लैंड में किया अभ्यास : लैंगर

मेलबर्न, आइएएनएस : ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर का मानना है जब बीते साल उनकी टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया था तभी दक्षिण अफ्रीका दौरे का अभ्यास कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। टीम के 2018 के विवादास्पद दौरे के बाद से पहली बार है जब दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है। बीते दौरे पर स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरून बैनक्राफ्ट को गेंद से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाया गया था और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इन तीनों को प्रतिबंधित कर दिया था।

2019 में इंग्लैंड में खेले गए विश्व कप और इसके बाद के एशेज सीरीज में स्मिथ और वार्नर को दर्शकों की बेरुखी का सामना करना पड़ा था। लैंगर ने कहा कि जब वे दोनों टीम में वापस आए थे तो तब टीम का शानदार तरीके से पुर्नगठन हुआ था। जब बहुत अच्छा काम किया गया था और इंग्लैंड में अपने दक्षिण अफ्रीका दौरे का अच्छा अभ्यास किया था। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के लिए वह मुश्किल दौरा रहा था और जिस तरह से दोनों ने अपने बल्ले से जवाब दिया था उस पर मुझे गर्व है।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कोच जस्टिन लैंगर। फाइल फोटो, एपी

महिला विश्व कप

भारतीय महिलाओं ने वेस्टइंडीज को हराया

ब्रिसबेन, प्रेट्र : स्पिनर पूनम यादव के तीन विकेट से भारत ने आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप के अभ्यास मैच में मंगलवार को यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ दो रन से जीत दर्ज की।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय महिला टीम निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर सिर्फ 107 रन का मामूली स्कोर बनाया। जीत के लिए 108 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 105 रन ही बना सकी। पूनम ने चार ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट लिए। वेस्टइंडीज की टीम 13 ओवर में एक विकेट पर 57 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी। दीप्ति शर्मा ने जैसे ही सलामी बल्लेबाज ली-एन किर्बी (42) को आउट किया, वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ा गई। इसके तुरंत बाद कप्तान स्टेफनी टेलर (16), चेडिन नेशन (00) और डिएंड्रा डोटिन (01) भी पवेलियन लौट गए जिससे टीम का स्कोर 17वें ओवर में पांच विकेट पर 67 रन हो गया।

विकेट लेने के बाद जश्न मनाती भारतीय स्पिनर पूनम यादव (दायें)। फाइल फोटो, प्रेट्र

हेली मैथ्यूज (25) और चिनले हेनरी (17) ने 19वें ओवर में तीन चौके और एक छक्का जड़ा जिसके बाद वेस्टइंडीज को जीत के लिए अंतिम छह गेंदों पर 11 रन बनाने थे। हेनरी ने पूनम की गेंद पर चौका मारा लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर मैथ्यूज आउट हो गईं। आखिरी गेंद पर जीत के लिए तीन रन की जरूरत थी लेकिन हेनरी वेदा कृष्णमूर्ति को कैच थमा बैठीं। इससे पहले भारत का शीर्ष क्रम भी लड़खड़ा गया। टीम ने चौथे ओवर की पहली गेंद तक 17 रन तक तीन विकेट गंवा दिए। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (04) छह गेंद ही खेल सकीं जबकि जेमिमाह रोड्रिगज खाता खोलने में नाकाम रहीं। युवा शेफाली वर्मा भी दो चौके लगाकर शामिलिया कोन्नेल की गेंद पर आउट हो गईं। कप्तान हरमनप्रीत कौर (11) और वेदा (05) भी प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहीं।

विविध

उप्र के शॉपिंग मॉल में सरकार की मर्जी से रखे जाएंगे कर्मी

गुरुदीप त्रिपाठी, प्रयागराज

- प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन कर सेवायोजन कार्यालय देगा कर्मचारी
- न्यूनतम वेतन निर्धारण होगा, शो रूम संचालकों की रुकेगी मनमर्जी

उप्र में शॉपिंग मॉल के शोरूम एवं मल्टीप्लेक्स में काम करने वाले कर्मचारियों को मनमर्जी से पैसा देकर काम लेने की व्यवस्था पर विराम लगने वाला है। सरकार इन कर्मचारियों पर भी न्यूनतम वेतनमान निर्धारण लागू करने जा रही है। इस तरह शोरूमों के लिए योग्य कर्मचारियों की तैनाती सेवायोजन कार्यालय से की जाएगी। इसके लिए क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेला लगाया जाएगा।

इस व्यवस्था से कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन का पालन हो सकेगा और शोरूम संचालकों को कर्मचारियों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। जिन्हें नौकरी दी जाएगी, उन्हें नियम के मुताबिक न्यूनतम 8067 रुपये से कम पर न रखा जाएगा। प्रदेश सरकार की योजना है कि अब यदि प्रदेशभर के शोरूमों के लिए कर्मचारियों की जरूरत होगी तो रिक्तियों का ब्योरा क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद रोजगार मेला लगाकर शोरूम संचालक कर्मचरियों को तलाशेंगे। तीन श्रेणियों (अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल) वर्ग में कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन भी संचालकों को देना होगा।

अप्रैल में जारी हो सकता है निर्देश

सूत्रों की मानें तो श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मंत्रालय की ओर से प्रदेश के सभी सेवायोजन कार्यालय को अप्रैल में निर्देश जारी किया जा सकता है।

अभी शासन से लिखित में ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है। हालांकि, तैयारी चल रही है कि मॉल के शोरूम में सरकार की मर्जी से कर्मचारियों को रखा जाए। इससे मॉल के शोरूम व मल्टीप्लेक्स के संचालकों के साथ ही बेरोजगारों को भी सहूलियत होगी।

- रत्नाकर अस्थाना, सहायक निदेशक सेवायोजन, प्रयागराज।

एजेंटों पर कार्रवाई का असर, यात्रियों को अब और मिल सकेंगे तत्काल टिकट

नई दिल्ली, प्रेट्र : अब यात्रियों के लिए और तत्काल टिकट उपलब्ध रह सकते हैं। रेलवे ने तत्काल टिकट की राह में रोड़ा साबित हो रहे गैरकानूनी साफ्टवेयर को नष्ट कर दिया है और 60 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। ये एजेंट ही तत्काल टिकटों को ब्लॉक करने के लिए गैरकानूनी साफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे। एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा कि गैरकानूनी साफ्टवेयर उन्मूलन अभियान का मतलब यह है कि पहले की तुलना में अब यात्रियों के लिए और तत्काल टिकट उपलब्ध रह सकेंगे। पहले बुकिंग शुरू होने के एक या दो मिनट के भीतर ही किसी यात्री को तत्काल टिकट मिल पाता था।

कौन-कौन से साफ्टवेयर कर रहे थे गैरकानूनी काम : अधिकारी ने स्पष्ट किया कि एएनएमएस, एमएसी और जगुआर जैसे साफ्टवेयर टिकट बनाने के लिए आइआरसीटीसी के लॉगइन कैप्चा, बुकिंग कैप्चा और बैंक ओटीपी को बायपास कर सकते हैं। एक वास्तविक यूजर को इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है। सामान्य यूजर को बुकिंग प्रक्रिया में करीब 2.55 मिनट लगते हैं, लेकिन जो इस साफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वह 1.48 मिनट के आसपास में ही टिकट बना सकते हैं। रेलवे एजेंटों को तत्काल टिकट बुक करने की इजाजत नहीं देता है और पिछले दो महीनों में आरपीएफ ने करीब 60 गैरकानूनी एजेंटों को दबोचा है। ये एजेंट साफ्टवेयर के माध्यम से तत्काल टिकट बुक कर रहे थे जिससे दूसरों के लिए इन्हें (तत्काल टिकट) लेना असंभव साबित हो रहा था।

वंदे भारत एक्सप्रेस का रद नहीं हुआ कोई फेरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत की पहली स्वदेशी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने परिचालन का एक साल पूरा कर लिया है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने वंदे भारत के एक साल के सफर को शानदार बताया है। रेलवे का दावा है कि एक साल में इस ट्रेन का एक भी फेरा रद नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 फरवरी को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ किया था। इसके बाद 17 फरवरी 2019 से इस ट्रेन की वाणिज्यिक सेवा शुरू हुई थी। इस ट्रेन से नई दिल्ली से वाराणसी का सफर आठ घंटे में पूरा किया जा सकता है। सोमवार व बृहस्पतिवार को छोड़कर यह ट्रेन सप्ताह में पांच दिन चलती है। इसके परिचालन का एक साल पूरा होने पर 17 फरवरी को रेलवे के अधिकारियों ने इस ट्रेन में सवार यात्रियों का स्वागत किया और सुविधाओं पर उनसे सुझाव भी लिए। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन नई दिल्ली- श्री वैष्णो देवी कटड़ा स्टेशन के बीच होता है।

- भारत की पहली स्वदेशी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन का एक साल पूरा

महाराष्ट्र में एक और बैंक घोटाला, 76 नामजद

- कर्नाला नागरी सहकारी बैंक में 512.54 करोड़ रुपये की अनियमितता सामने आई

ठाणे, प्रेट्र : पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले के बाद महाराष्ट्र में एक और बैंक घोटाला सामने आया है। नया मामला कर्नाला नागरी सहकारी बैंक में 512.54 करोड़ रुपये की अनियमितता से जुड़ा है। इसमें पूर्व विधायक समेत 76 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बैंक का मुख्यालय रायगढ़ जिले के पनवेल में है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

नवी मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पनवेल के पूर्व पीडब्ल्यूपी विधायक विवेकानंद शंकर पाटिल सरकारी बैंक के चेयरमैन हैं। रिपोर्ट में पाटिल के साथ-साथ बैंक के वाइस चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) समेत अन्य को नामजद किया गया है। इन सभी आरोपितों ने बैंक से कर्ज ले रखा है।

पुलिस की तरफ से जारी बयान के अनुसार, 'आरोपितों के खिलाफ विश्वासघात, धोखाधड़ी के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की विभिन्न धाराओं, सहकारी समिति कानून और महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।' इस अनियमिता का पर्दाफाश भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की तरफ से सहकारी बैंक की 17 शाखाओं में किए गए विशेष ऑडिट में हुआ। मामले की रिपोर्ट राज्य के सहकारी आयुक्त की शिकायत पर दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक उसकी स्थापना वर्ष 1996 में सहकारी बैंक कानून के तहत की गई थी। विवेकानंद पाटिल को बैंक की स्थापना के लिए आरबीआइ ने लाइसेंस प्रदान किया था।

उल्लेखनीय है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में करीब साढ़े छह हजार करोड़ रुपये का घोटाला प्रकाश में आने के बाद हड़कंप मच गया था। इस मामले में बैंक अधिकारियों व रियल एस्टेट कंपनी एचडीआइएल के प्रवर्तकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इनमें से कई की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।

कर्नाला नागरी सहकारी बैंक फाइल फोटो

'पंजाबी फिल्म 'शूटर' पर पाबंदी लगाने पर विचार करे केंद्र'

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- पंजाब सरकार पहले ही लगा चुकी है फिल्म पर रोक
- गैंगस्टर सुक्खा काहलवां की जिंदगी पर आधारित है फिल्म

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा है कि वह पंजाबी फिल्म 'शूटर' पर पाबंदी लगाने पर विचार करे। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार पहले ही राज्य में फिल्म पर रोक लगा चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से वकील धीरज जैन ने कहा, केंद्र या उसकी किसी भी अथॉरिटी ने फिल्म के सार्वजनिक तौर पर दिखाने के लिए कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है।

कोर्ट ने याची को कहा, वो इस याचिका की एक कॉपी केंद्र सरकार को दे। केंद्र सरकार याचिका को मांग पत्र मान कर उस पर कार्रवाई करे। कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी इस मामले में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि फिल्म गैंगस्टर सुक्खा काहलवां की जिंदगी पर आधारित है। काहलवां पर तीन दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इस फिल्म में हिंसा के साथ गन कल्चर को बढ़ावा दिया गया है। यह फिल्म हाई कोर्ट के 22 जुलाई, 2019 के उस आदेश के विपरीत है, जिसमें ऐसी किसी भी फिल्म, गाने आदि को नहीं चलने देने का निर्देश था, जो अपराध, हिंसा या गैंगस्टर बनने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला हो।

फिल्म 21 फरवरी को रिलीज हो रही है। इस लिए इस पर रोक जरूरी है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिल्म के एक प्रोड्यूसर केवी ढिल्लों के खिलाफ एक्शन लेने के भी आदेश दिए हैं। दरअसल, केवी ढिल्लों ने साल 2019 में लिखित में दिया था कि वे इस फिल्म को बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद पंजाब सरकार ने एक्शन लिया।

पंजाब और हरियाणा के मामलों की यहीं होती है सुनवाई। फाइल फोटो

अमिताभ का पहली बार मेकअप करने वाले पंढरी दादा का निधन

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

हिंदी सिनेमा में कई सितारों का मेकअप करने वाले मेकअप आर्टिस्ट पंढरी जुकर का निधन हो गया। पंढरी दादा के नाम से मशहूर 88 वर्षीय आर्टिस्ट लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने दिलीप कुमार, मीना कुमारी, नरगिस से लेकर शाह रुख खान और करीना कपूर खान जैसे कलाकारों का भी मेकअप किया था। पंढरी दादा ने ही अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में उनका मेकअप किया था। उनके निधन पर अमिताभ, जूही चावला, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोईराला, अभिषेक बच्चन जैसी कई फिल्मी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शोक जताया है।

यश चोपड़ा के साथ पंढरी जुकर ने लगभग 42 साल तक काम किया था। पंढरी दादा ने दीवार, त्रिशूल, क्रांति, डर और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों में मेकअप का कार्यभार संभाला था। आखिरी बार उन्होंने साल 2009 में रिलीज हुई मराठी फिल्म रीता में काम किया था।

फिल्मी हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि : अमिताभ ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पंढरी दादा नहीं रहे। उनको श्रद्धांजलि। फिल्म इंडस्ट्री के अग्रणी मेकअप कलाकार, जिन्होंने आज के कई मेकअप कलाकारों को प्रशिक्षित किया। शानदार, पेशेवर और आकर्षक व्यक्तित्व। मेरा पहला मेकअप उन्होंने ही किया था।' मनीषा कोईराला ने लिखा, 'मेरा पहला मेकअप पंढरी दादा ने किया था, सभी उनकी प्रशंसा और सम्मान करते थे। उनके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। हम आपको याद करेंगे दादा।'

मौसम विशेष

च. ह - चक्रवाती हवा का क्षेत्र, प. वि - पश्चिमी विक्षोभ

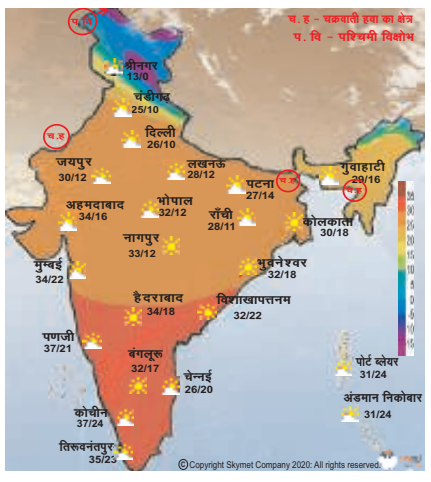

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा और बर्फबारी होगी। दिन के तापमान में गिरावट आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में मध्यम गति की हवाएं प्रभावित करेंगी। रात के तापमान में हल्की वृद्धि होगी तथा शुष्क मौसम जारी रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/21/आंवा	अहमदाबाद	36/16/स
कोलकाता	31/19/आंवा	बड़ौदा	36/14/स
चेन्नई	32/21/व	नागपुर	34/13/आंवा
हैदराबाद	35/19/आंवा	इन्दौर	32/13/आंवा
बंगलूरू	33/17/व	रांची	30/11/स
त्रिवेन्द्रम	35/23/आंवा	पटना	28/15/व
गुवाहाटी	29/17/स	जमशेदपुर	31/14/स
जंगटोक	13/08/स	पुणे	34/19/स

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

16

बुधवार 19 फरवरी 2020

www.jagran.com

कंप्यूटरीकृत रेलवे टिकट आरक्षण प्रणाली की शुरुआत

आज ही के दिन देश में पहली बार 1986 में कंप्यूटरीकृत रेलवे टिकट आरक्षण प्रणाली की शुरुआत हुई। उत्तर रेलवे शुरुआत करने वाला पहला जोन था। उस वक्त रेल यात्री बुकिंग काउंटर से तीन दिन पहले अनारक्षित टिकट खरीद सकते थे।

सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति बने पैड्रो

आज ही के दिन 1913 में पैड्रो लेसकुरेन करीब 45 मिनट के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति बने। दुनिया के इतिहास में वे किसी भी देश के सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति बनने वाले शख्स थे। वे मैक्सिको के 34वें राष्ट्रपति थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर

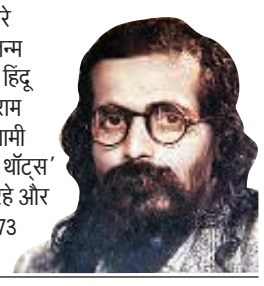

आज ही 1906 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर का जन्म नागपुर के रामटेक में हुआ था। 1927 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी की। संघ संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार से 1932 में मुलाकात हुई। रामकृष्ण मिशन के स्वामी अखंडानंद की सेवा में दो साल बिताए। 1966 में 'बंच ऑफ थॉट्स' पुस्तक आई। 1940 से 1973 तक संघ के सरसंघचालक रहे और इसे संस्थागत शक्ति बनाने में बड़ा योगदान रहा। 5 जून 1973 को नागपुर में निधन हो गया।

जलवायु परिवर्तन से जंग को 10 अरब डॉलर देंगे बेजोस

वाशिंगटन, एएफपी : दुनिया के सबसे अमीर शख्स और ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 10 अरब डॉलर (71 हजार 419 करोड़ रुपये) दान करने का एलान किया है। यह रकम उनकी कुल संपत्ति का 7.7 फीसद है। जेफ बेजोस की कुल संपत्ति करीब 130 अरब डॉलर (नौ लाख 28 हजार 444 करोड़ रुपये) है।

सोमवार को इंस्टाग्राम पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे बेजोस अर्थ फंड की शुरुआत करेंगे। पोस्ट में लिखा, 'जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए जलवायु परिवर्तन से जंग के वास्ते मैं अभी तक के ज्ञात तरीकों और इससे निपटने के नए तरीकों के लिए काम करने का इच्छुक हूं। पृथ्वी को बचाने के लिए शुरू की जाने वाली यह पहल जलवायु वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों को फंड मुहैया कराएगी। हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। इस पहल से बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, विभिन्न देश, वैश्विक संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर सभी एकजुट होंगे।' बता दें कि इंस्टाग्राम पर बेजोस के 14 लाख फॉलोअर हैं।

अमेजन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस की फाइल फोटो। एएफपी

- दुनिया के सबसे अमीर शख्स व अमेजन के संस्थापक ने अर्थ फंड शुरू करने का किया एलान
- वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एनजीओ को उपलब्ध कराएंगे फंड

कंपनी के कर्मचारियों ने चलाया था ऑनलाइन अभियान : पिछले महीने अमेजन के सैकड़ों कर्मचारियों ने ऑनलाइन अभियान चलाकर कंपनी पर जलवायु परिवर्तन से निपटने का दबाव बनाया था। उनका कहना था कि कंपनी की होम डिलीवरी स्कीम के चलते बड़ी मात्रा में कचरा पैदा होता है। साथ ही इस दौरान जिन वाहनों से डिलीवरी की जाती है, उनसे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। सितंबर 2019 में जेफ बेजोस ने साल 2040 तक कंपनी को कार्बन न्यूट्रल और साल 2030 तक 100 फीसदी नवीकरणीय ऊर्जा और 2030 तक एक लाख इलेक्ट्रिक वाहन की डिलीवरी करने की भी घोषणा की थी।

अपनी पूरी संपत्ति दान करने का एलान कर चुके हैं वॉरेन बफे

वॉरेन बफे फाइल फोटो

दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स और बर्कशायर हैथवे के सीईओ और चेयरमैन वॉरेन बफे ने 2006 में अपनी पूरी संपत्ति यानी 36 अरब डॉलर (ढाई लाख करोड़ से ज्यादा) दान करने का एलान किया था। जबकि वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वाल्टन की दिवंगत पत्नी हेलन वाल्टन ने 2007 में 16.4 अरब डॉलर (एक लाख पंद्रह हजार करोड़ रुपये) दान करने का एलान किया था।

दौलत से नहीं, व्यायाम से मिलती असली खुशी

वाशिंगटन, एएनआइ : धन या दौलत नहीं बल्कि शारीरिक व्यायाम व्यक्ति को अधिक खुश रखता है। 'द हिल' जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में इस बात का दावा किया गया है। ऑक्सफोर्ड और येल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग नियमित शारीरिक व्यायाम करते हैं वे अधिक खुश रहते हैं। शोधकर्ताओं ने 12 लाख लोगों पर सर्वेक्षण कर इसका अध्ययन किया है। इस अध्ययन को मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन में बताया गया कि जो लोग कुछ सक्रिय थे उनका एक साल में करीब 35 दिन मानसिक स्वास्थ्य खराब स्थिति में रहा। वहीं, जो लोग सक्रिय नहीं थे उनका एक साल में 53 दिन मानसिक स्वास्थ्य खराब स्थिति में रहा। अध्ययन में यह सामने आया कि धन का व्यक्ति की खुशी पर कम प्रभाव पड़ता है। बताया गया कि एक व्यायाम न करने वाले को व्यायाम करने वाले व्यक्ति जैसी खुशी हासिल करने के लिए अतिरिक्त 25000 डॉलर (18 लाख रुपये) खर्च करने होते हैं।

अंतिम सांस ले रहा सूर्य से 900 गुना बड़ा तारा बीटल्ज

रमेश चंद्रा, नैनीताल

स्पेक्ट्रम

- पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर कभी भी हो सकता है महाविस्फोट
- सूर्य से करीब 19 गुना भारी और 900 गुना बड़ा है यह तारा

आकाशगंगा का विशाल तारा बीटल्ज अंतिम सांस ले रहा है। पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर इस तारे में कभी भी महाविस्फोट हो सकता है। इसके बाद यह ब्लैकहोल या न्यूट्रान स्टार में तब्दील हो सकता है। पांच माह के अंतराल में तारे की चमक में 25 फीसद कमी आई है।

भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिक रिटायर्ड प्रो. आरसी कपूर के अनुसार यह मृग तारा समूह का है। सूर्य से करीब 19 गुना भारी और 900 गुना बड़ा है। इस तारे का भारतीय नाम आद्रा नक्षत्र है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके आकार बढ़ने का सिलसिला लगभग 40 हजार साल पहले शुरू हो चुका था, जो अब विशाल आकार ले चुका है। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी की वेरी लार्ज टेलीस्कोप इस पर नजर रखे हुए है। इसकी अंतिम अवस्था को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि विस्फोट के बाद आकाश में यह सूर्य व चंद्रमा के बाद तीसरे नंबर का चमकता हुआ दिखाई देगा। इसकी चमक लंबे समय तक नजर आती रहेगी। इस दुर्लभ खगोलीय घटना को लेकर वैज्ञानिक रोमांचित हैं। इसके विस्फोट को लेकर समय का आंकलन अभी नहीं हो सका है। किसी विशाल तारे में इस तरह का महाविस्फोट इससे पूर्व 1604 में हुआ था। इस तारे के बारे में वैज्ञानिकों को 1836 में पता चला था। तभी से इस पर नजर रखी जा रही है।

प्रतीकात्मक

सूर्य से 20 से 30 गुना बड़े होते हैं ये तारे : आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के खगोल वैज्ञानिक डॉ. शशिभूषण पांडे का कहना है कि दूसरी आकाशगंगाओं में बड़े तारों में विस्फोट होते रहते हैं। इस तरह के तारे सूर्य से 20 से 30 गुना बड़े होते हैं।

इधर-उधर की

10 साल तक फ्रिज में रखी स्नोबॉल

लंदन, एजेंसी : इंटरनेट के जरिए आप घर बैठे कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं।

हालांकि कुछ लोग ऐसी-ऐसी चीजें बेच रहे हैं, जिनके बारे में सुनकर आपको लगेगा कि यह वस्तु किसी के क्या काम आ सकती है। एक शख्स ईबे पर स्नोबॉल बेच रहा है। दावा है कि स्नोबॉल आम नहीं है, बल्कि उसने इसे दस सालों तक अपने फ्रिजर में रखा था। ब्रिटेन के ससेक्स के रहने वाले 43 साल के ली खुद भी आश्चर्यचकित थे कि दस सालों तक यह कैसे सुरक्षित रहा। ली के पिता ने बताया था कि एक शख्स ने 15 हजार पौंड (करीब 14 लाख रुपये) में 10 साल तक सुरक्षित रखे स्नोबॉल को बेचा था। ली का कहना है कि वे इतनी राशि मिलने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। फिलहाल 3.2 पौंड (298 रुपये) की बोली लगी है और वह इसके बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। दस साल पहले ली अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ बाहर गए थे और तब ही उन्होंने इस बारे में सोचा।

बैक्टीरिया से उत्पन्न होगी बिजली

तकनीक ▶ शोधकर्ताओं ने 'एयर-जेन' नामक डिवाइस विकसित की

बिना प्रदूषण के पैदा होगी बिजली, स्वच्छ ऊर्जा का एक और साधन

बोस्टन, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने एक नया उपकरण विकसित किया है जो प्राकृतिक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न प्रोटीन का प्रयोग करके हवा में मौजूद नमी से बिजली का निर्माण करता है। वैज्ञानिकों ने इसे अक्षय ऊर्जा का एक और साधन बताया है जो सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत घर के अंदर भी बिजली उत्पन्न कर सकता है।

नेचर जर्नल में वर्णित डिवाइस को 'एयर-जेन' या वायु संचालित जेनेरेटर कहा जाता है। इस डिवाइस को सूक्ष्मजीव जियोबैक्टर द्वारा बनाई गई अत्यंत छोटी विद्युत प्रवाहकीय प्रोटीन तारों द्वारा बनाया गया है। सूक्ष्मजीव जियोबैक्टर को 30 साल पहले अमेरिका की पोटोमैक नदी के दलदल में खोजा गया था।

अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार एयर-जेन इलेक्ट्रोड को छोटे प्रोटीन तारों से इस तरह से जोड़ता है कि यह वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से मौजूद जलवाष्प से विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। इस अध्ययन के सह लेखक जून याओ ने बताया कि एयर-जेन 24 घंटे स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। यह डिवाइस नवीकरणीय, कम लागत वाली है और बड़ी बात यह है कि इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं पैदा होता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह डिवाइस सहारा रेगिस्तान जैसे अत्यंत कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में भी बिजली पैदा कर सकती है। अध्ययन के दूसरे सह लेखक डेरेक लवली ने कहा, 'अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने की यह विधि सौर और पवन ऊर्जा से बहुत बेहतर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल घर के अंदर भी किया जा सकता है।'

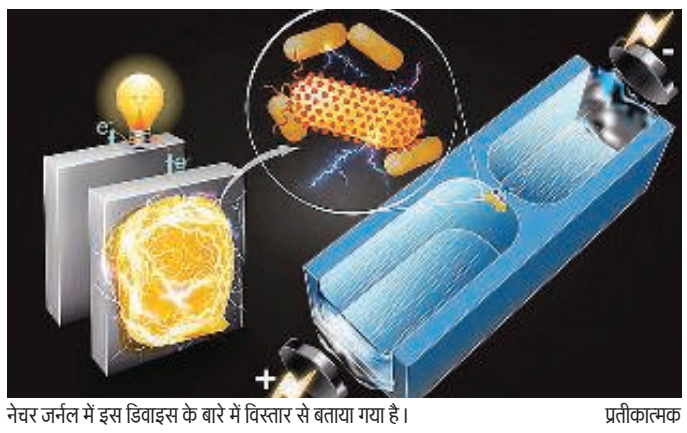

नेचर जर्नल में इस डिवाइस के बारे में विस्तार से बताया गया है। प्रतीकात्मक

शोधकर्ताओं ने बताया कि एयर-जेन डिवाइस के लिए छोटे प्रोटीन तारों की एक पतली फिल्म की आवश्यकता होती है, जो 10 माइक्रोमीटर से कम मोटी होती है और जलवाष्प को अवशोषित करती है। इस फिल्म का निचला सिरा एक इलेक्ट्रोड पर टिका है, जबकि एक इलेक्ट्रोड इस फिल्म के ऊपरी सिरे पर टिका है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इन प्रोटीन वायरों में विद्युत प्रवाह की योग्यता और इसके सतह की विशेष बनावट दो इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं।

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि छोटे इलेक्ट्रानिक्स को बिजली देने के लिए इस डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि शोध का अंतिम लक्ष्य इस सिस्टम को बड़े पैमाने पर विकसित करना है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर यह सोचा जा रहा है कि इस प्रौद्योगिकी को दीवार के पेंट में शामिल कर दिया जाए, जिससे की पूरे घर के लिए आसानी से 24 घंटे बिजली मिल सके या फिर इस प्रौद्योगिकी से संचालित एक जनरेटर भी विकसित किया जा सकता है।

शोधकर्ताओं ने हाल ही में अधिक तेजी से और सस्ते में बड़े पैमाने पर प्रोटीन के तारों का उत्पादन करने के लिए एक सूक्ष्मजीव का आनुवंशिक संस्करण विकसित किया है।

कैंसर कोशिकाओं को सुन भी सकते हैं वैज्ञानिक

लंदन, एएनआइ : शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक नई तकनीक से अब यह पता लगाया जा सकता है कि लाखों अलग-अलग कोशिकाएं ट्यूमर में एक-दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करती हैं। शोधकर्ताओं ने इसका ऑर्गनॉइड में प्रयोग भी किया है। ऑर्गनाइड किसी भी अंग का प्रतिरूप होता है, जिसे लैब में तैयार किया जाता है। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की इस तकनीक को 'नेटर मैथड्स' जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

यह पहली बार है कि वैज्ञानिकों ने ट्यूमर की प्रतिकृतियों के भीतर एक बार में कई अलग-अलग सिग्नलिंग अणुओं का विश्लेषण किया। कोशिकाओं के आपसी कम्युनिकेशन प्रक्रिया को जानकर यह पता लगाया जा सकता है कि किस तरह से ट्यूमर प्रतिरक्षा प्रणाली से बच जाता है और उपचार के दौरान इतना प्रतिरोधी हो जाता है कि उस पर किसी का असर नहीं होता। यह समझकर शोधकर्ता और अधिक प्रभावी दवाओं को विकसित कर सकते हैं। इससे डॉक्टर प्रत्येक मरीज के ट्यूमर का अध्ययन करके उसके लिए विशेष उपचार भी कर सकेंगे। इस तकनीक से व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका का तेजी से विश्लेषण किया जा सकता है। ये कोशिकाएं संकेतन अणुओं की तलाश में रहती हैं, इनके माध्यम से वह पड़ोसी कोशिकाओं को बताती हैं कि उन्हें कैसा व्यवहार करना है। प्रमुख शोधकर्ता डॉ. क्रिस टेप ने कहा कि यह तकनीक यह समझने में मदद करती है कि कोई उपचार क्यों काम करता है और क्यों नहीं। यह भी पता चलता है कि कोशिकाएं संवाद कैसे करती हैं।

फोटो न्यूज

नीरो के कॉमिक अवतार में ट्रंप

जर्मनी के मैंज शहर में अगले सप्ताह होने वाले रोज मंडे कॉर्निवाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोम के सम्राट नीरो के अवतार में नजर आएंगे। जिसके बारे में उक्ति प्रचलित है, रोम जल रहा था तो नीरो बंशी बजा रहा था। उनके इस कॉमिक रूप को मंगलवार को हुए प्रेस रिव्यू में सार्वजनिक किया गया। इसमें ट्रंप के हाथ में स्मार्टफोन वाला वाद्य यंत्र है। जबकि पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस आग की लपटों में घिरा है। रायटर

सफाई उत्पादों से शिशुओं में अस्थमा का खतरा

शोध अनुसंधान

कपड़ा और बर्तन धोने के काम आने वाले साबुन और डिटरजेंट जैसे घरेलू साफ-सफाई के उत्पाद शिशुओं के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। एक नए अध्ययन में पाया गया कि इस तरह के उत्पादों की जद में रहने वाले शिशुओं में अस्थमा और श्वसन संबंधी समस्या का खतरा हो सकता है। उन्हें बचपन के दौरान इस समस्या सामना करना पड़ सकता है। सीएमएजे पत्रिका में छपे अध्ययन के अनुसार, सफाई उत्पादों का जन्म से लेकर चार माह के दौरान शिशुओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर गौर किया गया। इसके बाद तीन साल की उम्र में अस्थमा को लेकर इनकी जांच की गई। कनाडा की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता टिम टेकरो ने कहा, 'अध्ययन में उन शिशुओं पर गौर किया गया, जिनका ज्यादा समय घर में गुजरता है और वे रासायनिक पदार्थों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं।' -प्रेट्र

फल-सब्जियों के सेवन से बुढ़ापे में रह सकते हैं स्वस्थ

फलों और सब्जियों से भरपूर मेडिटेरेनियन डाइट का एक नया फायदा सामने आया है। इस तरह के खानपान से बुढ़ापे में स्वस्थ रहने में मदद मिल सकती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि यह डाइट नुकसानदेह सूजन की रोकथाम करने के साथ स्वस्थ बुढ़ापे से जुड़े गट (आंत) बैक्टीरिया को बढ़ावा दे सकता है। आयरलैंड की यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क के शोधकर्ताओं के अनुसार, बुढ़ापे का संबंध सेहत में गिरावट और इंफ्लेमेशन (सूजन) में बढ़ोतरी से होता है। मेडिटेरेनियन डाइट बुढ़ापे में शारीरिक दुर्बलता और स्मृति में गिरावट को रोकने में मददगार हो सकता है। यह निष्कर्ष 65 से 79 साल की उम्र वाले 612 लोगों पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। अध्ययन के प्रारंभ और अंत में इनके गट बैक्टीरिया का विश्लेषण किया गया था। इन्हें एक साल तक मेडिटेरेनियन डाइट और सामान्य आहार खाने को कहा गया था। मेडिटेरेनियन डाइट फलों, सब्जियों, बादाम, फलियां और मछली से भरपूर होता है। -प्रेट्र

स्क्रीन शॉट

'रन लोला रन' की हिंदी रीमेक में होंगी तापसी पन्नू

हिंदी सिनेमा में विदेशी फिल्मों की आधिकारिक रीमेक बनाने का चलन इन दिनों जोरों पर है। 'फॉरेस्ट गंप' फिल्म को हिंदी में 'लाल सिंह चड्ढा' नाम से बनाया जा रहा है, जिसमें आमिर खान मुख्य भूमिका में हैं। हॉलीवुड फिल्म 'गर्ल ऑन द ट्रेन' को इसी नाम से हिंदी में बनाया जा रहा है, जिसमें परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं। दीपिका पादुकोण और ऋषि कपूर 'द इर्टन' फिल्म के हिंदी रीमेक में काम कर रहे हैं। अब तापसी पन्नू ने भी अपनी

आगामी फिल्म की घोषणा कर दी है, जो वर्ष 1998 में जर्मन भाषा में बनी क्लासिक फिल्म 'रन लोला रन' की आधिकारिक हिंदी एडैप्टेशन होगी। फिल्म का नाम 'लूप लपेटा' होगा। इस फिल्म में तापसी के साथ अभिनेता ताहिर राज भसीन होंगे। यह आज के समय में सेट की गई थ्रिलर कॉमेडी फिल्म होगी, जिसका निर्देशन आकाश भाटिया करेंगे। फिल्म अगले वर्ष 29 जनवरी को रिलीज की जाएगी। 'रन लोला रन' में फ्रैंका पोटेन्टे और मॉरित्ज ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म 'मर्दानी' में विलेन की भूमिका निभा चुके ताहिर ने बताया कि 'रन लोला रन' उन्होंने बचपन में देखी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि वह इस फिल्म की हिंदी रीमेक में काम करेंगे। फिलहाल तापसी की फिल्म 'थप्पड़' 28 फरवरी को रिलीज हो रही है। उनके पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है। 'थप्पड़' के बाद वह फिल्म 'हसीन दिलरुबा', 'मिताली राज की बायोपिक 'शाबाश मिट्ठू' और 'रश्मि रॉकेट' जैसी फिल्मों में नजर आएंगी। वहीं ताहिर की अगली फिल्म '83' होगी, जिसमें वह पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर के किरदार में नजर आएंगे। गौरतलब है कि तापसी अभिनीत फिल्म 'बदला' भी स्पेनिश फिल्म 'द इनविजिबल गेस्ट' की आधिकारिक रीमेक थी।

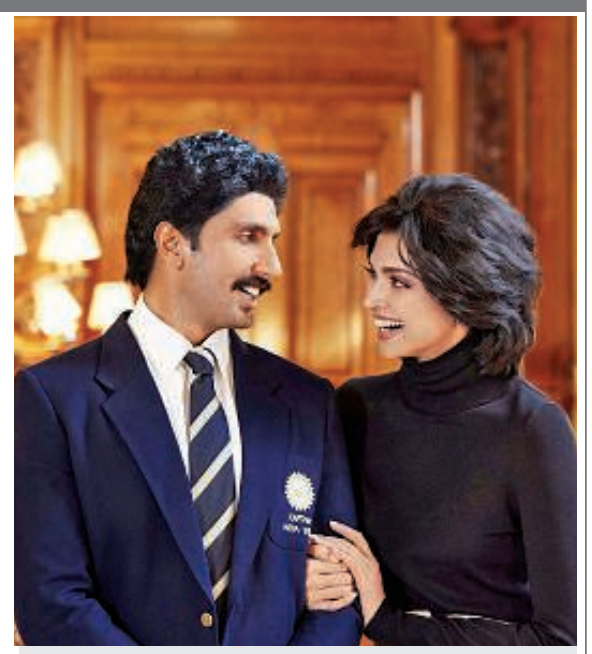

मिलिए '83' की रोमी देव से...

रियल लाइफ जोड़ी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पर्दे पर पहली बार शादी के बाद एकसाथ फिल्म '83' में नजर आएंगे। फिल्म में भी वह पति-पत्नी के ही किरदार में होंगे। रणवीर फिल्म में कपिल देव की भूमिका में होंगे, जबकि दीपिका उनकी पत्नी रोमी देव का किरदार निभा रही हैं। अब तक रणवीर और फिल्म से उनकी टीम के बाकी सदस्यों की तस्वीरें ही रिलीज हो रही थीं। दीपिका का लुक सामने नहीं आया था। अब मेकर्स ने दीपिका की झलक दिखा दी है। तस्वीर में दीपिका छोटे बालों में नजर आ रही हैं। किरदार को लेकर दीपिका का कहना है कि खेल के इतिहास से सबसे प्रतिष्ठित क्षणों में से एक फिल्म में एक छोटा-सा ही सही, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा निभाना उनके लिए सम्मान की बात है। उनका कहना है कि यह फिल्म हर उस महिला को समर्पित है, जो खुद से पहले अपने पति के सपनों को आगे रखती है। मेरी मां को मैंने यह करते हुए करीब से देखा है। '83' फिल्म 10 अप्रैल को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।

कुचिपुड़ी में प्रशिक्षित हैं मानुषी छिल्लर

फिल्म 'पृथ्वीराज' से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने जा रही मानुषी छिल्लर ने अपने पहले गाने की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि मानुषी संयोगिता की। वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गईं मानुषी प्रशिक्षित कुचिपुड़ी डांसर भी हैं। उन्होंने राजा व राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कुचिपुड़ी डांस का पर्याय माने जाने वाले राजा और राधा दंपती को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्मभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मानुषी ने बताया, 'बचपन में शास्त्रीय नृत्य में मिले प्रशिक्षण ने निश्चित रूप से 'पृथ्वीराज' के लिए मेरी मदद की है। मैं अपने माता-पिता की शुक्रगुजार हूं कि उस वक्त उन्होंने मुझ पर डांसिंग के लिए दबाव डाला, क्योंकि आज जब मुझे इन बड़े गीतों पर परफॉर्म करना है, तो यह करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। बड़े पैमाने पर फिल्माए गए इस गीत के बारे में वे कहती हैं कि निश्चित रूप से इसका फिल्मांकन काफी भव्य था, लेकिन डांसिंग में उनकी नींव मजबूत होने के कारण ही वे इस दबाव को मजबूती से झेल सकीं। वह कहती हैं, जिस डांस को मुझे परफॉर्म करना था, उसके पैमाने और स्टेप्स को देखकर मैं निश्चित रूप से अभिभूत थी, लेकिन रिहर्सल के दौरान मुझे

आत्मविश्वास महसूस होने लगा था। मुझे यकीन था कि मैं इसे कर सकती हूं और मैंने पहले जो कुछ भी सीखा था, वह सब मेरे पास वापस आ गया। मेरे निर्देशक और कोरियोग्राफर मेरे प्रदर्शन से खुश थे और इस बात से मैं भी खुश थी। यह मेरे लिए काफी मायने रखता है।'

कियारा ने कार में स्वीकार की थी 'गिल्टी'

पिछले साल 'कबीर सिंह' और 'गुड न्यूज' जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आने वाली कियारा आडवाणी डिजिटल में भी सक्रिय हैं। वह नेटफ्लिक्स की आगामी फिल्म 'गिल्टी' में नजर आएंगी। दो साल पहले वह 'लस्ट स्टोरीज' में नजर आ चुकी हैं। मंगलवार को मुंबई में फिल्म 'गिल्टी' के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर कियारा ने बताया कि करण जौहर ने उन्हें इस फिल्म की कहानी कार में कहीं जाते हुए सुनाई थी। करण को लगता था कि बड़ी फिल्में करने के बाद उन्हें इस फिल्म में काम करने में हिचक होगी, लेकिन कियारा ने कहानी सुनते ही अपनी स्वीकृति दे दी थी। फिल्म का निर्देशन रुचि नारायण कर रही हैं। रुचि ने कहा कि वह अपनी एक दूसरी फिल्म को लेकर कई बड़े सितारों के पास गई थीं, लेकिन महिला निर्देशक होने के कारण किसी ने भी उस फिल्म में काम करना स्वीकार नहीं किया। इस घटना का प्रभाव 'गिल्टी' में दिखेगा। इस फिल्म को करण और नेटफ्लिक्स ने मिलकर बनाया हैं। यह फिल्म छह मार्च को रिलीज होगी।

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' में आसिम को कास्ट नहीं कर रहे हैं करण जौहर

सोशल मीडिया पर खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। मंगलवार को 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' को लेकर खबरें आने लगीं कि करण जौहर आसिम रियाज और शाह रुख खान की बेटी सुहाना को इस फिल्म से लॉन्च करेंगे। आसिम रियलिटी शो 'बिग बॉस सीजन 13' के पहले रनअप थे। इन खबरों के तूल पकड़ने पर करण जौहर को सोशल मीडिया पर अपना रुख साफ करना पड़ा।

उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' को लेकर चल रही खबरों का खंडन किया।